{ संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 14 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

चुनावों के बीच बहस की मांग

18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव की प्रक्रिया आधी से अधिक पूरी हो चुकी है। सात में से चार चरणों के मतदान हो गए हैं अब केवल तीन चरण बाकी रह गए हैं। देश भर में राजनैतिक दलों की रैलियां और सभाएं हो रही हैं। टीवी और अखबारों में साक्षात्कारों का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन इन सबमें जनहित और देशहित के मुद्दों पर ठोस जवाब सामने नहीं आ रहे, बल्कि आरोप-प्रत्यारोप ही अधिक हो रहे हैं। मिसाल के लिए, अभी एक चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के वक्त महंगाई सबसे अधिक थी और इसी में श्री मोदी ने पं.नेहरू के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए द.कोरिया और उ.कोरिया की लड़ाई को जिम्मेदार बताया था, जबकि उसका प्रभाव यहां की अर्थव्यवस्था पर नहीं था। वह केवल बहाना ढूंढते थे।

10 साल सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अब भी इंदिरा गांधी या नेहरूजी के वक्त के शासन की कमियां गिना रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि वे अभी के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। 10 सालों में एक भी खुली प्रेस कांफ्रेंस न करने वाले नरेन्द्र मोदी इस चुनाव के वक्त अलग-अलग मीडिया घरानों के पत्रकारों को साक्षात्कार तो दे रहे हैं, लेकिन उनमें भी मुद्दों पर बात नहीं हो रही, केवल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमले हो रहे हैं। साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार भी सत्ता के प्रायोजक की भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि उनके सवालों में कोई धार नहीं दिखाई देती, न ही जवाबों पर प्रतिप्रश्न किए जाते हैं। जो कुछ नरेन्द्र मोदी के मुंह से निकल गया, उसे अमृतवाणी की तरह दर्शकों के लिए परोस दिया जाता है। इस तरह की पत्रकारिता से मीडिया घरानों का भला हो सकता है, देश का नहीं।

इस निराशाजनक स्थिति के बीच देश के दो पूर्व न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को सीधी बहस करने के लिए चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, और वरिष्ठ पत्रकार एवं द हिंदू के पूर्व एडिटर-इन-चीफ एन राम ने अपने पत्र में कहा है कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारे चुनावों पर दुनिया की नजर है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गैर-पार्टी और गैर-व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पर बहस करना चाहिए। इन तीनों ने पत्र में लिखा है कि रैलियां और भाषणों में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ने ही हमारे संवैधानिक लोकतंत्र से जुड़े अहम सवाल पूछे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सबके सामने कांग्रेस को आरक्षण, आर्टिकल 370 और संपत्ति के बंटवारे पर घेरा है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से संविधान, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, चीन के अतिक्रमण पर सवाल पूछे हैं और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है। पत्र में लिखा है कि हमें लगता है कि अगर एक गैर-दलीय और गैर-व्यावसायिक मंच पर सार्वजनिक बहस के जरिए जनता सीधे तौर पर हमारे नेताओं का पक्ष सुनेगी तो इससे जनता को फायदा होगा। हमें लगता है कि इससे हमारी संविधानिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। पत्र में यह भी लिखा है कि यह बहस कहां होगी, कितनी देर की होगी, इसमें सवाल कौन पूछेगा और इसका प्रारुप क्या रहेगा, यह श्री मोदी और राहुल गांधी दोनों की सलाह पर तय किया जा सकता है। अगर ये दोनों नेता बहस के लिए नहीं आ सकते हैं, तो वे अपनी तरफ से किसी को प्रतिनिधि के तौर पर भेज सकते हैं।

इस पत्र पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा की है और वे इसके लिए तैयार हैं। श्री गांधी ने लिखा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विज़न देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है।

हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से इस पर कोई जवाब देखने नहीं मिला है। अलबत्ता भाजपा के नेताओं और आईटी सेल के लोगों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाना जरूर शुरु कर दिया कि वे किस हैसियत से प्रधानमंत्री मोदी से बहस करेंगे। वे तो इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं हैं। लेकिन भाजपा के नेता यह भूल गए कि इस बहस के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कोई योग्यता है ही नहीं। श्री मोदी और श्री गांधी दोनों लोकसभा के सांसद हैं और अपनी-अपनी पार्टियों की ओर से उम्मीदवार भी, इस नाते दोनों के बीच सीधी बहस हो सकती है।

लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नरेन्द्र मोदी राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी भी नेता से सीधी बहस के लिए तैयार होंगे या नहीं। क्योंकि जब कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर उन्होंने भ्रामक बातें कहनी शुरु की, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनसे लिए चर्चा का वक्त मांगा था। वह वक्त आज तक श्री खड़गे को नहीं मिला। इस बीच स्मृति ईरानी जैसे नेता राहुल गांधी को ललकारते और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से बहस के लिए चुनौती देते नजर आए। यानी भाजपा बहस की बात तो करती है, लेकिन बहस करने के लिए तैयार नहीं होती।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में दोनों दलों के उम्मीदवारों के बीच सार्वजनिक बहस की परंपरा रही है। लेकिन भारत में चुनावों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और यहां दो दल नहीं, अनेक दलों वाली लोकतांत्रिक राजनीति होती है। इसलिए अमेरिका जैसी परंपरा यहां लागू नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मुद्दों पर आधारित सार्वजनिक बहस अगर दो प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं के बीच हो और गड़े मुर्दे उखाड़ने या निजी प्रहार करने की जगह तर्कों के साथ जवाब दिए जाएं, तो वाकई लोकतंत्र का बहुत भला होगा। भाजपा फिलहाल इस बहस के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बहस के बहाने राहुल गांधी पर प्रहार के लिए तैयार है। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा इस वक्त कितने पानी में है।

देखी तेरी तानाशाही!

कथा

2024 का चुनाव पलट चुका है? एक नहीं, कई इशारे हैं जो बताते हैं चुनाव पलट चुका है। बल्कि योगेंद्र यादव के शब्दों का सहारा लें तो इस बार चुनाव, 'मंझधार में पलट' चुका है। बेशक, तीसरे चरण के मतदान के साथ ही चुनाव आधे से ज्यादा गुजर चुका था। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई के मतदान के साथ, तीन-चौथाई चुनाव गुजर चुका है। जाहिर है कि अब तक चुनाव में सामने आए रुझानों को इस माने में इस पूरे चुनाव के रुझान की तरह लिया जा सकता है कि यहां से आगे बचे हुए चरणों में, बड़ी उलट-फेर की संभावना बहुत सीमित हो गई है।

चुनाव के पलटने का पहला इशारा तो, जिसकी ओर हमने अपनी पिछली टिप्पणियों में भी ध्यान खींचा था, 2019 के चुनाव के मुकाबले मत प्रतिशत में गिरावट होना ही है। बेशक, पहले दो चरणों में शुरूआती आंकड़ों के आधार पर, 6 फीसदी से ऊपर की जिस भारी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, वह चुनाव आयोग द्वारा असामान्य देरी से जारी किए गए मतदान के अंतिम आंकड़ों में, अपेक्षाकृत थोड़ी रह गई है। फिर भी, यह गिरावट 3 फीसदी के करीब बनी रही है और लगभग ऐसी ही गिरावट तीसरे चरण में भी दर्ज हुई है। इशारा साफ है कि 2019 में मोदी की भाजपा को तीन सौ पार कराने वाली लहर अब उतर चुकी है और जाहिर है कि मोदी के दस साल के राज पर लोगों की नाराजगी के धक्के से उतर चुकी है। और यह इस पूरे चुनाव का ही सच है, न कि सिर्फ शुरूआती चरणों का। और भाजपा के दुर्भाग्य ये, जिस हिंदी पट्टी को वह अपना मुख्य आधार मानती है और जहां से ही 2014 तथा 2019 के आम चुनावों में उसे असली ताकत मिली थी, वहां पर यह उतार और भी ज्यादा रहा है, शेष देश के मुकाबले कम नहीं। चौथे चरण में भी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, मत फीसदी में 2019 से भारी कमी के ही संकेत हैं।

दूसरा इशारा, जो वास्तव में इस पहले इशारे से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से पहले चरण के बाद से ही रंग-ढंग भांपकर, खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई में भाजपा के अपने दस साल के रिकार्ड से लेकर, अपने चुनावी घोषणापत्र तक और यहां तक कि मोदी की गारंटियों को भी बाजू में रखकर, हिंदुत्व की सांप्रदायिक दुहाई पर अपने प्रचार को केंद्रित करना है। बेशक, यह चुनाव आयोग की मदद के बिना नहीं हो सका है कि सिर्फ विरोधी राजनीतिक पार्टियों की ही नहीं, सामाजिक-नागरिक संगठनों की तमाम शिकायतों के बावजूद, मोदी की भाजपा ने इस खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक दुहाई को इस चुनाव में अपने प्रचार की स्थायी सिग्नेचर धुन बनाए रखा है।

बहरहाल, इसके साथ अपने मनुवादी चरित्र से प्रवाहित होते सवर्ण वर्चस्ववादी तथा मर्दवादी मूल्यों व आग्रहों के व्यवहार और विशेष रूप से महिलाओं समेत वंचित तबकों के शक्तिकरण के अपने विरोध को छुपाने की कोशिश को जोड़ते हुए, मोदी एंड कंपनी ने अपने बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक आग्रहों को जरा नवोन्मेषी शब्दावली देने की कोशिश भी की है। इसमें जाहिर है कि बिना किसी भी आधार के ही यह दावा किया जाता रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आ गई तो वे दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्ग को हासिल आरक्षण छीनकर, मुसलमानों को दे देंगे, जो उनके वोट बैंक हैं! कहने की जरूरत नहीं है कि हालांकि इसमें आरक्षण के मुद्दे पर अपने संदिग्ध रुख तथा अपने नेताओं के बीच से आई संविधान ही बदल डालने की हूंकारों से, इसी सब के लिए विरोधियों पर ही हमला करके अपना बचाव करने कोशिश भी है; फिर भी इसमें भी केंद्रीय सूत्र मुस्लिमविरोधी दुहाई का ही है। मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे के दावों के पीछे भी मुख्य धुन, हिंदू खतरे में है की ही है।

राजेन्द्र शर्मा

> **चुनाव के पलटने का पहला इशारा तो, जिसकी ओर हमने अपनी पिछली टिप्पणियों में भी ध्यान खींचा था, 2019 के चुनाव के मुकाबले मत प्रतिशत में गिरावट होना ही है। बेशक, पहले दो चरणों में शुरूआती आंकड़ों के आधार पर, 6 फीसदी से ऊपर की जिस भारी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, वह चुनाव आयोग द्वारा असामान्य देरी से जारी किए गए मतदान के अंतिम आंकड़ों में, अपेक्षाकृत थोड़ी रह गई है। फिर भी, यह गिरावट 3 फीसदी के करीब बनी रही है।**

और चूंकि चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया है, वैसे-वैसे ठीक इसी धुन को तेज से तेज करने की हड़बड़ी बढ़ती गई है, इस आख्यान की सेवा के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद तक को उतार दिया गया है। इस परिषद ने बिना किसी प्रसंग के चुनाव के बीचो-बीच एक परिपत्र प्रकाशित किया है, जो अब काफी पुराने पड़ गए आंकड़ों के सहारे, प्रकटत: तो यह साबित करने की कोशिश करता है कि अन्य अनेक देशों के विपरीत, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसे ठीक-ठाक है, लेकिन चुनाव के बीचो-बीच इसके खास संघी प्रचार को हवा देने का काम ही ज्यादा करता है कि भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है यानी हिंदू खतरे में हैं! कहने की जरूरत नहीं है कि भाजपा-आरएसएस के औपचारिक चुनाव प्रचार से भी बढ़कर, अनौपचारिक प्रचार में, इस 'खतरे' को जमकर उछाला गया है।

बेशक, इसी दौरान एक अवांतर प्रसंग के रूप में कांग्रेस के घोषणापत्र का नाम लेकर, पुनर्वितरण से जुड़ी धन्नासेठों की आशंकाओं से लेकर, साधारण लोगों की गलतफहमियों तक को भुनाने का भी प्रयास किया गया है। इसके पीछे वामपंथ का, संघ-भाजपा का बुनियादी डर भी काम कर रहा था, जिसके चलते कांग्रेस के घोषणापत्र पर यह कहकर हमला किया गया कि वह वामपंथ के प्रभाव में तैयार किया गया है! गहरी विडंबना है कि एक ओर आम लोगों की विपन्नता तथा साधनहीनता और दूसरी ओर मुट्ठीभर डालर अरबपतियों की संपन्नता में धरती-आकाश के अंतर को अश्लीलता की हद तक बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ही कथित पुनर्वितरण के डर को, वंचित साधारण जन की अपनी नगण्य सी परिसंपत्तियों की हिफाजत की चिंताओं तक भी फैला दिया। इसी सब को आगे बढ़ाते-बढ़ाते प्रधानमंत्री, तेलंगाना में एक चुनाव सभा में कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए, यह आरोप लगाने की हद तक चले गए कि उसे अडानी-अंबानी से टैंपो-टैंपो भर नोट मिले हैं!

बेशक, मोदी को फौरन इसका एहसास हो गया कि विपक्ष पर प्रहार करने की हड़बड़ी में, वह तो अपने पक्के दोस्तों पर ही चोट कर बैठे थे और उसके बाद दोबारा मोदी की जुबान पर यह दलील नहीं आई। बहरहाल, विपक्षियों के संपत्ति छीन लेने के 'डर' को शुरू से ही, 'मुसलमानों को बांट देंगे' के साथ जोड़ने के बावजूद, इसका खास असर न होता देखकर, मोदी और उनकी भाजपा ने संपत्ति छिनने के डर से हटाकर, 'आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देंगे' की ओर बढ़ा दिया। और मोदी की पिछली सारी गारंटियों को किनारे कर अब एक नयी गारंटी दी जाने लगी—'जब तक मोदी जिंदा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने नहीं देगा'; 'धर्म के आधार पर (यानी मुसलमानों और ईसाइयों को भी) आरक्षण देने नहीं देगा! ऐसा लगता है कि मोदी की भाजपा, जाति के छोंक के साथ, सांप्रदायिकता की इसी दुहाई के सहारे, अब अपना बाकी सारा का सारा चुनाव अभियान चलाने जा रही है।

बहरहाल, हाथ से फिसलते लग रहे चुनाव पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मोदी की भाजपा एक ओर अगर चुनाव आयोग की मदद से, सांप्रदायिकता के हथियार का खुलकर इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी ओर उसी चुनाव आयोग की मदद से, चुनाव की सीधी लूट का और जनता की जनतांत्रिक राय को कुचलने का सहारा ले रही है। सूरत से लेकर इंदौर तक और उससे पहले खजुराहो में तथा बाद में गांधीनगर में जो कुछ हुआ, उसे तो बेशक एक हद तक जनमत के स्तर पर दर्ज भी किया गया है, लेकिन चौथे चरण के मतदान की पूर्व-संध्या में कश्मीर में जो हुआ है और मतदान के दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, अनेक मुस्लिम इलाकों में जो कुछ हुआ है, उसे जनतंत्र की लूट ही कहना पड़ेगा। और इस जनतंत्र की लूट को और बहुत बड़ा बनाता है साधारण जनता के बीच बैठाया गया और चुनाव प्रचार के नाम पर लगातार पुख्ता किया जाता रहा आतंक, जो साधारण लोगों के लिए स्वतंत्रता से और स्वविवेक से, अपनी राय बनाने का रास्ता ही, एक पक्की दीवार खड़ी कर के बंद करने की कोशिश करता है। वैकल्पिक मीडिया में आ रहीं अनेक मैदानी रिपोर्टें अब धीरे-धीरे इस सच्चाई को सामने ला रही हैं कि आम लोगों के बीच फैला आतंक, न सिर्फ उनकी राय को अभिव्यक्त होने से रोकता है बल्कि स्वतंत्र रूप से उस राय के बनने को भी बाधित करता है। यही हरेक तानाशाही का लक्ष्य होता है।

इस सब के बावजूद, सारे इशारे इसी के हैं कि जनता मौजूदा निजाम की तानाशाही को खारिज कर रही है, बीच मंझधार में चुनाव पलट रहा है। अनेक इशारों के बीच इसका एक इशारा गोदी मीडिया के एक हिस्से में स्वरों का बदलना शुरू होना है। एक ओर इशारा शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव और देसी-विदेशी निवेशकों का बाजार से अपने हाथ पीछे खींचना है। बेशक, इस बदलाव का सबसे बड़ा साधन है, विपक्ष का हमलावर तेवर के साथ, लड़ाई के मैदान में उतरना और सत्ता को सीधे चुनौती देना। यह मौजूदा सत्ता के वर्चस्व को ही नहीं, लोगों के बीच उसके आतंक को भी तोड़ रहा है। लेकिन, हताश तानाशाह क्या आसानी से सत्ता हाथ से निकल जाने देगा। वह भी तब जब उसे चुनाव आयोग जैसी पालतू संस्थाओं का सहारा हासिल है। इसीलिए, जितनी उम्मीद की जगह है, उतनी ही दु:शंकाओं की वजह भी है। बेशक, जनता और तानाशाह की लड़ाई में हमेशा जीत जनता की ही होती है। लेकिन, अक्सर भारी कीमत चुकाने के बाद।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

केजरीवाल ने बहुत ही बिगाड़ दी भाजपा की रणनीति

■ सुशील कुट्टी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से यह और भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के यह संयोजक राजनीतिक रूप से कोई 'आम आदमी' नहीं बल्कि 'खास आदमी' हैं, जैसा कि तिहाड़ जेल में बंद दोनों आप नेता पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येन्द्र जैन। भाजपा को केन्द्र की सत्ता से बाहर करने की इंडिया गठबंधन की योजना के लिए आप संयोजक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हैं।

अरविंद केजरीवाल की पात्रता और 'खास आदमी' की स्थिति की पुष्टि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, जिसे आप संयोजक को 21 दिनों के लिए 'अंतरिम जमानत' देने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। आम चुनाव में प्रचार के लिए आप संयोजक को जमानत दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल आप के स्टार प्रचारक हैं, हालांक उन्हें बढ़चढ़कर अजीबोगरीब चुनावी वायदे करने के लिए जाना जाता है, और साथ में राजनीतिक अराजकता पैदा करने के लिए भी।

अपनी कार्यशैली के अनुरूप ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद मैदान में उतरे। आप कार्यकर्ताओं को 11 मई को कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में इकट्ठा होना था। यह ज्ञात है कि आप संयोजक अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए भगवान हनुमान का नाम लेते हैं। लोग यह भी भूल जाते हैं कि केजरीवाल 'बहुत चतुर राजनेताओं' की सूची में हैं और राजनीतिक विरोधी उन्हें 'चालाक' के रूप में उच्च दर्जा देते हैं।

तिहाड़ से बाहर निकलते हुए ही केजरीवाल ने मतदाताओं से 'भारत को तानाशाही से बचाने' का आग्रह किया। यह और बात है कि मीडिया अक्सर केजरीवाल को तानाशाह समझने की भूल कर बैठता है। जिन पत्रकारों ने केजरीवाल को नीचा दिखाया, उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है और इसमें एक युवा महिला पत्रकार भी शामिल है, जिसने केजरीवाल के 'शीश महल' पर स्टोरी ब्रेक की थी। उसने सलाखों के पीछे समय बिताया और उसके मीडिया मित्रों ने 'कष्टप्रद अनुभव' पर रिपोर्ट की। केजरीवाल में एक क्रूर प्रवृत्ति भी है जिसे कोई भी केवल अपने जोखिम पर ही नजरअंदाज कर सकता है।

केजरीवाल का जेल प्रवास 2 जून को फिर से शुरू होगा। इसका मतलब है कि जब 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आयेंगे तो दिल्ली का यह ताकतवर नेता सलाखों के पीछे होगा। केजरीवाल की जेल कोठरी की दीवार पर एक टीवी सेट है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इंडिया गठबंधन की जीत के लिए प्रार्थना कर रही होंगी। केजरीवाल गठबंधन के शीर्ष नेता हैं और दो राज्य उनकी सीधी कमान और प्रभाव में हैं।

केजरीवाल की पार्टी अक्सर डींगें हांकती रहती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक आदमी से डरते हैं तो वह हैं 'सच्चे अरविंद केजरीवाल'। उस मामले में, सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सीधे तौर पर मोदी के साथ प्रतिस्पर्धा में है, जो शीर्ष अदालत पर डर के कारण 'खास आदमी' पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निष्पक्षता के ऊपर इस थोपे हुए आरोप के साथ रहना होगा।

हालांकि, लोगों को पता होगा कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की शर्तों के साथ दंडित किया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जेल से बाहर रखा गया है। वहां एक अंतर है। अगर और जब ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जायेगा, तभी केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक के रूप में दोगुना नुकसान होगा।

तब तक कोई भी केजरीवाल को मिलने वाली सांत्वना से नाराज नहीं हो सकता। ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या केजरीवाल के इस दावे में दम है कि उनकी गिरफ्तारी उन्हें 2024 के आम चुनावों से बाहर रखने के लिए की गई थी? शीर्ष अदालत की अंतरिम जमानत में 'हां' लिखा है। अरविंद केजरीवाल कोई मामूली प्रचारक नहीं हैं और वह राजनीतिक रूप से सभी सही कदम उठाते हैं। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद उनके पहले शब्द थे, 'हमें इस देश को तानाशाही से बचाना है और मैं इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूं।'

भारत भर में राष्ट्रीय मीडिया और समर्थकों ने इसे हाथोंहाथ लिया। भाजपा को कतई उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल 21 दिन के लिए चुनाव मैदान में आ धमकेंगे। केजरीवाल के सौजन्य से, 'तानाशाही को हराना है' इंडिया गठबंधन का नवीनतम नारा है। फिर 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान के साथ, केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। आप संयोजक जगह-जगह जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत, वह सवालों के जवाब देने से नहीं डरते।

> **अदालत की निगरानी में प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू है और केजरीवाल को इस अंतर का ध्यान रखना होगा कि वह क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं? संभावनाएं प्रबल हैं कि आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से नियम तोड़ेंगे, इससे पहले कि 25 मई को दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो।**

लेकिन अदालत की निगरानी में प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू है और केजरीवाल को इस अंतर का ध्यान रखना होगा कि वह क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं? संभावनाएं प्रबल हैं कि आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से नियम तोड़ेंगे, इससे पहले कि 25 मई को दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो।

2014 और 2019 में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस बार अलग चुनावी नतीजा हो सकता है। इसलिए, केजरीवाल का डर खुला है। अगर आप दिल्ली की आधी सीटें भी जीत जाती है, तो यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी हार होगी, जिनकी '400 पार' ने उनकी नसों पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। इतना कि दबंग भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सज़ा सहना बहुत भारी हो गया है।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो खुद जमानत पर हैं, ने कहा, 'सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। तानाशाही खत्म होगी। सत्यमेव जयते।' 'यह नियमित जमानत नहीं है। यह एक अंतरिम जमानत है। वह प्रचार कर सकते हैं लेकिन जब भी वह प्रचार करने जायेंगे, लोगों को उत्पाद शुल्क स्कैम की याद भी दिला जायेंगे,' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया।

अमित शाह सही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी अपनी मुसीबत से बाहर नहीं हैं। आम चुनाव में भाजपा को हराना ही संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता है। आप-कांग्रेस गठबंधन को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। क्या 4 जून को इंडिया गठबंधन विजेता बनेगा? यह लाख टके का सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं जैसे जवाब पहले से ही ईसीआई की वेबसाइट पर है। अरविन्द केजरीवाल बेहतर जानते हैं। केजरीवाल बहुत ही कम समय के पट्टे पर हैं और उन्हें इस अल्पकालिक आज़ादी का अधिकतम लाभ उठाना है।

पावन प्रसंग

किशोर मन की सुकोमल भावनाएं

किशोर मन संवेदनशील होता है। यह खिलते हुए पुष्प के समान है। अगर हम अपने मित्रों व परिवार के लोगों को भी चुन सकते तो कितना सुखद होता। यह सिर्फ एक उक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई है। खासतौर से जब किशोरावस्था में भाई-बहनों के बीच तनावपूर्ण संबंध हो तो ऐसी स्थिति में किशोरों के मन में ऐसा ख्याल आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उम्र का ऐसा दौर है, जब किशोरों का कोमल मन छोटी-छोटी बातों से भी आहत हो उठता है, और इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। ज्यादातर मनोचिकित्सकों का ऐसा मानना है कि पिछले दस वर्षों के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जो बहनों और भाईयों के बीच मनमुटाव, ईर्ष्या और हिंसा से संबंधित थे। लगातार पनप रहे आपसी तनाव ने किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। किशोरों की इस समस्या के लिए अकेले अभिभावक ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। मसलन, अगर भाई-बहनों में झगड़ा हो तो अक्सर जो बड़े होते हैं उन्हें ही डांटा जाता है। ऐसे में बड़े को ये लगता है कि काश! हम भी छोटे होते तो हमें भी डांट नहीं पड़ती। हमें भी माता-पिता से ज्यादा प्रेम मिलता। मनोचिकित्सकों का मानना है, परिवारों में संवादहीनता की स्थिति ने भाई-बहनों के आपसी द्वेष को बढ़ावा दिया है। कुछ सामाजिक रूढ़ियों के कारण माता-पिता बच्चों की तुलना अक्सर एक दूसरे से करने लगते हैं। प्राय: ऐसे मामले देखने में आता है, जिनमें बच्चा अपने रंग-रूप और योग्यता को लेकर कुंठा से पीड़ित होता है। अपने भाई या बहन से तुलना किए जाने के कारण ऐसे बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की होती है कि परिवार में किशोर हो रहे बच्चों की भावनाओं को अभिभावक समझने की कोशिश करें और उन्हें भी खुलकर अपने मन की बातें कहने की स्वतंत्रता दें।

बहुधा ऐसा देखा जाता है कि दो बच्चों के बीच रंग-रूप बुद्धिमत्ता और कॅरियर को लेकर तुलना करने से उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। किशोरों के लिए यह स्थिति खासतौर पर घातक है. फैशन और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव की वजह से किशोरों में अपने बाहरी व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाने की ललक पैदा हुई है। ऐसे में सामान्य शक्ल-सूरत वाले किशोरों के मन में हीनभावना पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्षमा, धैर्य और प्यार से किशोर अपने भाई-बहनों की समस्याओं को समझकर उनका हल निकाल सकते हैं। जरुरत है तो सिर्फ भावनात्मक सहयोग की, जो कि पूरे परिवार की तरफ से मिलना चाहिए। परिवार में दो किशोरों के बीच तनाव और ईर्ष्या-द्वेष की भावना विकसित न हो इसके लिए जरूरी है कि अभिभावक शुरू से ही उनके व्यवहार को नियंत्रित रखें और बच्चा समझकर उनकी गलतियों को अनदेखा न करें। इस संबंध में समाजशास्त्री डॉ नैन्सी का कहना है कि माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के सामने अपना व्यवहार भी शालीन और संयत रखें। तभी माता-पिता का अनुसरण करते हुए अपने भाई-बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे और उन्हें यह सीख घर पर ही दी जानी चाहिए।

एक ही माता-पिता की संतान होने और एक ही माहौल में परवरिश होने की वजह से भाई-बहनों के बीच प्यार का बंधन स्वत: मजबूत होता है। लेकिन इसी वजह से इनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न होती है। यही ईर्ष्या आगे चलकर किशोरों में कुंठा को जन्म देती है। जरूरत है तो सिर्फ उनके मार्गदर्शन की, जो कि माता-पिता ही दे सकते हैं। किशोरों को कुंठित बनाने में माता-पिता के भी नकारात्मक नजरिये की भी भूमिका होती है। इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ सकारात्मक सोच की, प्यार की। किशोर का हाथ थामने की। तभी वह घर-परिवार व समाज में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा। किशोरों में अनेक प्रकार की समस्याएं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनके समाधान के लिए माता-पिता को मनोचिकित्सक की सलाह लेने में झिझकना नहीं चाहिए। उनके सही मार्गदर्शन से किशोरों की यह समस्या दूर हो सकती है।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

मातृ दिवस मनाने का औचित्य क्या है?

12 मई को पूरे विश्व में मातृ दिवस मनाया गया। भारत में भी मनाया गया है। एक दिन माता का सम्मान किया जाता है फिर सब भूल कर महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो जाता है। भारत में जिस तरह से मातृशक्ति का अपमान, शोषण एवं अत्याचार होता है, तो यह मातृदिवस मात्र एक दिखावा भर लगता है। आखिर वह कौन लोग हैं जो मातृशक्ति का शोषण करते हैं, अपराध करते हैं? रोजाना समाचार पत्र में मातृशक्ति के प्रति अत्याचार की घटनाओं के समाचार से भरा रहता है। इसके जिम्मेदारी कौन है? जिस घिनौने तरीके से महिलाओं का शोषण किया जाता है यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे अधिक तो कमजोर तबके की मातृशक्ति के साथ भयानक अत्याचार होते हैं। उनको एहसास कराया जाता है कि तुम सामंती व्यवस्था में केवल एक ऑब्जेक्ट हो। दूरदराज के इलाकों से ऐसी मन को विचलित करने वाली घटनाएं सामने आती हैं कि लगता है हम 18 वीं शताब्दी में जी रहे हैं, अंधकार युग में जी रहे हैं। देश की सभी सरकारों को मातृशक्ति के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए आगे आना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा जिसको अभी तक नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों और सरकार के नारों से कुछ भला नहीं होने वाला है। सरकार किसी की भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब प्रत्येक परिवार अपनी जिम्मेदारी ले कि उसका बेटा किसी की बहन-बेटी के साथ अत्याचार नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, इज्जत की निगाह से देखेगा और बराबर का दर्जा देगा। तब कहीं जाकर समस्या का हल होगा। अकसर बेटी को यह कहा जाता है कि रात को देर से घर मत आना, लेकिन परिवार को बेटे से पहले कहना होगा कि आप को रात को देर से नहीं आना है। परिवार की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है और सरकार के कठोर कदम भी लाभदायक हो सकते हैं, दोनों का समन्वय बेहद जरूरी है। न्यायपालिका की भूमिका इन दोनों संस्थाओं से बड़ी है यदि 3 महीने के अंदर रेपिस्ट /दरिंदे को फांसी की सजा हो जाती है तो काफी हद तक इन घटनाओं पर रोक लग सकती है।

विरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

मिलावटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दरकार

राजधानी जयपुर मिलावटियों की भी राजधानी बनती जा रही है। जी हां यहां हर चीज में मिलावट है जो धीमे जहर की तरह लोगों को अनेकों बीमारियों और फिर श्मशान के रास्ते पर धकेल रही है। लगता है कि मिलावट के इस खेल में बड़ी मछलियां और बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में जयपुर में मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कानून में कड़े प्रावधान नहीं होने की वजह से ये लोग कुछ दिन की सजा और जुर्माना भरकर फिर इस धंधे में उतर जाते हैं। जयपुर के गलता गेट इलाके में एक गोदाम पर रविवार सुबह खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मार 200 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर उसे नष्ट कराया। टीम ने पनीर ले जा रही कार को सीज कर लिया और गोदाम मालिक पर 47 हजार रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया।

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में इससे पहले भी एक केक बनाने वाली कम्पनी पर कार्रवाई की गई थी और वहां से बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ और दूषित केक फिंकवाया गया था। कई जगह तेल में मिलावट मिली है। मसालों में मिलावट मिली है। कई ढाबों और होटलों पर तय मापदंडों के हिसाब से साफ सफाई नहीं मिली। कई जगह बिना लाइसेंस के काम किया जा रहा था। पकड़ा गया पनीर हानिकारक सपरेटा दूध से बनाया गया था और देखने पर खराब और मिलावटी लग रहा था। इस दौरान पनीर से बदबू भी आ रही थी। उस पनीर के सैंपल लिए और सारे पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया। सैंपल लेने और पनीर को नष्ट करवाने के बाद कारोबारी अभिषेक और उसके कर्मचारी बलबीर को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस टीम ने जिस गाड़ी में पनीर रखा था, उससे भी जब्त किया है। इसी पनीकर विक्रेता के यहां इससे पहले कई बार कार्रवाई हो चुकी है। मतलब साफ है कि ये व्यापारी कुछ सजा प्राप्त करने के बाद वापिस आता है फिर अपना यही धंधा संभाल लेता है। ऐसे में कानून बनाने वाली केन्द्र और राज्य सरकार से इस बात की दरकार है कि वह मिलावटी और नकली समान बेचने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए और इन पर हत्या जैसी धाराओं में मुकदमें चलने चाहिए।

पीओके के हाथ से निकल जाने के डर से सहमा पाकिस्तान

पीओके के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। पीओके में आजादी के नारे लगने एवं उसे लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग के बाद शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों सकते में है। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ पीओकी की जनता जिस तरह खड़ी हो गई, उसने पाकिस्तानी नीति निर्माताओं को तनाव में ला दिया है। हजारों की संख्या में कश्मीरी लोग पीओके में जगह-जगह सड़कों पर उतर आए तो पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा है। पीओके में विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी दमन चक्र शुरू हो गया है। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स और फंटियर कोर को भी लगाया गया है।

ललित गर्ग

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान सरकार की तानाशाही, उदासीनता, उपेक्षा एवं दोगली नीतियों के कारण हालात बेकाबू, अराजक एवं हिंसक हो गये हैं। जीवन निर्वाह की जरूरतों को पूरा न कर पाने से जनता में भारी आक्रोश एवं सरकार के खिलाफ नाराजगी चरम सीमा पर पहुंच गयी है। गेहूं के आटे और बिजली की ऊंची कीमतों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों एवं सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गयी जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर हैं। पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा था। पीओके की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया है एवं आन्दोलनकारियों को दबाने की दमनकारी कोशिशें की जा रही है। पीओके के बगावती तेवर देख पाकिस्तान के हाथ-पांव फूल गये हैं।

दरअसल, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कब्जे के बाद से ही पीओके लगातार सरकार की उपेक्षा, उत्पीडन एवं उदासीनता झेल रहा है। उसकी समस्याओं और विकास पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान का जोर वहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खोलने पर ज्यादा रहा। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके का इस्तेमाल भारत में अशांति, आतंक एवं हिंसा फैलाने के लिये किया है, वह पीओके के माध्यम से कश्मीर को हडपने की हर संभव कोशिश करता रहा है, लेकिन वहां के निवासियों की जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं किया। यूं तो अभी समूचे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, गरीबी, महंगाई एवं आर्थिक दिवालियापन से घिरा है, दुनियाभर से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये झोली लिये घूम रहा पाकिस्तान भारत में अशांति एवं आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल, पाकिस्तानी कमरतोड़ महंगाई एवं जनसुविधाओं से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी देते समय कड़ी शर्तों लगाई थीं, जिसके कारण स्थिति और खराब हो गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी से दिक्कतें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इन्हीं जर्जर एवं जटिल हालातों के बीच पीओके के हालात पाकिस्तान के लिये नया सिर दर्द बन गया है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के मुजफराबाद मार्च को दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उतना ही उग्र हो रहा है। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी के मार्च और धरने के आह्वान के बाद बेकाबू होते हालात 1955 के अवज्ञा आंदोलन की यादें ताजा कर रहे हैं, जब पीओके के लोगों और पाकिस्तानी फौज में सीधा टकराव हुआ था। अब फिर पीओके के लोगों के उबलते गुस्से ने पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर बल बढ़ा दिए हैं, समस्या को अनियंत्रित एवं अनिश्चित हालात में पहुंचा दिया है। पीओके के सभी 10 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भाजपा की मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में पीओके को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत में शामिल करना पहले से निश्चित है। पीओके का ताजा संघर्ष एवं आन्दोलन भाजपा की राह को निश्चित ही आसान करेंगी। भारत के विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर की रियासत पर आक्रमण करने के बाद पीओके बनाया गया था। पाकिस्तानी सेना और आदिवासी हमलावरों के हमले के तहत, महाराजा हरिसिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पूरी रियासत पर कब्जा करने से रोक दिया। अब, लगभग सात-आठ दशक से अधिक समय के बाद, जबकि पाकिस्तान भारी वित्तीय, राजनीतिक और मानवीय संकट में फंस गया है, जबकि भारत अपने आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक मापदंडों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपनी सैन्य शक्ति को सशक्त कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, वहां के लोग शांति, शिक्षा, व्यापार एवं विकास की दृष्टि से नये कीर्तिमान गढ़ रहे हैं जबकि पीओके कम मानव विकास के साथ आर्थिक प्रगति से वंचित जनजीवन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। स्वयं को ठगा महसूस करते हुए पीओके की आम जनता अब शांति चाहती है, अमन चाहती है, विकास चाहती है, जोकि पाकिस्तान में रहते हुए असंभव है। दोगली नीतियों के चलते पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान खुलकर दोहन करता रहा, जबकि वहां के लोग ईंधन, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते रहे। पीओके के लोगों ने मई 2023 में बिजली की ऊंची दरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो एक साल बाद अब उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन से काफी पहले पीओके के लोगों का भारत के प्रति झुकाव समय-समय पर मुखर होता रहा है। पाकिस्तान की राजनीति की दूषित हवाओं ने पीओके की चेतना एवं सोच को आन्दोलनकारी बना दिया है। सत्ता के गलियारों में स्वार्थों की धमाचौकड़ी देखकर वहां के लोग समझ गये कि उनका शोषण एवं उत्पीडन ही हो रहा है। यही कारण है कि पिछले साल पीओके और गिलगित के लोगों ने पाकिस्तान की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने इलाकों को भारत के साथ मिलाने को ही अपने हित एवं शांतिपूर्ण जीवन के अनुरूप मानने लगे हैं। इसके लिये किये गये तब के प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वहां के लोग 'आर-पार जोड़ दो, करगिल को खोल दो' जैसे नारे लगाते नजर आए थे। वहीं, देश भर में गेहूं के आटे की कमी, बलूचिस्तान में उग्रवाद, अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष, पाकिस्तानी तालिबान द्वारा हमलों और एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ, पीओके में लोगों ने काफी कड़वे अनुभव किये हैं। निर्वासित पीओके नेता, शौकत अली कश्मीरी भी पीओके में लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने के लिए दिसंबर से विभिन्न देशों में बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जिनेवा में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि पाकिस्तान ने 1948 से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है लेकिन बदले में पीओके में लोगों को बेरोजगारी और निर्वासन मिला। अधिकांश लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

पीओके के लोग चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि गलियारे की आड़ में उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा और भारत के जवाबी हमले उन्हें झेलने पड़ेंगे। चूकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिये संभव नहीं रहा है, इसलिये बिना मतलब भारत के आक्रमण को झेलने से स्वयं को बचाने के लिये पीओके के लोग भारत में विलय को ही उचित मानते हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा है और भारत में विलय के स्वर उठ रहे हैं, उससे भविष्य में इस विवादित क्षेत्र पर निर्णायक पटकथा लिखे जाने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत को पीओके के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इससे हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल असर न पड़े एवं भविष्य की नीतियों का निर्धारण करने में सुविधा रहे।

आज का इतिहास

14 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- नीदरलैंड और इंग्लैंड ने 1702 में स्पेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- पराग्वे 1811 में स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ।
- थॉमस एडिसन 1879 में यूरोप की एडिसन टेलीफोन कंपनी से जुड़े।
- सन 1908 में पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी।
- 36,000 परशियन यहूदी को 1941 में गिरफ्तार किया गया।
- ब्रिटिश सैनिकों ने 1944 में कोहिमा पर कब्जा किया।
- इजराइल ने 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- कुवैत 1963 में संयुक्त राष्ट्र का 111 वां सदस्य बना।
- अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में सेना में महिलाओं के समान अधिकार को मंजूरी दी।
- सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉडर्स (इंग्लैंड) में 1999 में शुरुआत।
- भारत और मलेशिया में 2001 में सात समझौते।
- न्यूयार्क टाइम्स के प्रबंध सम्पादक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता ए.एम.रोसेंथल का 2006 में निधन।
- जापान ने 2007 में अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक को मंजूरी दी।
- टाइम्स एनआईई ने 2008 में इंटरनेशनल न्यूजपेपर मार्केटिंग एसोसियेशन (इनमा) अवार्ड-2008 जीता।
- भारत-रूस के बीच 2010 में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझोते हुए।
- इजरायल की जेलों में बंद 1500 फिलीस्तीनी कैदी 2012 में भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमत हुए।
- ब्राजील 2013 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 15वां देश बना।

14 मई को जन्मे व्यक्ति

- शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का 1657 को जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चन्द्र गुहा का 1892 में जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षाशास्त्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर का 1883 में जन्म हुआ।
- क्रोएशिया के राष्ट्रपति फ्रांजो टडमैन का 1922 में जन्म हुआ।
- भारतीय फ़िल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का 1923 में जन्म हुआ।
- भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री का 1981 में जन्म हुआ।
- फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का 1984 में आज ही के दिन जन्म हुआ।

14 मई को हुए निधन

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एन.जी.चन्दावरकर का निधन 1923 में हुआ।
- अल्ला बख्श का निधन 1943 में हुआ अंग्रेज़ी शासन के दौरान एक जमींदार, सरकारी ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे।
- प्रख्यात विद्वान् तथा राजनीतिक नेता डॉक्टर रघुवीर का निधन 1963 में हुआ।
- प्रसिद्ध नाटककार जगदीशचन्द्र माथुर का निधन 1978 में हुआ।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि वृंदा करंदीकर का निधन 2010 में हुआ।

बिना स्वतंत्र मीडिया के स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं

प्रियंका सौरभ

राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाज़ों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले पत्रकारों को शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी-कभी पत्रकारों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। मीडिया संगठन, विशेष रूप से छोटे संगठन, वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता मानकों से समझौता होता है और कॉर्पोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर निर्भरता होती है। महात्मा गांधी का यह कथन कि 'प्रेस की स्वतंत्रता एक अनमोल विशेषाधिकार है जिसे कोई भी देश त्याग नहीं सकता' आज के वैश्विक संदर्भ में दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है।

भारत में, एक जीवंत और स्वतंत्र प्रेस न केवल संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला भी है, जो एक प्रहरी, सूचना का प्रसारक और विविध आवाज़ों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति विभिन्न चुनौतियों के कारण जांच के अधीन है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति पर नज़र डाले तो भारत में एक विविध मीडिया परिदृश्य है जिसमें प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालाँकि यहाँ काफी हद तक स्वतंत्रता है, फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता और अखंडता के संबंध में चिंताएँ उठाई गई हैं। सेंसरशिप, स्व-सेंसरशिप, राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाज़ों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले- पत्रकारों को शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी-कभी पत्रकारों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। मीडिया संगठन, विशेष रूप से छोटे संगठन, वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता मानकों से समझौता होता है और कॉर्पोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर निर्भरता होती है। इंटरनेट ने मीडिया की पहुंच का विस्तार किया है, इसने गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता कम हो गई है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी की स्थिति पर कोई खतरा मंडराये।

विशेष आलेख

प्रवासी कामगारों से मजबूत होती अर्थव्यवस्था

ललित गर्ग

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) की 7 मई 2024 को जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों से सबसे ज्यादा धन पाने वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध हुआ है। मैक्सिको, चीन, फिलीपींस व फ्रांस जैसे देश भी इस सूची में भारत की तुलना में नीचले पायदानों पर है। भारत के लिये यह गौरव की बात है और इससे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने के भारत के प्रयासों को भी बल मिलेगा। नया भारत एवं सशक्त भारत के निर्माण में विदेशों में रह रहे भारतीय कामगारों ने अपने खून-पसीने की कमाई से अर्जित धनराशि में से वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर अपने देश भेजे हैं। यह आंकड़ा जहां विश्व में भारतीय श्रमशक्ति की गौरवपूर्ण गाथा को दर्शाता है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में उनके अमूल्य योगदान को दिखाता है। आईओएम की ताजा रिपोर्ट वैश्विक प्रवास पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करती है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। पूरे विश्व में अनुमानित 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ, संघर्ष, हिंसा, आपदा और अन्य कारणों से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या आधुनिक रिकॉर्ड में उच्चतम स्तर तक बढ़ गई है, जो 117 मिलियन तक पहुँच गई है, जो विस्थापन संकट को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

भारत में अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवासी के रूप में काम करने के लिए विदेश जाते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डॉक्टरों आदि जैसे पेशेवरों का अनुपात बढ़ गया है। इनके वेतन ज्यादा होता है और वे बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं। इनके अलावा भारतीय कामगार भी बड़ी संख्या में विदेशों में अपने श्रम से धन अर्जित करके न केवल अपने परिवारों का पालन-पोषण करते हैं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। निश्चित रूप से यह उन कामगारों के भारत के प्रति आत्मीय लगाव एवं देशप्रेम को ही दर्शाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान करने वाले इन श्रमवीरों के प्रति देश कृतज्ञ है। निश्चित रूप से इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं दुनिया में भारतीय श्रम-शक्ति एवं प्रतिभाएं अपनी क्षमता, कौशल एवं प्रतिभा से विपुल आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमूलक योजनाओं की नयी संभावनाओं के द्वार खोलती है, जिससे दुनिया में भारत की ताकत को नये पंख लगते हैं।

भारतीय कामगारों, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं एवं कौशल के लिए शीर्ष प्रवासन गलियारे संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब हैं जबकि राजनीतिक कारणों से भारत में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश से आती है। प्रश्न है कि भारतीय कामगार एवं प्रतिभाएं जितनी बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर अपनी क्षमताओं एवं प्रतिभा का लोहा मनवा रही है, विदेशी प्रतिभाएं उतनी संख्या में भारत नहीं आ रही है। वोट बैंक बढ़ाने के लिये बांग्लादेश आदि पडौसी देशों से गरीब एवं मुसलमानों का बड़ी संख्या में देश में आना, यहां के विकास को अवरोध करता है। इस तरह के लोगों के आने से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वही उनका भारत के विकास में योगदान नगण्य है और उनका भारत से कोई मजबूत एवं आत्मीय रिश्ता भी कायम नहीं हो पाता है, यह एक समस्या के रूप में भारत के विकास को बाधित करता है। दुनिया में भारतीय श्रम एवं कौशल की बड़ी मांग है। क्योंकि भारतीय मजबूर मेहनती, ईमानदार एवं कार्यनिष्ठ होते हैं। विकसित देशों में श्रमिकों की भारी कमी के बीच खेती, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करने के वास्ते भारतीय कामगारों को विदेश भेजने के लिए विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने का भारत सरकार का इरादा है। भारत सरकार उन देशों के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है, जहां आबादी तेजी से घट रही है। वैसे हम पहले ही जापान और फ्रांस के साथ लेबर सप्लाई एग्रीमेंट कर चुके हैं। इजरायल के साथ भी एक करार है, जिसके तहत हजारों भारतीय वहां खेती और मजदूरी के लिए भेजे जा रहे हैं। यूनान ने भारत से संपर्क किया है कि वह कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10,000 कामगारों को उसके यहां भेजे। विदेशों से धन भेजने के आकंड़े का बढ़ना दर्शाता है कि प्रवासियों का अपनी मातृभूमि के बीच कितना मजबूत, आत्मीय व स्थायी संबंध है। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार का दायित्व बनता है कि इस उपलब्धि की खुशी मनाते वक्त प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी पहचाना जाए और उनका समाधान किया जाये। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी कामगारों को वित्तीय शोषण, प्रवासन लागत के कारण बढ़ते ऋण दबाव, नस्लीय भेदभाव व कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनके निराकरण के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत अपने प्रवासी कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिये संबंधित देशों से रणनीतिक तरीकों से रास्ता निकालना चाहिए। निस्संदेह, भारत सरकार को प्रवासी कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिये हमारे दूतावासों के जरिये विशेष कदम उठाने चाहिए। दरअसल, खाड़ी सहयोग परिषद के राज्यों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन जारी है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कामगारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेष तौर पर अर्द्ध-कुशल श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कई तरह के संकटों को बढ़ा दिया था। बड़ी संख्या में उनकी नौकरियां खत्म हुई, वेतन नहीं मिला। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में कई लोगों को कर्ज में डूबना पड़ा। जिसके चलते बड़ी संख्या में ये कामगार स्वदेश लौटे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की तरफ भारतीय छात्रों के बढ़ते रुझान की ओर भी आईओएम की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इशारा कर रही हैं। बहरहाल, प्रवासन के बदलते परिदृश्य में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिये ठोस प्रयासों की जरूरत है। किसी भी तरह श्रमिकों का शोषण न हो और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय कामगारों के लिये सुरक्षित व व्यवस्थित प्रवासन मार्ग संभव हो सके। यह समावेशी विकास की पहली शर्त भी है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि विदेशों में कामगारों के हितों की रक्षा के साथ ही भारत में रह रहे उनके परिवारों का भी विशेष ख्याल रखा जाए। जिससे उनका देश के प्रति लगाव और गहरा हो सके। सरकार कामगारों को विदेश भेजने की पहल में काफी सक्रिय दिख रही है। कम से कम दो जरूरी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, जिन कामगारों की बात की जा रही है वे ज्यादा पढ़े-लिखे या कुशल नहीं हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि इन लोगों का चयन पारदर्शी तरीके से हो। अगर जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया में किसी तीसरे भरोसेमंद पक्ष को भी शामिल किया जाए। दूसरी बात, अलग-अलग देशों में जैसे-जैसे भारतीय मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, भारत को अपनी राजनयिक मौजूदगी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। झंझटों में न पड़ें। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

वृष
सही काम का भी विरोध हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी।

मिथुन
व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

कर्क
मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन बना रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें। शारीरिक कष्ट संभव है।

सिंह
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि तथा सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। जल्दबाजी से हानि होगी। राजभय रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा।

कन्या
यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। झंझटों में न पड़ें। शत्रुओं का पराभव होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। लेन-देन में लापरवाही न करें।

तुला
आय में निश्चितता रहेगी। दु:खद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेवजह किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। दूसरों के बहकावे में न आएं।

वृश्चिक
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। कार्य की बाधा दूर होगी।

धनु
विवाद से क्लेश होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐश्वर्य के साधनों पर सोच-समझकर खर्च करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। दूसरे अधिक अपेक्षा करेंगे।

मकर
प्रतिद्वंद्विता कम होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बात बिगड़ सकती है। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

कुंभ
स्त्री वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। नौकरी व निवेश में इच्छा पूरी होने की संभावना है। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। संचित कोष में वृद्धि होगी। देनदारी कम होगी।

मीन
सही काम का भी विरोध होगा। कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। कोई बड़ी समस्या बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने के प्रति रुझान रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

दैनिक इबादत सम्पादकीय

चिंताजनक हैं हालिया रिपोर्ट

अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के नतीजों को लेकर काफी चर्चा हो रही है यह रिपोर्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी की एक अध्ययन रिपोर्ट। ईएसी पीएम रिपोर्ट में 65 सालों के अंदर हिंदुओं की आबादी घटने की जानकारी दी गई है। अध्ययन के मुताबिक भारत में 1950 से लेकर 2015 तक बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.8 प्रतिशत घट गई है तो वहीं कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समाज की आबादी में काफी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कम हुई है तो वहीं जैन और पारसियों की संख्या भी घटी है। इसके विपरीत ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट की मानें तो 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में मुस्लिम समाज की आबादी में 43.15 फीसद की बढ़त दर्ज किया गया है तो वहीं सिखों में 6.58 फीसद, ईसाइयों में 5.38 फीसद और बौद्ध में बहुत थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके लिए दुनियाभर के 167 देशों का अध्ययन किया गया है। इसके लेखकों ने कहा है कि दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है, रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके मुताबिक चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों के साथ ही कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की अपेक्षा अधिक गिरावट दर्ज की गई है। जहां एक ओर भारत में बहुसंख्यक समाज की संख्या घटी है तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में बहुसंख्यकों की आबादी में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इन दोनों देशों में मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब बचे हुए चुनावों में यह मुद्दा बड़े जोर-शोर से उठेगा। इसके सियासी नफा-नुकसान का आकलन राजनीतिक गलियारों में किया जाने लगा है। जबकि कुछ लोगों ने ऐसी रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा है कि जब अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो यह आंकड़े कितने आधिकारिक हैं और कितने मान्य हैं। इस पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। गौर तलब है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य सकारात्मक है और इसमें कहा गया कि संबंधित आंकड़ों से संकेत मिलता है कि %समाज में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण है। यह रिपोर्ट अमेरिका जैसे उन पश्चिमी देशों के मुंह पर भी तमाचा है जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप लगाकर भारत पर सवाल उठाते रहते हैं। रिपोर्ट के आते ही राजनीतिक बवाल मच गया। जहां भाजपा ने हिंदुओं की जनसंख्या घटने और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर चिंता जताई है, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल रिपोर्ट आने से इसके जारी करने के समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि यदि भारत की आबादी इसी तरह बढ़ती रही संसाधन इसका बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। हम चीन को भी पीछे छोड़ कर दुनिया के सबसे जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, यदि अब भी सरकार ने कड़ाई से हम दो-हमारे दो जैसा कोई नियम-कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन नहीं करवाया तो खाने के लिए अन्न भी बाहर से आयात करना पड़ेगा। यदि देश को विकसित बनाना, अपना भविष्य सुखी एवं समृद्ध बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना ही होगा। धर्म कोई भी हो, यदि आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो न देश विकसित हो पाएगा और न ही भविष्य सुखी एवं सुरक्षित हो पाएगा।

भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता

– विजय गर्ग

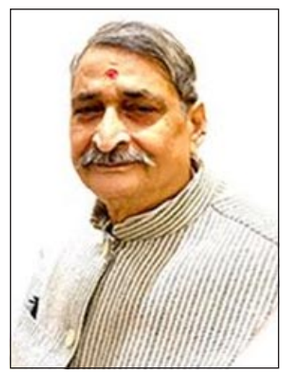

आज जब पूरी दुनिया में तकनीकी, समृद्धि और आधुनिकता कुलांचे भर रही है, विभाजित आर्थिकी वाले मानव समाज में भूख और कुपोषण समस्या बना हुआ है। हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (संयुक्त राष्ट्र) के महानिदेशक गिल्बर्ट हुंगबो ने इस सच्चाई से पर्दा उठाया है कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर महंगाई के बीच कोविड महामारी के बाद से मासूमों के साथ यह सितम और तेज हुआ है। ऐसा नहीं कि यह दुनिया के सिर्फ गरीब मुल्कों में हो रहा है, आनुपातिक रूप से ऊंची आर्थिकी वाले देशों में भी यह अधोगति जारी है। ज्यादातर बच्चों, किशोरों को खेती–बाड़ी, खनन, निर्माण आदि क्षेत्रों में झोंका जा रहा है। इस त्रासदी की वजह गरीबी और भूख है। दुनिया के लगभग सोलह करोड़ बच्चे ऐसे हालात से दो–चार हो रहे हैं। बीते दो दशकों में, पहली बार ऐसे हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। बाल मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन–रूस, इजराइल फिलिस्तीन युद्धों के कारण भी महंगाई ने लोगों की जिंदगी जटिल बना दी है। भूख मिटाने के लिए बच्चों को भी शारीरिक श्रम के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सच्चाई है कि अकेले भारत में सड़सठ लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। यह संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। सर्वेक्षक इसे 'शून्य खाद्य' की स्थिति करार देते हैं, जो गंभीर खाद्य असुरक्षा की गहन चिंताएं उत्पन्न करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक – 2023 के मुताबिक, इस त्रासदी की जद में काम पर जाने वाले बच्चे और किशोर ही नहीं, बल्कि उनमें छह से ग्यारह माह के तीस फीसद, 12 से 17 माह के तेरह फीसद और 18 से 23 माह के आठ फीसद शिशु भी शुमार हैं। इस बीच हमारे देश में अल्प–पोषण व्यापकता 14.6 फीसद से बढ़ कर 16.3 फीसद हो चुकी है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की निगरानी और उन्हें इस जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक, हमारे देश में लगभग साठ फीसद बच्चे दुग्ध आदि पोषक आहार से वंचित रह जा रहे हैं। बच्चों के भयावह शोषण की एक बड़ी वजह बाल तस्करी भी है। गरीबी, मानवीय संकट और शिक्षा की कमी इसकी उच्च दर को हवा दे रही है। मुश्किल तो यह है कि इसका कोई सटीक आंकड़ा मिल पाना आसान नहीं होता। वैश्विक चुनौती बन चुकी बाल मजदूरी के बारे में, एक अनुमान के मुताबिक, हर साल बीस हजार से अधिक बच्चों की तस्करी हो रही है। बच्चों की व्यापक सुरक्षा, तस्करी की रोकथाम, कानूनी प्रवर्तन और पीड़ितों की अपेक्षित सहायता के तकाजे के बावजूद, यह तादाद हर वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रति वर्ष कम से कम तीन लाख बच्चे अगवा होते हैं। उनमें से बड़ी संख्या में बच्चे तस्करों के हाथ लग जाते हैं। मानव तस्करी विरोधी संगठन 'थार्न' की एक रपट के मुताबिक इनमें से हर तेरहवां बच्चा यौन शोषण में झोंक दिया जाता है।

भारत में, बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम के बावजूद बच्चों का एक बड़ा अनुपात मजदूरी में लगा हुआ है। कहने को सीएलपीआर अधिनियम किसी भी बच्चे से मजदूरी कराने को गैरकानूनी करार देता हैं, लेकिन पिछली राष्ट्रीय जनगणना (2011) के मुताबिक, देश के कुल 25.964 करोड़ बच्चों में से 1.012 करोड़ भिन्न प्रकार की मजदूरी में पाए गए। विश्व में ऐसे बच्चों की संख्या 21.7 करोड़ से अधिक बताई जाती है। यूनिसेफ और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रपट बताती है कि पहले की अपेक्षा बाल मजदूरों की तादाद में 89 लाख तक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, बाल मजदूरी के सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज हो रहे हैं। असम दूसरे स्थान पर रहा है। ज्यादातर बच्चे ईंट निर्माण उद्योग में कार्यरत पाए गए हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कठोर श्रम कर रहे हैं। भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। प्रभावित आबादी खाद्य पदार्थों के साथ पेय जल और स्वच्छता से भी वंचित होती जा रही है। भारत में गरीबी और बाल श्रम की स्थितियां अब तो भयावह होती जा रही हैं, जिसके खतरनाक नतीजे बच्चों के भारी शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। पांच किलो राशन पर आश्रित 80– 81 करोड़ परिवारों में से ज्यादातर लोग आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

मोदी के लिए अपरिहार्य कैसे बने अमित शाह

अमित शाह की सरपरस्ती में,आंतरिक आतंकवाद का खतरा भी कम हुआ है। इस्लामिक स्टेट का उदय,पहले सीरिया और बाद में अफगानिस्तान में, चरमपंथी प्रवृत्ति वाले कई युवाओं को विदेशी जमीन में युद्ध लड़ने के लिए देश से बाहर जाते हुए देखा गया। इससे 2014 में कट्टरपंथ और ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंग के नए खतरों के बारे में चिंता पैदा हुई थी,लेकिन गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां आज इनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

– आर.के. सिन्हा

अमित शाह राजधानी में अपने साउथ ब्लॉक के दफ्तर में जब काम करते होंगे, तब उनके जेहन में भी देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल का ख्याल अवश्य आता होगा। लौह पुरुष सरदार पटेल नें भी इसी साउथ ब्लॉक में बने गृह मंत्री कार्यालय से ही से देश की आंतरिक सुरक्षा को एक नई दिशा दी थी। वे भी बोलने में कम और काम करने में अधिक यकीन करते थे। अमित शाह का एक गुण यह भी है कि वे किसी अनावश्यक विवाद को खत्म करने में देर नहीं करते।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शायद सोचा होगा कि वे अमित शाह को देश का भावी प्रधानमंत्री बताकर एक विवाद खड़ा कर देंगे। पर उनकी यह मंशा सफल नहीं हुई, क्योंकि अमित शाह ने साफ कर दिया कि नरेन्द्र मोदी ही 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अमित शाह ने पहले भाजपा के संगठन में रहते हुए और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए उनके संगठनात्मक कौशल को सबने देखा, लेकिन जो लोग उन्हें गुजरात के दिनों से जानते थे, वे बहुत हैरान नहीं हुए। फिर, 2019 में, वह केंद्रीय गृह मंत्री बने, और इसके साथ ही शुरू हुआ कई बड़े फैसलों को लेने का दौर। पिछले पांच वर्षों में, अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देखरेख में भारतीय दंड विधान (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को बदला गया। अमित शाह मानते हैं कि कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। 1860 से 2023 तक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। आपको याद होगा जब जब भारत अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे। नए आपराधिक कानून उनमें से एक को पूरा करते हैं। सरकार ने नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम दिया है। गृह मंत्री के रूप में अमित, शाह को प्रधानमंत्री का विश्वास और पूरा भरोसा प्राप्त है।

वास्तव में, जब कोई राजनीतिक या सरकारी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष लाया जाता है, तो कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति से अमित शाह से भी सलाह लेने के लिए कहते हैं। 2019 में, गृह मंत्री बनने के तीन महीने बाद, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकारी कदम में सबसे आगे थे। इसके लिए कुशल राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता थी। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन हासिल था। चार साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वैधता को बरकरार रखा, जो कि भाजपा ने भारत के अंतिम एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा था। अमित शाह 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की पीछे प्रेरक शक्ति भी रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई – जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं – उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आशंका थी कि सीएए को विपक्ष मुद्दा बनायेगा। पर यह नहीं हुआ। इसकी बेशक एक बड़ी वजह यह रही कि अमित शाह देश के मुसलमानों को भरोसा देता रहे कि सीएए कानून का उनसे कोई लेना–देना है। याद करें कि राजधानी के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ महिलाओं ने लंबा धरना दिया था। धरने देने वाली महिलाएं कह रही थीं कि सीएए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। धरना कोविड के फैलने के कारण सरकार ने सख्ती से बंद करवा दिया था। उस समय धमकी दी जा रही थीकि सीएए के खिलाफ धरना फिर शुरू होगा। पर यह नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित मोदी बार–बार मुसलमानों को भरोसा देते रहे कि सीएए से उन्हें घबराने की कोई वजह नहीं है। इसका सकारात्मक असर हुआ। जब केन्द्र सरकार ने सीएए की पिछली 11 मार्च को अधिसूचना जारी की तो एक बार लगा कि इसका विरोध होगा। पर कहीं कुछ नहीं हुआ।

लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए की अधिसूचना के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सीएए को लागू करने के मसले को लोकसभा चुनाव में उठाएंगे। सीएए, एनआरसी और धारा 370 जैसे मुद्दे काँग्रेस के घोषणापत्र से ही गायब हैं। सीएए पर दिल्ली से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गया था और जल्दी ही यह हिंदू- मुस्लिम विवाद में बदला था। दिल्ली में सार्वजनिक संपत्ति को खूब नुकसान पहुंचाया गया और विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हुए थे। एक लोकतांत्रिक देश में हर मुद्दे पर विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी हक है। जबकि विधेयक में पहले दिन से कहा गया था कि यह केवल उन शरणार्थियों पर लागू किया जाएगा जो 'धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर थे।

खैर, अमित शाह की सरपरस्ती में, आंतरिक आतंकवाद का खतरा भी कम हुआ है। इस्लामिक स्टेट का उदय, पहले सीरिया और बाद

में अफगानिस्तान में, चरमपंथी प्रवृत्ति वाले कई युवाओं को विदेशी जमीन में युद्ध लड़ने के लिए देश से बाहर जाते हुए देखा गया। इससे 2014 में कट्टरपंथ और ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंग के नए खतरों के बारे में चिंता पैदा हुई थी, लेकिन गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां आज इनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित राज्यों में, सुरक्षा बल धीरे–धीरे उन क्षेत्रों में वापस आ रहे हैं जिन्हें कभी रेड जोन माना जाता था। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्समलवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नक्स लियों पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऐसा पिछले साल दिसंबर महीने में भी देखने को मिला था। अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा के कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। फिर वो चाहे, नक्सुलवाद के खिलाफ हो या आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद और नक्सदलवाद लोकतांत्रिक तरीके नहीं हैं और इन्हें समाप्ति कर देना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

मीडिया के बयानवीर

– बाल मुकुन्द ओझा

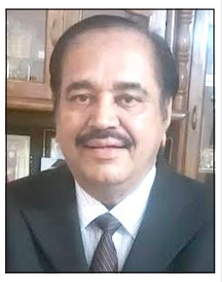

पहले सैम पित्रोदा और फिर मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान देकर चुनाव के मैदान में अपनी ही पार्टी (कांग्रेस पार्टी) की फजीहत करा दी हैं। कांग्रेस के इन बयानवीरों ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। राजनीति में शुचिता की दुहाई देने वाले नेता खुद बयानवीर होकर पहले अपनी पार्टी और फिर देश का बेड़ा गर्क करने की होड़ में जुट गए है। जनता ने इनमें से बहुत से नेताओं को चुनावी पटखनी देकर इनकी औकात बता दी तो कुछ की चुनावी बेतरणी पार लगाकर गले लगा लिया। देश को अमूमन हर साल कोई न कोई चुनाव का सामना करना ही पड़ता है।

जैसे ही चुनाव आते है नेताओं के बांछे खिल जाती है। गंदे बोलों से चुनावी बिसात बिछ जाती है। पिछले दो दशक से गंदे और विवादित बोल बोले जा रहे है। नेताओं के बयानों से गाहे बगाहे राजनीति की मर्यादाएं भंग होती रहती है। अमर्यादित बयानों की जैसे झड़ी लग जाती है। राजनीति में बयानबाजी का स्तर इस तरह नीचे गिरता जा रहा है उसे देखकर लगता है हमारा लोकतंत्र तार तार हो रहा है। देश में दिग्विजय सिंह, संजय राउत, लालू यादव जैसे दर्जनों नेता है जो गाहे बगाहे अमर्यादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते है। ये नेता मोदी पर विवादित बयान देने के लिए कुख्यात है। कभी मोदी को मौत का सौदागर बताते है तो कभी जमीन में गाड़ देने की धमकी देते है। बयानवीरों पर मोदी के बयान से देश की सियासत एक बार फिर गरमा गयी है। लोकसभा चुनाव में बयानवीरों के विवादित बयानों ने देश को शर्मसार कर दिया था। इन दिनों आपत्तिजनक और विवादित बयानों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सियासत में विवादास्पद बयान को नेता भले अपने पॉपुलर होने का जरिया मानें, लेकिन ऐसे बयान राजनीति की स्वस्थ परंपरा के लिए ठीक नहीं होते। यह बेहद दुखद है कि पिछले कुछ सालों से भारत में राजनीतिक–वैचारिक पतन तो हुआ ही है, साथ ही राजनीति की भाषा स्तरहीन और गंदी हो गई है। हमारे माननीय नेता आजकल अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। देश के नामी–गिरामी नेता और मंत्री भी मौके–बेमौके कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं, जिसे सुनकर कान बंद करने का जी करता है। जो किसी भी हालत में लोकतान्त्रिक और सभ्य समाज के अनुकूल नहीं कही जा सकती। चुनावी सीजन में किसी नेता को चोर, लुटेरा तथा बलात्कारी बताया जा रहा था तो किसी को गधा, कुत्ता, तड़ीपार और गेंडा बताया गया।

कहते है राजनीति के हमाम में सब नंगे है। यहाँ तक तो ठीक है मगर यह नंगापन हमाम से निकलकर बाजार में आजाये तो फिर भगवान ही मालिक है। सियासत में विवादास्पद बयान को नेता भले अपने पॉपुलर होने का जरिया मानें, लेकिन ऐसे बयान राजनीति की स्वस्थ परंपरा के लिए ठीक नहीं होते। हमारे माननीय नेता आजकल अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। देश के नामी–गिरामी नेता और मंत्री भी मौके–बेमौके कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं, जिसे सुनकर कान बंद करने का जी करता है। राजनीति में पिछले एक दशक से गंदे और विवादित बोल बोले जारहे है। चुनाव के बाद बयानवीरों की नयी खेफ सामने आयी वहीँ कुछ पुराने भी हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे है। विवादित बयान देने में कांग्रेस और भाजपा सहित कोई भी नेता पीछे नहीं है। सब एक दूसरे पर अटैक कर उसको भी अपनी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। अमर्यादित बयानों की जैसे झड़ी लग गई है। राजनीति में बयानबाजी का स्तर इस तरह नीचे गिरता जा रहा है उसे देखकर लगता है हमारा लोकतंत्र तार तार हो रहा है। देश में कई नेता अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे है। इनकी लम्बी सूची है। इनमें राहुल गाँधी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मणिशंकर अय्यर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, दिग्गी राजा, अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल , मणिशंकर अय्यर, केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, ममता और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदि प्रमुख है जिनके बयानों से गाहे बगाहे राजनीति की मर्यादाएं भंग होती रहती है। ये बयानवीर मीडिया में सुरखी पाने के लिए न्यूज चैनलों के कैमरे देखते ही बहकने लगते है। आग में घी डालने में खबरिया चैनल की भूमिका भी कम जिम्मेदार नहीं है। खबरिया चैनल बयानवीरों के विवादित बोल दिखाने बंद करदे तो आधी समस्या तो स्वत: ही निपट जाएगी।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

कविता

लंबी उम्र की ना दुआ किया करो

मोहब्बत में दर्द छुपा लिया करो,
दर्द के छालों को छुपा लिया करो।

आशिकी छुपाना होती नहीं आसां,
जमाने को मेरा नाम बता दिया करो।

हर दर्द की दास्तां होती है जुदा जुदा,
अपने दर्द को दिल में दबा दिया करो।

रूबरू होने की खुशियां चंद लम्हों की,
जुदाई के अहसास को दबा लिया करो।

सन्नाटे का शोर क्यों है इतना रातों में,
शोर को खामोशी में छुपा लिया करो।

इश्क में तेरे दुनिया लुट गई मेरी,
लंबी उम्र की ना दुआ किया करो।

संजीव ठाकुर (रायपुर छत्तीसगढ़)

राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाज़ों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले- पत्रकारों को शारीरिक हिंसा,उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है,खासकर जब वे भ्रष्टाचार,मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी-कभी पत्रकारों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह,मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है।

बिना स्वतंत्र मीडिया के स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं

– प्रियंका सौरभ

महात्मा गांधी का यह कथन कि 'प्रेस की स्वतंत्रता एक अनमोल विशेषाधिकार है जिसे कोई भी देश त्याग नहीं सकता' आज के वैश्विक संदर्भ में दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है। भारत में, एक जीवंत और स्वतंत्र प्रेस न केवल संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला भी है, जो एक प्रहरी, सूचना का प्रसारक और विविध आवाज़ों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति विभिन्न चुनौतियों के कारण जांच के अधीन है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति पर नज़र डाले तो भारत में एक विविध मीडिया परिदृश्य है जिसमें प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालाँकि यहाँ काफी हद तक स्वतंत्रता है, फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता और अखंडता के संबंध में चिंताएँ उठाई गई हैं। सेंसरशिप, स्व-सेंसरशिप, राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाज़ों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले- पत्रकारों को शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी–कभी पत्रकारों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। मीडिया संगठन, विशेष रूप से छोटे संगठन, वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता मानकों से समझौता होता है और कॉर्पोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर निर्भरता होती है। इंटरनेट ने मीडिया की पहुंच का विस्तार किया है, इसने गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता कम हो गई है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी की स्थिति पर कोई खतरा मंडराये। इस स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति या एक संस्था को जिम्मेवार मानना बहुत गलत होगा। लेकिन, इसके साथ ही यह भी सत्य है कि यह हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है। यह आत्मचिंतन सरकारों को करनी है, नेताओं को करनी है, पत्रकार बंधुओं को करनी है, रिपोर्टरों को करनी है और खास तौर पर पत्रकारिता संस्थानों के मालिकों को करनी है, कि हम किस तरह की पत्रकारिता चाहते हैं। आज यह आत्मचिंतन का विषय है कि हम क्यों पत्रकार बने या आनेवाली पीढ़ियों में कोई क्यों पत्रकार बने। आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं। साथ ही, किसी रैंकिंग आदि को देख कर यह समझना भी गलत है कि हम (प्रेस) बिल्कुल भी आजाद नहीं है। लेकिन, इतना सच जरूर है कि मीडिया में- खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में- आजकल खबरें कम, एजेंडा ज्यादा चलाया जा रहा है। यहीं आकर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि खबरों को इकट्ठा करनेवालों पर संस्थान मालिकों का दबाव होता है। ज्यादातर तो मालिक ही संपादक होते हैं, जो एजेंडा चलाये जाने के जाल में फंस जाते हैं।

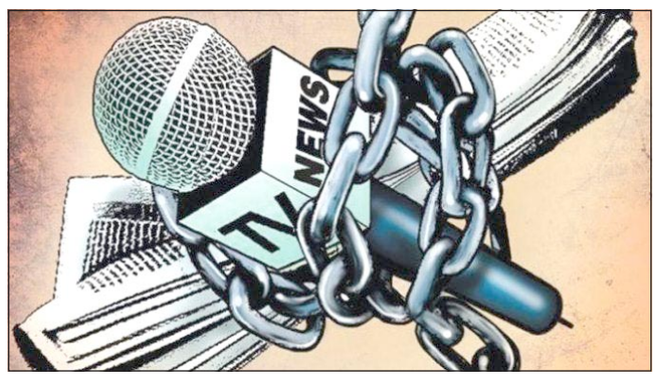

दरअसल, एजेंडा चलाना आज के दौर में मीडिया का बिजनेस मॉडल है और यह मॉडल जब तक रहेगा, तब तक तो प्रेस पर सवाल उठते रहेंगे कि आखिर वह कितना आजाद है और उस पूंजी कितनी हावी है।यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह यह कि मौजूदा दौर की वेब पत्रकारिता यानी डिजिटल मीडया इस बिजनेस मॉडल से थोड़ी अप्रभावित है, क्योंकि इसे चलाने में कम खर्च होने के चलते इस पर दबाव कम रहता है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने के संभावित उपाय देखें तो कानूनी सुधार से उन कानूनों को संशोधित या निरस्त करें जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के साथ संरेखित हों। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धमकियों या हमलों का सामना करने वाले पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करना तथा अपराधियों को जवाबदेह ठहराना होगा। मीडिया साक्षरता के माध्यम से प्रचार और गलत सूचना से विश्वसनीय जानकारी को पहचानने के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। नैतिक पत्रकारिता हेतु मीडिया संस्थानों को पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना और स्वतंत्र मीडिया के लिए बाहरी प्रभावों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वतंत्र मीडिया संगठनों को वित्तीय सहायता और नियामक समर्थन प्रदान करना कारगर उपाय होगा। महात्मा गांधी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस का अधिकार आवश्यक है। जबकि भारत में एक जीवंत मीडिया परिदृश्य है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, मीडिया संगठनों, नागरिक समाज और जनता के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखकर, भारत अपने लोकतांत्रिक ताने–बाने को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके नागरिकों की आवाज़ बिना किसी डर या पक्षपात के सुनी जाए।

(रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

भारतवंशियों का संबल

यह भारत के लिये गौरव की बात है कि सारी दुनिया में भारतीय कामगारों ने खून-पसीने की कमाई से अर्जित धनराशि में से वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर अपने देश भेजे हैं। इस तरह भारत दुनियाभर में भारतवंशियों की कमाई से सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले देश के रूप में स्थापित हुआ है। यह आंकड़ा जहां विश्व में भारतीय श्रमशक्ति की गाथा को दर्शाता है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को दिखाता है। निश्चित रूप से यह उन कामगारों के भारत के प्रति आत्मीय लगाव को भी बताता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान करने वाले इन श्रमवीरों के प्रति देश कृतज्ञ है। निश्चित रूप से इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरअसल, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस व फ्रांस सबसे ज्यादा धन पाने वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध हुए हैं। यह धन भेजने के आंकड़े का बढ़ना दर्शाता है कि प्रवासियों का अपनी मातृभूमि के साथ कितना मजबूत व स्थायी संबंध है। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार का दायित्व बनता है कि इस उपलब्धि की खुशी मनाते वक्त प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी पहचाना जाए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी कामगारों को वित्तीय शोषण, प्रवासन लागत के कारण बढ़ते ऋण दबाव, नस्लीय भेदभाव व कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनके निराकरण के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत है।

निस्संदेह, भारत सरकार को प्रवासी कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिये हमारे दूतावासों के जरिये विशेष कदम उठाने चाहिए। दरअसल, खाड़ी सहयोग परिषद के राज्यों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन जारी है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कामगारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेष तौर पर अर्द्ध-कुशल श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कई तरह के संकटों को बढ़ा दिया था। बड़ी संख्या में उनकी नौकरियां खत्म हुई, वेतन नहीं मिला। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में कई लोगों को कर्ज में डूबना पड़ा। जिसके चलते बड़ी संख्या में ये कामगार स्वदेश लौटे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की तरफ भारतीय छात्रों के बढ़ते रुझान की ओर भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इशारा कर रही है। बहरहाल, प्रवासन के बदलते परिदृश्य में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिये ठोस प्रयासों की जरूरत है। किसी भी तरह श्रमिकों का शोषण न हो और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय कामगारों के लिये सुरक्षित व व्यवस्थित प्रवासन मार्ग संभव हो सके। यह समावेशी विकास की पहली शर्त भी है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि विदेशों में कामगारों के हितों की रक्षा के साथ ही भारत में रह रहे उनके परिवारों का भी विशेष ख्याल रखा जाए। जिससे उनका देश के प्रति लगाव और गहरा हो सके।

स्वस्थ जीवनशैली उम्र में कर सकती है इजाफा

वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि व्यायाम लीवर, हृदय रोग और ऊतक की चोट से जुड़े मार्गों को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हुआ। विज्ञानियों द्वारा एकत्र डेटा से मानव स्वास्थ्य की अलग-अलग स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने इस बात का संभावित स्पष्टीकरण पाया कि व्यायाम के दौरान लीवर कम फैटी क्यों हो जाता है। इससे अल्कोहल के सेवन के बगैर होने वाले फैटी लीवर रोग के लिए नए उपचार के विकास में मदद मिल सकती है।

स्वस्थ जीवनशैली उम्र पर आनुवंशिकी के प्रभाव को 60 प्रतिशत से अधिक कम कर सकती है और आपके जीवन में पांच साल और जोड़ सकती है। यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि कुछ लोगों में आनुवंशिक कारणों से कम जीवनकाल की प्रवृत्ति होती है। यह भी सर्वविदित है कि जीवनशैली से जुड़ी कुछ बातें, विशेष रूप से धूम्रपान, शराब का सेवन, आहार और शारीरिक गतिविधि, दीर्घायु पर प्रभाव डाल सकती हैं। अभी तक यह समझने के लिए कोई जांच नहीं हुई थी कि एक स्वस्थ जीवनशैली आनुवंशिकी को किस हद तक संतुलित कर सकती है। लेकिन अब कई-कई दीर्घकालिक अध्ययनों के निष्कर्ष सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि एक स्वस्थ जीवनशैली जीवन को छोटा करने वाले जीन के प्रभावों को 62 प्रतिशत तक कम कर सकती है और आपके जीवन में पांच साल तक बढ़ा सकती है। दरअसल, इन अध्ययनों के परिणाम बीएमजे एविडेंस-बेस्ड मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अध्ययन जीवनकाल पर आनुवंशिक कारकों के प्रभाव को कम करने में स्वस्थ जीवनशैली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उनका यह भी मानना है कि जीवनशैली में सुधार के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूरक के रूप में काम कर सकती हैं। मानव जीवन पर आनुवंशिक कारकों के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

एक अध्ययन में यूके बायोबैंक में 353,742 लोगों को शामिल किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि उच्च आनुवंशिक जोखिम वाले लोगों में कम आनुवंशिक जोखिम वाले लोगों की तुलना में समय से पहले मृत्यु का खतरा 21 प्रतिशत अधिक होता है, भले ही उनकी जीवनशैली कुछ भी हो। इस बीच, चीन में झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और एडिनबरा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली वाले लोगों में जल्दी मौत की संभावना 78 प्रतिशत बढ़ जाती है, भले ही आनुवंशिक जोखिम जो भी हो। अध्ययन में कहा गया है कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली और कम जीवनकाल के जीन वाले लोगों में भाग्यशाली जीनों और स्वस्थ जीवनशैली वाले लोगों की तुलना में समय पूर्व मौत का खतरा दोगुना हो जाता है।

हालांकि, शोधकर्ताओं ने पाया कि कम उम्र या समय से पहले मौत के आनुवंशिक जोखिम को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर लगभग 62 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि उच्च आनुवंशिक जोखिम वाले लोग स्वस्थ जीवनशैली के साथ 40 वर्ष की आयु में लगभग 5.22 वर्ष की जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं। लंबे जीवन के लिए आदर्श जीवनशैली में धूम्रपान न करना, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और स्वस्थ आहार शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में औसतन 13 वर्षों तक लोगों का अनुसरण करने के बाद अपने निष्कर्ष निकाले हैं। विश्व कैंसर अनुसंधान कोष में स्वास्थ्य सूचना और प्रचार प्रबंधक मैट लैम्बर्ट ने कहा कि इस नए शोध से पता चलता है कि आनुवंशिक कारकों के बावजूद स्वस्थ जीवनशैली जीने से हमें लंबे समय तक जीने में मदद मिल सकती है। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम के कारण शरीर के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा जटिल और दूरगामी होती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के नए अध्ययन में पता लगाया है कि शारीरिक गतिविधियों के कारण जानवरों के सभी 19 अंगों में कई तरह के कोशिकीय और आणविक परिवर्तन होते हैं। व्यायाम कई बीमारियों के खतरे को कम करता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि व्यायाम शरीर को आणविक स्तर पर कैसे बदलता है। अधिकांश पिछले अध्ययनों ने एक ही अंग या लिंग पर ध्यान केंद्रित किया और इनमें सिर्फ एक या दो तरह के डेटा शामिल किए किए।

व्यायाम के जीव विज्ञान पर अधिक व्यापक नजर डालने के लिए अमेरिका के मॉलिक्यूलर ट्रांसड्यूसर ऑफ़ फिजिकल एक्टिविटी कंसोर्टियम के वैज्ञानिकों ने चूहों में शारीरिक गतिविधि से होने वाले आणविक परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला में तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग किया। ये चूहे कई हफ्तों तक गहन व्यायाम के दौर से गुजरे थे। वैज्ञानिकों के दल ने जानवरों के हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों जैसे अंगों के ऊतकों की एक श्रृंखला का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक अंग व्यायाम के साथ बदलाव देखा गया। इससे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने और तनाव का जवाब देने में मदद मिली।

वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि व्यायाम लीवर, हृदय रोग और ऊतक की चोट से जुड़े मार्गों को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हुआ। विज्ञानियों द्वारा एकत्र डेटा से मानव स्वास्थ्य की अलग-अलग स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने इस बात का संभावित स्पष्टीकरण पाया कि व्यायाम के दौरान लीवर कम फैटी क्यों हो जाता है। इससे अल्कोहल के सेवन के बगैर होने वाले फैटी लीवर रोग के लिए नए उपचार के विकास में मदद मिल सकती है। टीम को उम्मीद है कि उनके निष्कर्षों का उपयोग एक दिन किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप व्यायाम निर्धारित करने या व्यायाम करने में असमर्थ लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि के प्रभावों के अनुसरण करने वाले उपचार विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने व्यायाम के आणविक प्रभावों को ट्रैक करने के लिए लोगों पर अध्ययन पहले ही शुरू कर दिया है। व्यायाम के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों का कंसोर्टियम 2016 में स्थापित किया गया। इसमें एमआईटी, हार्वर्ड, स्टेनफर्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ हैल्थ जैसे अनेक अग्रणी संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। कुल मिलाकर विज्ञानियों ने रक्त और 18 ठोस ऊतकों पर लगभग 1.5 करोड़ माप लेने के लिए लगभग 10,000 परीक्षण किए। उन्होंने पाया कि व्यायाम ने हजारों अणुओं को प्रभावित किया। एड्रिनल ग्रंथि में सबसे चरम परिवर्तन देखे गए।

ध्यान रहे कि एड्रिनल ग्रंथि कुछ खास हार्मोन का उत्पादन करती है जो प्रतिरक्षा, मेटाबोलिज्म (चयापचय) और ब्लड प्रेशर जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शोधकर्ताओं ने कई अंगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित लिंग अंतर को भी उजागर किया। मादाओं के मामले में इम्यून रिस्पॉन्स का संकेत देने वाले अणुओं ने एक और दो सप्ताह के प्रशिक्षण के बीच स्तर में परिवर्तन दिखाया जबकि नर में चार और आठ सप्ताह के बीच अंतर देखा गया।

आज का इतिहास

- फ्रांस में 1610 में हेनरी द्व्ङ्क की हत्या और लुईस ङ्गद्वद्वद्व फ्रांस की गद्दी पर बैठा।
- नीदरलैंड और इंग्लैंड ने 1702 में स्पेन और फ्रांस के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा की।
- पराग्वे 1811 में स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ।
- थॉमस एडिसन 1879 में यूरोप की एडिसन टेलीफोन कंपनी से जुड़े।
- सन 1908 में पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में उड़ान भरी।
- 36,000 परशियन यहूदी को 1941 में गिरफ्तार किया गया।
- ब्रिटिश सैनिकों ने 1944 में कोहिमा पर कब्जा किया।
- इजराइल ने 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की।
- कुवैत 1963 में संयुक्त राष्ट्र का 111 वां सदस्य बना।
- अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में सेना में महिलाओं के समान अधिकार को मंजूरी दी।
- नासा ने 1981 में स्पेश व्हिकल स्–192 लांच किया।
- सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉडर्स (इंग्लैंड) में 1999 में शुरुआत।
- भारत और मलेशिया में 2001 में सात समझौते।
- न्यूयार्क टाइम्स के प्रबंध सम्पादक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता ए.एम.रोसेंथल का 2006 में निधन।
- जापान ने 2007 में अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक को मंजूरी दी।
- टाइम्स एनआईई ने 2008 में इंटरनेशनल न्यूजपेपर मार्केटिंग एसोसियेशन (इनमा) अवार्ड–2008 जीता।
- भारत–रूस के बीच 2010 में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझोते हुए।
- इजरायल की जेलों में बंद 1500 फिलीस्तीनी कैदी 2012 में भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमत हुए।
- ब्राजील 2013 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 15वां देश बना।
- शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का 1657 को जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चन्द्र गुहा का 1892 में जन्म हुआ।
- प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षाशास्त्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर का 1883 में जन्म हुआ।
- क्रोएशिया के राष्ट्रपति फ्रांजो टडमैन का 1922 में जन्म हुआ।
- भारतीय फ़िल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का 1923 में जन्म हुआ।
- भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री का 1981 में जन्म हुआ।
- फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का 1984 में आज ही के दिन जन्म हुआ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एन.जी.चन्दावरकर का निधन 1923 में हुआ।
- अल्ला बख़्श का निधन 1943 में हुआ अंग्रेज़ी शासन के दौरान एक जमींदार, सरकारी ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे।
- प्रख्यात विद्वान् तथा राजनीतिक नेता डॉक्टर रघुवीर का निधन 1963 में हुआ।
- प्रसिद्ध नाटककार जगदीशचन्द्र माथुर का निधन 1978 में हुआ।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से सेहत व कार्यक्षमता सुधारें

दुनिया में आबादी के लिहाज से पहले नंबर का देश तो भारत बन ही गया। आज तक इसकी पहचान युवा भारत के रूप में होती रही है। अब चौथे दशक के बाद बूढ़ों की संख्या में उसी तेजी से वृद्धि सामने नजर आएगी। तीसरी दुनिया के देशों, एशिया और प्रशांत देशों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 1.2 अरब हो जाएगी। यह कुल आबादी का लगभग एक-चौथाई होगी, दुनिया के इस हिस्से में और भारत में भी।

एशियाई विकास बैंक ने एक रिपोर्ट एजिंग वैल इन एशिया पेश की है। उसमें कहा गया है कि देश में बूढ़ों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है लेकिन उनकी सेहत, आय और कार्य सुरक्षा के बारे में नई दृष्टि नहीं बनी है। यह सही है कि आज भी देश की आधी आबादी कार्ययोग्य युवा पीढ़ी की है और उसमें से अधिकांश लोग बेकार हैं। रघुराम राजन जैसे आर्थिक विशारद यह भी कहते हैं कि विकास दर में सबसे आगे विकसित भारत में वंचित-प्रवंचित और भूख से मरते लोगों की संख्या भी काफी होगी। अब इसमें जुड़ रही है निरंतर बूढ़े होते लोगों की समस्या जिनके लिये सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एक ओर है दक्षिणी कोरिया और थाइलैंड, जहां सबको सेहत कवरेज मिल चुका है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत में केवल 21 प्रतिशत लोगों के पास जीवन बीमा की सुविधा है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य कवरेज की यह कमी इसलिए और भी विकट हो जाती है क्योंकि देश की बड़ी आबादी अनिश्चित कारोबार से जुड़ी है।

एजिंग वैल इन एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 50 फीसदी आबादी ऐसी है जो उचित सेहत सेवा से वंचित है। इनमें से 40 प्रतिशत निम्न वर्ग में से आते हैं। नई आयुष नीति की घोषणा करते वक्त कहा गया कि आयुर्वेद, एलोपैथी और यूनानी पद्धति के सम्मिलन से उपचार की क्रांति होगी। लेकिन देश की गरीब आबादी को इसका लाभ नहीं मिला।

आयुष्मान योजना की घोषणा तो पिछले वर्षों में हो गई थी। जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त उपचार सुविधा देने का वादा था। अब भाजपा के संकल्प पत्र में 70 साल से ऊपर के लोगों को यह मुफ्त सुविधा देने का वादा कर दिया गया है। लेकिन कितने लोगों को यह सुविधा मिली है? इस सुविधा को देने का दायित्व जब निजी क्षेत्र के कंधों पर आया तो उन्होंने उचित भुगतान न मिलने के कारण इस फ्री सर्विस को सहयोग देने से इंकार किया।

बेशक चिकित्सा पर्यटन की असीम संभावनाएं हमारे सेवा क्षेत्र में देश की कमाई के लिए निकलती हैं। दरअसल, दुनिया के अन्य देशों में मध्यवर्गीय लोगों को तत्काल उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं होती। हमारे देशों के पंचतारा अस्पतालों में बड़े-बड़े विशेषज्ञों द्वारा यह सेवा उपलब्ध है। सरकार भी मेडिकल पर्यटन पर बहुत जोर दे रही है। लेकिन इस मेडिकल पर्यटन की साख बनाए रखने के लिए भी देश के चिकित्सा विशारदों को अपने आप को न केवल नवीनतम ज्ञान से लैस करना होगा बल्कि उपचार की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी करना होगा।

देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों पर सेवानिवृत्त करने की बजाय उन्हें काम करने का नया मौका दिया जाए। उनकी शारीरिक और कार्यात्मक क्षमता को सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के लिये प्रेरित करना होगा। यदि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का उन्हें लाभ मिले तो उनकी अतिरिक्त सक्रियता से देश को लाभांश मिलेगा।

इसका अर्थ यह हुआ कि देश के युवा बल ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की मेधा और संभावित सक्रियता के उचित इस्तेमाल से भी देश अपने विकास पथ पर एक द्रुत लय से बढ़ सकता है। इस समय भारत उपचार और सेहत के लिहाज से एशिया और प्रशांत देशों में सबसे निचली कगार पर है। इसलिए गरीब लोगों को नकदी रहित बीमा देने वाली योजनाएं बुजुर्गों का स्वास्थ्य कवरेज करेंगी तो बेहतर होगा। केवल घोषणाएं करने से ही काम नहीं चलेगा। घोषणाओं के रास्ते में लालफीताशाही अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है। धनराशि के आवंटन की कमी भी इसके हाथ बांध देती है।

निश्चित रूप से अगर नौजवानों की शक्ति के इस्तेमाल के साथ-साथ वृद्धजनों के बल को भी उचित उपयोग का मार्ग देना है तो न केवल पूरी दृष्टि बदलनी होगी बल्कि उसके अनुकूल वातावरण बनाना होगा।?पिछले दिनों में यह प्रचार किया जा रहा था कि हमारे राजस्व में आशातीत वृद्धि हुई है।? हमने जीएसटी के डेढ़ लाख करोड़ के लक्ष्य को पार करके उम्मीदों के अनुरूप प्राप्ति कर ली है। इस धनराशि में से अगर उचित आवंटन देश के समावेशी सेहत विकास के लिए कर दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि देश की कार्ययोग्य श्रम शक्ति का संतुलित विकास न हो। अर्थात्? यह न हो कि यहां न तो नौजवानों को काम मिले और न ही बूढ़ों को बेहतर स्वास्थ्य तथा न ही देश?की अर्थव्यवस्था में योगदान के अवसर मिलें।

चुनावों का मौसम और उदासीन बुद्धिजीवी

नवीन अब 78 वर्ष के होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी के बारे में भी चर्चा है। स्वयं अब तक कुंवारे ही हैं। राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में अब वहां के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पांडियन का नाम चर्चा में चलता है। नवीन पटनायक की एक विशेषता यह भी है कि वह 'मीडिया केंद्रित' राजनीति पसंद नहीं करते।

चुनावों का मौसम आते ही चुनावी राजनीति से जुड़ी अनेक भूली-बिसरी यादें ज़ेहन में तैरने लगती हैं। इन यादों में युवाओं की उदासीनता, लेखन जगत से जुड़ी शख्सियतों का लगभग पूरी तरह हाशिए पर सरक जाना, भाषा के स्तर में गिरावट, मीडिया का बहरूपियापन आदि पर ध्यान अटकना स्वाभाविक है। बुद्धिजीवी वर्ग या कला-संस्कृति एवं साहित्य से जुड़े लोगों ने अधिकांशतः चुनावी-राजनीति से दूरी बनाए रखी है। वैसे भी उन्हें कभी वोट-बैंक आकर्षित करने वाला चुम्बक नहीं माना गया।

दक्षिण भारत व मध्य भारत में शुरुआती दौर में बुद्धिजीवियों ने कुछ भूमिका निभाई लेकिन उनकी लीक पर चलने में उनके अपनों ने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उड़ीसा में दो बार ऐसा हुआ। पहली बार नंदिनी सत्पथी ने वहां की सियासत में विशिष्ट पहचान बनाई, यद्यपि वह स्वयं और उनके पति तथागत की मूल पहचान लेखन के क्षेत्र से ही थी। दूसरी बार बीजू पटनायक के आकस्मिक निधन के पश्चात उनकी तीन संतानों में किसी एक को उत्तराधिकारी बनाने पर विचार हुआ। तब सबसे पहले बीजू के बड़े बेटे श्री प्रेम पटनायक का नाम उभरा। मगर वह किनारा कर गए। शेष दो में छोटे बेटे नवीन पटनायक और उनकी लेखिका बहन गीता मेहता का नाम चर्चा में चला। लेकिन गीता मेहता उन दिनों अमेरिका में थीं। उन्हें बुकर-पुरस्कार भी मिला था। वैसे भी उन्हें राजनीति या सत्ता के गलियारे से कोई जुड़ाव नहीं था। सबसे छोटे नवीन पटनायक 1970 के दशक में दक्षिणी दिल्ली में अपने यारों-दोस्तों की महफिलों में छाए हुए थे। उन्होंने कुछ वर्षों तक दिल्ली के ओबेराय होटल में अपना बुटीक भी चलाया। वहां पर अक्सर तीन काफी टेबल उनके नाम पर 'बुक' रहती थीं। इसी नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 'थ्री काफी टेबल्स'। उनके सहपाठियों में संजय गांधी भी शामिल थे। उन दिनों 'जींस-टी शर्ट' ही पहनते थे नवीन और जब सत्ता के गलियारे में धकेले गए तो पहचान ही बदल गई। अब कुर्ता-पायजामा ही उनकी पहचान बन चुकी है। नवीन की कुछ विशिष्ट बातें भी हैं, जिन्हें लेकर कई बार पार्टी में भी संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन उनका एक ही उत्तर होता है, 'मैं कोरे दिखावे या नाटकीयता में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। पार्टी में अक्सर उन्हें आग्रह किया जाता है कि उड़िया भाषा में लिखने-पढ़ने का अभ्यास कर लें। वह अक्सर जनसभाओं में भी ठीक से उड़िया भी नहीं बोल पाते थे। यह बात अलग है कि वह उड़िया की संस्कृति और वहां के साहित्य के बारे में अंग्रेजी में समुचित संवाद कर लेते हैं। यदि इस बार भी वह विधानसभा चुनावों में जीत गए तो देश में सर्वाधिक लम्बे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का उनका कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। वैसे इस समय इस सूची में सिक्किम के पवन कुमार चेमलिंग शिखर पर हैं।

नवीन अब 78 वर्ष के होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी के बारे में भी चर्चा है। स्वयं अब तक कुंवारे ही हैं। राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में अब वहां के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पांडियन का नाम चर्चा में चलता है। नवीन पटनायक की एक विशेषता यह भी है कि वह 'मीडिया केंद्रित' राजनीति पसंद नहीं करते। बहुत कम बोलते हैं और भाषा की गरिमा पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। वह न तो बड़बोले हैं, न ही बयानबाज़ी का कोई शौक है। ओडिशा में वैसे बुद्धिजीवी, लेखक सदा सक्रिय रहे हैं। कर्नाटक आदि में तो परंपरा यह भी रही है कि मुख्यमंत्री समय-समय पर प्रतिष्ठित लेखकों के घर भी जाते रहे हैं। तमिलनाडु, केरल में भी बुद्धिजीवियों के लिए राजनीति के गलियारे खुले रहे हैं। इसके विपरीति उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तरप्रदेश में डॉ. सम्पूर्णानंद, पीडी टंडन व प्रयाग-बनारस की कुछेक विभूतियों के बाद माहौल में बाहुबलियों की चर्चा ज़्यादा होने लगी थी। मध्यप्रदेश में भी शुक्ला बंधुओं से पहले द्वारिका प्रसाद मिश्र व कुछ अन्य साहित्य और लेखन दोनों में चर्चा का केंद्र बने।

विदेशों में सुरक्षित नहीं भारतीय युवा

विदेश में भारतीय छात्र महफूज नहीं हैं। पिछले छह साल में विदेश में 403 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी। विदेश मंत्री ने कहा कि 2018 से अब तक कुल 403 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। लोकसभा में उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मौत के मामले कनाडा से हैं।

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां के युवाओं में विदेश जाकर अपना भ?विष्य संवारने की ललक है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण भारत, लाखों भारतीय विदेशों में हैं और उन्होंने वहां के संविधान और संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। उच्च पदों पर बैठकर वे वहां के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

भारत में हर साल हजारों की संख्या में बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं। इन प्रोफेशनल्स की मांग देश और विदेशों में भी काफी है। कई को विदेशी कंपनियां मोटी सैलरी पर बुलाती हैं। इनमें वे युवा होते हैं जिनकी उपयोगिता उन देशों में बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों के बिना उनके यहां का काम नहीं चल सकता, जैसे- इंजीनियरिंग करके जाने वाले स्टूडेंट, डॉक्टर और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आदि। विदेशी कंपनियां उन्हें लुभाने वाले पैकेज देकर बुलाती हैं। वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो खुद को तैयार ही इस हिसाब से करते हैं कि वे विदेश में काम कर सकें और पैसा कमा सकें। भारतीय छात्र भी विदेशों में अच्छी ?शिक्षा प्राप्त कर वहीं पर जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग खुद को योग्य बनाकर कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ते हैं लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो बिना किसी तैयारी के, गलत तरीके से बेहतर ज़िंदगी की चाह में विदेश पहुंच जाते हैं और कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं। हजारों युवा जो शिक्षित भी नहीं हैं वे भी वहां श्रम करके पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। इन दिनों लगातार अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई में भारतीय युवाओं की मौत की खबरें दिल दहला देने वाली हैं।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय छात्र नवजीत संधू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। विक्टोरिया पुलिस के मुताबिक, 22 साल का नवजीत हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। नवजीत के चाचा ने बताया कि उसकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए उसके पिता ने आधा एकड़ जमीन बेच दी थी। वो जुलाई में अपने परिवार से मिलने आने वाला था। इसके अलावा नवजीत ऑस्ट्रेलिया में डेढ़ साल के वर्क वीजा पर था। दुबई में भी पंजाब के जालंधर छावनी के एक गांव के युवक पंकज की हत्या कर दी गई थी।

इसी वर्ष फरवरी माह में शिकागो में एक भारतीय छात्र पर हमला हुआ था। घटना का एक वीडियो सामने आया था। इसमें 3 हमलावर छात्र का पीछा करते नजर आए थे। इसके बाद तीनों ने उसे बुरी तरह पीटा था, फोन छीन लिया था और भाग गए थे। छात्र खून से लथपथ नजर आया था। जनवरी माह में अकुल धवन का शव इलिनोइस अर्बाना-शैंपेन यूनिवर्सिटी के बाहर मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हुई। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र विवेक सैनी की हत्या कर दी गई थी। फॉक्स न्यूज के मुताबिक 25 साल के छात्र विवेक के सिर पर एक बेघर शख्स ने हथौड़े से 50 बार वार किया था। इसके अलावा भी कई छात्रों की मौत बीमारी से भी हो चुकी है। कई छात्र दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं।

विदेश में भारतीय छात्र महफूज नहीं हैं। पिछले छह साल में विदेश में 403 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी। विदेश मंत्री ने कहा कि 2018 से अब तक कुल 403 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। लोकसभा में उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मौत के मामले कनाडा से हैं। कनाडा में पिछले 6 साल यानी 2018 से अब तक 91 छात्रों की मौत हुई है। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय छात्रों की मौत के सबसे अधिक 91 मामले कनाडा से रहे। मगर विदेश में भारतीय छात्रों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा के बाद दूसरे नंबर पर ब्रिटेन का नाम आता है। यहां पिछले 6 साल में 48 छात्र मौत के शिकार हुए हैं। वहीं, इस मामले में रूस तीसरे नंबर पर है। यहां 2018 से अब तक 40 छात्रों की मौत हुई है। अमेरिका में 36, ऑस्ट्रेलिया में 35, यूक्रेन में 21 और जर्मनी में 20 भारतीय छात्रों की इन छह साल में मौत हुई है। इसके अलावा साइप्रस में 14 छात्रों की मौत हुई है जबकि फिलीपींस और इटली में 10-10, कतर-चीन और किर्गिस्तान में 9-9 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

देश में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे?

प्रधानमंत्री सलाहकर परिषद द्वारा लोकसभा चुनाव के चलते जारी अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में आजादी के बाद देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने और हिंदुओं की आबादी घटने सम्बन्धी जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसकी प्रामाणिकता से भी ज्यादा अहम बात उसके टाइमिंग की है। देश में मतदान का तीसरा चरण पूरा होते ही यह रिपोर्ट जारी करवाई गई। पूरी रिपोर्ट का आशय हिंदुओं में अपनी संख्या और वर्चस्व को लेकर भय पैदा करना ज्यादा है। क्योंकि यह पुराने आंकड़ों पर आधाारित है। भारत में 2011 के बाद से सरकार ने जनगणना ही नहीं कराई है। कहा जा रहा है कि अब यह काम 2025 में होगा। लेकिन सचमुच होगा ही, यह कोई नहीं जानता और इस जनगणना के आंकड़े सरकार के एजेंडे के अनुकूल नहीं रहे तो सार्वजनिक भी होंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। रिपोर्ट का लुब्बो लुआब यही है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की आबादी 43.15 फीसदी बढ़ी है। वहीं, हिंदू आबादी 7.82 फीसदी घट गई। आशय यही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक। सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। रिपोर्ट बताती है कि हिंदुओं की आबादी हिंदू बहुल नेपाल में भी घटी है। परिषद ने ये आंकड़े 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन के बाद जारी किए हैं। इन देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है, जिनकी आबादी 75 फीसदी से अधिक है। वहीं, अमेरिका की शोध संस्था प्यू रिसर्च के 2020 के अनुमान के मुताबिक भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे पर पाकिस्तान है। परोक्ष रूप से यह रिपोर्ट हिंदुओं को अपने वजूद और धर्म की रक्षा के लिए चेताती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए हैं तो कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनगणना किए बिना हिंदू और मुस्लिम आबादी का निर्धारण कैसे कर लिया। केंद्र की भाजपा सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुओं-मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर रही है। आप बिना जनगणना कराए ही आंकड़ों पर कैसे पहुंच गए? वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 1971 के बाद वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को धर्मशाला और चारागाह बना दिया। एक अनुमान के अनुसार, 2024 में भारत की कुल तकरीबन 147 करोड़ की आबादी में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। वहीं, 1947 में आजादी के वक्त करीब 10 करोड़ मुस्लिम भारत में थे। बंटवारे के बाद करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम भारत ही रह गए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को आबादी के आधार पर आरक्षण देने पर तुली हुई है तो वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के हिस्से में कटौती करेगी। हकीकत यह है कि मुसलमानों में चार शादियों की इजाजत होने के बाद भी गिने-चुने मुसलमानों की एक से अधिक बीवियां हैं। यही नहीं शिक्षा के प्रसार व आर्थिक दबावों के चलते मध्य व उच्च वर्ग के मुसलमानों की संतानें भी अब दो या तीन ही होती हैं। इसलिए यह दावा कि आने वाले कुछ सालों में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, केवल खाम खयाली है। असल मकसद हिंदू वोटों को लामबंद करना है। भाजपा इस बार लोस के तीनों चरणों में तुलनात्मक रूप से कम वोटिंग के कारण चिंता में है। इसीलिए रिपोर्ट का जिन्न बाहर निकाला गया है।

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विमर्श की दरकार

महिलाओं के द्वारा ही समाज और परिवार की संस्था को कायम रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों के नाम पर इसे अनवरत आगे बढ़ाया जाता हैं बिना कोई प्रश्न किए क्योंकि इस व्यवस्था में प्रश्न का पूछा जाना विद्रोह है । बहरहाल महिलाओं को गढ़ने की इस प्रक्रिया में उन्हें एक बेहतर बेटी, पत्नी, मां, बहू और अन्य रिश्तों में भी परफेक्ट बने रहने की सीख दी जाती है। इन सीखों और नसीहतों के साथ वे अपनी मां, दादी और नानी की तर्ज पर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती रहती है बिना किसी प्रश्न के। इस विमर्श में पितृसत्ता के दोहरे चरित्र को भी देखे जाने की आवश्यकता है । इस व्यवस्था में शादी योग्य कन्या का शिक्षित होना भी आवश्यक है और उसी के साथ कहीं नौकरी करती हो और अच्छी खासी तनखवाह हो तो बात ही क्या लेकिन इसके साथ ही उसे संस्कारी होना भी आवश्यक है जो पूरे परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर सुपर वूमन की परिकल्पना को सार्थक करें ।

चित्रा माली

भारतीय परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जब तक कि वे बीमारी से संघर्ष करती हुई बिस्तरा न पकड़ लें। ऐसे में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की किसे परवाह हो सकती है । महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को गंभीरता से न लेते हुए हम बड़ी ही आसानी से इसे पाश्चात्य बता सकते है और इसके एवज में कई सारे तर्क दे सकते हैं लेकिन इस पर वर्तमान संदर्भों में बात करने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि अवसादग्रस्त महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और वे कई प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं । जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर की हैसियत एक पुर्जे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसी प्रकार से पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भी महिलाओं को, उनकी उपयोगिता को उनके श्रम से आंका जाता है । इस घरेलू श्रम का उसे कोई मेहनताना भी नहीं दिया जाता है और ना ही वे कभी इसकी मांग करती है । महिलाओं के द्वारा ही समाज और परिवार की संस्था को कायम रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों के नाम पर इसे अनवरत आगे बढ़ाया जाता हैं बिना कोई प्रश्न किए क्योंकि इस व्यवस्था में प्रश्न का पूछा जाना विद्रोह है। बहरहाल महिलाओं को गढ़ने की इस प्रकिया में उन्हें एक बेहतर बेटी, पत्नी, मां, बहू और अन्य रिश्तों में भी परफेक्ट बने रहने की सीख दी जाती है। इन सीखों और नसीहतों के साथ वे अपनी मां, दादी और नानी की तर्ज पर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती रहती है बिना किसी प्रश्न के। इस विमर्श में पितृसत्ता के दोहरे चरित्र को भी देखे जाने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में शादी योग्य कन्या का शिक्षित होना भी आवश्यक है और उसी के साथ कहीं नौकरी करती हो और अच्छी खासी तनख्वाह हो तो बात ही क्या लेकिन इसके

साथ ही उसे संस्कारी होना भी आवश्यक है जो पूरे परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर सुपर वूमन की परिकल्पना को सार्थक करें। आज हर कहीं परफेक्ट होने की मुहिम जारी है जिसमें महिलाओं को ब्रेन विथ ब्यूटी के साथ साथ एक बेहतर पत्नी जो अपने पति की हर छोटी बड़ी समस्या को हल करने में सक्षम हो उसकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके और उसके बच्चों की परवरिश करें उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उनकी सुपर मॉम बन हर काम को चुटकियों में खत्म कर दें। सास ससुर के साथ साथ अन्य रिश्तेदारों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें । जबकि पुरुषों के साथ इस तरह की कोई शर्त नहीं रहती है उसका सिर्फ कमा कर लाना ही परिवार के लिए काफी होता है । परिवार और दफ्तर की अलग अलग भूमिकाओं में उसके अपने अस्तित्व का कुछ अंश ही सांस ले पाता है या कहे विकसित हो पाता है । बाकी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनते बनते कहीं लुप्त हो जाता है। यही लुप्त हिस्सा कहीं न कहीं अवसाद का कारण भी बनता है। लगातार परफेक्ट बनने की चाह भी एक प्रकार की कुंठा को जन्म देती क्योंकि परफेक्ट जैसा कुछ है ही नहीं अन्यथा प्रकृति ने हमें क्यों विविधताओं और भिन्नताओं के साथ निर्मित किया है। अवसाद (डिप्रेशन) और चिंता विकार (एंजायटी) ये दो शब्द आजकल हर कहीं सुने जा सकते हैं । महिलाओं में इनके लक्षणों को हार्मोनल चेंजेस (हार्मोन परिवर्तन) के समय देखा जा सकता है । खासतौर पर मासिक धर्म के पहले के दिनों के आस पास, गर्भावस्था के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद जिसे प्रसवकालीन अवसाद कहा जाता है । ये सभी अवसाद अलग अलग होते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान जिसे पेरिमेनोपॉजल अवसाद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को उचित महत्व न मिलना, उनके अधिकारों का लगातार हनन होना, उनका उचित ध्यान न रखा जाना, उनका लगातार घरेलू और मानसिक हिंसा का शिकार होना, लंबी बीमारी से उपजा या हीनता के बोध से उपजा अवसाद भी हो सकता है । फ्रायड द्वारा विकसित मनोविज्ञान के अनुसार स्त्री लिंग की अनुपस्थिति से उपजे हीनता - बोध में ताउम्र जीती है। केट मिलेट ने फ्रायड की आलोचना की ओर कहा कि महिलाओं में हीनता का कारण मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक है । सिमोन द बोउवार ने महिलाओं को महज जैविक उत्पाद नहीं, बल्कि सामाजिक उत्पाद करार देते हुए इडिपस और कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स के विषय में कहा कि यदि लड़के और लड़की दोनों की परवरिश समान सामाजिक वातावरण में की जाए तो दोनों को ही ये ग्रंथियां नहीं झेलनी पड़ेगी। फ्रीडन ने दावा किया कि महिलाएं लिंग की अनुपस्थिति के कारण हीनता के बोध से ग्रसित नहीं होती है क्योंकि उनके पास प्रजनन का पूरा मैकेनिजम है जो जाहिर है कि पुरुषों के पास नहीं है। महिलाओं में अवसाद के सामान्य लक्षण जैसे अत्यधिक या कम सोना, हमेशा सिर दर्द का बना रहना, पाचन संबंधी समस्या, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कार्य करने की क्षमता में कमी, अत्यधिक भय और चिंता, ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देना जो वास्तव में है ही नहीं, भूख न लगना, लगातार उदासी या निराशा की बातें करना, लोगों से दूरी बना लेना, अकेले या चुप रहना, अत्यधिक उच्च या निम्न मनोदशा जिसमें अत्यधिक उत्साह या घोर निराशा और ऐसे विचार या व्यवहार जो काम, परिवार और सामाजिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। महिलाओं में अवसाद के ये लक्षण सामान्य लग सकते हैं लेकिन इनके पीछे के कारणों को जानना अत्यंत आवश्यक है जो कहीं न कहीं सामाजिक पारिवारिक हिंसा व भेदभाव के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं । समाज और परिवार में आज भी स्त्री - पुरूष में भेद किया जाता है । परिवार में जब कभी भी कोई पुरुष बीमार होता है तो उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है वहीं अगर कोई महिला अस्वस्थ होती है तो पहले तो वह खुद ही उसे गंभीरता से नहीं लेती है और यदि स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो परिवार द्वारा सामान्य इलाज करवा दिया जाता है लेकिन उसके खान पान पर, उसकी मानसिक परेशानियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अवसादग्रस्त महिलाओं को मानसिक स्पोर्ट की आवश्यकता होती है जिससे वे भय और चिंता से मुक्त हो सामान्य जीवन यापन कर सकें। महिलाओं के व्यवहार में इन बदलाओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि समय रहते उनकी परेशानियों को समझा जा सके और उनसे उन्हें निजात दिलाई जा सके। इसी के साथ महिलाओं को खुद के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत व जागरूक होने की भी जरूरत है। महिलाओं को स्व-देखभाल की भी आवश्यकता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

अध्यात्म

सर्वश्रेष्ठ हो, बस वही ईश्वर को समर्पित हो

एक नगर मे एक महात्मा जी रहते थे और नदी के बीच मे भगवान का मन्दिर था और वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते थे और ईश्वर को चढाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गये तो बीच रास्ते मे उन्हे एक फल वाले के वहाँ एक आदमी कह रहा था की कुछ सस्ते फल दे दो भगवान के मन्दिर चढाने है। थोड़ा आगे बढे तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था की दीपक का घी देना और वो घी ऐसा की उससे अच्छा तो तेल है। आगे बढे तो एक आदमी कह रहा था की दो सबसे हल्की धोती देना एक पण्डित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब वो मन्दिर गये तो जो नजारा वहाँ देखा तो वो दंग रह गये... उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी और वहाँ पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुये थे पर वो कुछ लोगों को नये नये वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा ह? महात्मन चाहे हम ज्यादा न कर पाये पर हम अपने ईश्वर को वो समर्पित करने की ईच्छा रखते है जो हमें भी नसीब न हो और जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मना करता है की इन्हे उतम वस्त्र पहनावे। और जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा ह? देव एक नारी के लिये उसके सिर के बाल अति महत्वपुर्ण है और वो उसकी बड़ी शोभा बढ़ाते है तो मैंने सोचा की मैं अपने इष्टदेव को वो समर्पित करूँ जो मेरे लिये बहुत महत्वपुर्ण है इसलिये मैं अपने ईष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। जब उन दोनो से पूछा की आप अपने ईष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी माँग भी सर्वश्रेष्ठ होगी तो उन दोनो ने ही बड़ा सुन्दर उत्तर दिया। ह? देव हमें व्यापारी नही बनना है और जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नही चाहिये। जब महात्मा जी मन्दिर के अन्दर गये तो वहाँ उन्होने देखा वो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आये साथ मे अपनी मांगो की एक बड़ी सूची भी साथ लेकर आये और भगवान के सामने उन मांगो को रख रहे है। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा ह? मेरे अतिप्रिय शिष्यों जो तुम्हारे लिये सबसे अहम हो जो शायद तुम्हे भी नसीब न हो जो सर्वश्रेष्ठ हो वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले मे कुछ माँगना मत और माँगना ही है तो बस निष्काम-भक्ति और निष्काम-सेवा इन दो के सिवा अपने मन मे कुछ भी चाह न रखना। इसीलिये हमेशा याद रखना की भले ही थोड़ा ही समर्पित हो पर जो सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित हो।

सैम पित्रोदा से उपजे कुछ सवाल

सैम की पहली गलती, इनहेरिटेंस टैक्स का ज़िक्र छेड़ते हुए ये कहा कि इस पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए, जिसे बीजेपी ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। सैम की दूसरी गलती, भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहाँ पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख़्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ़्रीकी जैसे लगते हैं। इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता। हम सब भाई-बहन हैं। स्टेट्समैन अख़बार को उन्होंने एक सवाल के उत्तर में जब यह दो गलतियाँ कर दी तो फिर बम फूटेगा ही। यह एक इंटेलेक्चुअल लोगों के बोल हैं। भारत में बात पकड़ने की आदत नहीं उडती हुई चिड़िया पकड़ने की भी आदत है। चुनाव का समय हो, चुनाव चल रहे हों, ऐसे समय में इंटेलेक्चुअल बात हो या सामान्य बात, सब पकड़ ली जाएगी।

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

सैम पित्रोदा ने आनन-फानन में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा था। सैम पित्रोदा खेल रहे थे अबूझ खिलाड़ी की तरह कबड्डी-कबाड़ी-कबड्डी। चुनाव के बीच में इन्तेल्क्चुअल कम्युनिटी के बीच खेलने वाले सैम पित्रोदा चित्त हो गए। अपने मान-मर्यादा को खोकर जाते जाते वह कांग्रेस का कुछ वोट खाकर गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सैम पित्रोदा नादान नहीं हैं। वह भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सूत्रधार रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का खूब लाभ लिया। खूब कांग्रेस से यश प्राप्त किया। देश में इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटी को ज्ञान देने वालों को भारत का पता नहीं है शायद। यदि उन्हें पता भी होगा फिर भी आखिर क्या वजह है कि वह कुछ भी बोल जाते हैं। कुछ भी नहीं पता है तो किसी कांग्रेस कैडर से कोचिंग ले लेते देश का तो पता चल जाता। वह ज्ञानी बनकर कुछ भी क्यों बोलते रहे? वह कुछ सोच-समझकर क्या अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस की मजबूती के लिए यह सबकुछ कर रहे थे।

दरअसल, यह देश मजावादी लोगों का है। देश की तमाम पोलिटिकल पार्टियों में कुछ ऐसी भी शख्सियतें होती हैं जो मजे लेती रहती हैं। उन्हें पार्टी की कुछ भी पड़ी नहीं होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं की पार्टियाँ ऐसे लोगों के कारण मात खाती हैं। सैम पित्रोदा कुछ ऐसी ही शख्शियत हैं जो पिछले चुनाव में बोल गए थे-जो हुआ, वो हुआ। इसे बीजेपी ने खूब भुनाया और सैम अंकल को उन दिनों भी समझ नहीं आया था कि 1984 के बारे में जो हुआ वो हुआ, बोलना चाहिए कि नहीं पर बोल गए थे। मतदाता बहुत उहापोह में है तो देश में सन 2024 के लोक सभा चुनाव के तीसरे चरण आते आते बोल गए सैम। बोले तो कुछ हल्का नहीं बोले पूरा का पूरा बम जैसा बोले जिससे कांग्रेस भी धड़ाम से गिरी।

सैम की पहली गलती, इनहेरिटेंस टैक्स का ज़िक्र छेड़ते हुए ये कहा कि इस पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए, जिसे बीजेपी ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। सैम की दूसरी गलती, भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहाँ पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख़्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ़्रीकी जैसे लगते हैं। इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता। हम सब भाई-बहन हैं। स्टेट्समैन अख़बार को उन्होंने एक सवाल के उत्तर में जब यह दो गलतियाँ कर दी तो फिर बम फूटेगा ही। यह एक इंटेलेक्चुअल लोगों के बोल हैं। भारत में बात पकड़ने की आदत नहीं उडती हुई चिड़िया पकड़ने की भी आदत है। चुनाव का समय हो, चुनाव चल रहे हों, ऐसे समय में इंटेलेक्चुअल बात हो या सामान्य बात, सब पकड़ ली जाएगी। कोई भी स्व-घोषित या तथाकथित इंटेलेक्चुअल हो, यह न सोचे कि वह कुछ भी कहकर निकल जाएगा और उसकी चल पड़ेगी। सैम पित्रोदा फिर भला किस कांफिडेंस से यह कहकर निकलना चाह रहे थे यह भी बात सोचने वाली है।

भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में सैम को इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी नहीं पता है। वह ऐसे ऊल-जुलूल बयान कैसे दे सकते हैं। वह इन्हेरिटेंस टैक्स की चर्चा कराना चाहते हैं और देश की विविधता को मजाक का विषय करार देकर भारतीय मानस में हीरो बनने कि इच्छा पालकर निकल जाना चाहते हैं, और यह भी सोचते हैं कि भारत में कुछ भी बोला जा सकता है। इन गलतियों ने इस बार सैम की हड्डी-पसली गला दी। उनकी सारी विद्वत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार कि मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं सहन कर लेता हूँ। लेकिन आज शहजादे के फिलॉस्फर-सैम पित्रोदा ने इतनी बड़ी गाली दी है, जिसने मुझमें गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे ये बताए कि क्या मेरे देश में चमड़ी के आधार पर योग्यता तय होगी? संविधान सिर पर लेकर नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो पूरा अटैक मुद्रा में जनता के बीच हैं। विपक्ष से पुरजोर ताकत के साथ लड़ने की मुद्रा में हैं वह भला ऐसे विषय को कैसे जाने देते, सारी सैम की बुद्धि पर ही सवाल खड़े कर दिए। सैम पर पूरा देश गुस्से से देखने लगा। सैम अब ज्ञान आयोग वाले सैम न होकर अज्ञान के महावीर बन गए।

यह देश बहुत ही कमाल का है। हर समय कुछ ऐसे किस्से के साथ बहता है कि देश के लोग मनोरंजन के मूड में आ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी हाल ही में मारिया आलम खान के वोट फॉर जिहाद वाला बयान ठंढा भी नहीं हुआ था कि सैम अंकल ने ये दूसरा मुद्दा ला खड़ा कर दिया। बन गया नया न नया बावला। यही तो भारत की जनता को मनोरंजन, बातचीत करने के लिए चाहिए। सैम और मारिया जैसे बहाने जनता भी ढूँढती है। भारत के हर नुक्कड़ पर, गोमटी-चौराहों पर अब मारिया और अंकल सैम बातचीत के लिए मुद्दा हैं। जहाँ चुनाव हो चुके वहां थोडा कम। जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहां पुरजोर इन्हीं को लेकर बातचीत हो रही है। यह इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि बातें बहुत होती हैं और जनता मजे भी लेती है। देश में जो भी हो सैम के भी परखचे उड़ गए। उन्हें कांग्रेस के उस विशिष्ट पद से हाथ धोना पड़ा और मुह छिपाकर आखिर भागना पड़ा है।

मध्य चुनाव में कांग्रेस के ये बडबोले सैम कांग्रेस पार्टी को अपनी क्षमता अनुसार जो खाद-पानी दिए थे, उसे वे सूद सहित उसूलते हुए उसको घाटा देकर गए हैं। देश में इंटेलेक्चुअल लोग भी कांग्रेस कि डुबाने में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी कांग्रेस को खूब नुकसान पहुँचाया है। इसका फायदा अगर बीजेपी को मिलती है और वह अपने 400 पार के आंकड़े को खड़ा कर लेती हैं तो इसमें निश्चित रूप से इन इंटेलेक्चुअल सैम जैसे अंकल का बड़ा सहयोग भी होगा जो अपने बडबोलेपन से कांग्रेस को मिटटी में मिलाने से पीछे नहीं हटे हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो सैम पित्रोदा के नाम से अब मशहूर हैं उनके जीवन की कहानी भी दिलचस्प है। उन्होंने भारत में आईटी को बढ़ाने में निःसंदेह बड़ी दिलचस्पी ली। राजीव गाँधी के बेहद करीबी थे। वह राजीव गाँधी की मृत्यु के उपरांत निराश हुए और विदेशों में अपने आपको सिमट जाने की भी सोच रखते थे लेकिन कांग्रेस से उनका लगाव भी रहा हा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने तरह से भारत को देखा। यह उनकी दृष्टि है लेकिन उन्होंने जो कहा वह उनकी भावनाओं तक केवल सिमट जाएगी, यह तो बात संभव ही नहीं है।

अब चाहे वह खुद इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा देकर भागने को बोला गया हो, यह सब कयास जनता लगाएगी ही। कांग्रेस का इससे जो सियासी नुकसान हुआ है उसे तो कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। उसके लिए उसके ही अपने ही लोग कांटे के जाल बिछा जाते हैं यह इससे ज़रूर तथ्य निकलकर सामने आया है। कांग्रेस के लिए अपने हिसाब से फूल बोने वाले लोग शूल बन जाएंगे, यह उसका अपना दुर्भाग्य है। सैम के बहाने कांग्रेस अपने हार के ठोकरे फोड़ने के बहाने भी अब ढूँढ़ चुकी है, उसका भी कोई फायदा हुआ हो या नहीं लेकिन यह फायदा उसे तो मिल ही गया है। भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के बाद हार के ठीकरे फोड़ने के बहाने निःसंदेह सैम अंकल बन ही जाएंगे। जो भी हो सैम पित्रोदा से उपजे सवाल निश्चय ही कांग्रेस को हिला दिए हैं।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहने वाला है। आप अपने कामों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। आप अपने किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे।

वृषभ
आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपकी आय तो बढ़ेगी लेकिन आपके खर्च भी अधिक रहेंगे।

मिथुन
आपके आसपास रह रहे लोग आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां का बहुत अधिक रहेगी।

कर्क
आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से कामों में आगे बढने के लिए रहेगा। आप अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं।

सिंह
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आप कार्यक्षेत्र में अपनी मनमर्जी चलाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा।

कन्या
आज का दिन आपके लिए कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए रहेगा। आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा।

तुला
कार्यक्षेत्र में सहयोगी आपके व्यवहार के कारण आपके कामों में आपका साथ नहीं देंगे, जिसका कारण आपको काम करने में समस्या आएगी।

वृश्चिक
आज का दिन आपके लिए कुछ नए लोगों से मिलजोल बढ़ाने के लिए रहेगा। ऑनलाइन काम कर रहे लोग आज अपने कामों पर पूरा फोकस बनाएं।

धनु
आज का दिन आपके लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करने के लिए रहेगा। आप अपने दिनचर्या में कोई बदलाव न करें, नहीं तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है।

मकर
आज का दिन आपके लिए अपने आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने कामों की सूची बनाकर आगे बढ़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।

कुंभ
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की तलाश खत्म होगी, क्योंकि उन्हें कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा।

मीन
आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। आपको अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों पर पूरा ध्यान दें। संतान कोई खुशखबरी दे सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

झड़पोंके बीच मतदान

लोकसभा चुनावके चौथे चरणमें सोमवारको नौ राज्यों और केन्द्रशासित जम्मू-कश्मीरकी कुल ९६ सीटों तथा आंध्रप्रदेश विधानसभाकी सभी १७५ और ओडिशाकी २८ विधानसभा सीटोंके लिए मतदानका कार्य सम्पन्न हुआ। लोकसभाके लिए कुल ६२.३० प्रतिशत मतदान हुए। मतदानके दौरान छिटपुट हिंसा और राजनीतिक कार्यकर्ताओंके बीच झड़पें भी हुईं। पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्रमें अलग-अलग कारणोंसे तीन लोगोंकी मृत्यु भी हुई। बिहारके मुंगेरमें मतदानके दौरान पर्ची नहीं देनेके आरोपमें कुछ लोगोंने सुरक्षाकर्मियोंपर पथराव किया। इसी प्रकार आंध्रप्रदेशमें भी मारपीटकी घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेशकी १३ सीटोंके अतिरिक्त आंध्रप्रदेशकी २५, तेलंगानाकी १७, महाराष्ट्रकी ११, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेशकी आठ-आठ, बिहारकी पांच, झारखण्ड और ओडिशाकी चार-चार और जम्मू-कश्मीरकी एक सीटके लिए मतदान हुए। कुछ राज्योंमें मौसम खुशगवार होनेसे मतदाताओंमें उत्साह दिखा। चौथे चरणमें उत्तर प्रदेशके शाहजहांपुर, खीरी, धरुहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच तथा बिहारके दरभंगा, उजियापुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर तथा झारखण्डके सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीटोंके लिए हुए मतदान कमोबेश शान्तिपूर्ण रहे। चौथे चरणमें १,७१७ प्रत्याशियोंके भाग्यका फैसला ईवीएममें कैद हो गये हैं। इनमें केन्द्रीयमंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुण्डा सहित उत्तर प्रदेशके पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव, लोकसभामें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, असुदुद्दीन ओवैसी, फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, केन्द्रीय मंत्री नित्यानन्द राय, जी. किशन रेड्डी, अजय मिश्र टेनी भी शामिल हैं। चौथा चरण मिलाकर कुल ३७९ सीटोंके लिए मतदान सम्पन्न हो गये। शेष तीन चरणोंमें अब १६३ सीटोंके लिए मतदान होंगे। सोमवारको प्रारम्भमें मतदानकी गति धीमी रही लेकिन बादमें इसमें तेजी आ गयी। लोकसभा चुनावोंमें मतदानका प्रतिशत उम्मीदसे कम होनेके कारण चिन्ता बढ़ गयी है। पहले चरणमें ६५.५ प्रतिशत मतदान हुए, जबकि दूसरे चरणमें ६६ प्रतिशत और तीसरे चरणमें ६५.६८ प्रतिशत मतदाताओंने अपने मताधिकारका प्रयोग किया। २०१९ के लोकसभा चुनावोंकी तुलनामे इस बार मतदान कम हुए। मतदानका प्रतिशत बढ़ाने लिए जागरूकता अभियान सतत जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भी अनेक बार मतदान करनेकी अपील भी कर चुके हैं। उम्मीद है शेष तीन चरणोंमें मतदानका प्रतिशत अवश्य बढ़ना चाहिए।

रिश्तोंमें सुधारकी उम्मीद

भारत-चीनके रिश्तोंमें आयी कड़वाहटका लम्बे समयतक जारी रहना दोनों देशोंके हितमें नहीं है। सीमा विवादको लेकर पूर्वी लद्दाखमें दोनों देशोंकी सेनाओंके बीच मई २०२० से गतिरोध जारी है। मुख्य रूपसे क्षेत्रमें गश्त करनेके अधिकार और गश्त क्षमताओं जैसे मुद्दोंको लेकर अबतक कई दौरकी सैन्य वार्ता हो चुकी है लेकिन सीमा विवादका पूर्ण समाधान अभीतक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्ष टकरावके कई स्थानोंसे पीछे हटे हैं लेकिन गतिरोधका जारी रहना गम्भीर चिन्ताकी बात है। भारतके परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरके इस बयानसे दोनोंके रिश्तोंपर जमी बर्फके पिघलनेकी उम्मीद जगी है कि चीनके साथ कई मुद्दे शीघ्र हल होंगे। इस सम्बन्धमें परराष्ट्रमंत्री जयशंकरका यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धोंकी वापसी सीमापर शान्तिपर निर्भर करती है। यह बात भारत लगातार कहता रहा है कि सम्बन्धोंको सामान्य बनानेके लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शान्ति महत्वपूर्ण है लेकिन चीनके अड़ियल रवैये और सीमा विस्तारकी उसकी महत्वाकांक्षाके चलते सीमा विवादका मुद्दा जटिलसे जटिलतम होता जा रहा है। चीनको इसपर अपने स्वार्थसे ऊपर उठकर गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। परराष्ट्रमंत्रीका पश्चिम एशियामें मौजूदा स्थितिको देखते हुए भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) के क्रियान्वयनपर चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्लीमें जी-२० शिखर सम्मेलनमें इसपर काफी जोर दिया गया था और इसके सभी हितधारक इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इस गलियारेके कार्यमें तेजी लानेकी जरूरत है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिसे यह सभी देशोंके हितमें है। भारतके साथ चीनकी सीमाकी स्थितिका तत्काल समाधान किये जानेकी आवश्यकता है। भारत-चीनके शान्तिपूर्ण सम्बन्ध दोनों देशोंके लिए ही नहीं अपितु विवादित क्षेत्र और पूरी दुनियाके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए चीनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

लोक संवाद

रहें अवसाद मुक्त

महोदय,-अवसाद एक गम्भीर मानसिक बीमारी है, जिससे विश्वभरमें करीब २८० मिलियन लोग प्रभावित हैं। अवसाद मनुष्यको महसूस करने, सोचने, कार्य करने तथा सामान्य जीवन व्यतीत करनेमें नकारात्मक रूपसे प्रभावित करता है। सन् २०२३ की गणनाके अनुसार विश्वभरमें १.३ अरब व्यक्ति विकलांग हैं। शारीरिक विकलांगताका संबंध प्रत्यक्ष रूपसे अवसादके साथ देखा जाता है। अवसादके मुख्य लक्षणोंमें लगातार उदास रहना, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासकी कमी, सदैव थकावट महसूस करना तथा ऊर्जाकी कमी, किसी कार्यमें ध्यान केंद्रित करनेमें मुश्किलका सामना करना, खाने-पीनेकी आदतों तथा सोनेके समयमें बदलाव, स्वयंको दोषी अथवा बेकार समझना, अपने मित्रों अथवा पारिवारिक सदस्योंसे स्वयंको दूर रखना, आत्महत्या तथा मौतके बारेमें सोचना, स्वयंको नुकसान पहुंचाना, लगातार चिड़चिड़ापन अथवा निराशावादी होना शामिल हैं। जीवनके उद्देश्यकी समाप्ति, जब व्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाएं करनेमें असमर्थ हो जाता है तो उसको निराशा घेर लेती है तथा वह अपने जीवनका उद्देश्य पूरा करनेमें मुश्किलोंका सामना करता है। जितना ज्यादा एक विकलांग व्यक्ति आत्मसम्मानकी कमीका शिकार होता है, उतना ही ज्यादा उसमें अवसादका स्तर बढ़ता है। विकलांगताके कारण कई व्यक्ति घरमें अथवा बाहर आने-जानेमें असमर्थ हो जाते हैं इसलिए उनको हमेशा किसी न किसी सहारेकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनमें निराशा, कुंठा, गुस्सा तथा बेचैनी बढ़ जाती है। विकलांग व्यक्तिको काम करने, खरीदारी करने अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियोंके लिए घरसे बाहर जाना पड़ता है, परन्तु उसकी उस स्थानपर पहुंच चुनौती बन जाती है जिससे वह निराश हो जाता है। समाजमें विकलांग व्यक्तिको नफरत अथवा घृणाकी दृष्टिसे भी देखा जाता है। समाजका संवेदनहीन व्यवहार उसमें एकाकीपन बढ़ाता है। अपनी शारीरिक असमर्थताके कारण एक विकलांग व्यक्तिको उसकी बौद्धिक योग्यताके अनुसार रोजगार नहीं मिलता तथा कई बार वित्तीय आवश्यकताओंको पूरा न कर पाना अवसादका कारण बनता है। यह बहुत मुश्किल है, परन्तु जबतक इस सचका सामना नहीं करेंगे तबतक जिन्दगीमें आगे नहीं बढ़ सकते। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाको दबाता अथवा अनदेखा करता है तो उसका तनाव बढ़ता है, जो धीरे-धीरे अवसादमें परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब भी दुख आये, दिल खोलकर रोना चाहिए। उस अवस्थामें खुश दिखनेका दिखावा नहीं करना चाहिए। विकलांगताके कारण कई साधारण क्रियाओंको दोबारा सीखना पड़ता है, जो पहले आसानीसे हो जाया करती थीं, परन्तु इससे निराश न होकर यथार्थको स्वीकार करके अपने उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। अपने परिवार अथवा मित्रोंका साथ एक व्यक्तिकी जिन्दगीको खुशहाल बना देता है। इसलिए अपने मित्रों तथा पारिवारिक सदस्योंके साथ मजबूत रिश्ता बनायें ताकि आप अपनी भावनाओंको खुलकर उनके आगे व्यक्त कर सकें तथा वे इसमें आपकी सहायता कर पायें। रचनात्मक नये कार्य, जैसे पेंटिंग करना, कहानियां या कविताएं लिखना, संगीतकी धुन बनाना आदि आपको संतुष्टि तथा खुशी प्रदान करेगा। इस थैरेपीसे मनुष्यको वर्तमान हालातोंका सामना करने तथा स्वयंको इसमें ढालनेमें मदद मिलती है। जो भावनाएं एक अवसादग्रस्त व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा दोस्तोंके साथ सांझा नहीं कर सकता, उनको एक अनजान व्यक्तिके साथ कर लेता है। अवसाद एक बीमारी है, यदि काऊंसलिंगके साथ इससे छुटकारा नहीं मिलता तो दवाई लेना उपयुक्त रहता है क्योंकि यह आपके दिमागमें उपस्थित रसायनोंको संतुलित करती है। किताबें सच्ची मित्र होती हैं और संगीत मनकी उलझनको खोलनेकी शक्ति रखता है। ध्यान तथा योग शारीरिक तथा मानसिक बीमारियोंसे लड़नेकी शक्ति प्रदान करते हैं। मैडिटेशनसे नकारात्मक तथा हिंसक भावनाओंपर काबू पाया जा सकता है। नकारात्मक विचारोंको स्वयंपर हावी न होने दें तथा मित्रों, पारिवारिक सदस्यों तथा डाक्टरके साथ संपर्क करके अवसादको अपने जीवनसे निकाल बाहर करें। **-पूजा शर्मा, वाया ईमेल।**

सीमांत विकाससे टूटेंगे चीनके मंसूबे

इतिहासको मनमाफिक गढ़ना और भौगोलिक हकीकतोंसे छेड़छाड़ चीनकी प्रवृत्ति रही है। यह उसकी आधिपत्यवादी प्रवृत्ति है। इसके लिए वह वास्तविकतासे परेके तथ्योंको गढ़ता है। चीन अकसर भारतीय भूमिके कई हिस्सोंपर अपना दावा ठोंकता आया है। अकसर अरुणाचल प्रदेशमें बस्तियों और भूभागका नाम बदलनेमें उसे खुशी होती है।

❒ **ले.जनरल प्रदीप बाली**

चीनी नागरिक उड्डयन मंत्रालयने २०१७ में गढ़े नामोंकी पहली सूची जारी की थी, जिसमें छह जगहोंका जिक्र था। फिर १५ नये नामोंवाली दूसरी सूची २०२१ में आयी, २०२३ की सूचीमें ११ जगहोंका नाम बदला हुआ था। भौगोलिक नाम बदलनेके इस खेलमें चौथी और नवीनतम सूची १ अप्रैल, २०२४ को जारी की गयी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेशकी ३० और जगहें शामिल की गयी हैं। खुद अरुणाचल प्रदेशका नाम चीनियोंने 'जगनान' रखा हुआ है। उम्मीदके मुताबिक भारतने कड़े प्रतिरोधके साथ इस नौटंकीको खारिज किया है। इस कृत्यके समांतर वास्तविक नियंत्रण रेखाके उत्तरमें सीमांत इलाकोंको विकसित करनेकी आड़में चीन शियाओकांग नामक रिहायशी बस्तियां समूची सीमा रेखाके ठीक बगलमें स्थापित कर रहा है। पिछले सालोंमें लगभग ६०० ऐसे गांव बसाये जा चुके हैं और 'विकास कार्यक्रम' के तहत और १७५ बस्तियां बनानेकी योजना है। बिना शक यह सारी प्रक्रिया चीनके इलाकाई दावोंको पुष्ट करने और पीपुल्स लिबरेशन आर्मीका अतिरिक्त सहायता तंत्र बनानेके मकसदसे है। यहां चीन 'कानूनी रणनीति' का कपटी खेल भी खेल रहा है। भारतके साथ सीमा रक्षा सहयोग संधि-२००५ के मुताबिक जब कभी वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखाकी निशानदेही होगी तो पूर्व-स्थापित आबादियोंको नहीं छेड़ा जायगा। चीनी रणनीतिका यह रंग-ढंग अन्य मुल्कोंसे सीमा विवादोंमें भी झलकता है। जापान प्रशासित सेन्काकु द्वीपको दियाओऊ नाम देकर, चीन उसे अपना हिस्सा बतानेका दावा करता आया है। सर्वविदित है कि चीनकी तथाकथित नौ-बिंदु सीमारेखा समस्त दक्षिणी चीन सागरमें उसके इलाकाई दावोंको मजबूत बनानेका एक पैंतरा है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनका उल्लंघन है, खासकर संयुक्त राष्ट्र सागरीय कानून अधिवेशनके प्रावधानोंका। दावेदारीकी यह रेखा ब्रूनेईके विशेष निर्यात क्षेत्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताईवान और वियतनामके इलाकोंका अतिक्रमण करती है। चीन समुद्रमें कंक्रीट डालकर छोटे द्वीपों और उभरी चट्टानोंको बड़े टापुओंमें तब्दील कर रहा है। इन मानव निर्मित भौगोलिक द्वीपोंका निर्माण करनेके पीछे उद्देश्य है सैन्य लाभ सुदृढ़ करना और अपने पड़ोसियोंको जताना कि भिड़नेपर भविष्यमें क्या हो सकता है। भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्योंको तोड़ने-मरोड़नेकी छूट लेनेकी उसकी यह प्रवृत्ति भूटानमें २०१७ में स्पष्ट जाहिर हुई, जब चीनकी पीएलएने डोकलाम पठारको झम्पेरी रिजतक कब्जानेका यत्न किया। इसने भारतको क्रोधित किया, क्योंकि यह अतिक्रमण हमारी रक्षा संबंधी चिन्ताओंको बढ़ाता है। तभी भारतीय सेनाको यह कब्जा आमने-सामनेके टकरावसे फिल करना पड़ा। किसी इलाकेका अतिक्रमण कर उसका बधियाकरण करनेका एक उदाहरण तिब्बत है, जिसे चीनने १९५१ ने कब्जाया था और १९५९ में पूर्ण नियंत्रण बना लिया। चीनी शासकोंने दिखावेको तिब्बत सार्वभौमिक क्षेत्रकी स्थापना की है, जिसे आमतौरपर राजनीतिक तिब्बत कहा जाता है और इसका क्षेत्रफल शेष तिब्बतसे कहीं छोटा है। ऐतिहासिक रूपसे जनजातीय तिब्बतमें तीन मुख्य इलाके हैं- यूत्सांग, खाम और अम्दो। वर्ष १९५५ में अम्दोका विलय किंगहाई प्रांतमें कर दिया और १९५७ में खाम कोगांजे सार्वभौमिक प्रदेशके साथ मिला दिया गया। इसी प्रकार तिब्बतके बाकी जनजातीय इलाकोंका विलय

सीमावर्ती इलाकेमें हमारी तरफकी भौगोलिकता अत्यधिक दुरुह है और भूभाग अधिकांशतः तीखा पर्वतीय या घना जंगल है। सीमा सड़क संघटन इस चुनौतीसे पार पानेमें प्रयासरत है। हालमें अरुणाचल प्रदेशमें सेला सुरंगका उद्घाटन भारतकी वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखाको लेकर तैयारियोंको बल देगा। हालांकि यह काम बहुत विशाल स्तरका है और हमें तीखी ऊंचाइयोंपर काम करनेकी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। लोगोंका सीमांत इलाकेसे पलायन रोकनेके लिए आर्थिक लाभकी पेशकश और तेज गतिकी संचार व्यवस्था बनाना पहला कदम है।

गनसू और युनान प्रांतोंमें कर डाला। वास्तवमें, मूल तिब्बत राज्यमें अब सिर्फ यू-त्सांग क्षेत्र ही राजनीतिक तिब्बत है। वर्ष १९११ और १९५१ के बीच तिब्बत चीनी गणतंत्रके मंसूबोंसे कमोबेश मुक्त रहा। अम्दोमें १४वें दलाईलामाका जन्म हुआ और उनके अंगरक्षक खाम इलाकेसे हैं, जिन्हें तिब्बतियोंकी लड़ाकू जातिके तौरपर जाना जाता है। चीनने साथ लगते और बहुत ज्यादा जनसंख्याके बोझ तले दबे हान प्रांतसे चीनी मूलके लोगोंको तिब्बतके विभिन्न हिस्सोंमें बसाकर अंदरूनी जनसंख्या स्थानांतरण करवाया है। अधिकांश सीमांत गांव समूची वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखाके ठीक साथ सटाकर बनाये गये हैं, जिनमें लगभग सभी हान हैं। इन चीनी प्रवासियोंको वहां बसने-रहनेकी एवजमें काफी आर्थिक लाभ दिये जाते हैं और तिब्बतका जातीय स्वरूप बदलनेमें यह मुख्य अवयव है। चीनकी धूर्त रणनीतिके जवाबमें भारतकी प्रतिक्रिया बेपरवाहीसे लेकर बड़ी-बड़ी बातें करनेतक ही रही है। नाम बदलनेके नवीनतम खेलपर रक्षामंत्री राजनाथ सिंहकी प्रतिक्रिया बेहद सधी रही। ९ अप्रैलको पूरबी अरुणाचल प्रदेशमें एक जनसभामें उन्होंने कहा, मैं अपने पड़ोसीको बताना चाहता हूं कि नाम बदलनेसे कुछ हासिल नहीं होनेवाला। कलको यदि हम चीनके राज्योंका नाम बदल दें तो क्या वह उन्हें हमें सौंप देगा। चीनसे हमारे सीमा संबंधी मुद्दे द्विपक्षीय चिंताओंवाले रहे हैं। तथापि पिछले कुछ समयसे, अमेरिका भारतकी पीठपर हाथ रख रहा है। भारतमें अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटीने हालमें बयान दिया, भारतके इलाकोंका नाम बदलना चीनका काम नहीं है और वे भारतीय भू-भागका हिस्सा हैं, यह स्वागतयोग्य कदम है। पूरबमें देखें तो शंघाई सहयोग संघटनमें चीनके विकृत दावोंने तीखी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पैदा की है। चाहे यह क्वाड संघ हो (जिसमें भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं) या ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं अमेरिकासे बना ऑकस संघ या फिर अमेरिका, जापान, फिलीपींसका त्रिकोणीय गुट, इन सबका ध्यान शंघाई सहयोग संघटनकी बैठकोंमें चीनी मंसूबोंका विरोध कर वैधानिक विश्व-व्यवस्था बनानेपर केंद्रित है। भारतको चीन द्वारा ऐतिहासिक-भौगोलिक तथ्योंसे छेड़छाड़के प्रयासोंका प्रत्युत्तर शिद्दत और निरंतरतासे देनेकी जरूरत है। हमें इन मुद्दोंको मजबूतीसे उठाना होगा और चीनी दावोंके विरोधमें लिखित प्रतिरोध करना होगा। वर्ना उन्हें तथ्यके तौरपर स्वीकार कर लिया जायगा। सीमावर्ती इलाकेमें हमारी तरफकी भौगोलिकता अत्यधिक दुरूह है और भू-भाग अधिकांशत: तीखा पर्वतीय या घना जंगल है। यह हाल ठीक वास्तविक नियंत्रण रेखातक है। अपने इलाकेमें हमें बुनियादी ढांचा विकसित करनेका काम निरंतर जारी रखना होगा। सीमा सड़क संघटन इस चुनौतीसे पार पानेमें प्रयासरत है। हालमें अरुणाचल प्रदेशमें सेला सुरंगका उद्घाटन भारतकी वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखाको लेकर तैयारियोंको बल देगा। हालांकि यह काम बहुत विशाल स्तरका है और हमें तीखी ऊंचाइयोंपर काम करनेकी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। लोगोंका सीमांत इलाकेसे पलायन रोकनेको हमें सीमापर गांव बसानेको प्रोत्साहित करनेकी जरूरत है। इसके लिए आर्थिक लाभकी पेशकश और तेज गतिकी संचार व्यवस्था बनाना पहला कदम है। जहां सेना इन कामोंमें मददगार हो सकती है, वहीं इस सबके लिए नीतियां बनाना राजनीतिक नेतृत्वका कार्यक्षेत्र है। सबसे ऊपर, जो भारतीय नागरिक सीमावर्ती इलाकेमें बसे हैं उनकी संवेदनशीलताको सदा जहनमें रखना आवश्यक है।

अस्तित्व बचानेका संकट

देशकी कम्युनिस्ट पार्टियोंके सामने अस्तित्वका संकट खड़ा हो गया है। साल २००४ कम्युनिस्ट पार्टियोंके उत्थानका काल कहा जाय तो उसके बाद वामदलोंका लोकसभामें प्रतिनिधित्व लगातार कम ही होता जा रहा है।

❒ **डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**

अब १८वीं लोकसभाके चुनावोंमें वामदलोंके सामने अपने अस्तित्वको बचायें रखनेका संकट खड़ा हो गया है। आजादीसे पहले और उसके बादके दौरमें एक समय था जब वामदलोंकी पूरे देशमें तूती बोलती थी। सरकार भले ही कम ही राज्योंमें रही हो परन्तु वामदल और उसके अनुसंघी संघटन चाहे वह स्टूडेंट फैडरेशन हो या मजदूर संघटन या लेखक संघ सभीकी अपनी पहचान और फोलोवर्स रहे हैं। परन्तु समयका बदलाव देखिये कि आज वामदलोंके सामने पहचान बनाये रखनेका संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगालमें तो वामदलों तीन दशकसे भी अधिक समयतक एक सत्र राज किया, वहीं त्रिपुरा, केरलमें भी वामदलोंकी सरकार रही है। परन्तु २०१९ के लोकसभाके चुनाव आते-आते तो हालात यह हो गयी कि वामदलोंके गढ़ पश्चिम बंगालमें तो वामदलोंको एक भी सीट नहीं मिली, वहीं त्रिपुरामें भी खाता खोलनेमें विफल रही। दरअसल समयकी मांगको समझना और उसके अनुसार समयानुकूल बदलाव करना अपने आपमें बड़ी बात होती है। जनभावनाको भी समझना जरूरी हो जाता है। केवल विचारधारा और एग्रेसिव होनेसे काम नहीं चल सकता। फिर अपने अपने अहम्के चलते समयपर सही निर्णय नहीं लेनेका परिणाम देर-सबेर भुगतना पड़ता है। ज्योति बसुके पास तीन बार प्रधान मंत्री बननेके अवसर आये परन्तु पोलिट ब्यूरोंने उन्हें प्रधान मंत्री बनानेपर सहमति नहीं दी। कल्पना कीजिए कि ज्योति बसु तीनमेंसे किसी एक अवसरपर प्रधान मंत्री बनते तो उसका लाभ अंततोगत्वा वामदलोंको ही मिलता परन्तु आपसी मतभेदों या मनभेदोंके चलते सही विकल्प नहीं चुननेका परिणाम आज सामने हैं। गत २०१९ के लोकसभा चुनावोंकी ही बात की जायं तो वामदलोंको लोकसभाके लिए छह सीटे मिली हैं। इसमें भी एक समय कम्यूनिस्टोंके गढ़ रहे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरामें तो वामदलोंका खाता भी नहीं खुल सका। तमिलनाडुमें गठबंधनके सहारे माकपा और भाकपाको दो-दो सीटे मिल गयी वहीं केरलमें माकपा और आरएसपी एक-एक सीटें जीतनेमें सफल हो सकी। जैसे-तैसे केवल माकपा राष्ट्रीय दलके रूपमें अपनी पहचान बनानेमें सफल रही है। यह भी कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि लोकसभाके इससे पहलेके तीन चुनावोंके पहले २००४ के चुनावोंमें वामदलोंके पास ५९ सीटें थी। हालात यह थे कि कांग्रेस-भाजपाके बाद लोकसभाकी तीसरी बड़ी ताकत वामदल थे। कांग्रेसके साथ गठबंधन कर वामदल सरकारमें भी शामिल हुए। लोकसभा स्पीकरका पद भी वामदलोंके पास ही गया। देखा जाय तो न्यूनतम साझा कार्यक्रमके तहत सरकार भी ठीक ही चली परन्तु परमाणु समझौतेके चलते बादमें वामदल सरकारसे बाहर हो गये। ममताके चलते पश्चिम बंगालमें वामदल लगभग अप्रासंगिक होता जा रहा है और पश्चिम बंगालमें वामदलके स्थानपर भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। राजनीतिक विश्लेषकोंका मानना है कि वायनाड़से राहुल गांधीका चुनाव लड़ना भी वामदलको हानि पहुंचाने वाला ही रहा है। फिलहाल यह अलग विचारणीय प्रश्न हो जाता है। एक समय था जब ज्योति बसुको केन्द्रकी राजनीतिमें लानेके प्रयास हुए परन्तु आपसी मतभेदोंके चलते वामदलोंने इसे सिरेसे चढ़ने ही नहीं दिया। वामदलोंकी अस्तित्वके संकटको यूं भी समझा जा सकता है कि किसी समय विपक्षी दलोंमें वामदलोंकी तूती बोलती थी आज कोई बड़ा नाम सामने नहीं आ पा रहा है। प्रकाश करात या सीताराम येचुरी आदिके नाम यदा-कदा ही सामने आ पाते हैं। एक समय था जब सोम दा, इन्द्र जीत गुप्त, एबी वर्द्धन, ज्योति बसु और उससे पहलेकी भारतीय राजनीतिपर दृष्टिगोचर किया जाय तो पी. सुन्दरैया, सी. राजेश्वर राव, ईएमएस नंबुदरीपाद, एके गोपालन, बीटी रणदीव जैसे अनेक नाम थे जिनका भारतीय राजनीतिमें अपनी अलग हैसियत और पहचान रही। वामदलोंकी चुनावोंमें सूखा २००९ के चुनावोंसे लगातार बढ़ता गया है। २००४ में जहां ५९ सीटे थी जो २००९ में कम होकर २४ रह गयी, २०१४ के चुनावोंमें उसकी भी आधी यानी १२ और २०१९ के चुनावोंमें उसकी आधी यानी कि छह रह गयी। अब २०२४ के लोकसभाके चुनावोंमें वामदलोंके सामने अपनी पहचान बनाये रखनेका संकट आ गया है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरासे कोई खास लगता नहीं हैं, केरलमें भी हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। दरअसल वामदलोंके हाशियेमें जानेके अन्य कारणोंके साथ ही ममताका पश्चिम बंगालमें पकड़ बनाये रखना है तो बीजेपी वहां अपनी पैठ लगातार बढ़ानेके प्रयास कर रही है। दूसरी ओर कहनेको कुछ भी कहा जायं परन्तु भाजपा या मोदीको सत्तासे हटानेके लिए विपक्षी दलों द्वारा आपसी सहमति या यूं कहें कि इंडीका कंसेप्ट भी चल नहीं पाया है। तस्वीरका एक पहलू यह भी है कि वामदल जिसे अपना वोट बैंक मानकर चलता रहा है उस वोट बैंकपर सेंध भी उन्हींके साथ समझौता कर रही कांग्रेस पार्टी है। केरलमें अल्पसंख्यकोंके साथ ही हिन्दुओंके वामदलोंके वोट कांग्रेस अपनी और करनेमें सफल रही है। फिर वामदलोंके नेताओंकी जो यूएसपी अच्छे वक्ताके रूपमें होती थी वह आज दिखाई नहीं देती। समयके साथ बदलावको आत्मसात् नहीं करनेके कारण ही सोशियल मीडिया जो आज प्रमुख माध्यम बन गया है, उस क्षेत्रमें वामदल कहीं पिछड़ गये हैं। दरअसल गठबंधनकी राजनीतिके अपनी लाभ हानि है और एक कारण यह भी है कि यह गठबंधन एक चुनावके लिए होता है तो राज्य स्तरपर होनेवाले चुनावमें प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। इससे जनतामें भी मैसेज अलग तरहका जाता है। ऐसेमें वामदलोंको १८वीं लोकसभामें अपनी पहचान बनाये रखनेके लिए कठोर परिश्रम करना होगा। वामदलोंके सामने दरअसल अभी विकल्प कम ही है। वामदलके कमिटेड वोटर्स छिटक गये हैं तो नेतृत्व द्वारा न तो दूसरी लाइनके नेता तैयार किये गया हैं और न ही केडरको मजबूत करनेके प्रयास किये गये हैं। जन-आन्दोलन जो कभी वामदलकी पहचान होती थी वह कहीं नेपथ्यमें चली गयी है। एक समय था जब छोटी-सी-छोटी जगह भी कोई न कोई कामरेड मिल जाता था जिसकी अपनी पहचान होती थी, उस तरहके नाम आज तलाशने पड़ते हैं। २०२४ के चुनावोंके नतीजे जो भी हो परन्तु आगेके लिए वामदलोंको भारतीय राजनीतिमें प्रासंगिक बने रहनेके लिए ठोस रणनीति बनाकर एग्रेसिव रूपसे आगे आना होगा।

कर्तव्य

❒ **श्रीराम शर्मा**

मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि असत्य अच्छा नहीं फिर भी वह उसीमें आसक्त रहता है। वह अपने दुर्गुणोंको नहीं छोड़ सकता। वह अपने दुर्गुणोंको नष्ट करनेके लिए प्रयत्नशील नहीं होता। इसका कारण क्या है। अविद्या रहस्यमयी है। बुरे संस्कारोंके कार्य रहस्यमय है। सत्संग तथा गुरुसेवाके द्वारा इस मोहको नष्ट किया जा सकता है। सभ्यताका आचरण वह प्रणाली है, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता है। कर्तव्यपालन करनेका तात्पर्य है नीतिका पालन करनेका अर्थ है अपने मन और इंद्रियोंको वशमें रखना। ऐसा करनेसे हम अपने आपको पहचानते हैं। यही सभ्यता है और इससे विरुद्ध आचरण करना असभ्यता है। हम भले ही अपने दुष्कर्मोंको भूल जायं, परन्तु कर्म छोटेसे छोटे और बुरेसे बुरे किसी भी कार्यको नहीं भूलता और समयपर उसका अवश्य भोग होता है। इसलिए यदि इस तथ्यको हम समझकर ग्रहण करें तो अनेक बुरे कार्य हमसे आप ही छूट जायंगे और इस प्रकार जीवन बहुत सुधर जायगा। आजका युग खूब कमाओ, मजा उड़ाओंकी भ्रांत धारणामें लगा है और सुखको दु:खमय स्थानोंमें ढूंढ़ रहा है। धनमें सुख नहीं है, अतृप्ति है, मृगतृष्णा है। संसारमें शक्तिकी कमी नहीं, आराम और विलासिताकी नाना वस्तुएं बन चुकी हैं, किन्तु इसमें तनिक भी शांति या तृप्ति नहीं। जबतक कोई मनुष्य या राष्ट्र ईश्वरमें विश्वास नहीं रखता, तबतक उसे कोई स्थायी विचारका आधार नहीं मिलता। अध्यात्म हमें एक दृढ़ आधार प्रदान करता है। अध्यात्मवादी जिस कार्यको हाथमें लेता है, वह दैवी शक्तिसे स्वयं ही पूर्ण होता है। भौतिकवादी सांसारिक उद्योगोंमें कार्य पूर्ण करना चाहता है, लेकिन ये कार्य पूरे होकर भी शांति नहीं देते। दूसरोंके अनुशासनकी अपेक्षा आत्मानुशासनका विशेष महत्त्व है। हमारी आत्म ध्वनि हमें सत्यके मार्गकी ओर प्रेरित कर सकती है। सत्य मार्गसे ही पृथ्वी स्थिर है, सत्यसे ही रवि तप रहा है और सत्यसे ही वायु बह रही है। सत्यसे ही सब स्थिर है। सत्यका ग्रहण और पापका परित्याग करनेको हमें सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। आस्तिकता हमें ईश्वरपर श्रद्धा सिखाती है। हमें चाहिए कि ईश्वरको चार हाथ-पांव वाला प्राणी न समझें। ईश्वर एक तत्व है, उसी प्रकार जैसे वायु एक तत्व है। वैज्ञानिकोने वायुके अनेक उपभाग किये हैं। इसके हर एक भागको भी स्थूल रूपसे वायु ही कहेंगे। यह तत्व सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। परमेश्वर हमारे ऋषि-मुनियोंकी सबसे बड़ी खोज है। इसलिए सदैव अपने अन्दर सद्गुणोंका ही अनुसरण करना चाहिए।

युद्धकी विभीषिकासे मानवताको क्षति

❒ **प्रो.मनोज डोगरा**

विश्वमें उथल-पुथल कई मोर्चोंपर चली रहती है जिसपर दुनियाका ध्यान आकर्षित होता रहता है। साथमें ही इसका प्रभाव शेष विश्वपर भी पड़ता है, लेकिन विश्वमें शांतिके लिए संघर्ष या युद्ध एक चिंतनका विषय है। एक तरफ अभी यूक्रेन-रशिया युद्धकी आग बुझी ही नहीं थी कि दूसरी ओर इसरायल और फिलिस्तीनके हमास आतंकवादी संघटनके बीच युद्ध छिड़ गया और ऐसा युद्ध जिसमें केवल बर्बरता, लाशें, आग, मलबा और रॉकेट दिख रहे हैं। लोग बेबस हैं, बच्चे अचंभित हैं, औरतोंके साथ बर्बरता हो रही है। आखिर लड़ाई किस चीजके लिए और आतंकवादियोंके पास इतना गोला-बारूद आया कहांसे, ऐसी कैसी ताकत जो ५००० रॉकेट २० मिनटमें दाग कर बर्बादीकी कहानी लिख गये, पैराशूटके साथ सीमा पार कर स्पेशल कमांडोकी तरह उतरकर दनादन गोलियां बरसाना, आखिर ऐसी ट्रेनिंग आतंकियोंकी कहां हो रही और आखिर इसके पीछे कौन है। ये चौंकानेवाली कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि ये केवल आतंकी नहीं, बल्कि इनके पीछे और ताकतें हैं। वैसे युद्ध किसी भी देशके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीत-हार तो बादकी बात है, पहले इसमें मानवताको हानि और क्षति होती है। इसलिए युद्ध न केवल मृत्यु और विनाशका कारण बनते हैं, बल्कि स्थायी शारीरिक और मानसिक चोट भी पहुंचाते हैं, जो अंततक उन लोगोंको अवश्य ही परेशान करती रहेगी जो उनसे प्रभावित होते हैं। पृथ्वीपर जीवन अनमोल और अद्वितीय है। तार्किक रूपसे, हम अपनी सभ्यताकी प्रगतिके ऐसे चरणमें हैं कि हमें युद्धोंके निहितार्थोंको जानना चाहिए और उन्हें होने ही नहीं देना चाहिए। युद्धोंमें कोई वास्तविक विजेता नहीं होता है, क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्षोंको परिणाम भुगतना पड़ता है जिसमें अकसर दोनों पक्षोंके हताहतोंकी संख्या अधिक होती है। जब भी युद्ध होता है, दोनों देशोंको मानवीय मूल्योंसे हाथ धोना पड़ता है। उन देशोंकी तो क्षति होती ही है, इसका असर दूसरे देशोंपर भी पड़ता है, चाहे वह आर्थिक तौरपर हो, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक तौरपर हो, युद्धोंसे होनेवाली क्षतिकी कभी भी भरपाई नहीं हो पाती। रूसके द्वारा यूक्रेनके खिलाफ छेड़ा गया युद्ध अभीतक जारी है और फिलहाल इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा, चाहे अब इसरायल-हमास हो परन्तु एक बात निश्चित है कि इसका प्रभाव पूरे विश्वमें पड़ रहा है। युद्ध चाहे कोई भी हो, कौन-सा भी हो, लेकिन वह कभी भी किसी भी देशकी लोकतांत्रिक राजनीति और अर्थव्यवस्थाके लिए ठीक नहीं होता। एक युद्ध जिन देशोंके बीचमें छिड़ता है, केवल उनकी ही नहीं, बल्कि पूरे विश्वकी शांति भंग करता है, इसका उदाहरण हमें यूक्रेन तथा रूसके युद्धसे मिला। अब इजरायल-हमास युद्धके परिणामोंके लिए हमें तैयार रहना होगा। इसरायल और हमासके बीच जंग छिड़ चुकी है तथा दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। यह जंग सिर्फ अब रॉकेट और मिसाइलके दमपर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि यह जंग साइबर वर्ल्डमें भी पहुंच चुकी है। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कोई जंग असल दुनियासे लेकर साइबर वर्ल्ड तक पहुंची हो। इससे पहले यूक्रेन और रूसके युद्धमें भी हमने साइबर अटैकके कई मामले देखे हैं। ऐसा ही कुछ हमास और इसरायलके बीच होता दिख रहा है। हालमें हमासने इसरायलपर अचानक हमला किया। इस हमलेमें सैकड़ों लोगोंकी मौत हुई है। इनमें सैनिकोंसे लेकर आम आदमीतक सभी शामिल हैं। पिछले वर्ष इजरायल बेस्ड मीडिया आउटलेट जेरूसलमने जानकारी दी कि उनके ऊपर कई साइबर अटैक हुए हैं। फोन ऐपको टार्गेट किया गया। इन अटैकों की वजहसे जेरूसलम पोस्टकी वेबसाइट क्रैश हो गयी। यहांतक कि कई लोकेशनसे उनकी वेबसाइटको एक्सेस भी नहीं किया जा पा रहा था। इस हैकिंगको एनोनिमस सूडानने अंजाम दिया था। इसके अलावा कई दूसरे मामले भी देखनेको मिले हैं। इसरायलका रेड अलर्ट फोन ऐप सिस्टम भी साइबर अटैकका शिकार हुआ है। इस ऐपकी मददसे इसरायलमें रॉकेट और मिसाइल हमलेके वक्त रियल टाइम अलर्ट मिलता है। ये चीजें बताती हैं कि जंगका अंजाम कितना घातक होता है। अबतक इस युद्धमें १५०० से अधिक लोग मारे जा चुके हैं तो हजारों लोग बर्बरताका शिकार हो रहे हैं। न जाने अभी और कितने मरेंगे और कितने जीवनभरके लिए युद्धके जख्म सहनेको मजबूर होंगे। पूरा विश्व इस बीच दो गुटोंमें बंट चुका है। कुछ देश फिलिस्तीनके साथ तो कुछ इसरायलको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन युद्धके मुख्य किरदार एक-दूसरेके अस्तित्वको ही मिटानेकी जिद्दमें गोला-बारूद दाग रहे हैं। मानो नामोनिशान ही मिटा देंगे, लेकिन इस बीच खुदको बचानेके लिए कुछ लोग बंकरोंमें छिप रहे हैं तो कुछ मातृभूमिकी रक्षाके लिए युद्धके मैदानमें लड़ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध किसीका भी हो, जख्म बच्चों, महिलाओंपर बर्बरताके साथ मिलते हैं जो मानवताको शर्मसार करते हैं। ऐसा ही वहां भी हो रहा है। युद्धके पीछे कई कारण हैं, लेकिन बर्बरताका आलम देखकर हर कोई चिंतित एवं स्तब्ध है। युद्ध और उसके अंतसे उत्पन्न परिणामोंसे निबटनेके बजाय यह पाठ लोगों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणपर इसके प्रत्यक्ष प्रभावोंपर गौर करेगा। युद्धोंमें जहां सैनिक शहीद होते हैं वहीं बूढ़े-बच्चे-महिलाएं-पुरुष और न जाने कितने निर्दोष लोग मृत्युके आगोशमें समा जाते हैं, जहां दोनों देशोंको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, चारों तरफ तबाहीका मंजर होता है। यहांतक कि आनेवाली पीढ़ी भी याद रखती है कि कभी इस धरतीपर युद्ध हुआ था। दुआ है कि दोबारा कभी भी युद्ध न हो।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नैरेटिव बदलने की कोशिश

अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के प्रधानमंत्री का सवालछ उठाकर उस नैरेटिव को पलटने की कोशिश की, जो विपक्षी गठबंधन इंडि गठबंधन को लगातार रक्षात्मक मुद्रा में बनाए हुए था। भाजपा पिछले एक दशक से हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती आई है। उसकी यह रणनीति कामयाब भी रही है। इसके बरक्स वह विपक्ष से यह सवाल करती आई है कि मोदी के मुकाबले कौन? इस लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति के केंद्र में इसी सवाल को रखा कि विपक्षी गठबंधन का नेता कौन है? विपक्षी खेमे की अनिश्चितता के मुकाबले एनडीए की सुनिश्चितता मोदी के नाम और चेहरे के रूप में स्पष्ट थी। लेकिन भाजपा ने यह कायदा बनाया था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र का होने पर पार्टी के नेता सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे। विपक्ष ने इसी आधार पर यह सवाल किया है कि अगले साल मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या उनकी जगह कोई और नेता लेगा? और अगर ऐसा है तो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का असली प्रत्याशी किसे माना जाए? सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भाजपा घोषणापत्र में इस बार किए जा रहे वादों को पार्टी 'मोदी की गारंटी' के रूप में पेश कर रही है। भाजपा ने भी सवाल की गंभीरता को समझा। तत्काल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे शीर्ष नेता सामने आए और स्पष्ट शब्दों में बताया कि पार्टी के चुनाव जीतने की स्थिति में न केवल नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे बल्कि वह अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। वैसे राजनीति में उम्र कोई सीमा नहीं मानी जाती है। इस बात का श्रेय भाजपा और खासकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा कि वह अपनी पार्टी के जरिए भारतीय राजनीति में रिटायरमेंट का चलन लेकर आए। 2014 के बाद भाजपा के कई प्रभावशाली नेता इस नए चलन के मुताबिक रिटायरमेंट की राह पर बढ़ते देखे गए। इसे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी माना गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जारी रखने की पार्टी की घोषणा चाहे-अनचाहे बहस को इस सवाल की ओर ले जाएगी कि क्या पार्टी नरेंद्र मोदी को इस नियम का अपवाद मान चुकी है? अगर हां तो क्या यह पार्टी के अंदर लोकतंत्र के कमजोर होने का सूचक है? अच्छी बात यह है कि अब लोकसभा चुनाव के दौरान इन सवालों पर वोटरों की राय भी दर्ज हो जाएगी।

मोदी के लिए अपरिहार्य कैसे बने अमित शाह

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

अमित शाह राजधानी में अपने साउथ ब्लॉक के दफ्तर में जब काम करते होंगे, तब उनके जेहन में भी देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल का ख्याल अवश्य आता होगा। लौह पुरुष सरदार पटेल नें भी इसी साउथ ब्लॉक में बने गृह मंत्री कार्यालय से ही से देश की आंतरिक सुरक्षा को एक नई दिशा दी थी। वे भी बोलने में कम और काम करने में अधिक यकीन करते थे। अमित शाह का एक गुण यह भी है कि वे किसी अनावश्यक विवाद को खत्म करने में देर नहीं करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शायद सोचा होगा कि वे अमित शाह को देश का भावी प्रधानमंत्री बताकर एक विवाद खड़ा कर देंगे। पर उनकी यह मंशा सफल नहीं हुई, क्योंकि अमित शाह ने साफ कर दिया कि नरेन्द्र मोदी ही 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

गृह मंत्री के रूप में अमित, शाह को प्रधानमंत्री का विश्वास और पूरा भरोसा प्राप्त है। वास्तव में, जब कोई राजनीतिक या सरकारी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष लाया जाता है, तो कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति से अमित शाह से भी सलाह लेने के लिए कहते हैं। 2019 में, गृह मंत्री बनने के तीन महीने बाद, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकारी कदम में सबसे आगे थे। इसके लिए कुशल राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता थी। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन हासिल था। चार साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वैधता को बरकरार रखा, जो कि भाजपा ने भारत के अंतिम एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा था। अमित शाह 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की पीछे प्रेरक शक्ति भी रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं - उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए।

अमित शाह ने पहले भाजपा के संगठन में रहते हुए और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए उनके संगठनात्मक कौशल को सबने देखा, लेकिन जो लोग उन्हें गुजरात के दिनों से जानते थे, वे बहुत हैरान नहीं हुए। फिर, 2019 में, वह केंद्रीय गृह मंत्री बने, और इसके साथ ही शुरू हुआ कई बड़े फैसलों को लेने का दौर। पिछले पांच वर्षों में, अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देखरेख में भारतीय दंड विधान (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को बदला गया। अमित शाह मानते हैं कि कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। 1860 से 2023 तक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ।

आपको याद होगा जब जब भारत अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे। नए आपराधिक कानून उनमें से एक को पूरा करते हैं। सरकार ने नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम दिया है।

गृह मंत्री के रूप में अमित, शाह को प्रधानमंत्री का विश्वास और पूरा भरोसा प्राप्त है। वास्तव में, जब कोई राजनीतिक या सरकारी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष लाया जाता है, तो कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति से अमित शाह से भी सलाह लेने के लिए कहते हैं। 2019 में, गृह मंत्री बनने के तीन महीने बाद, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकारी कदम में सबसे आगे थे। इसके लिए कुशल राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता थी। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन हासिल था। चार साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वैधता को बरकरार रखा, जो कि भाजपा ने भारत के अंतिम एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा था।

अमित शाह 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की पीछे प्रेरक शक्ति भी रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं - उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आशंका थी कि सीएए को विपक्ष मुद्दा बनायेगा। पर यह नहीं हुआ। इसकी बेशक एक बड़ी वजह यह रही कि अमित शाह देश के मुसलमानों को भरोसा देता रहे कि सीएए कानून का उनसे कोई लेना-देना है। याद करें कि राजधानी के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ महिलाओं ने लंबा धरना दिया था। धरने देने वाली महिलाएं कह रही थीं कि सीएए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। धरना कोविड के फैलने के कारण सरकार ने सख्ती से बंद करवा दिया था। उस समय धमकी दी जा रही थी कि सीएए के खिलाफ धरना फिर शुरू होगा। पर यह नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित मोदी बार-बार मुसलमानों को भरोसा देते रहे कि सीएए से उन्हें घबराने की कोई वजह नहीं है। इसका सकारात्मक असर हुआ। जब केन्द्र सरकार ने सीएए की पिछली 11 मार्च को अधिसूचना जारी की तो एक बार लगा कि इसका विरोध होगा। पर कहीं कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए की अधिसूचना के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सीएए को लागू करने के मसले को लोकसभा चुनाव में उठाएंगे। सीएए, एनआरसी और धारा 370 जैसे मुद्दे कांग्रेस के घोषणापत्र से ही गायब हैं। सीएए पर दिल्ली से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गया था और जल्दी ही यह हिंदू- मुस्लिम विवाद में बदला था। दिल्ली में सार्वजनिक संपत्ति को खूब नुकसान पहुंचाया गया और विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हुए थे। एक लोकतांत्रिक देश में हर मुद्दे पर विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी हक है। जबकि विधेयक में पहले दिन से कहा गया था कि यह केवल उन शरणार्थियों पर लागू किया जाएगा जो ₹धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर थे।

खैर, अमित शाह की सरपरस्ती में , आंतरिक आतंकवाद का खतरा भी कम हुआ है। इस्लामिक स्टेट का उदय, पहले सीरिया और बाद में अफगानिस्तान में, चरमपंथी प्रवृत्ति वाले कई युवाओं को विदेशी जमीन में युद्ध लड़ने के लिए देश से बाहर जाते हुए देखा गया। इससे 2014 में कट्टरपंथ और ऑनलाइन ब्रेनवाशिंग के नए खबरों के बारे में चिंता पैदा हुई थी, लेकिन गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां आज इनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित राज्यों में, सुरक्षा बल धीरे-धीरे उन क्षेत्रों में वापस आ रहे हैं जिन्हें कभी रेड जोन माना जाता था। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नक्सलियों पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऐसा पिछले साल दिसंबर महीने में भी देखने को मिला था। अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा के कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। फिर वो चाहे, नक्सलवाद के खिलाफ हो या आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद और नक्सलवाद लोकतांत्रिक तरीके नहीं हैं और इन्हें समाप्ति कर देना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

लोकसभा चुनाव के दौरान रंग भेद की राजनीति

सुरेश हिंदुस्तानी

कुछ इसी प्रकार के बयान कांग्रेस के अन्य नेता भी देते रहे हैं। एक बार मैंने अपने एक लेख में लिखा था, जिसका उल्लेख अन्य लेखक भी कर चुके हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अनजाने में देश का विरोध करने लगती है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का आशय देश विरोध का नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते ही क्यों हैं, जिसका एक अर्थ ऐसा भी निकलता है, जिससे देश का विरोध होने का संकेत मिलता है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए कोई छोटा नाम नहीं है। वे कांग्रेस के मुख्य कर्ता धताओं में गिने जाते हैं। हालांकि चुनाव में उनके बयान का विपरीत प्रभाव न हो, इसलिए सैम पित्रोदा का इस्तीफा देना एक राजनीतिक कदम भी हो सकता है। अगर सैम पित्रोदा का इस्तीफा लेना ही था तो उनके पहले दिए बयानों पर भी तो लिया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इससे कांग्रेस की सोच का पता चलता है और बैठे ठाले ही कांग्रेस ने भाजपा को एक और मुद्दा दे दिया। सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की एक बार फिर से फजीहत करा दी।

लोकसभा चुनाव के दौरान राजनेताओं के बयान सुनकर ऐसा लगने लगता है कि ये अपनी हदों को पार कर करने लगे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान की मीमांसा की जा रही है। इसके तारतम्य यही है कि इस नेता ने भारत में भेद पैदा करने के प्रयास किए हैं, जो कभी सफल नहीं होने चाहिए। भारत में जिस प्रकार से सामाजिक विघटन की राजनीति की जा रही है, उससे समाज की शक्ति का लगातार पतन ही हुआ है। कभी तुष्टिकरण तो कभी वोट बैंक की राजनीति के बहाने सामाजिक एकता की राह में अवरोध पैदा करने के प्रयास किये गए, जिसके कारण समाज के कई हिस्से अलग अलग दुकान खोलकर बैठ गए और इसकी आज की राजनीति ने इसे मुंह मांगा इनाम भी दिया। जिसके कारण भारतीय समाज के बीच जो विविधता की एकता को दशार्ने वाली परंपरा रही, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का अनवरत प्रयास किया गया। यह सभी जानते हैं कि जिस देश का समाज कम से कम राष्ट्रीय मामलों पर एक स्वर व्यक्त करता है, वहां किसी भी प्रकार की सामाजिक बिखराव के प्रयास धूमिल ही होते है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को यह सामाजिक एकता अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाते हुए ही अपनी राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को भारत की सांस्कृतिक एकता खटकती है। ऐसे लोग कुत्सित राजनीति के माध्यम से भारत की जनता के मानस में ऐसे बीज बोने का ही काम करते हैं, जो प्रथम दृष्टया विभाजनकारी ही कहे जा सकते हैं। ऐसे बयानों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। क्योंकि यह विचार देश का भला नहीं कर सकता। अगर ऐसा विचार लेकर कोई राजनीतिक दल राजनीति करता है तो उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल हो सकते हैं।

राजनीतिक दलों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए पूर्व और पश्चिम को अलग पहचान के रूप में प्रचारित करने में जोर लगाया, तो वहीं उत्तर और दक्षिण के लोगों के मन में नफरत की दरार को और ज्यादा चौड़ा किया। जबकि हमारे देश के नायकों ने एक भारत के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। आज की राजनीति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उनके सपनों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जा रहा। इसी कारण कहीं जातिवाद को हवा दी रही है तो कहीं तुष्टिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राजनीतिक दल समाज को एक करने की दिशा में कदम उठाएं। इससे समाज का तो भला होगा ही, देश भी मजबूत होगा।

वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अस्तित्व बरकरार रखने के जिस प्रकार का परिश्रम किया जा रहा है, वह निसंदेह आवश्यक भी था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भी पार्टी के इस अभियान को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल विदेशी अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, उसे अनजाने में दिया बयान समझकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सैम पित्रोदा कांग्रेस नेताओं के बहुत खास रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी के विदेशी दौरे भी यही प्रबंधित करते हैं। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, उससे भारत की कांग्रेस ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन विदेशों में सैम पित्रोदा भारत को किस रूप में प्रस्तुत करते होंगे, इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सैम पित्रोदा के बयान का आशय यह भी निकाला जा सकता है कि वे भारत को एक देश के रूप में नहीं देख सकते। उनकी नजरों में शायद भारत की चारों दिशाओं में अलग अलग देश दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे ही बयानों के कारण कांग्रेस अपने अस्तित्व से जूझ रही है।

कुछ इसी प्रकार के बयान कांग्रेस के अन्य नेता भी देते रहे हैं। एक बार मैंने अपने एक लेख में लिखा था, जिसका उल्लेख अन्य लेखक भी कर चुके हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अनजाने में देश का विरोध करने लगती है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का आशय देश विरोध का नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते ही क्यों हैं, जिसका एक अर्थ ऐसा भी निकलता है, जिससे देश का विरोध होने का संकेत मिलता है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए कोई छोटा नाम नहीं है। वे कांग्रेस के मुख्य कर्ता धताओं में गिने जाते हैं। हालांकि चुनाव में उनके बयान का विपरीत प्रभाव न हो, इसलिए सैम पित्रोदा का इस्तीफा देना एक राजनीतिक कदम भी हो सकता है। अगर सैम पित्रोदा का इस्तीफा लेना ही था तो उनके पहले दिए बयानों पर भी तो लिया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया।

इससे कांग्रेस की सोच का पता चलता है और बैठे ठाले ही कांग्रेस ने भाजपा को एक और मुद्दा दे दिया। सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की एक बार फिर से फजीहत करा दी। राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजनीति करने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं के पलायन करने के बाद भी अगर शीर्ष नेतृत्व इस बात से अनभिज्ञ है कि कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? तो स्वाभाविक ही है कांग्रेस को अपनी पिछली दो शर्मनाक पराजय का बोध भी नहीं हो सकता। अभी तक के राजनीतिक इतिहास में अपने सबसे बड़े दुर्दिनों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी समूहों में विभाजित होकर अवनति के मार्ग पर बेलगाम बढ़ती जा रही है। यह समस्याएं उसकी खुद की देन हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि आज की कांग्रेस में स्पष्ट दिशा और स्पष्ट नीति का अभाव सा पैदा हो गया है। उसके जिम्मेदार नेताओं को यह भी नहीं पता कि कौन से मुद्दे पर राजनीति की जानी चाहिए और किस पर नहीं।

इसी कारण कांग्रेस का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वह अविश्वसनीयता के घेरे में समाता जा रहा है। यह स्थिति जहां एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति अनास्था की धारणा को जन्म देने वाला कहा जा सकता है, वहीं यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि राहुल गांधी युवाओं को आकर्षित करने में असफल साबित हुए हैं। इसमें उनकी अनियंत्रित बयानबाजी भी कारण है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार झूठे बयान दिए हैं, जिसमें वे माफी भी मांग चुके हैं। यह बात सही है कि झूठ के सहारे आम जनता को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है, तब उसकी कलई खुल जाती है। सबसे बड़ी विसंगति तो तब बनती है, जब अपने नेता के बयान को कांग्रेस के अन्य नेता समर्थन करने वाले अंदाज में निरर्थक रूप से पुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयासों से भले ही यह भ्रम पाल ले कि उसने केन्द्र सरकार को घेर लिया, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसके भंवर में वह स्वयं ही फंसी नजर आती है।

कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए भले ही भाजपा पर आरोप लगाने की राजनीति करे, लेकिन सत्य यह है कि इसके लिए कांग्रेस की कुछ नीतियां और वर्तमान में नेतृत्व की खामियां भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। बयानों की राजनीति के बीच कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर है। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेसी नेता सफाई भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे बयान भारत को शक्तिशाली बनाने से रोकते हैं। इसलिए यह आज की आवश्यकता है कि भारत को शक्ति संपन्न बनाने की राजनीति की जाए।

केजरीवाल को जमानत

चुनाव पर असर

अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है जिससे चुनाव थोड़ा और जटिल हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा करोड़ों रुपयों के 'शराब घोटाले' में संलिप्तता के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 50 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब अंतरिम जमानत मिलने से उनका चुनाव प्रचार में प्रवेश हो गया है। अपनी बड़बोली शैली के लिए जाने जाने वाले आम आदमी पार्टी–आप नेता ने अपने भाषण से 'भाजपा समर्थक' मतदाताओं में यह कह कर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष की आयु पूरे होने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। स्वयं अमित शाह ने इसका खंडन करते हुए कहा कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मोदी न केवल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि वे 2029 में भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

विपक्ष के कुछ नेताओं को केजरीवाल की अंतरिम जमानत से खुशी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को चिन्ता है कि 'आप' उसे नुकसान पहुंचा सकती है। 'आप' पर निकट अतीत में लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण जनता में उसकी छवि को भारी धक्का लगा है। विडंबना है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले 'भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन' से उपजी आम आदमी पार्टी स्वयं भ्रष्टाचार के कीचड़ में गले तक डूब गई है। पार्टी के कई नेता व पूर्व मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। मजेदार बात है कि इन नेताओं को केजरीवाल 'कट्टर ईमानदार' होने का प्रमाणपत्र देते रहते थे। अब स्वयं 'आप' नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की

'शराब घोटाले' में गिरफ्तारी से पार्टी की छवि मिट्टी में मिल गई है। केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है और उनको 2 मई को पुन: पुलिस के समक्ष पेश होना है। ऐसे में केजरीवाल पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के साथ ही संभवत: 'वारिस' की तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पत्नी को विधायकों से स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे। केजरीवाल की रिहाई से पंजाब और दिल्ली में 'आप' की संभावनाओं पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। पंजाब में पहले ही बहुकोणीय मुकाबले हो रहे हैं, जहां भगवंत मान सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहां भाजपा तथा अकाली दल 'आप' सरकार पर लगातार हमलावर हैं। मुख्यमंत्री मान पर आरोप है कि वे पंजाब की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय 'आप' प्रचारक का काम कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी उनको 'लोकतंत्र सेनानी' की तरह पेश कर जनता से भावनात्मक समर्थन मांग रही थी। अब उनकी अंतरिम जमानत पर रिहाई से उसका यह 'कार्ड' बेकार हो गया है। इसके साथ ही खासकर दिल्ली में भाजपा को आम आदमी पार्टी तथा केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ और तीखे हमले करने का बेहतर मौका मिल गया है। अब वह लोकसभा चुनाव में सीधे केजरीवाल से भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांग सकती है। भाजपा ने केजरीवाल की रैली के बाद दिल्ली में अपने सिख समर्थकों की विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाल कर मजबूत जनाधार का परिचय दे दिया है। केजरीवाल भले ही अपने बड़बोले व हास्यास्पद बयानों से मीडिया में सुर्खियां बटोर लें, पर इससे वे 'भाजपा समर्थकों' में भ्रम पैदा करने में सफल नहीं होंगे। वैसे भी अब आम जनता में आम आदमी पार्टी–आप की छवि पहले जैसी नहीं रह गई है।

पाकिस्तानी सेना का कठोर शिकंजा

सैनिक अवस्थापना से टकराव के कारण इमरान खान का पतन हुआ है। इमरान खान अपने इस दृष्टिकोण के कारण और ज्यादा अलग–थलग हुए हैं।

भोपिंदर सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं)

पाकिस्तान में सैनिक अवस्थापना से टकराव के कारण इमरान खान का पतन हुआ है। इमरान खान अपने इस दृष्टिकोण के कारण और ज्यादा अलग–थलग हुए हैं। पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व देश में शुरू से ही बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना का देश के समाज और विचारधारा पर भी व्यापक प्रभाव है। पाकिस्तानी सेना के इसी व्यापक प्रभाव की चर्चा करते हुए अमेरिकन विद्वान स्टीफेन कोहेन ने अपने लेख 'पाकिस्तान: आर्मी, सोसाइटी एंड सिक्यूरिटी' में लिखा है, 'दुनिया में ऐसी सेनायें हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, लेकिन कुछ सेनाओं को समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने की चिन्ता होती है। कुछ सेनायें ऐसी भी होती हैं जो किसी लक्ष्य या विचार की रक्षा करती हैं। पाकिस्तानी सेना ये तीनों काम करती है।' हालांकि, पाकिस्तानी सेना एक ऐसी सेना है जिसने कभी कोई युद्ध नहीं जीता है। इनमें 1947–48, 1965, 1971 या 1999 के युद्ध शमिल हैं। पाकिस्तानी सेना वर्तमान समय में ड्यूरंड रेखा के दोनों ओर 'धार्मिक अतिवादी' तत्वों को सीमित रखने के लिए कठिन संघर्ष कर रही है। यह पाकिस्तानी समाज का अंतिम ऐसा संस्थान है जो शुद्धतावाद के ऐसे रास्ते पर चला है जो पहले से ही जर्जर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यह तर्क दिया जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना ने सत्तारूढ़ त्रयी के अन्य दो हिस्सों–सिविलियन राजनेताओं तथा धर्मगुरुओं के साथ मिल कर संप्रभु के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यह भी कहा जा सकता है कि अपने तमाम हथकंडों और कमियों के बावजूद पाकिस्तानी 'अवस्थापना' या सेना अब भी पाकिस्तानी राज्य का विघटन रोकने और उसे रक्षा देने में सक्षम एकमात्र संस्थान है।

पाकिस्तान में जमीन से कटे राजनेता और धर्मगुरु नस्लवाद, क्षेत्रवाद व अन्य कबीलाई आधारों पर विभाजन के प्रयास करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अनुशासित व 'एकरूपी' पाकिस्तानी सेना ब्रिटिश राज से विरासत में मिली अपनी विविधताओं को बलूच रेजीमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजीमेंट, पंजाब रेजीमेंट, सिंध रेजीमेंट, आदि के माध्यम से एकजुटता सुनिश्चित करती रही है। जनरल जियाउल हक या हमीद गुल जैसी कुछ विकृतियों को छोड़ दें तो यह संस्थान तुलनात्मक रूप से पश्चिमीकृत, मध्यमार्गी तथा समावेशी रहा है। इसने पूरी ताकत से बजट में अपने अधिक आबंटन तथा अपने तरीकों व हितों की रक्षा की है तथा यह सुनिश्चित किया है कि वह हमेशा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अपना वर्चस्व बनाए रखे और अपने अधिकार की रक्षा करे। उसने बिना किसी वैचारिक आधार के अवस्थापनाओं का चयन किया है तथा अपने दृष्टिकोण पर चलने या न चलने वालों को सत्ता में लाने या उससे हटाने का काम किया है। उसे विरोधाभासों और बदलती पसंदों की जरा भी चिन्ता नहीं रही है। उसने भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी–पीपीपी तथा शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़–पीएमएलएन को चुनने में यही दृष्टिकोण अपनाया। 2018 में 'अवस्थापना' ने पीपीपी और पीएमएल–एन, दोनों से मुक्ति पाने के लिए इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इन्साफ–पीटीआई का 'चयन' सरकार चलाने के लिए किया, हालांकि पड़ोसी रावलपिंडी ने जनरलों ने जंजीरों से उसे खींचना जारी रखा।

लेकिन उन्होंने पूरी गंभीरता से इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि मियांवाली का यह पठान अपनी अपरिपक्वता के कारण अपनी शक्ति बढ़ाने का काम करने लगेगा और इस प्रकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। इमरान ने गलती से सोच लिया था कि वे इतने बड़े हो गए हैं कि पाकिस्तानी 'अवस्थापना' की जकड़ से बाहर निकल सकते हैं। यह सोचना उनकी भारी गलती थी। एक जिद्दी, बड़बोले व चीख–पुकार मचाने वाले इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया और अतीत के कुछ अन्य चेहरों की तुलना में उनका भारी अपमान भी किया गया। यह पाकिस्तानी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण सबक था। इससे स्पष्ट हुआ कि हवा उलटने पर जनरलों को अच्छी लगने वाली कोई भी राजनीतिक शक्ति सत्ता में वापस आ सकती है। इनमें शायद जिद्दी इमरान खान जैसे लोग शामिल नहीं हैं जो इतिहास में जीवित हैं तथा इतिहास से कोई सबक लेने को तैयार नहीं हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने '9 मई' को दंगों और लूट की ऐसी योजना बनाई जिससे कोई बचा नहीं। इसमें छावनियों और जनरलों के आवास भी शामिल थे जो एक प्रकार से 'प्रतिबंधित' क्षेत्र थे।

ऐसे में पाकिस्तानी 'अवस्थापना' ने वही काम किया जो वह बहुत अच्छी तरह कर सकती है। उसने इमरान खान की लोकप्रियता की जरा भी चिन्ता किए बिना उनके पार्टी कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। यह तर्क दिया जाता था कि इमरान खान बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जबकि भुट्टो और शरीफ परिवार बहुत बदनाम हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना के आर्शीवाद से आज वही सत्ता में हैं। इस प्रकार जिद्दी इमरान खान ने स्वयं को एक कटघरे में बंद कर लिया है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े होने के कारण उनकी पहचान संकट में है। पाकिस्तानी सेना इमरान खान को वापसी का कोई मौका नहीं देना चाहती है। ऐसे में इमरान खान की सफलता का एकमात्र रास्ता यही है कि वे अपनी वर्तमान रणनीति उलटना है जिससे पाकिस्तानी सेना ज्यादा प्रासांगिक बन जाएगी। लेकिन यह एक काल्पनिक स्थिति है। इसके साथ ही वर्तमान स्थितियों को देखते हुए एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का बने रहना भी संकट में है। इमरान से सुलह–समझौते के मामले में सेना में विभाजक रेखायें गहरी होती जा रही हैं। सेना का 'माउथपीस' कजे जाने वाले इंटर सविर्सेज़ पब्लिक रिलेशन–आईएसपीआर ने जोर दिया है कि पीटीआई के साथ संवाद तभी संभव है जब वह 'सार्वजनिक रूप से पूरे देश के समक्ष ईमानदारी से अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे।' उसने यह भी कहा है कि पीटीआई को 'रचनात्मक राजनीति' करनी चाहिए तथा 'अराजकता की राजनीति' से बचना चाहिए। स्पष्ट रूप से आईएसपीआर या सेना की ऐसी मांगें मानना इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीके इन्साफ–पीटीआई के लिए आत्मघाती होगा। यदि अनेकानेक नाटकीय घटनाओं को अंजाम देने के बाद पीटीआई इतना नीचे गिरती है तो उसकी पूरी भूमिका संदिग्ध हो जाएगी। इस प्रकार उसे इतिहास में 'अराजकतावादी' और 'देशद्रोही' के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा और पाकिस्तानी जनता के दिमाग में पाकिस्तानी सेना देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित हो जाएगी। सेना और पीटीआई के बीच ऐसी स्थिति पीटीआई के 'फाल्स फ्लैग आपरेशन' के आरोपों को भी ध्वस्त कर देगी। स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना पीटीआई और इमरान खान को 'अवस्थापना' को चुनौती देने की पूरी सजा देना चाहती है। इस प्रकार पीटीआई से संबंध सामान्य बनाने की उसकी पूर्वशर्त का अर्थ ऐसी कठोर परिस्थितियां तैयार कर देना है जिसमें पीटीआई व इमरान खान अपने दृष्टिकोण में नरमी न ला सकें।

ऐसा लगता है कि देश की वर्तमान स्थितियों से सबक लेते हुए पाकिस्तानी सेना अपने ऐतिहासिक सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध सामान्य बनाने के सारे प्रयास कर रही है। इसका कारण यह है कि इमरान खान ने खासकर अपनी सरकार गिराने के प्रयासों के लिए अमेरिका पर निशाना लगाया था। पाकिस्तानी सेना चीन से समर्थन के मामले में संतुलन बरतते हुए अरब शेखों के साथ संबंध सुधारना चाहती है। वर्तमान समय में पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में जड़ें जमाए तहरीके तालिबान पाकिस्तान–टीटीपी से भयानक खूनी संघर्ष में उलझी है। उल्लेखनीय है कि इमरान खान या 'तालिबान खान' खासतौर से टीटीपी के प्रति बहुत नरम दृष्टिकोण अपनाते थे। स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी राज्य अब उस विद्रोही या अतिवादी दृष्टिकोण से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है जिसकी पैरवी इमरान खान ने उसकी ओर से की थी। पाकिस्तान में सारी राजनीति सेना को केन्द्र में रख कर घूमती है, ऐसे में ऐसे में सभी नीतियां, पीटीआई ढांचा तथा व्यक्तिगत रूप से इमरान खान पाकिस्तानी सेना के लिए बलि के बकरे से अधिक और कुछ नहीं हैं। इस स्थिति के लिए कोई और नहीं, बल्कि स्वयं इमरान खान ही दोषी हैं।

चुनावी दौर में नैतिकता दरकिनार

"तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की विशेषता वाले गर्म राष्ट्रीय चुनावों के बीच, हम नैतिकता और नैतिकता के चिंताजनक क्षरण को देख रहे हैं।"

विनोद बहल
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राजनेताओं के आध्यात्मिक दावे और धर्मनिरपेक्ष प्रतिज्ञाएँ उनके सच्चे उद्देश्यों को झुठलाती हैं। भयंकर चुनावी घमासान से चिह्नित राष्ट्रीय चुनावों की गर्मी और धूल में, हम नैतिकता के साथ मानवता का बदसूरत चेहरा देख रहे हैं। पहली नज़र में, सभी प्रकार के राजनेता अपनी आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष साख का प्रदर्शन करते हैं, धार्मिक स्थलों के चक्कर लगाते हैं और धर्मनिरपेक्ष संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन चुनावी रैलियों और आचरण में उनके सार्वजनिक प्रवचन इसके विपरीत हैं क्योंकि वे धोखे और झूठी कहानियों को अपनाते हैं जिसमें सच्चाई सबसे बड़ी क्षति होती है। अपने जहरीले विस्फोटों से, वे अपने अपवित्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए चरित्र हनन का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाते। इस डिजिटल युग में, ढ्ढ का बड़े पैमाने पर उपयोग मामलों को और भी बदतर बना देता है।

आज चुनाव क्षेत्र में जहां धन और बाहुबल एक पर्याय बन गए हैं, हम देखते हैं कि गरिमा, ईमानदारी और बड़प्पन का स्थान लालच, बेईमानी, दुष्टता और अनैतिकता ने ले लिया है। राजनीतिक दलों द्वारा दलबदलू और चुनावी इंजीनियरिंग के लगातार बढ़ते चलन को देखकर हम पाते हैं कि समाज को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर बेधड़क बांटा जा रहा है।

सचमुच, हमारे साथ समस्या यह है कि हम मनुष्य सत्ता और भौतिक संपत्ति की अंधी दौड़ में हैं। यह हमें आध्यात्मिकता से दूर करता है। भौतिकवाद का प्रभाव इतना प्रबल है कि हम आध्यात्मिक प्राणी (परमात्मा/दिव्य आत्मा–ईश्वर का एक घटक) के रूप में अपनी वास्तविक पहचान भी भूल जाते हैं। इसके बजाय, हम भौतिक शरीर और उससे जुड़ी सभी भौतिक संपत्तियों को अपनी पहचान मानते हैं।

भौतिकवाद की चकाचौंध से अंधे होकर हमारा वास्तविक स्वरूप– पवित्रता और बड़प्पन पूरी तरह से धूमिल हो जाता है और हम पाप को गले लगा लेते हैं। और फिर हम भौतिक लाभ और गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वार्थ, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिकता में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते हैं। धन और शक्ति का हमारा नशा हमें नैतिक दिवालियेपन की ओर ले जाता है और हमसे सुख और शांति छीन लेता है। हमारे पास धन और उच्च पद हो सकते हैं। लेकिन अगर यह हमारे नैतिक मूल्यों और नैतिकता की कीमत पर आता है तो इसका क्या फायदा? ऐसी भौतिक सफलता आनंद से रहित है। मनुष्य इस पृथ्वी ग्रह पर सभी प्रजातियों में से एक सर्वोच्च रचना है और हमें यह दुर्लभ जन्म ईश्वर को जानने और उसके साथ एक होने के मिशन के साथ दिया गया है। ईश्वर की एकता मानवता की एकता की ओर ले जाती है। एक बार जब हममें आत्म–बोध आ जाता है, तो हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ धीरे–धीरे दैवीय गुणों का स्थान ले लेती हैं। अपनी आत्मा की पवित्रता बनाए रखने से हम सच्चे इंसान बनते हैं, वास्तविक और शाश्वत सुख और शांति हमारे जीवन में आती है जब हम प्रेम, खुशी और शांति के पावरहाउस एक ईश्वर से जुड़े रहते हैं और आध्यात्मिकता और भौतिकवाद के बीच संतुलन बनाए रखना सीखते हैं। .

तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की विशेषता वाले गर्म राष्ट्रीय चुनावों के बीच, हम नैतिकता और नैतिकता के चिंताजनक क्षरण को देख रहे हैं। राजनेताओं के आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बाहरी प्रदर्शन के बावजूद, उनके कार्य एक अलग कहानी बताते हैं क्योंकि वे चुनावी लाभ के लिए धोखे और चरित्र हत्या का सहारा लेते हैं। जैसे–जैसे राजनीतिक परिदृश्य पर पैसा और ताकत हावी होती जा रही है, गरिमा और ईमानदारी जैसे सिद्धांतों पर लालच और अनैतिकता हावी होती जा रही है। जाति, समुदाय और धार्मिक आधार पर विभाजन पर आधारित राजनीतिक रणनीतियाँ समाज को और अधिक खंडित करती हैं। मौलिक रूप से, मानवता की शक्ति और भौतिक संपदा की निरंतर खोज ने हमें हमारे आध्यात्मिक सार से दूर कर दिया है। हम अक्सर आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अपनी वास्तविक पहचान पर भौतिक संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं, जिससे नैतिक पतन होता है और किसी भी कीमत पर स्वार्थी लाभ की प्राप्ति होती है। हालाँकि, सच्ची संतुष्टि हमारी आध्यात्मिक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और परमात्मा से जुड़ने में निहित है, जो एकता और वास्तविक शांति को बढ़ावा देती है।

आप की बात

ऑनलाइन मतदान

इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि आधुनिक तकनीक की बढ़ती व्यवस्थाओं, कम मतदान प्रतिशत तथा लोगों की बढ़ती व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ऑनलाइन मतदान का विकास करना चाहिए। आज लाखों मतदाता या तो सफर में रहते हैं या व्यापार–उद्योग अथवा अन्य जरुरी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मोबाईल करीब–करीब सबके हाथों में रहता है। ऐसे में व्यस्त रहने के बावजूद वे उसका उपयोग करके मतदान में कहीं से भी भाग ले सकते हैं। आधार कार्ड या वोटर कार्ड भी सबके पास होता है। अत: उसी के आधार पर वोट करने की सुविधा से मतदान में बढ़ौतरी संभव भी है। फिलहाल आनलाइन मतदान में मतदाता की गोपनीयता, निजता तथा उसके स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान को लेकर कुछ सवाल जरूर उठते हैं, पर उनके तकनीकी समाधान खोजे जा सकते हैं। आनलाइन मतदान से देश के साथ ही विदेशों में पढ़ाई या नौकरी कर रहे भारतीय युवाओ और युवतियों को मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे भारतीय राजनीति की अनेक विकृतियां दूर होंगी तथा देश की युवा पीढ़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्रनिर्माण व उसके विकास की दिशा तय करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगी। आनलाइन मतदान समय की आवश्यकता है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

ऊर्जा से भरे नरेन्द्र मोदी

केजरीवाल ने पूछा है कि अगले साल मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या उनकी जगह कोई और नेता लेगा? केजरीवाल ने इस संबंध में अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अमित शाह ने फौरन इसका खंडन करते हुए कहा कि मोदी 2029 में भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। मोदी अभी जितने मजबूत, ऊर्जावान और उत्साह से लबरेज है उसे देखते हुए उम्र के लिहाज से उन्हें अपने पद से हटने की कोई जरूरत नहीं है और न बीजेपी ऐसा चाहेगी। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति भी उम्रदराज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर सवाल उठते रहे हैं, फिर भी वे सत्ता का बखूबी संचालन कर रहे हैं। मोदी तो इनके मुकाबले अभी बहुत मजबूत है। यदि विपक्ष यह सवाल उठा रहा है तो क्या वह मान चुका है कि भाजपा फिर से सत्ता में पक्के तौर से आने वाली है? आज न सिर्फ राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी की कार्यक्षमता, बौद्धिकता व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की लोग प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय विपक्षी नेताओं के तमाम हथकंडों के बावजूद देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की जरूरत हो या न हो देश को अभी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी और सिर्फ मोदी की जरूरत है।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

मनोवैज्ञानिक संघर्ष

कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा चुनावी मनोवैज्ञानिक संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। इससे कांग्रेस की मुखरता और भाजपा का रणनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। साफ है कि राजनीतिक दल अपना समर्थन मजबूत करने के लिए जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहते हैं। ऐसे में जनता को सचेत रह कर केवल मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे आर्थिक विकास, रोजगार, और सामाजिक न्याय, आदि पर ध्यान देना चाहिए। हमें राजनीतिक दलों के वादों और रणनीतियों के बजाय, उनके पिछले कार्यों, नीति निर्माण तथा राष्ट्रीय प्रगति में उनके योगदान पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी माहौल में भावनात्मक अपीलों और निजी हमलों की बाढ़ आ जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्तिगत हमलों से जनता के लिए अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने मताधिकार का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। राजनीतिक दलों की रणनीतियों को समझते हुए हमें अपने निर्णयों को सही सूचनाओं व तार्किक विश्लेषणों पर आधारित करना चाहिए। भ्रामक सूचनाओं से बचने व सही तथ्यों के लिए आधिकारिक सूत्रों का उपयोग करना भी बहुत जरूरी हो गया है।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

मजबूत सरकार आवश्यक

देश में चुनावी माहौल है। सारी दुनिया की नजरें भी चुनाव परिणामों तथा नई सरकार के गठन की तरफ लगी हुई हैं। हर देश देखना चाहता है कि भारत में मजबूत सरकार बनती है या मजबूर। वर्तमान वैश्विक स्थितियों में आत्मनिर्भर भारत की छवि उभर रही है। इससे लगता है कि भारत दुनिया में नेतृत्व के लिए तैयार है। भारत ने पिछड़े देशों की सूची से निकलकर ढांचागत निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक के विकास, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा व्यापार व व्यवसाय, आदि क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उसके पीछे मजबूत सरकार के संकल्प ही हैं। आज अनेक महाशक्तियां भारत को अपना मित्र मानती हैं तो इसकी एक वजह भारत का व्यवहार और उसकी सबके साथ समान व्यवहार वाली नीति भी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र में अपने पैरों पर खड़ी मजबूत व प्रचंड बहुमत वाली सरकार का गठन होना जरूरी है जो जरूरत के समय तुरंत फैसले ले सके, गठबंधन सहयोगियों के दबाव में न आए तथा पूरे देश के भविष्य में साहसी व लीक से हट कर फैसले ले सके। लोकसभा चुनाव से ऐसे जनादेश की आशा है।

– **अमृतलाल मारू,** इन्दौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई–मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 75

वृद्धि के लिए बैंकिंग

पिछला वित्त वर्ष (2023-24) निजी बैंकों के लिए बेहतर और सरकारी क्षेत्रों के लिए शानदार रहा। सभी बैंकों की समेकित शुद्ध आय में विस्तार हुआ और ज्यादातर समय शुद्ध ब्याज मार्जिन भी बरकरार रहा। बैंकों की गैर ब्याज आय भी बढ़ी क्योंकि बैंकों ने पूरक उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था बढ़ाई और उनकी शुल्क आय भी बढ़ी है। समस्त फंसे हुए कर्ज (जीएनपीए) में तेजी से कमी आई। शुद्ध एनपीए में भी कमी आई है। कई मामलों में प्रोविजन में कमी आई है या उनकी स्थिति उलट गई है क्योंकि मुश्किल कर्ज की वसूली हुई है। इससे मुनाफा बढ़ा है और ऋण की लागत कम हुई है। वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में ब्याज आय की बात करें तो निजी बैंकों के लिए यह सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़ी जबकि सरकारी बैंकों के मामले में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

एनपीए की बात करें तो नॉमिनल और ऋण के प्रतिशत दोनों ही रूपों में इसमें कमी आई है। सरकारी बैंकों का समेकित जीएनपीए मार्च 24 में 3.4 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि मार्च 22 में यह 5.4 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 24 में शुद्ध एनपीए 72,544 करोड़ रुपये रहा जबकि मार्च 22 में यह 1.54 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 24 में निजी बैंकों का जीएनपीए 1.24 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि दो वर्ष पहले यह 1.74 लाख करोड़ रुपये था। निजी बैंकों का शुद्ध एनपीए मार्च 24 में 29,000 करोड़ रुपये रहा जबकि दो वर्ष पहले यह 40,500 करोड़ रुपये था। अधिकांश बैंक प्रोविजन को कम करते हुए भी अपने एनपीए को एक फीसदी से कम रखने में कामयाब रहे। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश बैंकों की बैलेंस शीट अब बेहतर है। इस संदर्भ में शेयर बाजार की प्रतिक्रिया विश्लेषण करने लायक है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के निजी बैंक सूचकांक ने गत वर्ष 6 फीसदी प्रतिफल दिया। यह मानक निफ्टी 50 की तुलना में कमजोर रहा। बैंक निफ्टी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी बैंक दोनों (निजी बैंकों का भार अधिक) शामिल हैं ने 8.3 फीसदी प्रतिफल दिया। सरकारी बैंक सूचकांक ने 7.8 फीसदी प्रतिफल दिया।

सरकारी बैंकों का मूल्यांकन कम रहा और फंसे हुए कर्ज का स्तर अधिक था। हालांकि निजी बैंकों को अभी भी मूल्यांकन पर अधिक रियायत मिल रही है और उनकी बैलेंस शीट बेहतर है। सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट में उल्लेखनीय सुधार का अर्थ यह है कि उनमें से कई की रेटिंग में सकारात्मक सुधार होगा। तीन अंकों के प्रतिफल के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नैशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक शामिल हैं। ये सबसे अधिक जीएनपीए वाले बैंक थे। इसके विपरीत भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो दो सबसे मजबूत और बेहतर पूंजीकरण वाले बैंक हैं उनके शेयरों को भी अपेक्षाकृत कम मान्यता मिली, हालांकि उन्होंने भी 40 फीसदी से अधिक प्रतिफल दिया जो अपेक्षाकृत बेहतर है।

बड़े निजी बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक को पिछले वर्ष ऋणात्मक प्रतिफल हासिल हुआ। एचडीएफसी के साथ उसके एकीकरण के असर को लेकर बाजार अभी भी अनिश्चित है। कई तरह से देखें तो बैंक सकारात्मक भविष्य की ओर देख रहे हैं। वे मजबूत कारोबारी ऋण और वृद्धि में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें यह उम्मीद भी है कि मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य तक पहुंचने के बाद मौद्रिक नीति सहज होगी और दरों में कटौती की जाएगी। बहरहाल केंद्रीय बैंक ने असुरक्षित ऋण की कई श्रेणियों में जोखिम का आकलन बढ़ा दिया है और अधोसंरचना संबंधी ऋण की प्रोविजनिंग बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऋण-जमा अनुपात भी सख्त है और ऐसे में बैंकों पर जमा पर ब्याज बढ़ाने का दबाव है। इसका असर ब्याज मार्जिन पर भी पड़ेगा। यह क्षेत्र अच्छी स्थिति में है और रिजर्व बैंक का सख्त नियंत्रण निकट भविष्य में मुनाफे पर असर डालेगा। वृहद आर्थिक नजरिये से बैंकिंग क्षेत्र अभी इस स्थिति में है कि निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में सुधार का समर्थन कर सके।

अजय मोहंती

भारत की वृद्धि प्राथमिकताओं को सही करने की जरूरत

आकार ही नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी अपने समकक्षों की बराबरी करने के लिए भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बता रहे हैं जनक राज

ऐतिहासिक रूप से देखें तो अकेले आर्थिक वृद्धि या आय को ही मानव विकास का प्राथमिक मानक माना जाता था। समय बीतने के साथ-साथ आय के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा धीरे-धीरे मानव विकास के अहम तत्त्व बनकर उभरे। मानव विकास की व्यापक अवधारणा को सन 1990 में उस समय गति मिली जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक के देशव्यापी आंकड़े जारी करने शुरू किए। ये आंकड़े आय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानव विकास के तीन पहलुओं के आधार पर देश की औसत उपलब्धियों को पेश करते हैं। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक संदर्भ में शोध यह स्थापित करता है कि मानव विकास के आय और गैर आय घटक यानी शिक्षा और स्वास्थ्य आदि आपस में संबद्ध हैं और एक दूसरे को बल देते हैं। कोई भी देश लंबी अवधि में तब तक आर्थिक वृद्धि नहीं जारी रख सकता है जब तक कि उसे मानव विकास का समर्थन नहीं हासिल हो।

'इंटर-लिंकेज बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ ऐंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया- अ स्टेट लेवल एनालिसिस' नामक एक हालिया अध्ययन जिसे मैंने वृंदा गुप्ता और आकांक्षा श्रवण ने मिलकर लिखा है, में पाया गया है कि देश में आर्थिक वृद्धि और मानव विकास में दोतरफा संबंध है। इससे यह भी स्थापित हुआ कि मानव विकास से आर्थिक वृद्धि होती है और इसका उलटा भी उतना ही सही है।

हमने ऊपर जिस अध्ययन का जिक्र किया है उसमें यह भी पाया गया कि द्वितीयक स्तर की शिक्षा का स्तर कृषि और विनिर्माण में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला है जबकि उच्च शिक्षा सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। उच्च शिक्षा में नामांकन का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव द्वितीयक शिक्षा के कृषि और विनिर्माण पर प्रभाव का चार गुना है। प्राथमिक शिक्षा का आर्थिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं दिखा। इससे संकेत मिलता है कि कम से कम द्वितीयक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है ताकि संज्ञानात्मक कौशल विकसित किए जा सकें। ऐसे कौशल आर्थिक वृद्धि से सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है।

हाल ही में हुए देशव्यापी अध्ययन बताते हैं कि द्वितीयक शिक्षा में निवेश से अहम आर्थिक वृद्धि हासिल होती है जो प्राथमिक शिक्षा से हासिल होने वाले प्रभाव से बहुत अधिक है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक शिक्षा को आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है तो यह अहम है कि द्वितीयक शिक्षा के व्यापक प्रावधान किए जाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में अब प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा के चुनिंदा लक्ष्य भी शामिल हैं। यह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के उलट है जो केवल सबके लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है।

इन्हीं लेखकों के 'इकनॉमिक ग्रोथ ऐंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया- आर स्टेट्स कन्वर्जिंग?' नामक एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर और कम मानव विकास वाले राज्य आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों के करीब नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि जब विभिन्न राज्यों को आर्थिक विकास और मानव विकास के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर प्रांत समान मानव विकास वाले आर्थिक रूप से बेहतर राज्यों की ओर बढ़ते नजर आते हैं।

दोनों अध्ययनों से एक संदेश साफ निकलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को अगर अधिक समृद्ध राज्यों की बराबरी करनी है और भारत को प्रति व्यक्ति आय तथा आकार के मामले में विकसित देशों की बराबरी करनी है तो मानव विकास को आर्थिक नीति निर्माण के केंद्र में रखना होगा।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो देश में नीति निर्माताओं ने आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा की अनदेखी सी कर दी है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद के एक फीसदी से भी कम है। यह स्थिति पिछले तीन दशकों से बनी हुई है। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इसके लिए 2.5 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन हम उसके आसपास भी नहीं हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हमारा व्यय रूस के 5.3 फीसदी, ब्राजील के 4.5 फीसदी, थाईलैंड के 3.6 फीसदी और चीन के 2.9 फीसदी से काफी कम है। इसी तरह शिक्षा पर भारत का सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 फीसदी के बराबर है जो 6 फीसदी के वांछित स्तर से काफी कम है। इसे 6 फीसदी करने का लक्ष्य सबसे पहले 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रकट किया गया था और 2020 समेत बाद की सभी शिक्षा नीतियों में दोहराया गया। यह भी ध्यान रहे कि 6 फीसदी का यह लक्ष्य तीन दशक पहले यानी 1986 में हासिल होना था।

जन स्वास्थ्य के लिए कम आवंटन के चलते आम परिवारों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। एक अध्ययन बताता है कि स्वास्थ्य पर खर्च के चलते 2011-12 में 5.5 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में 50 फीसदी से अधिक इसी प्रकृति का होता है जो दुनिया में सर्वाधिक स्तरों में शामिल है। इसके चलते लोगों को कर्ज लेना पड़ता है और कई बार संपत्ति बेचनी पड़ती है।

शिक्षा पर कम सरकारी व्यय के कारण बड़ी तादाद में बच्चे आज भी बुनियादी स्तर से आगे की स्कूली शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं। भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी व्यय बढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को अनावश्यक व्यय न करना पड़े।

इसमें दो राय नहीं कि आर्थिक वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से मानव विकास में योगदान के रूप में सरकार और व्यक्तियों को अधिक संसाधन मुहैया कराती है ताकि वे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कर सकें। बहरहाल ऐसे योगदान की गति बहुत धीमी है। बीते तीन दशक में हमारे मानव विकास सूचकांक में केवल 0.20 का सुधार हुआ है। सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत अहम स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानकों पर समकक्ष देशों से पीछे है। मानव विकास के मामले में हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि ऊपर से आने वाली बेहतरी नीचे हालात को ठीक करेगी। हमें मानव विकास को प्राथमिकता देनी होगी और इसके लिए विशिष्ट कदम उठाने होंगे। ऐसा करके ही हम पूर्ण आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकेंगे।

(लेखक सीएसईपी में फेलो और आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। लेख में व्यक्तिगत विचार हैं)

अर्थव्यवस्था भले हो नई, आदतें वही पुरानी

दुनिया तेजी से हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब यह सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, ताकि ऊर्जा प्रणाली से कोयला और गैस को हटाया जा सके; इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है ताकि परिवहन से तेल की जरूरत को खत्म किया जाए; हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रही है ताकि उद्योगों और ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की जरूरत को खत्म किया जाए। ये ऐसे तीन बड़े बदलाव हैं जो कि एक ऐसी दुनिया में उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं जो तेजी से गर्म हो रही है और जिसमें बड़े नतीजे वाली मौसम संबंधी आपदाएं देखी जा रही हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया को काफी गति और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन वह कारोबारी मॉडल क्या होगा, जिसे हम नई हरित दुनिया में ले जाएंगे? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि संसाधनों के उपयोग के पुराने मॉडल के साथ अंतर्निहित समस्याएं हैं और इससे सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम भी जुड़े हैं।

अब खनिज दोहन का ही मामला देख लें- चाहे कोयला हो, लौह अयस्क या एल्युमीनियम। ऊर्जा और उद्योग की जरूरतों के लिए इन कच्चे माल के खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। भारत में, जैसा कि हमने दर्दनाक रूप से पाया है, इस तरह की खनिज संपदाएं अक्सर वनों, वन्यजीव पर्यावास और जनजातियों की बस्तियों के पास पाई जाती हैं। इसी वजह से हमारा कहना है कि संसाधन का यह अभिशाप समृद्ध भूमि और गरीब लोगों के बारे में है। तथ्य यह भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक खनिजों को प्राप्त करने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ा और स्थानीय समुदायों को विस्थापित करना पड़ा, जो इस पर्यावास में रहते थे। इस निष्कर्षण और राजस्व पैदा करने वाले आर्थिक मॉडल की त्रासदी यह रही है कि इन जमीनों पर रहने वाले लोगों को संसाधनों से शायद ही कोई लाभ हुआ हो। यही वह मूल बात है जो हमारी दुनिया में गलत हो रहा है, न कि केवल उद्योगों से उत्सर्जन जो हमें विनाशकारी जलवायु परिवर्तन की ओर ले गया।

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

मै यह सवाल इसलिए उठाती हूं कि नई हरित अर्थव्यवस्था में भी दुनिया को खनिजों की जरूरत होगी, भले ही कुछ अलग तरह के- जैसे लीथियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट- और वे भी जंगलों में ही पाए जाते हैं, हमेशा सबसे हाशिये के लोगों की भूमि पर। यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए सच है। न्यूयॉर्क मुख्यालय वाले बाजार सलाहकार एमएससीआई की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में निकल का 97 फीसदी, तांबे का 89 फीसदी, लीथियम का 79 फीसदी और कोबाल्ट का 68 फीसदी भंडार उस महज 55 किलोमीटर के दायरे में सीमित है जो मूल अमेरिकी लोगों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। मध्य अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया तक, दूसरे क्षेत्रों का भी यही हाल है।

हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का मतलब यह है कि इन खनिज संसाधनों की जरूरत में कई गुना बढ़त होगी। तो क्या हमारी धरती और उसके लोगों के साथ आचरण करने के तरीके में कोई अंतर होगा? लड़ाई तो पहले से ही लड़ी जा रही है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के एरिजोना में खनन की दिग्गज कंपनियों रियो टिंटो और बीएचपी बिलिटन की रिजोल्यूशन तांबा खदान मूल निवासी समुदायों के गुस्से की चपेट में हैं क्योंकि खुदाई उनकी पवित्र भूमि पर होनी है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी नए सोने की होड़ है वहां की यही कहानी है, इस धंधे के कोई नए नियम-कायदे नहीं हैं।

भारत में हमने खनिज दोहन को पर्यावरण और सामाजिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए लंबा प्रयास किया है- लेकिन दुर्भाग्य से कोई कारगर समाधान नहीं निकल पाया है। वर्षों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने समता फैसले के तहत यह आदेश दिया था कि जनजातीय समुदाय की भागीदारी के बिना आदिवासी भूमि पर कोई खनन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जनजातीय लोगों को कम से कम किसी कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बनाना होगा। लेकिन इसे नकार दिया गया। इसके बाद यह प्रयास किया गया कि खनन से होने वाले राजस्व का हिस्सा स्थानीय समुदायों को दिलाया जाए।

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) बनने का पहला मसौदा स्थानीय समुदायों को कारोबारों में भागीदार बनाने के लिए ही था, लेकिन इसे भी हल्का कर दिया गया। मुनाफे का हिस्सा देने या खनिज विकास में लोगों को साझेदार बनाने के महान विचार को महज खनिजों पर अतिरिक्त उपकर लगाने तक सीमित कर दिया गया। इस उपकर को डीएमएफ के पास जमा किया जाता है और सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल खनिज संसाधनों वाली भूमि पर रहने वाले लोगों की अधिक भागीदारी के बिना ऐसे कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, जिसे वह विकास मानती है। पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियों के मामले में भी कुछ ऐसे ही स्थिति है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन समुदायों के पास परियोजनाओं के लिए सहमति देने का अधिकार हो; नए वन भूमि पर किसी परियोजना के मामले में उनकी आपत्तियों को पूरा वजन दिया जाए। लेकिन विकास के नाम पर इस संरक्षण को भी छीना जा रहा है, जबकि इससे सामाजिक रूप से समावेशी और पूर्ण हरित भविष्य के निर्माण में मदद मिलती।

पुरानी अर्थव्यवस्था में हमेशा विवाद का विषय बनने वाला एक और मसला होता था परियोजनाओं का स्थान- तापीय बिजली संयंत्रों से लेकर लौह भट्टियों तक- क्योंकि स्थानीय समुदायों को इस बात की आशंका रहती थी कि प्रदूषण उनके जीवन और आजीविका को खतरे में डाल देगा। अब पवन चक्कियों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में भी ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं- कि वे ऐसे इलाकों में लगाए जा रहे हैं जहां लोगों या वन्यजीवों की बसावट है। अब इसमें फिर से वही सवाल उठता है: सपने दिखाने वाली हमारी हरित अर्थव्यवस्था में क्या सरकारें ऐसे नियम-कायदे बनाएंगी जिनसे टकरावों का समाधान इस तरीके से निकलेगा कि स्थानीय समुदायों और उनके पर्यावरण का भला हो, या इस बदलाव की ओर दौड़ का मतलब वही पुराने या उससे भी बदतर तरीके होंगे?

तथ्य यह है कि पुरानी अर्थव्यवस्था में संपदा सृजन का वास्तव में गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ। जिन जगहों पर कोयला खनन होता है और ऊर्जा उत्पादन होता है, वे अब भी अंधेरे में हैं। क्या नई अर्थव्यवस्था में यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वह समावेशी हो? अगर ऐसा हुआ तो ही वह टिकाऊ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो नई अर्थव्यवस्था को न तो नई कहना सही होगा और न ही हरित।

आपका पक्ष

फेक न्यूज पर लगाम के लिए उठे कदम

फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्त्वपूर्ण साधन हैं। लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि स्रोतों को कैसे सत्यापित किया जाए, दावों का या तथ्यों का परीक्षण कैसे किया जाए। फेक न्यूज के लिए देश में कुछ कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें और तत्परता से लागू करने की जरूरत है। तेजी से विकसित होते ऑनलाइन मीडिया परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कानूनों को अद्यतन करते रहने की भी जरूरत है। फेक न्यूज की पहचान करने तथा उन्हें हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों को और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। वे फेक न्यूज की पहचान करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट-चेकिंग संगठन समाचारों की पुष्टि करने और लोगों को फेक न्यूज के बारे में शिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य परीक्षण इकाई ने अब तक गलत सूचना के हजारों मामलों का खुलासा किया है। लोगों को भी अपने सोशल मीडिया उपयोग के लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

फेक न्यूज के लिए देश में कुछ कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्हें और तत्परता से लागू करने की जरूरत है

मसालों में मिलावट का हो सही परीक्षण

देश की दो प्रतिष्ठित मसाला निर्माता कंपनियों के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड जैसे कीटनाशक का निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में पाया जाना चिंताजनक है। सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग के इस प्रतिबंध से भारतीय मसालों की गुणवत्ता के साथ ही देश की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है। उच्च स्तरीय सूक्ष्म परीक्षण द्वारा मसालों के मिश्रण की वास्तविकता उजागर होना इसलिए भी आवश्यक है कि करोड़ों भारतीय भी इनका उपयोग कर ही रहे हैं।

रमेश चंद्र कर्नावट, उज्जैन

मसालों की जांच के प्रति गंभीर हो सरकार

विदेशों में भारतीय मसालों में हानिकारक कीटनाशक मिलने की रिपोर्ट के बाद सरकार ने खाद्य नियामक एफएसएसएआई से इनकी जांच करने को कहा है। भारत को मसालों का देश भी कहा जाता है और यहां मसालों की गुणवत्ता दुनिया भर में सबसे अच्छी है। ग्राहकों को भी मानकों का ज्ञान होना आवश्यक है। मसालों की जांच के लिए खाद्य नियामक को गंभीर होना चाहिए।

शुभम सोनी, मनावर

स्थानीय स्तर पर भी मसालों की जांच जरूरी

भारतीय मसालों पर एथिलीन ऑक्साइड के अधिक प्रयोग के कारण विदेशों में लगे प्रतिबंध की स्थानीय स्तर पर भी जांच जरूरी है। प्रतिबंधित करने वाले देशों का गठजोड़ चीन से गहरा है। इससे भारतीय मसाला ब्रांड को बदनाम करने की साजिश भी दिख रही है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मसाला उद्योग पर लगभग पूरा नियंत्रण भारत का ही है। अमेरिका, कनाडा जैसे उच्च तकनीक वाले देशों में भारतीय मसाले पूरी तरह से फिट हैं। बहरहाल वास्तविक स्थिति तो जांच से आएगी लेकिन भारत को सचेत रहने की जरूरत है।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, रीवा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास 'शक्ति' का सातवां संस्करण सोमवार को मेघालय में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य विविध क्षेत्रों में अभियान के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 14 मई 2024

वोट की कीमत

चौथे चरण के मतदान के दौरान जहां 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नजरें मतदान प्रतिशत के आंकड़े पर थी, वहीं आंध्र प्रदेश में चुनाव की पूर्वसंध्या पर हुए एक खास घटनाक्रम पर ही सबका ध्यान अटका था। मामला कई क्षेत्रों में वोटरों के बीच धन वितरित किए जाने के आरोपों से जुड़ा था और वोटिंग के बीच भी यह सवाल बना हुआ था कि चुनाव आयोग इन खबरों पर किस तरह से रिएक्ट करता है।

आंध्र में नकदी बांटने के आरोप

मतदाताओं का प्रदर्शन | हालांकि इस तरह के आरोप प्रायः हर चुनाव में देश के अलग-अलग हिस्सों से सुनने को मिलते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश का मामला इस रूप में खास है कि इसमें मतदाताओं की अति सक्रियता ने पोल खोल दी। कई इलाकों में लोगों ने पैसों की मांग करते हुए या पैसा बांटने में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

वादाखिलाफी का आरोप | यह मामले में वोट के बदले कैश को अधिकार समझकर वोटरों ने इस मामले में हुई कथित वादाखिलाफी के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों की शिकायत थी कि कैश बांटते समय उन्हें छोड़ दिया गया तो कुछ अन्य मामलों में कैश का वादा नहीं निभाने का आरोप था।

भ्रष्ट चलन की निरंतरता | साफ है कि इसके पीछे राजनीतिक दलों की ओर से गरीब मतदाताओं को कैश देकर उनके वोट खरीदने का बरसों पुराना चलन है। एक भ्रष्ट चलन का चुनाव-दर-चुनाव बने रहना कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और चुनाव आयोग की नाकामी तो है ही, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में मतदाताओं को जागरूक बनाने का काम कितने आधे-अधूरे ढंग से आगे बढ़ा है।

नहीं बदले हालात | एक बड़ा सवाल मतदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी है। जो मतदाता अपने वोट से पांच साल के लिए देश और राज्य के शासक चुनता है, वह इस अधिकार के इस्तेमाल की एवज में चाहता क्या है तो महज एक से छह हजार रुपये के बीच की कोई रकम। इससे अगर वोट देने के अपने अधिकार को लेकर उसकी कमजोर समझ उजागर होती है तो यह भी स्पष्ट होता है कि उसकी अपनी जिंदगी के हालात कितने बुरे हैं।

बीमारी व्यापक है | कैश वितरण की ये घटनाएं भले ही समाज के कमजोर माने जाने वाले हिस्सों की कहानी कहते हों, यह बीमारी अन्य हिस्सों में भी है। इसका उदाहरण भी आंध्र प्रदेश में ही मिल गया जब ये खबरें आईं कि कई पॉश माने जाने वाले अपार्टमेंट और गेटेड सोसायटी में RWA की तरफ से कई प्रत्याशियों के पास वोट की एवज में जेनरेटर और सोलर पावर की फरमाइशें भिजवाई गईं।

धूप-छांव

कसम की कसक

प्रणव प्रियदर्शी

कसम खाने या खिलाने में कोई ऐसी बात भी है जो हमारे व्यवहार को किसी न किसी रूप में निश्चितता प्रदान करती है, यह समझने में वक्त लगा। हालांकि कितने मामलों में करती है और किस हद तक करती है, यह अलग सवाल है। बचपन में तो 'मां कसम' के बगैर जैसे कोई वाक्य ही न पूरा होता था। प्राइमरी और मिडल स्कूल के दौरान सहपाठियों के व्यवहार से पता चला कि कुछ खास कसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मसलन, मां कसम की निरर्थकता से वाकिफ कुछ लड़कियों ने सोच-विचार के बाद 'विद्या कसम' की परिपाटी शुरू कराई थी। हालांकि खाने वाले वह भी उसी निर्द्वंद्व भाव से खाते थे।

'तुम्हें मेरी कसम है', या 'तुम्हारी कसम कहता हूं' जैसे वाक्य शिद्दत से कहे जाएं, वह स्थिति तो बिल्कुल अलग होती है। मगर उन रोमांटिक हालात को छोड़ दिया जाए तो कॉलेज में एक बंदा ऐसा था जिसकी कसम खाने की आदत से सब वाकिफ थे। वह हमेशा सामने वाले की कसम खाता था। जैसे ही कसम खाता, सामने वाला भड़क उठता कि 'अबे मेरी कसम क्यों खा रहा है? खाना ही है तो अपनी कसम खा।'

हंसी-मजाक के इन उदाहरणों के बीच अधूरी कसम का एक मामला भी है, जो दिल में ऐसा फंसा है कि निकलना मुश्किल है। एक नवविवाहिता कपल में भावनात्मक करीबी बढ़नी शुरू ही हुई थी कि एक बार लड़की ने किसी बात पर अपनी कसम दे दी। लड़का इस कदर गंभीर हो गया कि मेरे लिए सोचना भी मुश्किल था, कोई मामूली सी कसम जैसी बात पर भी इस तरह रिएक्ट कर सकता है। उसने कहा, 'देखो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो और मन में बैठा लो कि मेरे लिए दुनिया में कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसकी तुलना तुमसे करूं। इसलिए इस बार दे दी, ठीक है। लेकिन आगे से कभी, किसी भी स्थिति में तुम अपनी कसम मत देना।'

मैं तो समझता था कसमें कुछ घंटों का ही मामला हुआ करती हैं। मगर इस मामले में कई साल बाद ऐसा मौका आया, जब लड़की ने फिर अपनी कसम दी। वह मामला था भी ऐसा कि लड़की को लगा ब्रह्मास्त्र ही छोड़ना पड़ेगा। मगर इस बार, लड़के की सूरत पर गहन निराशा के भाव थे। बस तीन ही शब्द आए जबान पर, 'ऐसा क्यों किया।' ब्रह्मास्त्र लड़की का बेकार गया, पीड़ा ज्यादा लड़के के चेहरे पर थी, लेकिन कुल नतीजा तो यही था कि कसम बेमानी साबित हो चुकी थी। पर उसका असर! ऐसे समझें कि लड़के को दुनिया से विदा हुए युग बीत चुके हैं। लड़की भी अब अपनी उम्र पूरी हुई मान चुकी है, पर उस कसम की कसक दिल से नहीं जा रही।

बोल वचन

भैया राम सनेही!

राहुल पाण्डेय

एक जमाना था, जब अवध के ग्रामीण इलाकों में होने वाले समारोहों में इनमें से दो नाम अक्सर मिल जाते थे- राम सनेही, या फिर राम पदारथ। राम पदारथ का मतलब ऐसा इंसान, जिसमें राम का पदार्थ है, उनका अंश है। और राम सनेही, यानी जो राम का स्नेही है। एक राम सनेही संप्रदाय भी है, जिसकी स्थापना 17वीं सदी में महात्मा रामचरण ने की थी। अवध के राम रंग में रंगा सनेही शब्द अवधी में संस्कृत के स्नेहः से आया है। बालक की तरह स्नेह के भी आठ रूप होते हैं, जिनमें अगर द्विवचन और बहुवचन मिला दिए जाएं तो स्नेह के कुल मिलाकर 24 रूप बन जाते हैं। लेकिन सनेही, स्नेह के इन रूपों से भी कहीं आगे की चीज है। सनेही सिर्फ दुलार ही नहीं करता, या सिर्फ प्रेम ही नहीं करता। हिंदी का एक शब्दकोश बताता है कि सनेही का एक अर्थ चितेरा भी होता है, तो एक अर्थ तेल-मालिश करने वाला भी होता है। सनेही वह डॉक्टर या फिर वो वैद्य भी होता है, जो हमारे घाव पर मलहम लगाता है। राम सनेही अवधी से जब मैथिली या मगही में जाते हैं तो कहीं-कहीं राम अनुरागी भी बन जाते हैं। मैथिली और मगही में सनेही अनुरागी भी होता है। सनेही के लिए इंग्लिश में affectionate, tender, fatherly जैसे शब्द हैं, लेकिन यह सनेही के लिए नहीं बल्कि स्नेह के लिए हैं। समय के साथ चलते-चलते सनेही ने जितने अर्थ हासिल किए हैं, उतने स्नेह के दो दर्जन रूप मिलकर भी अर्जित नहीं कर पाए हैं। यह बताता है कि शब्द जब लोक में आते हैं, तभी अपने अर्थ का असली विस्तार पाते हैं।

Subrata Dhar

पीएम मोदी ने सकारात्मक मुद्दों से चुनाव अभियान शुरू किया, मगर बाद में नकारात्मकता बढ़ गई

क्या कहते हैं चार चरणों के चुनावी ट्रेंड

Trend

अवधेश कुमार

लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे होने के बाद कुल 543 में से 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं, 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो चुका है। हालांकि अभी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में मतदान बाकी है। फिर भी अभी तक के मतदान के आधार पर कुछ संकेतों और संदेशों को समझने की कोशिश की जा सकती है।

कम मतदान | इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मतदान प्रतिशत गिरने के ट्रेंड की हो रही है। चौथे चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत आने में समय लगेगा, जबकि तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ। 2019 में इस चरण में 68.4% मतदान हुआ था। पहले चरण में 66.14% और दूसरे में 66.71% मतदान हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 69.43% और दूसरे में 69.64% मतदान हुआ था। इस तरह देखें तो पहले चरण में 3.3%, दूसरे में करीब 2.9% और तीसरे चरण में 2.72% की कमी आई है। कुल मिलाकर, 2019 की तुलना में करीब 3% मतदान राष्ट्रीय स्तर पर कम हुआ है।

राज्यों में उतार-चढ़ाव | सामान्यतया राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रतिशत मतदान कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन राज्यों के अनुसार देखें तो इनमें काफी उतार-चढ़ाव है। मसलन- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल में मतदान का प्रतिशत कम रहा। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर के लोगों ने भारी मतदान किया। पश्चिम बंगाल का 73-74% मतदान भी पिछले चुनाव से काफी कम है। ऐसे में सबके दिमाग में यह सवाल है कि किसके मतदाता कम संख्या में निकले?

वोटिंग पैटर्न के संकेत
- वोटरों में उदासीनता है, गुस्सा नहीं
- मंदिर का माहौल कमजोर पड़ा है
- विपक्ष के दुष्प्रचार का असर नहीं

महिला मतदाताओं का रुझान | पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में माना जा रहा था कि जहां भी BJP है वहां महिला वोटरों के ज्यादातर मत उसे ही मिलते हैं। इन चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या असम और पश्चिम बंगाल में 83% से अधिक रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। बाकी जगहों पर महिलाओं का मतदान सामान्य रहा और पुरुषों की तुलना में ज्यादातर जगह कम।

मंदिर का उत्साह कम हुआ | विपक्ष के दावों के बावजूद कहीं भी व्यापक स्तर पर जनता के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हर हाल में उखाड़ फेंकने का माहौल नहीं है। इसी तरह विपक्ष को केंद्र की सत्ता में स्थापित करना है, ऐसा सामूहिक भाव भी नहीं देखा गया। स्थानीय स्तर पर BJP के नेताओं-कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक समूह में कई कारणों से उदासीनता जरूर दिखी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बना हुआ स्वाभाविक अभूतपूर्व वातावरण भी कमजोर पड़ा है।

uday deb

समर्थकों में विचलन नहीं | बावजूद इसके, BJP के प्रतिबद्ध समर्थक एकमुश्त उसके विरुद्ध मतदान करेंगे, ऐसा मानने का ठोस आधार नहीं दिखता। BJP विरोधी जितना प्रचार करें, चार चरणों के चुनाव में इस तरह की व्यापक प्रवृत्तियों की रिपोर्ट नहीं है। हां, अप्रतिबद्ध मतदाता इधर से उधर जाते हैं और इस चुनाव में गए हैं। हालांकि अभी तक की प्रवृत्तियों में ऐसा नहीं दिखा है कि दो लोकसभा चुनावों से BJP के साथ खड़े मतदाताओं का बहुत बड़ा समूह उसे हराने की मानसिकता में चला गया।

विपक्ष की कमजोरी | मगर अभी तक के चुनाव में विपक्ष ने उन मुद्दों को सबसे ऊपर लाने की कोशिश की है, जिनमें ज्यादातर सच नहीं है। उदाहरण के लिए, BJP ने 400 सीटों का नारा इसलिए दिया कि वह संविधान और आरक्षण को खत्म कर सके। या फिर यह कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो आगे चुनाव नहीं होगा। ये सब वही आरोप हैं जो संघ परिवार और BJP पर वर्षों से लगाए जाते रहे और गलत साबित हुए। इन 10 वर्षों के शासनकाल में भी ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है, इस पर मतदाताओं का व्यापक समूह विश्वास नहीं कर सकता।

अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे | गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले चरण के साथ विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमान से जुड़े उन मुद्दों को उभारा, जिनके विरुद्ध प्रतिक्रिया में BJP की ताकत बढ़ती रही है। खुद प्रधानमंत्री और BJP की इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाओं ने निश्चय ही मतदान को प्रभावित किया होगा।

दक्षिण के राज्य | तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में साफ दिख रहा है कि सनातन, हिंदुत्व, राम मंदिर मतदाताओं को प्रभावित करने वाला बड़ा कारक है। वहां सत्तारूढ़ दलों के विरुद्ध प्रतिक्रिया में BJP को वोट मिला है। संदेशखाली बंगाल चुनाव को प्रभावित कर रहा है। बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में BJP शानदार प्रदर्शन करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह केरल और तमिलनाडु में भी उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो सकता है।

पॉजिटिव मुद्दों से शुरुआत | दरअसल, सभी पार्टियों को चुनाव में परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवहार का परिचय देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने चुनाव अभियान की शुरुआत 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने जैसे मुद्दों से की। लेकिन संविधान और आरक्षण खत्म करने, लोकतंत्र का अंत करने जैसे आरोप इतने हावी हो गए कि अंततः ये चुनाव का मुख्य मुद्दा हो गए। अब जो स्थिति है, उसमें यह मानने का कोई कारण नहीं कि शेष तीन चरणों में ये मुद्दे नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में श्रीरामलला के दर्शन और रोड शो करना वास्तव में चुनाव को जातीय, स्थानीय और छोटे स्वार्थों वाले मुद्दों से निकालकर व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की पटरी पर लाने की कोशिश है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

एक रापचिक गारंटी अपुन की तरफ से भी

नमिता जोशी

सर्किट ने फाइनली इलेक्शन फाइट करने का डिसाइड कर लिया। अपुन कू फेल होने के माफिक फीलिंग आ रयेली है। बोले तो मुन्ना भाई फर्स्ट टाइम सर्किट को रास्ते से भटकने से नहीं रोक पाया। इस बार सर्किट का लॉजिक अलग लेवल का था, तो अपुन कू भी हार मानना इच पड़ा। अपुन ने सर्किट कू भोत समझायेला था कि तू काइकू इलेक्शन के चक्कर में फंस रयेला है। कहां तू अक्खा टाइम मि. इंडिया के माफिक गायब रहने वाला इंसान है और कहां तू नेताजी का रोल पकड़ने की तैयारी कर रयेला है। तू तो उस फ्रूट के माफिक है जो खाली एक सीजन में आता है।

अपुन का फ्रूट वाला मिसाल चिरकुट कू पसंद नहीं आया। बोला, क्या मुन्ना भाई? ये सर्किट कू तुम काइकू फ्रूट से कंपेयर कर रयेले हो? ये तो किचन के कॉक्रोच के माफिक है। लाइट बंद होने पर इच नाली से बाहर निकलता है। लाइट खुलते इच वापस नाली की तरफ भागता है। इसका तो बस एकइच इलाज है, स्प्रे वाली दवाई छिड़को, तभीच होश में आएंगा और इलेक्शन का गाना बंद करेगा। चम्मन चिरकुट ने कंपेयर तो एकदम परफेक्ट किएला था, पन अपुन हंसी कंट्रोल करके बोला, सर्किट बता, तू क्या देगा पब्लिक कू? अक्खा इंडिया के नेता गारंटी दे रयेले हैं। कोई इस बात की गारंटी दे रयेला है, कोई उस काम की गारंटी। तेरे कू काइकू वोट देगी पब्लिक? अपुन कू एक सॉलिड लॉजिक दे दे, अपुन तेरा भेजा फ्राई नहीं करेगा।

अपुन की बात सुन के सर्किट के फेस पर ट्यूबलाइट के माफिक चमक आ गई। बोला, अब की तुमने काम की बात इस कंट्री के फ्यूचर लीडर से। देखो मुन्ना भाई, ये तो तुमको मालूम इच है कि अक्खा इंडिया के नेता लोग पब्लिक कू कोई ना कोई गारंटी दे रयेले हैं। तो अपुन भी अपनी पब्लिक के वास्ते एक अइसा रापचिक गारंटी का आइडिया सोच के लाया है। बोले तो अपुन का कैंपेन में भोत जरूरी गारंटी मिलने वाली है पब्लिक कू- स्पैम मेसेज से मुक्ति की गारंटी, लोन वाले कॉल से मुक्ति की गारंटी, वॉट्सऐप-फेसबुक में फालतू ज्ञान भरे मेसेज भेजने से छुटकारा दिलाने की गारंटी। फालतू रील से छुटकारा दिलाने की गारंटी, जिसमें कोई गांव का लड़का अपुन कू चप्पल कैसे पहनें, शर्ट का बटन कैसे लगाएं जैसे फालतू के काम सिखा रयेला हो। आखिर अपुन के काम की भी तो वैल्यू है कोई। अभी तो अमिताभ बच्चन भी परेशान है रील से। अपुन का गारंटी पे अमिताभ बच्चन भी अपुन कू इच वोट देंगा।

भेजा फ्राई

Ai Image

सर्किट की बात सुन के तो अपुन की आंख ऐसी फटी, जैसे खरबूजा जमीन पे गिरकर फट गयेला हो। ये वाली गारंटी तो आज तक किसी नेता के भेजे में नहीं आई होगी। सोचो, सुबह-सुबह फैमिली ग्रुप में चाय-कॉफी के कप और लाल गुलाब के नीचे उड़ती चिड़िया के मुंह से गुड मॉर्निंग निकलने वाला मेसेज कभी अपुन कू नहीं मिलेंगा। वो दूर के चाचा जो अपुन से डायरेक्ट फाइट करने से डरता है, पन स्टेटस पे ज्ञान वाले मेसेज लगा-लगा के अपुन कू धमकाने का कोशिश करता है, उससे छुटकारा मिलने की गारंटी मिल जाए तो मजा ही मजा। वो दूर की मामी, जिनको लगता है कि अक्खा दुनिया का अकल खाली उनके इच भेजे में है, अक्खा ज्ञान का टोकरा डेली अपुन कू चिपका देती है, उससे छुटकारे की गारंटी।

वाह सर्किट! और वो रील कि गमला कैसे उगाएं, चश्मा कैसे पहनें, डांस कैसे करने का..उस सबसे छुटकारा। सर्किट तू बिंदास इलेक्शन लड़। अपुन तेरे साथ है। खाली अच्छा और नया वाला जोक्स और मस्त रील बनेगी तो अपने देश का तरक्की तो अपने आप हो जाएंगा। सर्किट तू ये सारे वादे पूरे करने की गारंटी दे दे, अपुन तेरे कू गारंटी देता है कि तेरे कू भर-भर के वोट मिलेंगा और उससे भी ज्यादा बोनस में मिलेंगी दुआएं।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर nbtreader@timesgroup.com और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

---

75 सीटों पर हो गया है दिलचस्प सीन

Scene

नरेन्द्र नाथ

आम चुनाव अब अपने सेकंड हाफ में पहुंच गया है। ऐसे में अब सियासत बस चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रह गई है। तमाम राजनीतिक दल 4 जून की संभावित सियासी तस्वीर को समझने और decode करने में जुट गए हैं। हालांकि पक्ष-विपक्ष, दोनों पूरे आत्मविश्वास से यही बताने में लगे हैं कि अभी तक हुई वोटिंग उनके पक्ष में जाती दिख रही है। लेकिन सियासत में कई अनकहे सवालों के बीच ही आने वाले कल के भी संकेत छुपे होते हैं। चार चरणों के चुनाव के बाद जिस एक बात पर सभी सहमत हैं, वह है कि वोटिंग ने सभी का गणित बिगाड़ दिया है। इसके चलते इस बार चुनाव में बूथ मैनेजमेंट सबसे अहम फैक्टर हो गया है। बिना लहर वाले सामान्य चुनाव में वोटिंग ट्रेंड बहुत ही नियमित है। यह भी तय है कि इसमें 2019 के मुकाबले कुछ गिरावट तो होगी ही। चार राउंड के बाद दल यह तय कर रहे हैं कि किसका वोटर कम निकला है। सभी दलों में समीक्षा करने का भी दौर तेज है। हर उस जगह से फीडबैक लिए जा रहे हैं। कई सीटों पर अपेक्षाकृत कम वोट पड़े हैं तो कुछ जगहों पर उम्मीद से अधिक।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

चुनाव क्षेत्र के अंदर के अलग-अलग ट्रेंड

पूरा सीन तो 4 जून को नतीजे के आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन सभी इस बारे में अपने-अपने हिसाब से अर्थ तो निकाल ही रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड का नजदीकी आकलन कर रहे समीक्षकों के अनुसार, इस बार बहुत ही अलग बात सामने आ रही है। एक ही संसदीय क्षेत्र में अलग-अलग विधानसभा से लेकर गांव-शहरी क्षेत्रों वाले इलाके में वोटिंग में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। स्वाभाविक ही, इसका राजनीतिक संदेश बदल जा रहा है। कुछ इलाकों में BJP ने माना कि उसके मजबूत इलाकों में अधिक वोटिंग हुई, तो कहीं इसका उलटा होने का भी दावा किया गया है। ऐसे ही दावे विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे हैं। जाहिर है वोटिंग ट्रेंड ने आम चुनाव की जंग कांटे की बना दी है।

जानकारों के अनुसार, नजदीकी मुकाबले में जो राजनीतिक दल अपने-अपने वोटरों को बूथ तक भेजने में सफल होगा, वह अधिक लाभ में रहेगा। खासकर ऐसे मुकाबले में, जहां पिछले दो चुनावों से जीत-हार का अंतर मामूली रहा है। 2019 के आम चुनाव में लगभग 75 ऐसी लोकसभा सीटें थीं, जहां टक्कर एकदम कांटे की थी। इन सीटों पर जीत-हार का अंतर 20 हजार से भी कम वोटों का था। कम वोटिंग होने से ऐसी सीटों पर बहुत असर पड़ेगा और परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। आमतौर पर अधिक वोटिंग होने से ऐसा संदेश जाता है कि यह परिवर्तन के लिए उमड़ी भीड़ है जबकि वोटिंग में उदासीनता बताती है कि वोटरों में इसके प्रति उत्साह नहीं, जिसे सत्ता पक्ष अपने लिए उम्मीद के रूप में देखता है। हाल के दिनों में हुए तमाम दूसरे चुनावों को देखें तो हर चुनाव में वोटिंग में औसतन सात से दस फीसदी की वृद्धि होती रही है। ऐसे में इन दोनों ट्रेंड के बीच भी कई बार उलटे परिणाम देखने को मिले। देखा जाए तो इस बार कई राज्यों में वोटिंग 2014 के मुकाबले या तो कम हुई या लगभग उसी अनुरूप हुई। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से सभी राजनीतिक दलों ने वोटिंग के बाद अपनी रणनीतिक मीटिंग की और ग्राउंड से फीडबैक लिया। अब वोटिंग मूल रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों और शहरी इलाकों में होगी। यहां पहले ही बाकी जगहों के मुकाबले कम वोट डालने का ट्रेंड रहा है। ऊपर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अगले कुछ दिनों में गरमी बढ़ने वाली है।

Ai Image

पिक्चर अभी बाकी है

एक ओर कम वोटिंग पर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक बार फिर से महिला वोटरों ने अपना दमखम दिखाया है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में तो पुरुष वोटरों के मुकाबले महिलाओं ने छह से सात फीसदी तक अधिक वोट डाला है। हाल के वर्षों में यह फैक्टर चुनाव परिणाम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया है। अधिकतर चुनावों में इसका लाभ BJP को मिला भी है। इसकी वजह पिछले कुछ सालों में BJP सरकार की ओर से शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। ऐसे में महिला वोटर बढ़ने से सत्तारूढ़ खेमे में उत्साह का माहौल है। लेकिन यहां भी विपक्ष इसे रिवर्स ट्रेंड मान रहा है। इनका दावा है कि पिछली गलतियों से सीख लेते हुए उनकी राज्य सरकारों ने भी महिलाओं को कई लाभ दिए और उनपर आधारित योजनाएं शुरू कीं। विपक्षी खेमा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसका लाभ पाने का दावा कर रहा है। हालांकि बिहार और पश्चिम बंगाल में पुरुष वोटरों के मुकाबले महिलाओं की अधिक वोटिंग को कुछ जानकार पलायन से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि चूंकि इन राज्यों में अधिकतर पुरुष दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चले जाते हैं, यहां महिलाएं ही बचती हैं वोट डालने के लिए। बहरहाल, आम चुनाव में इस इंटरवल के बाद सियासी क्लाइमेक्स अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, और जनता के मन में छुपे रहस्य पर से परदा 4 जून को ही हटेगा।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ उम्र नहीं ऊर्जा देखिए

13 मई का संपादकीय 'मोदी हैं शीर्ष नेता' पढ़ा। विपक्ष ने कहा है कि अगले साल मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तब उनकी जगह कोई और नेता लेगा। अगर ऐसा हुआ, तो BJP की तरफ से PM पद का असली प्रत्याशी किसे माना जाए? मोदी अभी जितने मजबूत, ऊर्जावान और उत्साह से लबरेज हैं, उन्हें अपने पद से हटने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी भी ऐसा नहीं चाहेगी। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति भी उम्रदराज हैं। फिर भी वे सत्ता का बखूबी संचालन कर रहे हैं। दूसरी बात, देशवासी भी अभी PM के रूप में मोदी को ही देखना चाहते हैं।

सुभाष बुडावन वाला, ईमेल से

■ भेजा फ्रेश हो गया

30 अप्रैल को प्रकाशित लेख 'शॉर्ट कट से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए' बहुत अच्छा लगा। **भेजा फ्राई** लोकप्रिय पात्र सर्किट और मुन्नाभाई के बीच संवाद मजेदार है। इनके जरिए दमदार तरीके से सामयिक विषयों पर रचना के लिए लेखिका को बधाई। लेखिका ने टपोरी (मुंबई शैली) का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। यह लेख एनबीटी के पाठकों के मानस को तरोताजा कर देता है। इसलिए इसे भेजा फ्राई नहीं, भेजा फ्रेश कहना चाहिए।

आनंद, ईमेल से

■ अनसुलझी गुत्थी

यह पत्र 11 मई के संपादकीय 'नहीं मिले सारे जवाब' से संबंधित है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में 11 साल बाद फैसला आया है। इस हत्या के पीछे किस संगठन का हाथ था और हत्या का मकसद क्या था, इसका जवाब अभी तक नही मिल पाया है। 2015 में गोविंद पानसारे और एम.एम. कलबुर्गी तथा 2017 में हुई गौरी लंकेश की हत्या के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इस हत्याकांड की साजिश से जुड़े सवालों के जवाब मिलने चाहिए।

वारिस अली खान, ईमेल से

nbteditpage@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

दो दिन की राहत के बाद फिर हवा खराब - एक खबर
- अभी चुनाव का माहौल है, तो हवा भी तेवर दिखा रही है!

अंजलि राणा

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

समय का साथ चाहिए तो खुद को स्वीकार करो

गोपाल अग्रवाल

संसार में इकलौता इंसान ही है जो एक बार में ही भूत, भविष्य और वर्तमान- तीनों में टहल सकता है। इसे मन कहें, सोच कहें या कल्पना ही कह लें, इंसान इनके जरिए समय के इन तीनों प्रकारों में एक साथ भी रह सकता है और चाहे तो तीनों से अलग भी रह सकता है। एक दो उदाहरण हैं, जिनसे बात थोड़ी और खुलेगी। एक चित्रकार अतीत का चित्र बनाता है, भविष्य की कल्पना करके भी चित्र बनाता है तो वर्तमान में मौजूद चीजों को भी उकेर सकता है। एक और उदाहरण हमारी सोच में मिलता है। सोचते-सोचते हम पुरानी यादों में चले जाते हैं, तो भविष्य की कल्पनाओं में खुद को खड़ा पाते हैं, यहां तक कि महसूस भी करने लगते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में एक साथ विचरण करने की यह क्षमता हो या उनसे विलग रहने की, यह इंसान को ईश्वर के इतना नजदीक लाती है कि वह स्वयं उनका स्वरूप बन जाता है। अब ईश्वर तो सर्वशक्ति संपन्न हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात तो है नहीं। वह जब चाहें, कसी भी समय में आ सकते हैं या जा सकते हैं। लेकिन वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को इस काबिल बनाती है?

हम सभी सुनते आए हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। होश संभालने से लेकर होश गंवाने तक मनुष्य चिंतन करता रहता है। शास्त्रों में कहा है कि जो इंसान चिंतन नहीं करता, वह मृतक समान है। यही चिंतन उसे भूत, भविष्य और वर्तमान में विचरण करने की क्षमता प्रदान करता है तो इसी से वह इनसे बाहर भी निकल सकता है। चिंतन मनुष्य की चेतना का फ्यूल है। चेतना तभी आगे बढ़ती है, विकसित होती है, जब मनुष्य चिंतन करता है। बहुत से लोग चिंतन को चिंता समझ लेते हैं। चिंता कभी चिंतन नहीं होती। चिंतन के लिए ध्यान योग जरूरी है। चिंता कभी ध्यान केंद्रित नहीं करने देती है। चिंता अपने जाल में हमें उलझाती जाती है, जबकि चिंतन हमें विषय और समय, दोनों से मुक्त होने में मदद करता है। जब हम समय से मुक्त होते हैं, तभी हम सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। सत्य, यानी स्वयं हम, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी मुक्ति और आनंद। चिदानंद का द्वार चिंतन-मनन से विकसित चेतना ही खोल सकती है।

कोई पूछ सकता है कि चिंतन है क्या? जैसा कि पहले बताया, चिंतन ही चेतना का फ्यूल है। चिंतन सकल जगत का नहीं। चिंतन स्वयं को पहचानने का। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मुझे क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं? क्या मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है? यह चिंतन के रास्ते में आने वाली कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां चिंतक कुछ देर बैठता है, उन्हें पहचानता है, उन्हें धारण करता है और फिर आगे अगली जगह के लिए बढ़ जाता है। हर स्थान उसे एक नई चेतना से लैस करता है। अंत में वह पाता है कि वह खुद के सामने है, खुद को देख पा रहा है, समझ पा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं को स्वीकार कर पा रहा है। जो स्वयं को स्वीकार करते हैं, समय भी उसे ही स्वीकार करता है। अन्यथा मनुष्य कालयात्रा तो करता रहता है, लेकिन उसके साथ उसका स्वयं, या उसका आत्म नहीं होता। इसीलिए उसे न तो भूत यानी यादों में कोई आनंद मिल पाता है, न भविष्य में और न ही वर्तमान में।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 14 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

जल्द सामने आए सच

पश्चिम बंगाल की विवादित संदेशखालि घटना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता गंगाधर कयाल कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख व उनके सहयोगियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 70 महिलाओं को दो-दो हजार रुपए दिए गए थे। शेख पर यौन उत्पीड़न व ग्रामीणों की जमीनें हड़पने के आरोप हैं। बीते सप्ताह भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कयाल कह रहे हैं कि बलात्कार के आरोप मनगढंत हैं। उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले करीब 50 चुनाव बूथों पर अशांति पैदा करनी है, इसके लिए 50 पिस्तैलों व 600 कारतूसों की जरूरत होगी। वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा बैकफुट पर है और स्वाभाविक तौर पर वीडियो को फर्जी कह कर हाथ झाड़ रही है, जबकि भाजपा की संदेशखालि की उम्मीदवार व प्रदर्शनकारी रेखा पात्रा का दावा है कि जिन बलात्कार पीड़िताओं को राष्ट्रपति से मिलाने ले जाया गया था, उन्हें वह नहीं जानतीं।

स्थानीय भाजपा नेता चुनाव के पहले टीएमसी फर्जी हवा चलाने के लोभ में वीडियो का प्रयोग कर रही है। घटना के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में झड़पें हिंसक हो गईं। यह मसला साधारण नहीं माना जाना चाहिए। सच और झूठ का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। खासकर चुनावों के दरम्यान होने वाली छींटाकशी आम है। मगर इस तरह महिलाओं के चरित्र की फजीहत करने पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। इस पर दलों के प्रमुखों को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके साथ अपराध हुआ या उन्हें बरगला कर छद्म आरोप मढ़े गए, यह जांच का विषय है। कानून अपना काम करता रहेगा। मगर फौरी तौर पर इसे चुनावी फायदा उठाने वाला विषय बनाए जाने से बाज आना चाहिए। खास बात वीडियो के सामने आने की टाइमिंग की। शिक्षित और सभ्य समाज से यह उम्मीद कतई नहीं की जाती कि वे मतदाता को भावनात्मक तौर पर प्रभावित करने के लिए बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को मुद्दा बनाए। यौन उत्पीड़न के आरोप गलत हैं या सही, इसका खुलासा जल्द हो। साथ ही दोनों ही स्थितियों में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो ताकि भविष्य में कोई राजनैतिक दल यौन शोषण जैसी संवेदनशील घटनाओं से लाभ का लोभ लेने के प्रति भयभीत रहें। एक बात तो तय है कि संदेशखालि का मसला भाजपा के लिए बेहतर मौका लेकर आया, मगर अब जिस तरह से तथ्य बाहर आ रहे हैं, वो कुछ और कहानी बयां करती हैं।

पीओके के हालात

पीओके में आसमानी महंगाई और बढ़े बिलों से आम आदमी बेहाल है। बेहतर नागरिक व्यवस्था की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे लोग हिंसक तक हो रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी मारा गया है और 100 के लगभग घायलों में बड़ी तादाद पुलिसकर्मियों की है। हिंसा का यह घनत्व अहिंसक विरोध से उकताहट को साबित करता है। बुनियादी जरूरतों-सुविधाओं को लेकर पीओके-बाशिंदों का विरोध पाक के अवैध कब्जे के बाद से ही है। पीओके माने पाकिस्तान आक्रांत कश्मीर। 1947 में आजादी के तत्काल बाद बिना उकसावे के पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में जम्मू-कश्मीर का यह हिस्सा पाक के कब्जे में चला गया था। हालांकि यहां के बाशिंदों का बहुमत तभी से पाकिस्तान से स्वायत्त रहना चाहता था, लेकिन वह पाकिस्तान के कालांतर बढ़ते दमनों के आगे बेबस हो गया। पर भारतीय कश्मीरियों को उनके बनिस्बत मिली बेहतर सुविधाएं और आजादी को लेकर पीओके के मन में न मिटने वाला आकर्षण बना रहा। आज स्थिति यह है कि पीओके अवाम नागरिक सुविधाओं के मोहताज हो गए हैं। आटा-दाल का भाव आसमान पर है। वह बिजली भी नदारद है, जिसका पीओके में प्रभूत उत्पादन हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि यह स्थिति नहीं बदलने वाली है। भारत में अनुच्छेद 370 के खात्मे के पहले और उसके बाद से सभी सरकारों के लिए कश्मीर प्राथमिकता रहा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 'विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर' कार्यक्रम में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं दी हैं। इसमें कृषि और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में काम होना है। यहां लोगों के पास रोजगार और नौकरियां हैं। इनसे पीओके हालात का कोई मुकाबला नहीं है। तंग आए पीओके के लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं और अपनी सीमा भारत की ओर खोलने की मांग कर रहे हैं। वे इसके लिए आंदोलनरत रहे हैं। अभी भी वैसी ही स्थिति है। सवाल है कि इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? क्या वह हस्तक्षेप कर सकता है? विदेश मंत्री एस जयशंकर के ताजा बयान और भारतीय नेताओं के समय-समय पर दिए गए वक्तव्य इसके संकेत देते हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटें पीओके के लिए सुरक्षित भी रखी गई हैं। पीओके में अंतिम हद तक बेकाबू होते हालात भारत के लिए तश्तरी में परोसे गए अवसर इतिहास बदलने वाले होंगे।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

मास्क और रिश्ते

घर के किसी कोने में देखिये कोरोना काल में प्रयुक्त होनेवाला मास्क पड़ा होगा उपेक्षित टाइप।

मास्क का हाल भी रिश्तों जैसा है इन दिनों, जो यूज न होते, उन्हे कोने में डाल दिया जाता है।

खबर है कि कोविशील्ड का टीका जिन्होंने लिया, उन्हें खतरा है। खतरा तो साहब उनको भी है, जिन्होंने कोविशील्ड ना लेकर कोई और डोज लिया है। भारत भूमि खतरों के खिलाड़ियों की भूमि है, गरमी में जो लू से ना मरेंगे, वह बरसात में बाढ़ से मरने के खतरे में हैं। बरसात से बच लिये तो सर्दी मार सकती है। हम भारतीय बहुत बेशर्म टाइप के लोग हैं, हमारी बेशर्मी बचा जाती है हमको। मास्क की तरह उपेक्षित ना रहिये ऐसे बनिये कि आपकी जरुरत किसी को हमेशा महसूस हो, मतलब सिगरेट जैसे ना बनिये की उसकी जरुरत बतौर लत महसूस करे कोई, कुछ-कुछ घंटों के बाद। आक्सीजन बनिये कि उसके बिना जीना संभव ना हो। खैर कोरोना मास्क का हाल अब मार्गदर्शक मंडल के नेताओं जैसा हो गया है, हैं वो, बस पड़े हुए हैं कोने में। कोरोना मास्क सुल्तान हुआ करता था एक वक्त कपड़ों का।

सूट बूट सब चकाचक पहनकर भी कोरोना मास्क पहनना जरूरी हुआ करता था। बल्कि एक वक्त तो हालत तो यह हो गई कि बंदा सब कुछ पहना भूल जाए पर मास्क जरूर पहनना होता था। कोरोना पर फिर चर्चा हो गई है। बस डर यह है कि कोरोना फिर कभी लौट ना आए। नागिन सीजन वन, नागिन सीजन टू ,नागिन सीजन थ्री, नागिनों के कई सीजन पब्लिक को झेल सकती है। कोरोना के नया सीजन न झेल सकती पब्लिक। चुनाव के कई सीजन भी पब्लिक झेल जाती है। चुनाव चालू है, पब्लिक और भी ज्यादा चालू है। पब्लिक ऐसे ऐसे जवाब दे रही है टीवी चैनल रिपोर्टरों को कि ताड़ना मुश्किल है कि पब्लिक के मन में क्या है। एक टीवी रिपोर्टर ने हाल के विधानसभा चुनाव में एक कंस्टूटेंसी में सौ लोगों से बात की, सब के सब कह रहे थे कि वह वाला कैंडीडेट जीतेगा। टीवी रिपोर्टर ने चुनाव आयोग से पहले घोषित कर दिया कि वह वाला नेता पक्के तौर पर ही जीतेगा। पर जब रिजल्ट आए तो उस कैंडीडेट तीन वोट मिले थे, जबकि उसके घर में पंद्रह लोग थे।

चर्चा में राहुल की उम्मीदवारी

सामयिक

अवधेश कुमार

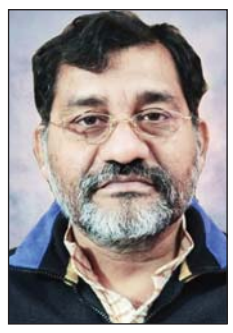

उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी लोक सभा सीट के संभावित उम्मीदवारों को लेकर इतनी लंबी चर्चा शायद ही कभी चली हो। यह इसलिए स्वाभाविक था कि इन दोनों को सोनिया गांधी परिवार का विरासत स्थान माना जाता है। चूंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं और उन्होंने अपने पत्र में आगे चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। राहुल गांधी अमेठी से तीन बार सांसद रह चुके हैं और चौथी बार 2019 में पराजित हुए, इसलिए वे वहां से लड़ेंगे ऐसी कल्पना अस्वाभाविक नहीं थी।

कांग्रेस के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्वयं को उस पार्टी का जानकार मानने वाले पत्रकारों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वायनाड का चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी की अमेठी तथा प्रियंका की रायबरेली से उम्मीदवारी की घोषणा हो जाएगी। यह सामान्य स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो नामांकन की अंतिम तिथि के ठीक पहले। वायनाड मतदान खत्म होने के बाद एक सप्ताह का समय लिया जाना बताता है कि राहुल को वहां से लड़ने के लिए मनाना कितना कठिन रहा होगा। प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? रायबरेली से राहुल के उम्मीदवार होने और अमेठी से न होने तथा प्रियंका के चुनावी मैदान में न उतरने के मायने क्या हैं? कांग्रेस पर दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि ज्यादातर नेता चाहते थे कि राहुल अमेठी एवं प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन राहुल ऐसा नहीं चाहते थे।

2019 में पराजय के बाद कांग्रेस में यह सोच दृढ़ हुई कि लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिसा जैसे राज्यों में कांग्रेस का पुनर्उद्भव अभी कठिन है। उसे राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी स्थिति पानी है तो दक्षिण भारत में फोकस कर उत्तर की ओर बढ़ना होगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी मानना रहा है कि मुस्लिम वोट का एकमुश्त निकल जाना कई राज्यों में उसके लगभग समाप्त होने का एक बड़ा कारण रहा और उसकी जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने ले लिया। तो मुस्लिम वोट की वापसी उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया। केरल में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन है और वायानाड से संदेश जा सकता था कि कांग्रेस और मुसलमान साथ हैं। इसे ध्यान में रखें तो निष्कर्ष आएगा कि राहुल यदि 2019 में अमेठी जीत जाते तब भी वायनाड को नहीं छोड़ते। हां, उस स्थिति में शायद प्रियंका को वहां से लड़ाने की कोशिश होती या राहुल किसी विश्वसनीय व्यक्ति को खड़ा करते। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी एवं कांग्रेस के पास कोई विकल्प बचा नहीं था। राहुल गांधी अमेठी को लेकर वाकई अनिच्छुक थे? क्या

उनके अंदर वहां के लोगों को लेकर गुस्सा है? लोक सभा चुनाव हारने के बाद अमेठी पर जुलाई 2019 की एक समीक्षा बैठक में वे शामिल हुए। उसके ढाई वर्ष बाद दिसम्बर 2022 में जन जागरण यात्रा के लिए अमेठी गए और फिर अब न्याय यात्रा के दौरान। यानी पराजय के बाद उन्होंने अमेठी की ओर मुंह मोड़ा ही नहीं। न उस पर कोई बयान दिया न संसद कोई प्रश्न पूछा। ऐसे में राहुल वहां से चुनाव लड़ते तो लोगों के सामने अपने पक्ष में कौन सा तर्क रखते? दूसरे, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पांच विधानसभा क्षेत्र में से केवल एक क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही थी।

राहुल को उनके रणनीतिकारों तथा भारत से लेकर विश्व के वामपंथियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समानांतर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड के रूप में उभारने की कोशिश की है। अगर अमेठी से हार जाते तो ब्रांड ही ध्वस्त हो जाता। स्मृति ईरानी ने बाहरी का तमगा हटाने के लिए वहां घर बनाया तथा गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के मैदान गांव से मतदाता हैं। इस बीच अमेठी से सोनिया गांधी परिवार के अनेक करीबी व प्रमुख नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जोखिम रायबरेली में भी है। रायबरेली के सारे राजनीतिक समीकरण पिछले 5 वर्षों में बदल चुके हैं। हालांकि सोनिया गांधी की सीट होने के कारण उनके रणनीतिकारों को वहां संभावना ज्यादा नजर आई है। राज्य सभा में जाने के साथ सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी किया जिसमें क्षेत्र को लेकर भावुक बातें थी। कांग्रेस के सामने प्रश्न था कि दोनों सीटों में किसी पर सोनिया परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव न लड़ा तो संदेश यही जाएगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है या हार के भय से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हालांकि कुछ प्रश्न अभी भी बने हुए हैं।

मसलन, प्रियंका को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया? कहा जा रहा है कि वह चुनाव लड़तीं तो एक जगह अटक जाती, पूरे देश में प्रचार नहीं कर पातीं। क्या ऐसा होता है कि किसी पार्टी के शीर्ष नेताओं की टोली इसलिए चुनाव नहीं लड़ती कि उसे दूसरों का प्रचार करना है? प्रथम परिवार पर पूरी पार्टी की जिम्मेवारी है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे चुनाव लड़े ही नहीं। इसलिए यह तर्क गले नहीं उतरता। कायदे से देखा जाए तो रायबरेली को परिवार की शत प्रतिशत परंपरागत सीट मानने में हिचक होगी। 1952 और 57 में वहां से फिरोज गांधी चुनाव लड़े थे जिनसे यह परिवार अपना रिश्ता जोड़ता नहीं। प्रयागराज के उनकी कब्र पर कभी सोनिया गांधी परिवार को जाते किसी ने नहीं देखा। उसके बाद इंदिरा गांधी राजनीति में 1964 में राज्य सभा से आईं। 1971 में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ना शुरू किया, जीतीं, पर 1977 में हार गईं। 1980 में उन्होंने रायबरेली के साथ आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव लड़ा और दोनों जीतने के बाद रायबरेली से त्यागपत्र दिया। राजीव गांधी ने रायबरेली को अपना क्षेत्र बनाने की जगह 1981 में उस अमेठी से चुनाव लड़ा जहां से 1980 में संजय गांधी ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। सोनिया गांधी ने भी 1999 में अपने चुनावी राजनीति की शुरुआत अमेठी से की और 2004 में राहुल गांधी को विरासत सौंप कर स्वयं रायबरेली शिफ्ट हो गईं।

इस तरह परिवार की विरासत सीट रायबरेली से ज्यादा अमेठी होनी चाहिए। कुल मिलाकर राहुल भले अंतिम समय में रायबरेली से उम्मीदवार बन गए, लेकिन इसका वह संदेश नहीं गया जो कांग्रेस के लिए ऐसे कठिन समय में उनके समर्थकों और आम जनता के बीच में जाना चाहिए था। दरअसल, कांग्रेस अभी भी विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व यानी नेतृत्व को लेकर दिशाभ्रम और अनिश्चितता का शिकार है और यही रायबरेली एवं अमेठी के संदर्भ में प्रदर्शित हुआ है।

सोनिया गांधी ने भी 1999 में अपने चुनावी राजनीति की शुरुआत अमेठी से की और 2004 में राहुल गांधी को विरासत सौंप कर स्वयं रायबरेली शिफ्ट हो गईं। इस तरह परिवार की विरासत सीट रायबरेली से ज्यादा अमेठी होनी चाहिए। कुल मिलाकर राहुल भले अंतिम समय में रायबरेली से उम्मीदवार बन गए, लेकिन इसका वह संदेश नहीं गया जो कांग्रेस के लिए ऐसे कठिन समय में उनके समर्थकों और आम जनता के बीच में जाना चाहिए था

दिनोंदिन बढ़ रही है भारत में 'गिग वर्कर्स' की संख्या

- आज अधिकतर युवा और प्रोफेशनल किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते। खुद के ही बॉस बनने में विश्वास रखते हैं।
- पत्रकार, वकील, आर्किटेक्ट, लेखक, फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर और किसी कंपनी के विशेष प्रोजेक्ट से जुड़कर कार्य करने वालों, जो उस कंपनी के वैतनिक कर्मचारी नहीं होते, को 'गिग वर्कर्स' कहा जाता है
- एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में 2027 तक कार्यक्षम लोगों में 50 प्रतिशत संख्या 'गिग वर्कर्स' की होगी। भारत की जहां तक बात है, तो 2021 में भारत में 'गिग वर्कर्स' की संख्या करीब 1.5 करोड़ थी, जो हर दिन बढ़ने पर है

(मीडिया इन्पुट्स)

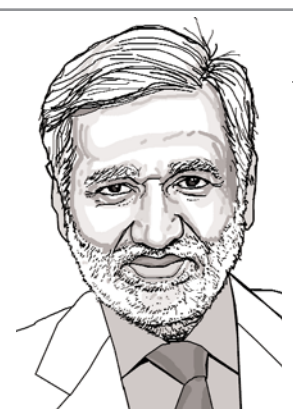

अपने देश में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, पर चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं के बीच 'पब्लिक डिबेट' हो तो यह अच्छा कदम होगा! विपक्ष अगर तैयार है तो सत्तापक्ष को भी तैयार होना चाहिए।

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

जमीन धंसाव | डॉ. हंसा मीना

अंधाधुंध विकास से बचके

पश्चिमी राजस्थान में घटित जमीन में धंसाव की हालिया दो घटनाओं ने समूचे देश का ध्यान आकर्षित किया है। सोलह अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के सहजरासर गांव में एक खेत का लगभग डेढ़ बीघा हिस्सा जमीन में अचानक धंस गया। इस घटना के कारणों के विषय में कई तरह के कयास लगाए जा रहे है, जैसे भूगर्भीय प्लेटों में हलचल का होना एवं इस क्षेत्र में व्याप्त विशाल जल राशि के दोहन से उत्पन्न हुए वैक्यूम का लगातार कम होना। किंतु भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक जिस संभावित कारण को सर्वाधिक मान रहे हैं वह है-थार के मरुस्थल के नीचे प्रवाहित सरस्वती नदी के जल के सूखने से उत्पन्न हुए वैक्यूम का लगातार कम होना।

इसी तरह की घटना सात मई को बाड़मेर के नागाणा क्षेत्र में घटित हुई है। यहां तेल के कई कुएं हैं, जिनसे क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में मंगला टर्मिनल के वेल पेड 3 से 7 के बीच में करीब डेढ़ से दो किलोमीटर लंबी जमीन में दरार आई है। यहां भी जमीन से भारी मात्रा में तेल के दोहन से उत्पन्न हुए रिक्त स्थान के कारण इस घटना का होना माना जा रहा है। वर्ष 2000 के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। पूर्व में कोलायत में ऐसे ही जमीन का धंसाव हुआ है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी बड़ी भूगर्भीय हलचल के होने की ओर इशारा कर रही हैं, जो चिंता का विषय है। ऐतिहासिक तथ्य है कि सरस्वती नदी राजस्थान में थार के मरुस्थल से होकर बहती थी जो कालांतर में लुप्त हो गई। इसके पश्चात जीआईएस डाटाबेस के आधार पर इसको पुनर्जीवित करने के अभियान की शुरुआत 'प्रोजेक्ट सरस्वती' के तहत हुई। सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि सरस्वती नदी की घाटी हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में समाहित है, जबकि राजस्थान में यह नदी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और थार के मरुस्थल से होते हुए खम्बात की खाड़ी तक जाती है। बीकानेर और बाड़मेर में हुई घटनाएं सरस्वती नदी घाटी की दिशा में ही घटित हुई हैं। साल 1998 में मिशन सरस्वती योजना के तहत इस क्षेत्र में कई बोरवेल खोदे गए थे जिनसे स्वतः ही पानी निकलता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इनसे निकलने वाले पानी को तीन हजार से चार हजार साल पुराना होने का दावा किया है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे मीठे पानी की लगभग 40-50 मीटर मोटी परत है। जमीन के नीचे

बहती नदी जब सूखने लगती है तो जहां-जहां पानी गहरा होता है उन स्थानों पर तालाबनुमा और झीलनुमा जलीय स्रोत रह जाते हैं। इस क्षेत्र के आस पास सौ से दो सौ किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में किसानों द्वारा पानी दोहन हो रहा है, जिससे पाताल में लगातार वैक्यूम बन रहा है। जिन स्थानों पर यह स्थिति बन रही है उन रिक्त स्थानों पर जमीन बैठने लगती है। बीकानेर में जमीन धंसने से हुआ लगभग 82 फुट गहरा गड्ढा इसी के परिणामस्वरूप बनता प्रतीत हो रहा है जो लगातार गहरा होता जा रहा है। बाड़मेर में जिस स्थान पर जमीन में दरार आई है वहां ऑयल एंड गैस प्लांट है। इस घटना के कारणों के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा प्रथम दृष्ट्या यह आशंका जताई जा रही है कि तेल निकालने के लिए होने वाली ड्रिलिंग के चलते लगभग दो किलोमीटर जमीन में दरार आई है, जबकि कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि यहां कई तेल के कुएं हैं, जिनसे दशकों से क्रूड ऑयल का दोहन हो रहा है, इससे आस पास के क्षेत्र में लगातार वैक्यूम बन रहा है। इस कारण से भी दरार का बनना माना जा रहा है। अतः यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी की भूमि धंसाव एक मानव प्रेरित घटना है। विश्वभर में भूमि धंसाव के सभी मामलों में लगभग 70 प्रतिशत मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं, जिसमें भूजल निष्कर्षण 60 प्रतिशत है।

उपरोक्त घटनाओं ने भविष्य के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी अतःइन स्थितियों से निपटने के लिए हमें अनुकूल समाधान निकालने होंगे जो इस प्रकार हो सकते हैं-भूजल निष्कर्षण कम करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भूजल पुनर्भरण को लागू करना इत्यादि। भूजल पुनर्भरण में कृत्रिम पुनर्भरण जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से भूजल संसाधनों को फिर से भरना शामिल है। इस प्रक्रिया का उपयोग जलभृतों में पानी की मात्रा बढ़ाने, भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने और अत्यधिक भूजल दोहन के कारण होने वाली भूमि धंसाव को रोकने के लिए किया जाता है।

यह न केवल भूमि धंसाव को रोकती है, बल्कि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए पानी का एक वैकल्पिक स्रोत भी प्रदान कर सकती है और साथ ही भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकती है। पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण करके भी इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जल संसाधनों का उपयोग करना होगा। 'सतत विकास' की अवधारणा को अपने जीवन में अपनाने के साथ ही 'जल ही जीवन है' इसे संस्कार के रूप में आत्मसात करना होगा तब जाकर हम एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

मन का खेल | ओशो

बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण कश्यप। वह निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया। अब मेरे साथ-साथ डोलने की कोई जरूरत न रही।

अब तू जा। अब तू गांव-गांव, नगर-नगर घूम और डोल। मेरी खबर ले जा। मेरे पास तूने जो पाया है, उसे लुटा। पूर्ण ने कहा : भगवान, किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा : अब तू खुद ही समर्थ है। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा 'सूखा' नाम का एक इलाका था बिहार में-वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है। वह जगह भली नहीं। लोग सज्जन नहीं। लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत-वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं। तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी जरूरत है। किसी को तो जाना ही होगा। कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा। आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, जा; मगर मेरे दो-तीन सवालों के जवाब दे दे। पहला अगर वे तुझे गालियां दें, अपमान करें, तो तुझे क्या होगा 'तो पूर्ण ने कहा, यह भी आप मुझसे पूछते हैं, क्या होगा? आप भलीभांति जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा। क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक। मगर अगर मारे न, मारने ही लगें, तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते हैं? आप भलीभांति जानते हैं कि पूर्ण प्रसन्न होगा, कि धन्यभाग कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल, पूर्ण। अगर मार ही डालें, तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप, और पूछते हैं? आपको भलीभांति मालूम है कि जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में होगा, धन्यभाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल-चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा। अब तुझे जहां जाना है, तू जा, तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता, कोई मार नहीं सकता। अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली न देंगे; गाली तो वे देंगे, लेकिन तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे नहीं; मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने, कोई तुझे मार भी डाले; लेकिन अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। 'उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया-जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है।'

रीडर्स मेल

ध्वनि प्रदूषण पर काबू जरूरी

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के रास्ते पर तेजी से बढ़ते शहरों में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति दिनोंदिन भयावह होती जा रही है। सामान्यतः, हमारे कान एक निश्चित ध्वनि की दर को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे कान नियमित तेज आवाज को सहन नहीं कर पाते हैं और हमारे कान के पर्दे बेकार हो जाते हैं, परिणामस्वरूप अस्थायी या स्थायी रूप से सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण बहरापन, कान में दर्द, कमजोरी, अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्त दाब, वार्तालाप समस्या आदि का जन्म होता है। अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है एवं मानव, पशु-पक्षी और पेड़-पौधे सभी के जीवन के लिए असंतुलन का कारण है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार को भी ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ कठोर कानून बनाने चाहिए एवं आम जनता में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

चार आर से बनेगी बात

भारत दुनिया में कचरा पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल करीब 30 करोड़ टन से भी ज्यादा सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन हम इसका 60 फीसद ही निस्तारित कर पाते हैं। यह कचरा जल, वायु और भूतल प्रदूषण का कारण बन रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा कचरा उत्पन्न होता है। इस मामले में दिल्ली ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। प्लास्टिक कचरा का कम से कम उत्पादन ही दुनिया को कचरे से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। इस संदर्भ में विशेषज्ञ चार आर का सिद्धांत अपनाने की बात करते हैं। इसमें पहले आर का अर्थ रिफ्यूज यानी प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग से इनकार करना, दूसरे आर का अर्थ रिड्यूस यानी प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करना, तीसरे आर का अर्थ रीयूज यानी नए की बजाय पुराने प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग करना और अंत में रिसाइकिल यानी पुराने प्लास्टिक पदार्थों को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग करना है।

अमित बैजनाथ गर्ग, जयपुर

सख्त कार्रवाई हो

देश में अस्थिरता फैलाने और प्रशासन और सरकार को फिजूल सांसत में डालने के लिए धमकी भरे मेल का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले तीन-चार दिनों से जांच दल ऐसी ही पड़ताल में लगे हैं, लेकिन न तो मेल भेजने वाले गिरफ्त में आ रहे हैं ना ही दहशत कम हो पा रही है। दिल्ली, गुजरात में शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों में बम की धमकी अब गुजरात तक जा पहुंची है। मेल के जरिए राज्य के दो स्कूलों को उड़ाने की धमकी से वहां नई दहशत कायम हो गई है। बम निरोधी दस्ते और पुलिस को फिलहाल कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस तरह की धमकियों से स्कूलों में बच्चों और अस्पताल में मरीज और उनके परिजन चिंतित हो जाते हैं। जब देखो तब मेल भेज कर सरकार और प्रशासन को परेशान किया जा रहा है बावजूद इसके सरकार को ऐसे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या जाने कब अनहोनी हो जाए?

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 270 | आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 | *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AINewsPaper

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

जस्टिन ट्रूडो की खुल गई पोल

कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद भारत कनाडा संबंधों में तनाव बना हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर अनर्गल आरोप लगाए जाने के बाद भारत की तीखी प्रतिक्रिया से कनाडा के तेवर भले ही ठंडे न हुए हो लेकिन पूरे घटनाक्रम ने जस्टिन ट्रूडो की पोल खोलकर रख दी है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा पुलिस ने चौथे आरोपी अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कनाडा पुलिस ने एडमांटन में तीन भारतीय नागरिकों करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। निज्जर हत्याकांड को लेकर पहले ही यह कहा जाता रहा है कि यह हत्याकांड गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई का परिणाम है। अभी तक कनाडा सरकार ने भारत सरकार को निज्जर हत्याकांड में कोई ठोस सबूत नहीं दिया है और न ही कोई औपचारिक सम्पर्क भेजा है। निज्जर हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों ने भी अभी तक राजनयिक पहुंच की मांग नहीं की है। ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार भारतीय एजैंसियों को बदनाम करने की साजिश कर रही है और खुद आतंकवादी तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

पिछले साल नवंबर में अमेरिकी फेडरल अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक पर अभियोग लगाया था कि वह भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। भारत ने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है और अमेरिकी सरकार से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद को बताया था कि ऐसी जांच की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पन्नू को भारत ने आतंकियों की सूची में रखा है। उसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। वह अमेरिका में रहकर भारत विरोधी आयोजन करता रहता है तथा आतंकी हमलों की धमकी देता रहता है। ऐसे कई आतंकी और अपराधी सरगना अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में हैं।

> **अब सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खड़े हैं। उनकी मजबूरी यह है कि उनकी सरकार कट्टर खालिस्तानी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 24 सांसदों के समर्थन से ही चल रही है। ट्रूडो इस समूह को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। कनाडा में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। कनाडा की कुल आबादी लगभग 3.8 करोड़ के आसपास है और सिखों की आबादी वहां लगभग पौने आठ लाख के लगभग है यानि सिख आबादी का लगभग 2 प्रतिशत है। सर्वेक्षणों में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कम हो रही है।**

भारत के इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद कनाडा अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। कनाडा और अमेरिका की सरकारों और पश्चिमी मीडिया द्वारा इनकी पैरोकारी ही की जाती रही। बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हें संरक्षण भी दिया जाता रहा है। पिछले माह ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालसा दिवस पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और वे इस पर मुस्कुराते रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी समूहों को इस तरह की गतिविधियां करने की छूट देना अच्छी बात नहीं है। उस कार्यक्रम में ट्रूडो ने सिखों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की कसम खाई। अपने देश में किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना अच्छी बात है, पर सवाल है कि जिस व्यक्ति या समूह के लिए यह बात की जा रही है, उसकी मंशा और राजनीति क्या है।

एक देश का नेतृत्व करते हुए क्या ट्रूडो को इस बात को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि खालिस्तानी अलगाववाद की समस्या भारत को किस तरह प्रभावित करती है? एक समुदाय के रूप में सिखों का योगदान भारत के लिए बेहद अहम रहा है और एक आम सिख भारत से प्यार ही करता है। ऐसे में चंद अलगाववादी तत्वों को प्रश्रय देकर ट्रूडो क्या दर्शाना चाहते हैं? स्वाभाविक ही ताजा मामले को लेकर भारत ने कनाडा के उप-उच्चायुक्त को तलब कर सख्त विरोध दर्ज कराया।

अब सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खड़े हैं। उनकी मजबूरी यह है कि उनकी सरकार कट्टर खालिस्तानी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 24 सांसदों के समर्थन से ही चल रही है। ट्रूडो इस समूह को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। कनाडा में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। कनाडा की कुल आबादी लगभग 3.8 करोड़ के आसपास है और सिखों की आबादी वहां लगभग पौने आठ लाख के लगभग है यानि सिख आबादी का लगभग 2 प्रतिशत है। सर्वेक्षणों में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कम हो रही है। बढ़ रही महंगाई जीवनयापन के लिए लोगों के पास पैसों की कमी और महंगे होते घर देश के लोगों के बीच सबसे बड़े मुद्दे हैं। मजबूरन ट्रूडो को खालिस्तानी नेताओं की वैसाखी थामनी पड़ रही है। जस्टिन ट्रूडो को केवल चुनावों की चिंता है इसलिए वे भारत-कनाडा संबंधों को नजरंदाज कर रहे हैं। इसके नजीते अंतत: कनाडा को ही नुक्सान होगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

क्यों घसीटते हैं अंबानी और अडानी को...?

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐतिहासिक प्रसंग बताता हूं। इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में बजाज और बिड़ला का महान योगदान रहा है। एक बार रामनाथ गोयनका ने महात्मा गांधी से पूछा कि बापू आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये दोनों उद्योगपति बजाज और बिड़ला आपको निचोड़ रहे हैं? बापू ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें निचोड़ रहा हूं। आजादी की इतनी बड़ी जंग में कार्यकर्ताओं के आने-जाने, रहने और भोजन के प्रबंध में पैसा लगता है। इसके लिए खासकर ये दोनों परिवार पैसा खर्च कर रहे हैं।

इस प्रसंग को मैं इसलिए याद कर रहा हूं ताकि नई पीढ़ी को यह पता चल सके कि आजादी की लड़ाई में उद्योगपतियों का कितना योगदान रहा है। आजादी के बाद भारत के निर्माण में उद्योगपतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब कुछ राजनेताओं को औद्योगिक घराने पर हमला करते देखता हूं। आज जिसे देखिए वही अंबानी और अडानी समूह पर ऐसे हमला करता रहता है जैसे इन लोगों ने भारी भ्रष्टाचार किया हो। मैं नहीं जानता कि आरोपों में कितनी सच्चाई होती है लेकिन यदि कोई सच्चाई हो भी तो उसका निर्णय न्यायालय के कठघरे में होना चाहिए, न कि राजनीति के मैदान में।

राहुल गांधी हमेशा यह आरोप चस्पा करते रहे हैं कि अंबानी और अडानी समूह की प्रधानमंत्री के साथ नजदीकी है, आशय यही रहा है कि इनके विकास में सरकारी पक्षपात की भूमिका है। राहुल गांधी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, धीरूभाई अंबानी के तो इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से संबंध रहे हैं। दोनों ने एक-दूसरे की मदद की है। उद्योगपति तो वैसे भी अपनी क्षमता के अनुरूप सभी पार्टियों की मदद करते हैं, दुनिया के हर देश में ऐसा होता है। जापान में उद्योगपति यह तय करते हैं कि किस पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में भी उद्योगपतियों की राजनीति में भूमिका होती है। यह कोई नई बात तो है नहीं। हमारे यहां इस तरह की भी चर्चा होती है कि अंबानी और अडानी मूल रूप से गुजरात के हैं इसलिए उनके प्रति सरकारी रवैया सहानुभूति भरा होता है, मैं इस तरह की शंका को भी दरकिनार करता हूं।

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि राहुल गांधी इन दिनों अंबानी-अडानी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उनके पास टैम्पो भर-भर कर पैसा पहुंचा क्या? लोगों को आश्चर्य हुआ कि पीएम ने इस तरह से इन उद्योगपतियों का नाम लिया। मुझे भी इसीलिए इस विषय पर लिखने की जरूरत महसूस हुई। पीएम की टिप्पणी पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की लेकिन सवाल फिर वही है कि हम अपने उद्योगपतियों को राजनीति के मैदान में क्यों घसीटते हैं? क्यों उन्हें भ्रष्टाचारी साबित करने पर तुले रहते हैं? इस देश में उद्योगपति होना और अपने उद्योग का विकास करना क्या कोई अपराध है? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उद्योग स्थापित करना, चलाना और उसे एक बड़े मुकाम पर पहुंचाना और समूह को एक बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। धीरूभाई अंबानी की शानदार परंपरा को मुकेश अंबानी ने आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया लेकिन अनिल अंबानी नहीं बढ़ा पाए।

> **हम अपने उद्योगपतियों को राजनीति के मैदान में क्यों घसीटते हैं? क्यों उन्हें भ्रष्टाचारी साबित करने पर तुले रहते हैं? इस देश में उद्योगपति होना और अपने उद्योग का विकास करना क्या कोई अपराध है? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उद्योग स्थापित करना, चलाना और उसे एक बड़े मुकाम पर पहुंचाना और समूह को एक बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है।**

बिड़ला समूह की परंपरा को केवल कुमार मंगलम बिड़ला ही आगे ले जा पाए। अन्य बिड़ला पिछड़ गए, केशुब और हरीश महिंद्रा की शानदार परंपरा को आनंद महिंद्रा ने बढ़ाया। आज अडानी ने इतने कम समय में जो मुकाम हासिल किया है, वह आसान है क्या? निश्चय ही उद्योगों ने जो मुकाम पाया है, उसमें उनके मालिकों का समर्पण और उनकी तीक्ष्णता का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

मैंने राजनीति का लंबा दौर देखा है और हर दौर में राजनीतिक नजरिया उद्योगों के विकास का रहा है। पहले हमारे पास दुनिया के स्तर पर अपनी पहचान रखने वाला केवल टाटा और बिड़ला समूह हुआ करता था लेकिन आज दर्जनों कंपनियां दुनिया में भारत का नाम रौशन कर रही हैं। किसी भी उद्योग को विकसित होने के लिए सरकारी सहयोग की जरूरत होती ही है। जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जापान जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर जाते हैं और दूसरे देशों से कहते हैं कि इनका सहयोग कीजिए। हमारे यहां तो यह जुल्म जैसा है।

मैं इन दिनों अमेरिका-मैक्सिको की यात्रा पर हूं। कैलिफोर्निया की जिस सिलिकॉन वैली में मैं हूं, वह ऐसे उद्योगपतियों का गढ़ है जिनमें से कईयों की हैसियत कई देशों की जीडीपी के बराबर है। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यह बता सकूं कि यहां उद्योगपतियों को कैसे संभाला जाता है और हमारे यहां क्या हालत है? कई सारे उद्योगपति भारत छोड़ कर चले गए। यह अच्छी बात नहीं है, आज हिंदुजा, मित्तल, लोहिया, बागड़ी, अनिल अग्रवाल और बहुत से उद्योग या तो ब्रिटेन से या फिर दुबई से अपने समूह का संचालन कर रहे हैं। आखिर क्यों? यदि उद्योग नहीं होंगे तो रोजगार कैसे सृजित होगा? सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा?

संदर्भ के लिए बता दें कि भारत के जीडीपी में उद्योगों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 27 प्रतिशत से ज्यादा है। यदि टैक्स नहीं मिलेगा तो विकास कहां से होगा? सामाजिक विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? औद्योगिक संपन्नता के लिए पहली जरूरत है कि हम उद्योगपतियों की टोपी न उछालें बल्कि सच्चे अर्थों में उनके मददगार बनें, उद्योग बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा।

अमित शाह का अलग है अंदाज

आर.के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

अमित शाह राजधानी में अपने साउथ ब्लॉक के दफ्तर में जब काम करते होंगे, तब उनके जेहन में भी देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल का ख्याल अवश्य आता होगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने भी इसी साउथ ब्लॉक में बने गृह मंत्री कार्यालय से ही देश की आंतरिक सुरक्षा को एक नई दिशा दी थी। वे भी बोलने में कम और काम करने में अधिक यकीन करते थे। अमित शाह का एक गुण यह भी है कि वे किसी अनावश्यक विवाद को खत्म करने में देर नहीं करते। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पीएम संबंधी प्रश्न पर खुद अमित शाह ने साफ कर दिया कि नरेन्द्र मोदी ही 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

अमित शाह ने पहले भाजपा के संगठन में रहते हुए और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए उनके संगठनात्मक कौशल को सबने देखा, लेकिन जो लोग उन्हें गुजरात के दिनों से जानते थे, वे बहुत हैरान नहीं हुए। फिर, 2019 में, वह केंद्रीय गृह मंत्री बने और इसके साथ ही शुरू हुआ कई बड़े फैसलों को लेने का दौर। पिछले पांच वर्षों में, अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देखरेख में भारतीय दंड विधान (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को बदला गया। अमित शाह मानते हैं कि कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। 1860 से 2023 तक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। आपको याद होगा जब भारत अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे। नए आपराधिक कानून उनमें से एक को पूरा करते हैं। सरकार ने नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम दिया है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को प्रधानमंत्री का विश्वास और पूरा भरोसा प्राप्त है। वास्तव में, जब कोई राजनीतिक या सरकारी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष लाया जाता है, तो कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति से अमित शाह से भी सलाह लेने के लिए कहते हैं।

2019 में, गृह मंत्री बनने के तीन महीने बाद, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकारी कदम में सबसे आगे थे। इसके लिए कुशल राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता थी। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन हासिल था। चार साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वैधता को बरकरार रखा, जो कि भाजपा ने भारत के अंतिम एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा था।

अमित शाह 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की पीछे प्रेरक शक्ति भी रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई -जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं - उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आशंका थी कि सीएए को विपक्ष मुद्दा बनायेगा। पर यह नहीं हुआ। इसकी बेशक एक बड़ी वजह यह रही कि अमित शाह देश के मुसलमानों को भरोसा देता रहे कि सीएए कानून का उनसे कोई लेना-देना है। याद करें कि राजधानी के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ महिलाओं ने लंबा धरना दिया था। धरने देने वाली महिलाएं कह रही थीं कि सीएए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा।

धरना कोविड के फैलने के कारण सरकार ने सख्ती से बंद करवा दिया था। उस समय धमकी दी जा रही थी कि सीएए के खिलाफ धरना फिर शुरू होगा। पर यह नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बार-बार मुसलमानों को भरोसा देते रहे कि सीएए से उन्हें घबराने की कोई वजह नहीं है। इसका सकारात्मक असर हुआ। जब केन्द्र सरकार ने सीएए की पिछली 11 मार्च को अधिसूचना जारी की तो एक बार लगा कि इसका विरोध होगा। पर कहीं कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए की अधिसूचना के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सीएए को लागू करने के मसले को लोकसभा चुनाव में उठाएंगे। सीएए, एनआरसी और धारा 370 जैसे मुद्दे कांग्रेस के घोषणापत्र से ही गायब हैं। सीएए पर दिल्ली से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गया था और जल्दी ही यह हिंदू-मुस्लिम विवाद में बदला था। दिल्ली में सार्वजनिक संपत्ति को खूब नुकसान पहुंचाया गया और विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हुए थे। एक लोकतांत्रिक देश में हर मुद्दे पर विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी हक है। जबकि विधेयक में पहले दिन से कहा गया था कि यह केवल उन शरणार्थियों पर लागू किया जाएगा जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर थे।

> **छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित राज्यों में, सुरक्षा बल धीरे-धीरे उन क्षेत्रों में वापस आ रहे हैं जिन्हें कभी रेड जोन माना जाता था। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी।**

खैर, अमित शाह की सरपरस्ती में, आंतरिक आतंकवाद का खतरा भी कम हुआ है। इस्लामिक स्टेट का उदय, पहले सीरिया और बाद में अफगानिस्तान में, चरमपंथी प्रवृत्ति वाले कई युवाओं को विदेशी जमीन में युद्ध लड़ने के लिए देश से बाहर जाते हुए देखा गया। इससे 2014 में कट्टरपंथ और ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंग के नए खतरों के बारे में चिंता पैदा हुई थी, लेकिन गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां आज इनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित राज्यों में, सुरक्षा बल धीरे-धीरे उन क्षेत्रों में वापस आ रहे हैं जिन्हें कभी रेड जोन माना जाता था। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी।

लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नक्सलियों पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऐसा पिछले साल दिसंबर महीने में भी देखने को मिला था। अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा के कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। फिर वो चाहे, नक्सलवाद के खिलाफ हो या आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद और नक्सलवाद लोकतांत्रिक तरीके नहीं हैं और इन्हें समाप्त कर देना चाहिए।

हरियाणा: देवीलाल, हुड्डा परिवार के सदस्य चुनावी रण में; भजनलाल व बंसीलाल का कुनबा नदारद

चंडीगढ़, (पंजाब केसरी): हरियाणा के 1966 में पृथक राज्य बनने के बाद से इसकी राजनीति चार प्रतिष्ठित सियासी परिवारों- देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा- के इर्दगिर्द घूमती रही है। पहले हरियाणा के तीन लाल- देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल ने दशकों तक बारी-बारी से राज्य में शासन किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 2014 में अपने दम पर सत्ता में आने से पहले हुड्डा परिवार के हाथ में राज्य की कमान थी।

दो प्रसिद्ध लालों- पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और भजनलाल के रिश्तेदार वर्षों से संसदीय चुनावों में मैदान में उतरते रहे थे,लेकिन इस बार उन्हें उनकी संबंधित पार्टियों से टिकट नहीं मिला है।

हालांकि, 'ताऊ' देवीलाल के नाम से मशहूर पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के चार सदस्य हिसार और कुरूक्षेत्र सीट से चुनावी मैदान में हैं।

दिलचस्प है कि देवीलाल के परिवार के तीन सदस्य हिसार लोकसभा सीट से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे है। इनमें देवीलाल के बेटे और हाल में भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला, जननायक जनता पार्टी (जजपा) प्रमुख एवं देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला की विधायक पत्नी नैना चौटाला (57) और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के चचेरे भाई रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला (47) शामिल हैं। रवि चौटाला देवीलाल के दिवंगत बेटे प्रताप सिंह चौटाला के बेटे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने भी हिसार सीट से कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारने पर विचार नहीं किया। कुलदीप पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे हैं। कांग्रेस ने भिवानी-महेंद्रगढ़ से मौजूदा विधायक राव दान सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया है। श्रुति चौधरी 2009 में भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद चुनी गईं थी, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के धर्मबीर सिंह ने उन्हें हरा दिया था। इससे पहले, उनके दिवंगत पिता सुरेंद्र सिंह और दादा बंसीलाल कई बार भिवानी सीट से संसद पहुंचे थे। साल 2009 में भजनलाल हिसार से चुने गए थे। उनके निधन के बाद 2011 के उपचुनाव में उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने यह सीट जीती थी। वर्ष 2019 में कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर हिसार सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे और नौकरशाही से राजनीति में आए बृजेंद्र ने हराया था जो तब भाजपा के उम्मीदवार थे। अब कुलदीप और भव्या भाजपा में हैं, जबकि बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह हाल में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के गढ़ रोहतक से चुनाव मैदान में हैं। दीपेंद्र रोहतक से तीन बार सांसद रहे हैं और 2019 में वह भाजपा के अरविंद शर्मा से हार गए थे। इस बार भी उनके खिलाफ शर्मा ही हैं। कांग्रेस द्वारा भिवानी-महेंद्रगढ़ से टिकट न दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा, ''मुझे 2009 में मौका मिला और मैंने क्षेत्र के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया। एक विपक्षी सदस्य के रूप में मैंने अपने लोगों के मुद्दों को उठाना जारी रखा... पहले इस निर्वाचन क्षेत्र (भिवानी) की सेवा मेरे दादा और मेरे पिता ने की थी।'' इस बार टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला स्वीकार करना होगा।

उन्होंने कहा, ''मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि वे निराश न हों।'' हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे।

अमानतुल्लाह व पुत्र के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी

नोएडा, (पंजाब केसरी): नोएडा के फेज-1 थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप में हुई मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह के करीबी और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विधायक, उनके बेटे और एक अन्य आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (वारंट) भी जारी किया है। माना जा रहा है कि अब अमानतुल्लाह और उनके बेटे की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। पुलिस ने दर्ज एफआईआर में गैर-जमानती धाराएं भी जोड़ दी हैं। इसके चलते गिरफ्तारी के बाद बेल मुश्किल होगी। नोएडा पुलिस ने एफआईआर में कई संगीन धाराएं भी जोड़ दी हैं। अमानतुल्लाह खान, बेटे अनस और अबू बकर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। इस मामले में सोमवार को इकरार अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अमानतुल्लाह खान का मैनेजर है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से भी सभी का आपराधिक इतिहास मांगा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना फेज-1 पुलिस ने पहले दर्ज एफआईआर में धारा 427/323/504/506 लगाई थी। इसके बाद जांच की गई और सबूतों के आधार पर धारा 147/149/452/307/394/34 और 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट भी लगा दी गई है। इस मामले में वांछित इकरार अहमद को कालिंदी कुंज के बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। 50 वर्षीय इकरार अहमद के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि वह हापुड़ जिले का मूल निवासी है।

दुर्घटना में जान गंवाने वाले केरल के सैनिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सैंकड़ों लोग

कोझिकोड (केरल), (पंजाब केसरी): हिमाचल प्रदेश में एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैनिक पी. आदर्श को सोमवार को जिले के फेरोक के पास उनके पैतृक स्थान पर सैकड़ों लोगों ने श्रद्धाजंलि दी। एक रक्षा सूत्र ने यहां बताया कि फेरोक के पास चुंगम के रहने वाले 27 वर्षीय आदर्श की 10 मई को हिमाचल प्रदेश में सेना के एक वाहन पर चट्टान गिरने से मौत हो गई थी।

- **27 वर्षीय आदर्श की 10 मई को हिमाचल प्रदेश में सेना के एक वाहन पर चट्टान गिरने से मौत हो गई थी**

सैनिक का पार्थिव शरीर रविवार रात पास के कारीपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया और आज सुबह उनके पैतृक स्थान ले जाया गया। जब उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए उनके पैतृक स्थान पर रखा गया तो बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े थे। बाद में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि आदर्श की छह महीने पहले ही शादी हुई थी और वह शादी के कुछ दिन बाद ही ड्यूटी पर लौटे थे। वह पिछले सात वर्ष से भारतीय सेना में सेवारत थे। परिवार के एक सदस्य ने कहा, वह यहां सभी का प्रिय था। महज छह महीने पहले उसकी शादी हुई थी।''

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

चाबहार का समझौता

मध्य एशिया और व्यापक यूरेशिया क्षेत्र तक भारत का जुड़ाव बढ़ाने में ईरान का चाबहार बंदरगाह एक अहम कड़ी है. दस वर्षों के लिए इस बंदरगाह के प्रबंधन का जिम्मा भारत को मिलना न केवल ईरान के साथ गहरे होते संबंधों का परिचायक है, बल्कि इससे यह भी इंगित होता है कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है. हालांकि चाबहार परियोजना में भारत लंबे समय से सहभागी है, लेकिन यह पहला अवसर है, जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में ले रहा है. चाबहार के ठीक पड़ोस में चीन के सहयोग से पाकिस्तान अपने ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है. इस बंदरगाह और चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट-रोड परियोजना के साथ संतुलन स्थापित करने में चाबहार बड़ी भूमिका निभा सकता है. इसके माध्यम से ईरान के अलावा भारत का सीधा और आसान संपर्क अफगानिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्यों तथा विभिन्न यूरेशियाई देशों तक हो सकता है, जो पाकिस्तान की हेठी के साथ बाधित होता रहा है. उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने कुछ माह पहले ही चाबहार के रास्ते व्यापार करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया है. कुछ समय से ईरान और अरब देशों के संबंधों में सुधार आया है तथा वे सड़क और रेल मार्गों का साझा विस्तार की योजना बना रहे हैं. ऐसे में चाबहार अरब से जुड़ने का भी एक अहम जरिया बन सकता है. भारत ने चाबहार परियोजना में बड़ी मात्रा में साजो-सामान मुहैया कराया है. इसके अलावा उसने टर्मिनल निर्माण एवं विकास के लिए 85 मिलियन डॉलर के निवेश का वादा भी किया है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिये थे. इस कारण बंदरगाह का काम भी अवरुद्ध हुआ और भारतीय सहभागिता भी थम गयी. लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और 2018 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के भारत दौरे में यह एक प्रमुख विषय था. इस वर्ष जनवरी में विदेश मंत्री जयशंकर तेहरान गये थे. नेतृत्व और अधिकारी स्तर पर वार्ताओं के दौर का परिणाम है कि दीर्घकालिक समझौता साकार हुआ है. हालांकि पश्चिमी देशों और ईरान के संबंध अभी भी बहुत तनावपूर्ण हैं. लेकिन भारत की स्वायत्त विदेश नीति तथा सभी देशों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने की मंशा को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि चाबहार और उससे संबंधित परियोजनाओं पर अंतरराष्ट्रीय तनातनी का असर नहीं होगा. बंदरगाह से हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार तक मध्य एशिया की पहुंच के साथ-साथ भारतीय व्यापारियों एवं निवेशकों के लिए भी नये अवसर मिलेंगे.

यह पहला अवसर है, जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में ले रहा है.

मुद्दों से भटकाव लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

लोकतंत्र के असली चौकीदार भारत के लोग हैं. हर पांच साल बाद लोग बड़े घरों, फ्लैटों, गांवों, झुग्गियों आदि से भारी तादाद में निकलते हैं और शासक वर्गों के भाग्य का निर्धारण करते हैं. यह एक ऐसी सेना है, जो सरकार बना और हटा सकती है. भारत के लोग मतदान के दिन को सशक्तीकरण के दिन के रूप में देखते हैं, न कि सत्ता हड़पने के दिन के तौर पर. वे स्वच्छ वाणी और स्वच्छ शासन की अपेक्षा रखते हैं.

अब्राहम लिंकन ने कहा था, 'चुनाव लोगों का निर्णय होते हैं. अगर वे आग से मुंह मोड़ते हैं और शरीर के पिछले हिस्से को जला लेते हैं, तो उन्हें अपने घावों पर बैठना पड़ेगा.' थॉमस फ्रीडमैन का मानना था, 'जब लोकप्रिय नेता बिना सोचे-समझे कुछ भी कहने-बोलने लगते हैं, तो बड़े मुद्दों पर समझदारी से विचार कर पाना लोकतंत्र के लिए असंभव हो जाता है.' हमारे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में मुद्दे मर चुके हैं और वे अनर्गल प्रलापों के राजनीतिक कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं. अभद्रता हावी हो चुकी है. लड़ाई उच्च नैतिक आधार से शुरू हुई थी. वह लड़ाई 2047 में विकसित भारत बनाने और सभी के लिए न्याय के बीच थी. कई दिनों तक मुद्दे शासन में सक्षम सरकार चुनने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को तबाह करने वाली पार्टी को हराने के इर्द-गिर्द घूम रहे थे. भाजपा और प्रधानमंत्री ने अपने अभियान का प्रारंभ विकास के अस्त्र के साथ किया था. भगवा खेमे के नेता हर दिन 35 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने, सौ नये हवाई अड्डे बनाने, आतंकी हमले और सांप्रदायिक दंगे रोकने, रिकॉर्ड वृद्धि दर हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते महत्व जैसी एक दशक की सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कर रहे थे. 'मोदी की गारंटी' का स्वर्णिम संकल्प एक ऐसे नेता पर विश्वास का आह्वान था, जिसने वादों से कहीं अधिक काम कर दिखाया है. विपक्षी पार्टियां अतीत के अपने कार्यों तथा भविष्य के वादों तक सीमित थीं. जब मोदी ने भारत की समस्याओं के लिए गांधी परिवार को दोषी ठहराया, तो कांग्रेस ने इस पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक एवं औद्योगिक भारत की नींव उसके संस्थापकों द्वारा रखी गयी थी.

यहां तक तो सब ठीक था, पर जल्दी ही परिदृश्य बदल गया. नेताओं का ध्यान व्यापक परिप्रेक्ष्य से हट गया और वे मामूली मसलों पर झगड़ने लगे. चुनाव दो नकारात्मक आख्यानों के झंझट में बदल गया. आधी सीटों पर मतदान होने तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों के बीच का माहौल विषाक्त हो गया. नेता, समर्थक और प्रायोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जातिगत एवं सांप्रदायिक बातों को उठाकर बेशर्मी से प्रचार अभियान को गर्त में ले जाने लगे. यह चुनाव अब व्यक्तिगत झगड़ा बन गया है. अल्पसंख्यक, मंगलसूत्र और मंदिर राजनीतिक सलीब के घाव बन चुके हैं. चुनाव आक्रामक मोदी और प्रयासरत राहुल के बीच की लड़ाई बन गयी है. इस प्रक्रिया में मोदी ने राहुल और कांग्रेस को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के तौर पर परिभाषित किया है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शहजादा रफाल मुद्दे के नाकाम होने के बाद पांच उद्योगपतियों का नाम ले रहे थे और फिर वे अंबानी-अदानी कहने लगे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने ये दो नाम लेना भी बंद कर दिया है. मोदी ने आगे पूछा कि अंबानी और अदानी से कितने पैसे मिले हैं कि अब उनका नाम नहीं लिया जा रहा है. दाल में कुछ काला होने के मोदी के इस भाषण से उनके कट्टर समर्थकों को भी अचरज हुआ. लेकिन मोदी ने यह बात तेलंगाना में इसलिए कही क्योंकि हाल में वहां की कांग्रेस सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए अदानी समूह से करार किया है.

भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि यह चुनाव मोदी और राहुल के बीच है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि मतदाताओं को मोदी की 'भारतीय गारंटी' और राहुल की 'चीनी गारंटी' में से चुनाव करना है. शाह कट्टर भगवा गद्य का इस्तेमाल कर हिंदुत्व-आधारित विचारधारात्मक अभियान के लिए माहौल बना रहे हैं. वे भले तेलंगाना में बोल रहे थे, पर उनका संदेश देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए था. उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और एआइएमआइएम को 'तुष्टिकरण की तिकड़ी' बताते हुए कहा कि ये लोग तेलंगाना को शरिया और कुरान के आधार पर चलाना चाहते हैं. हैदराबाद में प्रचार करते हुए अभी-अभी भाजपा में आयीं महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा ने 2013 में अकबरूद्दीन ओवैसी के एक भाषण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंद्रह मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं. राणा ने कहा कि उनको तो पंद्रह मिनट लगेंगे, हमें तो बस पंद्रह सेकेंड लगेंगे. उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी माधवी लता हैदराबाद को पाकिस्तान नहीं बनने देंगी तथा कांग्रेस या एआइएमआइएम को वोट देना पाकिस्तान को वोट देना है. प्रमुख भाजपा नेता धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 'अबकी बार, 400 पार' के प्रधानमंत्री के नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोदी का मूल उद्देश्य नहीं था. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ओडिशा में कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि बाबरी मस्जिद दुबारा न बन सके तथा हम देश के हर मंदिर को मुक्त करायेंगे.

विपक्ष भी हमलावर है. शिव सेना (उद्धव ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने मोदी की तुलना औरंगजेब से की और प्रधानमंत्री के लिए वैसी ही परिणति की भविष्यवाणी की. राजनीति और एजेंसियों के दबाव से घिरीं ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं को 'लुटेरा' बताया, जो पश्चिम बंगाल को तबाह करना चाहते हैं. उन्होंने मोदी को 'इंसान-हत्या का सौदागर' कहा. इससे सोनिया गांधी के 'मौत का सौदागर' वाले बयान की याद आती है, जो उल्टा पड़ गया था. प्रियंका और राहुल गांधी भी सोशल मीडिया चुटकुलों और मंचों के निरर्थक बातों से मोदी का मजाक उड़ाने में बहुत पीछे नहीं हैं. क्या हमारे वाचाल नेता यह भूल गये हैं कि अनुचित बयानों और तरीकों से चुनाव नहीं जीते जाते? मोदी ने 2014 में भ्रष्टाचार विरोध के मुद्दे पर जीत हासिल की थी. राहुल गांधी के गढ़े नारे 'चौकीदार चोर है' के बावजूद 2019 में उन्हें बड़ा जनादेश मिला. लोकतंत्र के असली चौकीदार भारत के लोग हैं. हर पांच साल बाद लोग बड़े घरों, फ्लैटों, गांवों, झुग्गियों आदि से भारी तादाद में निकलते हैं और शासक वर्गों के भाग्य का निर्धारण करते हैं. यह एक ऐसी सेना है, जो सरकार बना और हटा सकती है. भारत के लोग मतदान के दिन को सशक्तीकरण के दिन के रूप में देखते हैं, न कि सत्ता हड़पने के दिन के तौर पर. वे स्वच्छ वाणी और स्वच्छ शासन की अपेक्षा रखते हैं. भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले विंस्टन चर्चिल ने दंभ से कहा था कि देश की सत्ता बदमाशों के हाथ में चली जायेगी और वे सब आपस में लड़ेंगे. अगर चर्चिल सही साबित होंगे, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा. सौभाग्य से, समृद्ध होता एकजुट भारत अभी सुरक्षित हाथों में है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

शेयर बाजार में मौजूदा हलचल के मायने

अभिजीत मुखोपाध्याय
अर्थशास्त्री
abhijitmukhopadhyay@gmail.com

विभिन्न कारकों की वजह से शेयर मार्केट में मौजूदा गिरावट देखने को मिल रही है. इस सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक यह स्थिति बनी रह सकती है. उसके बाद कुछ स्थिरता की अपेक्षा की जा सकती है.

बीते शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के प्रदर्शन ने निराशाजनक हफ्ते का संकेत दिया. करीब दो महीने में शेयर बाजार का यह सबसे खराब हफ्ता रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ) का वोलाटिलिटी इंडेक्स 11 सत्रों से लगातार बढ़ता जा रहा है. अप्रैल में यह कम रहा था, पर अब आशंका उच्च स्तर पर है. यह इंडेक्स निफ्टी 50 सूचकांक के शेयर मूल्यों के अग्रिम अनुमान के आधार पर अगले 30 दिनों में बाजार के उतार-चढ़ाव का आकलन करता है. एनएसई ने फरवरी 2014 में इंडिया वोलाटिलिटी इंडेक्स के आधार पर अग्रिम अनुबंधों का कारोबार करना शुरू किया था. वोलाटिलिटी इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स नकारात्मक तरीके से एक-दूसरे से संबद्ध हैं. इसका अर्थ है कि आम तौर पर ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं. जब निफ्टी 50 सूचकांक बढ़ता है, तो सामान्य रूप से वोलाटिलिटी इंडेक्स नीचे का रुख करता है. जब वोलाटिलिटी इंडेक्स नीचे जाता है, तो शेयर बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिलता है. अभी इंडिया वोलाटिलिटी इंडेक्स 19 के ऊपर है, तो यह माना जा रहा है कि इस सप्ताह भी स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल रहेगी, हालांकि सोमवार को बहुत मामूली सुधार देखने को मिला है.

कई विशेषज्ञों में इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि मौजूदा उथल-पुथल की मुख्य वजह लोकसभा चुनाव के परिणामों की अनिश्चितता है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल को पहले के अनुमानों से कहीं कम सीटें मिल सकती हैं. हालांकि आम तौर पर अभी भी यही अनुमान है कि सत्तारूढ़ दल को तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश मिलेगा, लेकिन सामान्य बहुमत नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इन सुधारों में मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना तथा चीन के एक संभावित विकल्प के रूप में वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करना शामिल हैं. भाजपा ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 400 से अधिक सीटें जीतने के दावे के साथ की थी, लेकिन अब लगने लगा है कि ऐसा परिणाम नहीं आयेगा. विभिन्न चरणों में मतदान प्रतिशत में कमी भी बढ़ती चिंता में योगदान कर रही है. चुनाव के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव असामान्य बात नहीं है. वर्ष 2019 में मतों की गिनती से पहले के एक महीने में वोलाटिलिटी इंडेक्स 20 प्रतिशत से अधिक हो गया था.

मौजूदा उतार-चढ़ाव में कुछ अन्य कारकों का भी योगदान है. पिछले महीने विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार बिकवाली की थी. इस बिकवाली की वजह यह थी कि तब यह साफ हो गया था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जल्दी कोई कमी नहीं करेगा. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है तथा रोजगार के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं. लेकिन मुद्रास्फीति अभी उस स्तर पर नहीं आयी है, जैसी फेडरल रिजर्व की इच्छा है. इसलिए फेडरल रिजर्व अभी इंतजार कर रहा है और इसके लिए उसे अच्छे सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार के बढ़ते अवसरों से महत्वपूर्ण समय भी मिल रहा है. अमेरिका में अधिक ब्याज दर होना हमेशा भारत समेत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी के पलायन के लिए कारक बन सकता है. इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने के संबंध में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए नये नियमों का प्रस्ताव रखा, जिससे देनदार और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में बेचैनी है. प्रस्तावित नियमों में कर्ज के बढ़ते दबाव की गहन निगरानी का प्रावधान भी है. यदि ये नियम लागू हो जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा लिये जाने वाले कर्ज का खर्च बढ़ सकता है. साथ ही, देनदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मुनाफे पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसी वजह से निवेशकों ने पिछले सप्ताह स्टॉक मार्केट खुलते ही बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयरों को भारी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया.

बीते सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को सार्वजनिक उपक्रम पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन के शेयरों के दाम में क्रमशः 12.6 और 8.9 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गयी. इसी प्रकार अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों, मसलन- एनबीसीसी, एचजी इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शन, के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गयी. निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को अधिक आघात सहना पड़ा. केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों के मूल्य में क्रमशः 7.8, 6.2 और 3.3 प्रतिशत की कमी आयी. एलआईसी को भी 5.7 प्रतिशत का झटका लगा. व्यापक उथल-पुथल के साथ-साथ इन सभी कारकों की वजह से शेयर मार्केट में मौजूदा गिरावट देखने को मिल रही है. इस सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक यह स्थिति बनी रह सकती है. उसके बाद कुछ स्थिरता की अपेक्षा की जा सकती है. तब तक स्टॉक मार्केट के निवेशकों, विशेष रूप से खुदरा निवेशकों, को खरीदारी और बिकवाली में सचेत रहना और संयम रखना चाहिए. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

ब्रिटेन में मानसिक स्वास्थ्य समस्या में वृद्धि चिंताजनक

ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित मानसिक कल्याण के नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ ब्रिटेन में भी मानसिक संकट का अनुपात सबसे अधिक हो गया है- उन 71 देशों में से जिनका आकलन किया गया है. उन देशों की तुलना में, जिनका आकलन किया गया है, ब्रिटेन में मानसिक स्वास्थ्य में अधिक गिरावट आयी है. यह आश्चर्यजनक है कि यह बात हेडलाइन क्यों नहीं बनी? इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट स्मार्टफोन और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन को जिम्मेदार मानता है. इसमें कोई शक नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने में इन दोनों की भूमिका है, परंतु ऐसा केवल ब्रिटेन में ही नहीं है. मुझे लगता है कि इसका एक कारण लोगों के भीतर इस भावना का होना है कि ब्रिटेन में लोगों का जीवन, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से पीछे की ओर जा रहा है. एक समय था जब ब्रिटेन में लगभग सभी लोग इन वादों पर विश्वास करते थे कि अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार सभी का जीवन स्तर ऊपर उठायेगी. सभी के पास एक अच्छा घर होगा. नौकरी की कठिनाइयां कम होंगी और नौकरियां अधिक दिलचस्प हो जायेंगी. लोग अधिक आर्थिक सुरक्षा और अधिक अवकाश के समय का आनंद उठा सकेंगे. सभी सामाजिक वर्गों के बीच शैक्षिक उपलब्धि बढ़ेगी. स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा. ब्रिटेन हमेशा के लिए स्वच्छ और हरा-भरा बन जायेगा. वर्ष दर वर्ष शासन और लोकतांत्रिक भागीदारी बेहतर होती जायेगी. आसानी से सभी चीजें उपलब्ध होंगी. पर इसकी बजाय लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया है. गरीबी, रुग्णता, शैक्षिक बहिष्कार, खराब आवास व ढहते बुनियादी ढांचे और खराब रोजगार या काम करने में असमर्थता बढ़ गयी है. देश में अव्यवस्था व अराजकता, चरम राजनीतिक शिथिलता और कुशासन, प्रभावशाली लोगों को छूट और शक्तिहीनों के प्रति क्रूरता भी पनप चुकी है.

-जॉर्ज मॉनबियोट

बोधि वृक्ष

प्रभावी ढंग से खुद को बदलें

वर्तमान में हम सभी अनिश्चितता और निरंतर पुनर्मूल्यांकन के ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां हम अपने भविष्य के लिए नयी रणनीतियों को खोजने की तलाश में निरंतर संघर्ष में रहते हैं. ऐसे हालात में यह कहना गलत नहीं होगा कि हम परिवर्तन काल की स्थिति में जी रहे हैं. आज शताब्दियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है और कुछ हद तक उनकी अनदेखी भी की जा रही है. तेजी से बदलते परिवेश के साथ लोगों का आकर्षण अब स्व-प्रबंधन एवं संकट प्रबंधन की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाह्य वातावरण का प्रबंधन करना अधिकांश लोगों के लिए शायद ही संभव है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा जोर अब अपने आंतरिक वातावरण के प्रबंधन पर दिया जा रहा है. जिसमें परिवर्तन नहीं है, वह जीवन ही क्या. हमें सदा सुखी व आनंदित रहने के लिए परिवर्तन को सहर्ष स्वीकारने की कला अपने अंदर धारण करनी चाहिए. किंतु अमूमन ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग परिवर्तन को स्वीकार करने के अनुकूल नहीं होते हैं, क्योंकि वे असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए साहसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि हम परिवर्तन का सफल नेतृत्व कर दूसरों के भीतर भी उसे लाने की प्रक्रिया का आरंभ कर सकें. आज की तारीख में 'परिवर्तन' ही असली खेल का नाम है. जिसने इस खेल में निपुणता हासिल कर ली, वह असीमित प्रगति करता जायेगा. सही समय की परख करने के बाद परिवर्तन करना समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति की पहचान है. एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी दुनिया में किसी भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए प्रभावी रूप से परिवर्तन का प्रबंधन न कर पाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. अतः जो लोग परिवर्तन का प्रभावी प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, वे न केवल अपने काम के मामले में, अपितु समाज में अपनी सार्थक भागीदारी के मामले में भी बेमानी हो जाते हैं. ऐसे में एक ही रास्ता है- पूरे मन से परिवर्तन की प्रक्रिया में सम्मिलित होना तथा उसका आनंद उठाना.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

क्रिकेट का मार्गदर्शक मंडल

आलोक पुराणिक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

सीनियर होना बहुत मुश्किल काम है. नये बच्चे कुछ समझते नहीं हैं. पुराने वक्त की इज्जत रहती नहीं है. पुराने दिन याद आते हैं और आफत इसलिए ज्यादा हो जाती है. पुराने लोगों की सबसे बड़ी आफत यही होती है कि हाय वो पुराने दिन ना रहे. रोहित शर्मा के पुराने दिन ना रहे. पुराने दिन किसी के भी ना रह सकते. वक्त और इंसान कभी एक से नहीं रह सकते. कवि, वकील और शराब- ये जितने पुराने हों, उतना ही ज्यादा असरदार होते हैं. पर यह बात क्रिकेटर के बारे में नहीं कही जा सकती. क्रिकेटर जो पुराने हो जाते हैं, वे या तो कॉमेडी करने लगते हैं, सिद्धू की कसम, या कमेंट्री करने लगते हैं, गावस्कर जैसे. जो ना कॉमेडी कर सकते, ना कमेंट्री, उनके लिए आफत है कि क्या करें.

सचिन तेंदुलकर भी इन दिनों कई किस्म के आइटम बेच लेते हैं. पर ऐसे कई हैं, जो कुछ भी ना बेच पाते. बेचाधिकार सबको मिलने चाहिए. जो कुछ ना बेच पाता, वह फिर भुनभुनाता है. इस मुल्क में जो कुछ नहीं कर सकता, वह भी भुनभुनाने के काम तो कर ही लेता है. तो बेचाधिकार से वंचित पुराने क्रिकेटर भुनभुना सकते हैं, बस छोटी सी आफत यह है कि भुनभुनाने के पैसे ना मिलते. पुराने क्रिकेटरों को ऐसे काम मिलने चाहिए, जिनसे कुछ पैसे भी मिलें. आइपीएल टूर्नामेंट में यह लगातार साफ हो रहा है कि पुराने वैसे रिजल्ट ना दे रहे जैसे रिजल्ट नये वाले दे रहे है. नये वालों का जलवा बेहतर हो रहा है. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है. एक वक्त की बहुत सुपरस्टार टाइप हीरोइन कुछ वर्षों बाद भाभी या मां के रोल में आ जाती है. जगह छोड़नी पड़ती है, आप चाहें या नहीं चाहें. क्रिकेटरों का भी यही हाल है. जगह छोड़नी पड़ती है. पर जगह कोई छोड़ना नहीं चाहता है. सिर्फ पॉलिटिक्स के कारोबार में यह संभव है कि बंदा अस्सी पार जाकर भी अड़ा रहे कि मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा. भतीजे अजित पवार कुड़कुड़ाते रह जाते हैं, चाचा शरद पवार यही कहते हैं- हम हूं ही ना, बल्कि हमीं हूं, और कौन आयेगा.

चुनाव जैसे-जैसे आगे जा रहे हैं, वैसे तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. औरंगजेब की इलेक्शन ड्यूटी भी लग गयी है. महाराष्ट्र में संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब गुजरात में पैदा हुए थे, उनका इशारा गुजरात आधारित नेताओं पर व्यंग्य करने का था. पर राउत की यह बात सुनकर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा भी दुखी हो सकती है कि उन्हें गुजरात का माना जाता है, इसलिए वह औरंगजेब के लेवल पर रखे जा रहे हैं. औरंगजेब बहुत वर्षों पहले चले गये, पर वह गये नहीं हैं.

आपके पत्र

राजनीति में हावी हुआ परिवारवाद

देश की राजनीति में परिवारवाद हावी होता जा रहा है. यह रोग किसी एक दल का नहीं है. लगभग सभी दलों ने राजनेताओं के बेटे या संबंधियों को लोकसभा में टिकट दिया है. इसको रोकने के लिए आम लोगों को ही आगे आना होगा. चुनाव के दौरान ऐसे नेताओं को वोटर नकार दें, तभी इस पर रोक लगेगी. किसी भी दल के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं कि पार्टी उनको आगे बढ़ायेगी. लेकिन, चुनाव आते ही हवाई नेता उनके बीच उतार दिया जाता है. इससे कार्यकर्ताओं में हताशा होती है, जबकि कार्यकर्ता के बिना कोई भी दल मजबूत नहीं हो सकता.

संतोष कुमार, सीतामढ़ी

लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी

लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है. यदि विपक्ष कमजोर होता है, तो सत्ता निरंकुश हो जाती है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. विपक्ष सत्ता के जनविरोधी नीतियों का तर्कसंगत विरोध करता है और इसे आम लोगों के बीच ले जाता है. लेकिन, हाल के दिनों में ऐसा वातावरण बना है कि सत्ता के विरोध में बोलनेवालों को तरजीह नहीं दिया जाता है. विपक्ष को भी तर्कसंगत तरीके से सत्ता के विरोध में बात रखनी चाहिए. इसमें भाषा की गरिमा का भी ध्यान रखना जरूरी है.

हर्षवर्धन 'हर्ष', इमेल से

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें** : patna@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

परीक्षा परिणाम

अपने देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। समग्रता में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे हैं। 10वीं में 93.60 प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली है। कुल 22,38,827 विद्यार्थियों में 20,95,467 उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं के परिणाम भी बेहतर हैं, 87.98 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 10वीं के परिणामों की बात करें, तो इस साल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2023 में 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत 92.12 था, पर इस साल पास प्रतिशत 93.60 है। इस बार भी लड़कियों की सफलता का प्रतिशत अच्छा रहा है। जहां 92.71 प्रतिशत लड़कों को सफलता मिली है, वहीं सफल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत 94.75 और सफल होने वाले ट्रांसजेंडर का प्रतिशत 91.30 है। ट्रांसजेंडर और लड़कियों के बीच पढ़ाई की लगातार बढ़ती जागरूकता सुखद है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 10वीं या 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई पर कोरोना और लॉकडाउन का भयानक काला साया देखा है। अब आने वाले वर्षों में हम ज्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं।

इन परिणामों के आधार पर अगर स्कूलों की गुणवत्ता को देखें, तो एक बार फिर जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने सबसे बेहतर 99.09 प्रतिशत प्रदर्शन किया है। निजी व स्वतंत्र स्कूलों के भी 94.54 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए हैं। सरकारी स्कूलों में सफलता का प्रतिशत 86.72 है। यह सवाल फिर एक बार प्रासंगिक हो गया है कि क्या सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के स्तर का बनाया जा सकता है? सरकारी स्कूलों और विशेष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त इन स्कूलों के 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत बच्चों को अगर कामयाबी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है, इन स्कूलों में प्रत्येक दस में से एकाधिक बच्चों की पढ़ाई चुनौती है। ऐसे बच्चों के बीच अध्ययन होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में अगर सौ में से शायद कोई एक विद्यार्थी ही विफल होता है, तो इनकी तारीफ करने के साथ ही, इनके बुनियादी ढांचे और पढ़ाई से सीखने की जरूरत है। ताजा परिणाम फिर इशारा हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शैक्षणिक माहौल में भी सुधार की जरूरत है। सरकारी स्कूलों के साथ चलताऊ व्यवहार अब छोड़ देना चाहिए।

ताजा परिणाम फिर इशारा हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शैक्षणिक माहौल में भी सुधार की जरूरत है।

दक्षिण भारत के स्कूलों का प्रदर्शन उत्तर भारत के स्कूलों से बहुत बेहतर है। परीक्षा देने वाले ज्यादातर बच्चों के बीच खुशी का माहौल है और 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,12,384 है, जबकि 95 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 47,983 है। मतलब ढाई लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पर जिन विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम अंक मिले हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें निराश हो जाना चाहिए। जिन्होंने अपेक्षाकृत कम अंकों के साथ 10वीं पास किया है, उनके पास 12वीं की परीक्षा ज्यादा बेहतर अंकों के साथ पास करने का मौका है। 10वीं और 12वीं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों ने भी आगे जिंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ये परीक्षा परिणाम तो महज एक पड़ाव हैं, इनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

अमन-चैन से सरकार चुन रहा कश्मीर

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उसका नतीजा जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्वक चल रहे मतदान में साफ दिख रहा है।

साल था 1993 और महीना जनवरी का, जब कश्मीर घाटी में चिल्ला-ए-कलां की सर्दियां और आतंकवाद अपने उरूज पर थे। घाटी में मेरी तैनाती का तीसरा दिन था और मेरे पूर्वाधिकारी मुझे इलाके से परिचित कराने के लिए बांदीपुर के पास मलनगाम नामक बड़े से पहाड़ी गांव पर लेकर गए थे। सुलग रहे तत्कालीन कश्मीर से उस पहले साक्षात्कार की एक बात जो मुझे आज भी याद है, वह यह है कि हमारे इर्द-गिर्द एकत्र ग्रामीणों ने बातचीत करते समय बताया था कि घाटी में भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे हैं। यह मेरे लिए एक आश्चर्यजनक सूचना थी, पर आज चुनावों के मौके पर याद आ रही है। ग्रामीणों के बीच मोरारजी भाई की लोकप्रियता का राज आम चुनावों में निहित था, इसीलिए आज भी प्रासंगिक है।

आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित तो हुआ, पर असाधारण घटनाक्रम के बाद। यह भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था कि जितनी तकलीफदेह विलय की प्रक्रिया थी, उससे कम चुनौतियां इस सीमावर्ती राज्य में भविष्य में निष्पक्ष चुनाव कराने में नहीं आईं। लगभग सारे आम चुनावों में धांधलियों के आरोप लगते रहे। चुनावों के दौरान एक आम दृश्य यह होता था कि सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध लड़ रहे ज्यादातर उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो जाते थे और सत्ता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता था। धांधलियों के आरोपों के बीच जून 1977 के विधानसभा चुनाव पहले चुनाव थे, जिन्हें आम तौर से साफ-सुथरा माना गया। उन दिनों मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला बहुत लोकप्रिय न होने के बावजूद बड़े बहुमत से चुनाव जीते थे। उन्हें जनता का विशाल बहुमत सिर्फ इसलिए मिला कि मतदाताओं के बीच प्रचार हो गया कि नई दिल्ली उन्हें हारता हुआ देखना चाहती है। इन चुनावों में कोई धांधली नहीं हुई और इससे मोरारजी देसाई की

मकबूलियत खूब बढ़ी और इसी कारण मलनगाम में मुझे वह प्रतिक्रिया मिल रही थी, जो मेरे लिए भी कम चौंकाने वाली नहीं थी और आज भी याद आ रही है।

जम्मू-कश्मीर के हालिया चुनाव कई अर्थों में पहले के चुनावों से भिन्न हैं। एक तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं और दूसरे, ये उस समय हो रहे हैं, जब राज्य का एक बड़ा भूभाग लद्दाख अब एक पृथक केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है। यह हाल के दिनों का पहला मौका है, जब चुनावों के बहिष्कार का कोई बड़ा आह्वान नहीं किया गया है। कश्मीरी जनता ने उस कुप्रचार को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद उसके और भारतीय गणराज्य के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सकेंगे। इन चुनावों में जितनी बड़ी चुनावी सभाएं हुईं, जितने उत्साह से लोगों ने मतदान में भाग लिया और जितनी कम हिंसा हुई, वह कुछ दिनों पहले तक अकल्पनीय थी। साल 2019 के पिछले आम चुनावों के दौरान बहिष्कार की आवाज इतनी मजबूत थी कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में तो सिर्फ नाम मात्र के मत पड़े थे। इस बार न सिर्फ क्षेत्रीय, बल्कि राष्ट्रीय दलों को भी अपनी बड़ी सभाएं करने का मौका मिल रहा है और अब तक जितने चरणों के चुनाव हुए, सबमें पहले के मुकाबले बंपर मतदान हुआ है। मतदान में धांधली के कोई बड़े आरोप अभी तक नहीं लगे हैं। इसका एक कारण तो शायद यही है कि वे सभी पृथकतावादी नेता जेल मे हैं, जो चुनाव के मौके पर बहिष्कार की अपील किया करते थे। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उसका नतीजा अभी तक हो चुके मतदान चरणों के शांतिपूर्वक संपन्न होने में दिख रहा है।

चुनावी प्रक्रिया में जनता की बढ़ती भागीदारी के पीछे एक दिलचस्प कारण हमारे पड़ोस में हाल में घटित घटनाएं भी हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में भी आम चुनाव हुए और तमाम धांधलियों के बावजूद बमुश्किल एक कमजोर सरकार वजूद में आ सकी। देश के दो मजबूत इदारों, न्यायपालिका और फौज ने खुलेआम चुनाव आयोग से मिलकर इमरान खान को हराने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हुए। उनके हस्तक्षेप के बावजूद जनता ने इमरान की पार्टी को नेशनल असेंबली में अकेली सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। पहले से आर्थिक बदहाली का शिकार देश पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है और बड़ी मुश्किल से आईएमएफ की मदद से अपने कर्जे चुका पा रहा है। ऐसे में, स्वाभाविक है कि घाटी में पाकिस्तान समर्थक विमर्श धीरे-धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है।

एक विदेशी अखबार में प्रकाशित कश्मीरी छात्र का इंटरव्यू इस सोच को भली-भांति अभिव्यक्त करता है। पहले पाक समर्थक पृथकतावादी आंदोलनों में भाग लेने की स्वीकारोक्ति करने वाला यह छात्र इस चुनाव में वोट डालने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की परिस्थितियां उसे निराश कर रही हैं। उसकी यह समझ बनी है कि आर्थिक अवसरों से भरपूर एक धर्मनिरपेक्ष भारत उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय एक इस्लामी पाकिस्तान के, जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

साल 2024 के चुनाव कई मामलों में भारतीय गणराज्य को अद्भुत अवसर प्रदान करने वाले हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिसंबर 1989 में धधक उठी आतंकवाद की ज्वाला किसी शून्य से नहीं उपजी थी। इसका तात्कालिक कारण 1987 के वे चुनाव थे, जिनमें जमकर धांधली हुई थी। इन चुनावों में जनता को बिना किसी दबाव या भय अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देकर हम उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शरीक होने का मौका देंगे।

अब समय आ गया है कि कश्मीरी जनता को उनका सांविधानिक अधिकार वापस किया जाए। विधानसभा की सीटों का परिसीमन पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 2024 के चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार की प्राथमिकताओं में जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली पहली प्राथमिकता होगी। यह भी हमेशा याद रखने की जरूरत है कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत से ही कश्मीर का रिश्ता अटूट रहेगा। निष्पक्ष चुनाव पिछली गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। अब तक तो लग यही रहा है कि ये चुनाव जनता को एहसास कराने में सफल होंगे कि उनके मताधिकार पर कोई डाका नहीं डालेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पक्षियों की परवाज में बदलाव आपदा का संकेत तो नहीं

आनंद बनर्जी | वन्यजीव संरक्षणवादी

भारतीय वन सर्वेक्षण ने इसी 12 मई को बताया है कि बीते एक हफ्ते में जंगल में आग लगने की 342 बड़ी घटनाएं देश भर में दर्ज की गईं, जिनमें से 209 तो अकेले उत्तराखंड की थीं। ये आग अमूमन मानवीय लापरवाही या शरारती तत्वों के कारण लगीं। ऐसी आग तब बेकाबू हो जाती है, जब सूखी भूमि का सामान्य से अधिक तापमान वाली हवा के साथ संयोग होता है। उल्लेखनीय है, मार्च से जून तक का समय पक्षियों के लिए प्रजनन का चरम वक्त होता है। ऐसे में, जंगल की आग प्रजनन वाले पक्षियों पर अभूतपूर्व असर डालती हैं। छोटे-बड़े तमाम जीवों पर इनका खासा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था पर इसके असर की कल्पना करना काफी कठिन है।

साफ है, गरम होती दुनिया पक्षियों का जीवन भी बदल रही है। विशेषकर, भोजन और आश्रय के लिए सर्द उत्तरी अक्षांश से उष्णकटिबंधीय, यानी गरम क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी पक्षियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। चूंकि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, इसलिए साल भर भोजन उपलब्ध हो, तो पक्षियों की कुछ प्रजातियां कठिन यात्राएं शायद ही करेंगी। बेशक, पक्षियों का प्रवासन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसी रिपोर्टें हैं, जो बताती हैं कि अपने प्रजनन-काल में पक्षी अमूमन जहां जाया करते थे, अब उनमें से कई नहीं जाते। अगर आप दिल्ली के ओखला पक्षी अभयारण्य घूमने जाते रहे हों, तो आपने देखा होगा कि आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले कई पक्षी अब तक यहां नहीं आए हैं। इस साल तो कीटों पर भी ध्यान दिया गया, जिनकी आबादी मूलतः कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग और प्रकाश प्रदूषण के कारण घट रही है।

कई रिपोर्ट बताती हैं कि अपने प्रजनन काल में पक्षी जिन जगहों पर अमूमन आया करते थे, अब उनकी आमद में कमी हो रही है।

जाहिर है, प्रवासी पक्षियों और उनके भोजन-स्रोतों का आपसी समय मेल नहीं खा रहा। इससे पक्षियों की आबादी में संकुचन या विस्तार हो सकता है। आलम यह है कि तमाम प्रकार की चीजों को खाने वाली और हर वातावरण में अनुकूलन करने वाली प्रजातियां बढ़ रही हैं और खास आबोहवा में रहने वाली व खास आहार वाली प्रजातियां कम हो रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण बैंक मैना है, जो अब टोल प्लाजा व रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा दिखती है, क्योंकि इसका प्राकृतिक आवास बाढ़ और विकास की भेंट चढ़ गया है। दरअसल, पक्षियों को ट्रैक करने के उपकरणों ने पक्षी विज्ञानियों को दुनिया भर में पक्षियों के प्रवासन को जानने का मौका दिया है कि किस तरह पक्षी मौसम के अनुसार उत्तर से दक्षिण जाते हैं? आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय उप-महाद्वीप सर्दियों में 600 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर बनता है, लेकिन इनमें से 240 प्रजातियों की आमद घटती जा रही है। हालांकि, विदेशी पक्षी बार-हेडेड हंस के मामले में लाभ की स्थिति है। बेशक, भारत की आबोहवा विदेशी पक्षियों के लिए विविध परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं, लेकिन इन पर विकास योजनाओं की गाज गिर रही है। चरम मौसमी घटनाओं ने ही नहीं, बढ़ते तापमान ने भी पक्षियों के आवास को खत्म किया है। ऐसे में, बैंक मैना या बार-हेडेड हंस की तरह अन्य प्रजातियां भी नए माहौल में अनुकूलन कर पाती हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी!

'स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स (2023) रिपोर्ट' कहती है कि पिछले आठ वर्षों में कम से कम 217 प्रजातियां या तो स्थिर हुई हैं या उनमें वृद्धि हुई है और 204 प्रजातियों में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, खुले पारिस्थितिकी तंत्र, नदियों और तटों पर रहने वाले पक्षियों की प्रजातियां सर्वाधिक घटी हैं, लेकिन जैसे-जैसे प्रवासन का पैटर्न बदल रहा है, हमें जनसंख्या अनुमान मॉडल का या तो विस्तार करना चाहिए या इसे नया गढ़ना चाहिए।

साल 2024 के चरम मौसम को एक वैश्विक खतरा मानना होगा। हिंद महासागर भी स्थायी गरम लहरों में तब्दील हो रहा है। पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में अप्रैल में काफी ज्यादा तापमान जलवायु संकट की गंभीरता ही बताता है। मगर क्या सिर्फ हमारे अस्तित्व के लिए ही जलवायु परिवर्तन पर बात होनी चाहिए? नहीं, हम उन तमाम जीव-जंतुओं से भी जुड़े हुए हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनके प्रति उतना ही संजीदा होना चाहिए, जितना हम अपने लिए हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

यथार्थ से आमना-सामना

यह सवाल बहुत स्वाभाविक है कि क्या आपने यथार्थ का साक्षात्कार कर लिया है? क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वर क्या है? मैं पूछता हूं, आप कैसे जानते हैं कि मैंने साक्षात्कार कर लिया है? यह जानने के लिए तो आपको खुद भी साक्षात्कार करना होगा। मैंने जो कहा, वह कोई चतुराई से भरा उत्तर नहीं है। किसी अवस्था को जानने के लिए आपको भी उसी स्थिति में होना चाहिए। आपको भी वही अनुभव होना चाहिए, इसलिए साफ है कि आपके इस कथन का कोई अर्थ नहीं है।

आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, यथार्थ क्या है? क्या अवर्णनीय को शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या असीम को मापा जा सकता है? क्या आप वायु को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? और यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो क्या वह वायु है? यदि अपरिमेय को आप मापते हैं, तो क्या वह यथार्थ है? यदि आप उसका प्रतिपादन करते हैं, तो क्या वह यथार्थ है? एकदम नहीं, क्योंकि जब आप किसी अवर्णनीय तत्व का वर्णन करते हैं, तो वह यथार्थ नहीं रहता। जिस क्षण आप अज्ञेय को ज्ञात में अनूदित करते हैं, वह फिर अज्ञेय नहीं रह जाता। फिर भी हम अज्ञात को जानने के लिए लालायित रहते हैं। सोचते हैं कि तभी हम चरम प्रसन्नता को, स्थायित्व को हथिया सकने में सफल होंगे। हम ज्ञान चाहते हैं, क्योंकि हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम बुरी तरह संघर्षरत हैं, हम थक गए हैं, पस्त हो गए हैं। फिर भी हम इस साधारण से तथ्य से परिचित नहीं होते कि हम पतनोन्मुख हैं। हमें जो ज्ञात है, उससे दूर हटकर हम अज्ञात की ओर बढ़ना चाहते हैं। वह अज्ञात पुनः ज्ञात बन जाता है और इसलिए हम कभी भी यथार्थ को नहीं पा सकते।

अतः किसने साक्षात्कार कर लिया है या ईश्वर क्या है, यह पूछने के बजाय आप अपना सारा ध्यान, पूरी जागरूकता, 'जो है' उसी को क्यों नहीं देते? तब आप अज्ञात को खोज लेंगे, या यह कहें कि वह आपके पास आएगा। यदि जो ज्ञात है, उसे आप समझ लेंगे, तो आप उस मौन का, उस अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे, जो थोपी हुई नहीं है और फिर अनुभव करेंगे उस

क्या अवर्णनीय को शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या असीम को मापा जा सकता है? क्या आप वायु को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? और यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो क्या वह वायु है?

सर्जनशील रिक्तता का, केवल जिसके रहते यथार्थ का आगमन संभव है। यथार्थ उस तक नहीं आएगा, जो कुछ बनने में लगा है, संघर्षरत है; वह केवल उसी तक आ पाता है, जो विद्यमान है, जो बस है, जो उसे समझ रहा है 'जो वस्तुतः है।' तब आप देखेंगे कि यथार्थ कहीं दूर नहीं है, अज्ञात दूर नहीं है, 'जो है', उसी में वह है।

जैसे किसी समस्या का उत्तर समस्या में ही निहित होता है, उसी प्रकार यथार्थ भी 'जो है', उसी में होता है। यदि हम इसे समझ सके, तो सत्य को जान लेंगे।

जे कृष्णमूर्ति

अल्लू अर्जुन | अभिनेता

अपना वोट अवश्य डालें। हमारे लिए यह बहुत जिम्मेदारी भरा समय है। मैं जानता हूं कि गरमी है, मगर थोड़ा प्रयास कीजिए। आपका एक दिन देश के अगले पांच वर्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 14 मई, 1949

इजरायल को मान्यता

यहूदियों ने आखिर अलग राष्ट्र स्थापित करने की अपनी कल्पना को चरितार्थ कर दिखाया। जो बात दलीलों अथवा बहस से नहीं बनी, वह तलवार की नोक पर मनवा ली गई। फिलस्तीन में यहूदियों ने ब्रिटेन की सत्ता को खुली चुनौती दी और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ब्रिटेन के लिए फिलस्तीन पर अपना शासन कायम रखना मुश्किल हो गया। ब्रिटेन को फिलस्तीन से हट जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इधर ब्रिटेन की सत्ता ने फिलस्तीन से मुंह मोड़ा और उधर यहूदियों ने इजरायल के नाम से अपने पृथक राष्ट्र की स्थापना कर डाली। यह बड़े दुस्साहस का काम था। किन्तु यहूदियों को दुनिया की बड़ी ताकतों का समर्थन प्राप्त था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलस्तीन के विभाजन की योजना को मंजूर किया था, इसलिए इजरायल को दुनिया के लोकमत का नैतिक समर्थन मिल गया। इजरायल का मार्ग सरल न था। अरब राष्ट्रों के संयुक्त विरोध का उसे सामना करना पड़ा, किन्तु वह खम ठोक उस विरोध का मुकाबला करने को डट गया। दुनिया ने आश्चर्य के साथ देखा कि नवजात इजरायल ने अरब राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति को भी पराजित कर दिया और हमलावरों को स्वयं अपने बचाव की फिक्र करनी पड़ी। अरब राष्ट्रों को धीरे-धीरे वास्तविकता का अनुभव होने लगा और उन्होंने समझ लिया कि वे अपने बीच यहूदी राष्ट्र की स्थापना को नहीं रोक सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच-बचाव का लाभ उठाकर उन्हें एक के बाद एक इजरायल के साथ विराम-संधि करनी पड़ी। इजरायल की यह पहली बड़ी जीत थी।

अब इजरायल ने दूसरी बड़ी विजय हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने संघ का सदस्य बनने की इजरायल की प्रार्थना को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ का ५९वां सदस्य होगा। संघ द्वारा इजरायल को मान्यता देने का अर्थ स्पष्ट है। अब उसके अस्तित्व को कोई आसानी से चुनौती न दे सकेगा। यह मान लिया गया है कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों और विधान को मानता है और सदस्य राष्ट्र पर जो जिम्मेदारियां आती हैं, उन्हें पूरा करने की क्षमता रखता है। अरब राष्ट्रों के लिए इजरायल एक कड़वी घूंट है, जिसे उन्हें जबर्दस्ती गले उतारना पड़ रहा है। उनके और इजरायल के बीच सीमाओं का निर्धारण अभी शेष है।

केदारनाथ के दृश्य गंभीर खतरे के संकेत

केदारनाथ के कपाट खुलने पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसे गंभीर संकट का आगम जानना चाहिए। हमारे धाम, विशेष क्षेत्र में विशेष नियमों से बांधे गए हैं, जो मूल रूप में ऋतु से बंधे सृष्टि के नियम हैं। मगर जो नया हिंदुत्व है, वह सनातन दर्शन को जानने-समझने और आत्मोत्थान के पुरुषार्थ-चतुष्टय को मानने वाला आचरण और विचार नहीं रखता है। इसमें आस्था धार्मिक विश्वास से अधिक प्रदर्शन का विषय बन गई है। लोगों में अपनी आधी-अधूरी समझ से कर्मकांड, मान्यताओं का कुतर्की विश्लेषण कर नए-नए आचरण स्थापित करने की होड़ मची है। बहुत कम लोगों में गंभीरता और निष्ठा दिखती है।

हिमालय क्षेत्र में साधना के नियम हैं। बद्रीनाथ में शंख तक नहीं बजाया जाता है। कोलाहल, प्रदूषण नियंत्रण के इतने उच्च मानक पारंपरिक रूप से रखे गए हैं। मगर केदारनाथ में जिस तरह ढोल-नगाड़ा बजा और अंधाधुंध भीड़ के साथ उच्चतम स्तर पर नारों का शोर सुनाई दिया, उससे ईश्वर तो प्रसन्न नहीं ही होंगे, उल्टे वहां की सूक्ष्म ऊर्जा का लय जरूर बिगड़ जाएगा। वास्तव में, देवता ऊर्जा के पुंज होते हैं, जिन्हें भारतीय मनीषा ने अध्यात्म के चरम स्तर पर जाकर समझा है। यदि इस बिंदु पर खड़े होकर भी हम नहीं चेते, तो फिर अवसर भी नहीं मिलने वाला और इसके दोषी सिर्फ हम होंगे, कोई दूसरा नहीं।

ऊर्जा केंद्रों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़, अतिक्रमण या किसी भी प्रकार के प्रदूषण, कोलाहल पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। ये क्षेत्र दुर्गम ही रहने चाहिए। हमें समझना होगा कि ऐसे अध्यात्म साधना क्षेत्र सूक्ष्म जगत के प्राणियों के साधना स्थल हैं। उन्हें तंग करने का तमाशा बंद होना चाहिए, अन्यथा परिणाम शीघ्र ही सामने होगा। जो जहां है, वहीं धर्माचरण करे। जप, ध्यान, साधना, भजन, सत्संग करे। गुरु, मंदिर, यथायोग्य पात्र की सेवा करे। यथोचित प्रकृति अनुरूप व्यवहार करे। दैवी शक्तियों की कृपा प्राप्त होगी। हर किसी की परंपरा में दोष निकालने के लिए जबरन विशेषज्ञ बनने वाले, भोज्य-अभोज्य, पहनावा, परंपरा, रीति-रिवाज पर विरोध में झंडा बुलंद करने वालों को इस प्रकार का तमाशा नहीं दिखाई देता, जिसका दुष्प्रभाव पूरे देश, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और पर्यावरण पर होगा! किसी भी क्षेत्र के स्थानीय नियम और अधिकार-क्षेत्र में टांग अड़ाने, मौज-मस्ती ढूंढ़ने की प्रवृत्ति अनुचित है। यदि यह समझ आ जाए, तो ठीक, अन्यथा प्रकृति तो समझा ही देगी, लेकिन वह समझाने की जो कीमत लेगी, वह बहुत बड़ी होगी।

अभिलाषा द्विवेदी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

आस्था या पर्यटन

इसे लोगों की भीड़ नहीं, आस्था कहिए

विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद खोल दिए गए। इस अवसर पर आस्था का मानो सैलाब उमड़ आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर के गवाह बने। लोगों में जोश इतना था कि हर तरफ बाबा केदार के जयकारे लग रहे थे। ढोल-नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। ये सब मानो स्वतः स्फूर्त था। यह एक अलग तरह का रोमांच था, जिसे सभी दर्शनाथी महसूस कर रहे थे। आखिर यह रोमांच हो भी क्यों नहीं? बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां जमा हो गए थे। कपाट खुलने के बाद बाबा केदारनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना हुई और भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश की गई। यह नए भारत का संकेत है। यह बताता है कि लोग अब अपनी आस्था को खुलकर जाहिर करने लगे हैं। वे अब किसी से दब-छिपकर अपनी आस्था का पालन नहीं करते। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों में यह भरोसा क्यों आया है?

कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। उनको लगता है कि इससे यहां की प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। उनके मुताबिक, प्रकृति इसका बदला ले सकती है? ये सब बातें वास्तव में आस्थावान लोगों में भय पैदा करने के लिए कही जा रही हैं? बाबा केदार अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं हो सकते। अगर कुछ अधिक संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं, तो भला इसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी, केदारनाथ धाम बिल्कुल खुला हुआ है। ढोल अथवा नगाड़े की ध्वनि से जो नाद उत्पन्न हो रहा था, उसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है, जो केदार का भक्त हो। वे स्वर लोगों के अंतर में उतर रहे थे और सभी केदारनाथ की आस्था की गंगा में डूबकी लगा रहे थे।

ऐसे आयोजनों पर सवाल उठाकर हमें श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट नहीं करनी चाहिए। यह सही बात है कि प्रकृति है, तभी हम हैं, लेकिन अब प्रकृति के प्रति लोग पहले से अधिक संजीदा हो गए हैं। वे समझ गए हैं कि हमें प्रकृति की हरसंभव रक्षा करनी होगी, तभी हमारी भी रक्षा हो सकेगी। इसलिए, यह नहीं कह सकते कि जान-बूझकर ऐसा आयोजन किया गया और स्थानीय पारिस्थितिकी को जान-बूझकर खतरे में डाला गया। यह सब आस्था का मामला है और इसे आस्था की नजर से ही देखना चाहिए। एक दिन का आयोजन शायद ही स्थानीय प्रकृति के लिए कथित तौर पर नुकसानदेह हो सकेगा। यह बात कथित पर्यावरणविदों को भी समझ लेनी चाहिए।

दीपक रस्तोगी, टिप्पणीकार

https://epaper.livehindustan.com

दैनिक जागरण

संग्रह का लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता

बेनकाब होता पाकिस्तान

यह देखना उल्लेखनीय है कि जब भारतीय कश्मीर में लोग मतदान के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अशांति और उपद्रव के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसे देश ही नहीं, दुनिया को भी देखना चाहिए और उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के बिगड़ते हालात और वहां हो रहे लोगों के दमन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करे। वहां की स्थितियों को विश्व मंचों पर उठाने में इसलिए संकोच नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर भारत का ही भू-भाग है और संसद में इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया जा चुका है कि इस हिस्से को हासिल किया जाएगा। इस नाते भारत का यह नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने इस भू-भाग में लोगों के दमन और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वहां के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और दूसरे, पाकिस्तान ने यह माहौल बना रखा है कि उसे भारतीय कश्मीर के मामले में बोलने का अधिकार है। वह जब-तब भारतीय कश्मीर को लेकर विश्व मंचों पर बोलता भी रहता है। यह सही समय है कि पाकिस्तान को आईना दिखाया जाए। उस पर चौतरफा दबाव बनाने का भी यही सही वक्त है, क्योंकि वह भारतीय कश्मीर में हस्तक्षेप करने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है।

भारत को उस पार के कश्मीर के लोगों को यह संदेश लगातार देना चाहिए कि उनका हित भारत से जुड़ने में है। वहां मानवाधिकारों का जैसी निर्ममता के साथ दमन किया जा रहा है, उसे इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले जिस इलाके को आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में स्थितियां कितनी खराब हैं, इसका पता इससे चलता है कि वहां जब पुलिस से हालात नहीं संभले और उसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, तब सेना को बुलाना पड़ा। इससे भी बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग महंगाई के साथ-साथ अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और यह जान गए हैं कि कश्मीरियों का हितैषी बनने की आड़ में पाकिस्तान किस तरह उनका शोषण करने में लगा हुआ है। वहां के लोग यह भी देख रहे हैं कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद भारतीय कश्मीर में किस तरह हालात तेजी से सुधर रहे हैं और वे पाकिस्तान के शासन के तहत किस प्रकार दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। उनकी केवल हर स्तर पर उपेक्षा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनके संसाधनों का दोहन करने के बाद भी उन्हें विकास से वंचित रखा जा रहा है।

गंभीर लापरवाही

पर्यावरण को लेकर जहां किसानों की ओर से उदासीनता दिखाई जा रही है वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है। पंजाब में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे उसके अवशेष यानी नाड़ जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पर्यावरण को गंभीर क्षति तो पहुंच ही रही है, धुएं के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हादसों में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले अमृतसर में नाड़ के धुएं के कारण हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। एक अन्य दुर्घटना में बाइक सवार जल गया था। अलग-अलग घटनाओं में कुछ लोग झुलस भी चुके हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। लोगों की जान से कीमती कुछ नहीं है। जहां तक पर्यावरण की बात है तो नाड़ को आग लगाने वाले किसान भविष्य के लिए भी परेशानी बढ़ा रहे हैं। चाहे नाड़ हो या फिर पराली, इसे आग लगाने से कई मित्र कीट खत्म हो जाते हैं, जबकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में उनका योगदान होता है। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर के कई पोषक तत्व भी नाड़ को आग लगाने से खत्म हो जाते हैं जिनका पैदावार बढ़ाने में योगदान होता है। इसकी भरपाई के लिए किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं जिससे जमीन की गुणवत्ता धीरे-धीरे कम हो जाती है। ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से अनाज या सब्जियों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। प्रशासन को नाड़ जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सक्रियता दिखानी चाहिए। अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों व किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी आवश्यक है।

गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे उसके अवशेष को आग लगाने से प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, धुएं के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए

चुनाव को प्रभावित करने वाले पहलू

राहुल वर्मा

आधारभूत राजनीतिक पहलू ही किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनावों के लिए चार चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान को लेकर चौथे चरण के अंतिम आंकड़े आना अभी शेष हैं। चूंकि तीन चरणों में मतदान पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुआ है, जिसकी पक्ष-विपक्ष अपनी-अपनी सुविधा से व्याख्या कर रहे हैं। नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसके लिए सट्टा बाजार से लेकर शेयर बाजार की चाल को पैमाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर भी जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। चूंकि इंटरनेट मीडिया के इस दौर में हर व्यक्ति विश्लेषक बना हुआ है तो चुनाव परिणामों के परिदृश्य को लेकर तरह-तरह के अनुमान एवं आकलन तैर रहे हैं। इन्हीं अनुमानों के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना विमर्श गढ़कर राजनीतिक बढ़त बनाने के प्रयास में हैं।

चुनाव शुरू होने से पहले व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग आसानी से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के दो-तीन हफ्तों के बाद मतदान के कमजोर रुझान और विमर्श का कोई एक बिंदु न उभरने के कारण स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं दिख रहीं। कहीं पर कुछ स्थानीय तो कुछ राज्यों के मुद्दे उभर गए या कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। मतदान के घटते रुझान से भी कोई दल किसी तरह का दावा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या मोदी-फैक्टर अब उतना प्रभावी नहीं रहा है? क्या चुनाव की एकाएक तस्वीर इस प्रकार से बदल गई है कि उसमें राजनीतिक आधारभूत पहलुओं की कोई भूमिका नहीं रह गई है?

आधारभूत राजनीतिक पहलुओं की बात करें तो यही किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं। भाजपा ने भी इन्हीं पहलुओं के इर्दगिर्द अपनी रणनीति बनाई थी और उनके आधार पर ही उसे अपनी जीत का भरोसा रहा। आधारभूत पहलुओं में पहला बिंदु है सामाजिक समीकरणों का। पिछले कुछ समय से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने का प्रयास किया है। यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे पद के माध्यम से भी प्रतीकात्मक संदेश देने का काम किया गया। पहले दलित समुदाय से आने वाले राम नाथ कोविन्द को राष्ट्रपति बनाया गया, फिर उनके बाद आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मु को रायसीना हिल पहुंचाया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लेकर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री चुनते समय इसका ध्यान रखा गया कि सामाजिक समीकरण सधे रहें। क्या डेढ़ महीनों में ही ये सामाजिक समीकरण बदल गए होंगे? कांग्रेस ने भी दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष बनाया, पर वह उसका वैसा संदेश नहीं दे पाई।

दूसरा बिंदु नेतृत्व क्षमता का है, जिसमें भाजपा विपक्षियों पर भारी पड़ती है, क्योंकि उसके पास मोदी जैसा जांचा एवं परखा हुआ चेहरा है, जबकि विपक्षी दल किसी सर्वमान्य नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बना पाए। इसमें तीसरा बिंदु सांगठनिक कौशल का है, जिसमें भाजपा अपने विरोधियों से मीलों आगे दिखाई देती है, क्योंकि एक तो वह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग भी उसकी क्षमताएं बढ़ाता है। सांगठनिक कौशल के मामले में विपक्षी दलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती। चौथा बिंदु विचारधारा और मूल मुद्दों का है, जिस मोर्चे पर भाजपा खासी मुखर रहती है। पार्टी राम मंदिर के निर्माण और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 की समाप्ति जैसे मूल वैचारिक वादों की पूर्ति के साथ ही समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत देकर समर्थकों को आश्वस्त करने में लगी है। जबकि विपक्षी दल वैचारिक मुद्दों पर भ्रम एवं दुविधा के शिकार दिखते हैं। जैसे आइएनडीआइए के घटक दलों ने चुनावी घोषणा पत्रों में ऐसे वादे किए हैं, जिनसे शायद दूसरा दल ही पूरी तरह सहमत नहीं। आधारभूत पहलुओं के पांचवें स्तंभ में सरकारों का कामकाज परखा जाता है। इस मोर्चे पर मोदी बार-बार अतीत में कांग्रेस की असफलताओं को रेखांकित करते रहे हैं तो साथ ही अपनी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का बखान भी करते हैं। विपक्षी दल मोदी के नैरेटिव की काट में उतने प्रभावी नहीं दिखते। इन पांचों पहलुओं को देखा जाए तो भाजपा के नेतृत्व वाला राजग चुनावों से पहले जिस तरह आश्वस्त दिख रहा था, अब शायद उसने कुछ रक्षात्मक रणनीति अपना ली है।

विपक्षी दलों ने भाजपा नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है कि उनका चार सौ पार का नारा हवा-हवाई था और कुछ चरणों के चुनाव के बाद वह गायब हो गया है। विपक्षी दल महंगाई से लेकर बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में भाजपा के ट्रंप कार्ड राम मंदिर के प्रभाव को हल्का करने के लिए सवाल कर रहे हैं कि इससे आम आदमी को क्या लाभ होगा? यह कहना मुश्किल है कि उनका यह दांव कारगर सिद्ध होगा या आत्मघाती? जहां मोदी विभिन्न वर्गों को लक्षित करने वाली अपनी कल्याणकारी योजनाओं के सहारे हैं तो विपक्ष उन्हीं योजनाओं में मीनमेख निकालकर अपनी राजनीतिक संभावनाएं खोज रहा है। विपक्षी दल भाजपा पर हिंदू आक्रामकता को बढ़ाने, तानाशाह रवैये को पोषित करने और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखना होगा कि ऐसे आरोप आम मतदाताओं के कितने गले उतरते हैं। जहां तक चुनावी समीकरणों की बात है तो भाजपा ने करीब एक चौथाई सांसदों का टिकट काटा है तो उसे कुछ आंतरिक असंतोष भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसका एक लाभ यह भी होता है कि सांसदों के प्रति असंतोष का खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना पड़ता। पिछले कई चुनावों में भाजपा इस फार्मूले को आजमाती आई है। क्या उसी फार्मूले के सहारे भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी या फिर विपक्षी दलों की व्यूह रचना में फंसकर रह जाएगी? इसका जवाब तो चार जून को ही मिल सकेगा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश

गिरीश्वर मिश्र

मतदाताओं को रिझाने के लिए गैर जिम्मेदाराना ढंग से कुछ भी कहना प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है

चुनाव आयोग संग ईवीएम भी निशाने पर। फाइल

जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए शासन के महास्वप्न को साथ लेकर लोकतंत्र की शासन विधा आधुनिक युग में सबसे प्रबुद्ध, व्यावहारिक और विवेकशील सरकार चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार की गई है। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के चुने प्रतिनिधि या सीधे जनता से चुने लोगों को शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके मूल में 'सर्वे भवंतु सुखिनः' का ही आदर्श सक्रिय है। सबकी भागीदारी के लिए अवसर देना, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ शासन चलाना, शांति और समानता के सिद्धांतों को जमीनी हकीकत बनाने के साथ प्रतिबद्धता लोकतंत्र की जान होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता से शासन करने के लिए मिली शक्ति की स्वीकार्यता और ठीक-ठीक पहचान बनी रहे। यह भी जरूरी है कि शासन में सत्ता का वितरण विकेंद्रित हो और जनता से सलाह-मशविरा होता रहे। इसमें नियमित रूप से जांच और संतुलन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चुनाव में मतदान से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए नियमपूर्वक और समय से चुनाव होने चाहिए। नियमों और कानूनों का पालन होना चाहिए तथा कानून को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। देश के नागरिकों के सभी मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे। इस सिलसिले में जीवन की, बोलने की, अभिव्यक्ति की और स्वच्छंद घूमने-फिरने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है।

लोकतांत्रिक शासन के संचालन की दृष्टि से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया चार प्रमुख आधार-स्तंभ हैं। इनकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता अखंड बनी रहनी चाहिए। समानता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत भी व्यापक संदर्भ का काम करते हैं जिससे अनुप्राणित होकर ही नियम-कानून बनते हैं, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। सरकार एक जीवनशैली जैसा उपाय है, जो देश और समाज के स्वस्थ विकास के लिए प्रयुक्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने को सुनिश्चित करने में हर स्तर पर समाज की अधिकाधिक जनभागीदारी होनी चाहिए। वह प्राणवायु की तरह होती है, यदि वह अवरुद्ध हो जाए या उसके साथ छेड़खानी हो तो लोकतंत्र और देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद के भारत के संविधान में पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए 1950 में किया गया। संविधान में करीब 80 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए। संविधान की उद्देशिका में बदलाव लाने का भी अभूतपूर्व कार्य किया गया। देश में लोकतंत्र को स्थगित कर आपातकाल लगाना और संविधान को निरस्त करना निश्चय ही लोकतंत्र का गला घोटने जैसा कार्य था। यह भी कांग्रेस का काम था। अनेक राज्य सरकारों को उठाने-गिराने का खेल भी हुआ। अनुच्छेद-370 को लेकर भी कांगेस ने जिस मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया, वह संविधान की प्रतिष्ठा के अनुकूल न था।

पिछले कांग्रेसी शासन में घोटालों की धूम मच रही थी और लगातार तुष्टीकरण पर जोर दिया जाता रहा, ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। अब पंथ-मजहब को आधार बनाकर आरक्षण की बात और विभिन्न वर्गों को मुफ्त की खैरात बांटने एवं कर्जमाफी के प्रस्तावों के साथ जो बेहिसाब उद्घोषणाएं हो रही हैं, उनका कोई वित्तीय आधार नहीं दिखता। सरकार को पूरे देश के समग्र विकास के लिए सोचना होता है और इस दृष्टि से भी विपक्ष कोई विकल्प नहीं दे पा रहा, सिवाय यह कहने के कि मौजूदा सरकार का कार्य पूरी तरह निरर्थक है।

तथ्य यह है कि आज विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था वाला भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है। भारतीयों में अब अपनी आस्था, भाषा और सभ्यता-संस्कृति के प्रति हीन भावना नहीं है। गत दिनों राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विदेश में रहने वाले हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के अनेक अवसर भी हमने देखे। महिलाओं के सशक्तीकरण, आदिवासी समुदायों के उत्थान, समाज के अंतिम जन को अच्छे जीवन का अवसर मुहैया कराने, शिक्षा को प्रासंगिक बनाने और भ्रष्टाचारमुक्त भारत के लिए कठिन संघर्ष की यात्रा जारी है, पर राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थाओं के संचालन में बाधाएं भी आ रही हैं। इसलिए सब ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता।

अगली लोकसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव के लिए प्रचार के माहौल में मतदाताओं को रिझाने के लिए साम, दाम, दंड, और भेद हर तरह की तरकीबों का उपयोग किया जा रहा है। स्टार प्रचारक सामान्य शिष्टाचार भूलकर जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारा विषवमन भी होता दिख रहा है। लोकतंत्र पर खतरा, संविधान परिवर्तन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के हनन और आरक्षण की व्यवस्था को लेकर भय एवं संदेह पैदा करने का प्रयास हो रहा है। चुनाव आयोग के साथ ईवीएम पर अनावश्यक संदेह कर और सवाल खड़े कर एक तरह का हौवा खड़ा करके आम जन को भयाक्रांत करने के लिए काफी विस्फोटक मसाला पैदा किया जा रहा है। गैर-जिम्मेदाराना ढंग से कुछ भी कहना जनता में भ्रम फैलाता है। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह व्यवस्था लोकसंभव होती है यानी लोक या समाज के भीतर से उपजने वाली लोक शक्ति ही इसके लिए नियामक होती है। इसको बचाए रखने की जरूरत है। तभी हम सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। परिवारवादी और वंशवादी सोच की जगह 'लोकाः समस्ताः सुखिनो भवंतु' की सर्वसमावेशी कामना ही हमारा ध्येय होना चाहिए।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन का साथ होना

यह मानव जीवन परमात्मा प्रदत्त है। यह इस सृष्टि में परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, पर प्रायः मनुष्य निज जीवन की महत्ता को नहीं समझता है। यह जीवन प्रभु ने हमें क्यों दिया है? इससे प्रायः मनुष्य अनभिज्ञ ही रहता है। महापुरुष, संत, महात्मा अपने जीवन को अभियान के तहत जीकर इस जगत में महान बन जाते हैं। कभी आलस्य, प्रमाद, कामना, वासना, लोभ-लालच, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं। उनकी चेतना कभी सोई नहीं रहती है। उनका मन कभी सुस्त नहीं रहता है। सदा उनके साथ रहता है। उनके मन में सदा क्रांति की चिंगारी धधकती रहती है। तभी तो वे विचार क्रांति का अभियान छेड़कर युग परिवर्तन का इतिहास रचने में सक्षम हो पाते हैं।

जिसका मन सदा साथ होता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श कर पाता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए सोचें तो सर्वप्रथम मन ही पीछे हट जाता है। यही मन की दुर्बलता एवं कुसंस्कारित होने का प्रमुख लक्षण है। मन जब सुसंस्कारित होता है, तभी वह मनुष्य का साथी बन पाता है। मन को साथी बनाना कठिन है, पर मुश्किल नहीं। मन में जब पाप, कुसंस्कार एकत्रित हो जाते हैं तो मन व्यसन, वासना, कामना, निकृष्ट कर्म, आराम और सुषुप्तावस्था को पसंद करने लगता है। वहीं जब मन में पुण्य की प्रबलता होती है तो वह उत्कृष्ट चिंतन, सत्कर्म, जप, तप, सत्संग और ईश्वर उपासना को महत्व देता है।

मन को अपना साथी बना लेने से जीवन सुखी, संतुष्ट, समुन्नत एवं आनंदित हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। अतः मन की सुस्ती, गंदगी, कुसंस्कार को दूर कर इसमें शुभ संस्कार प्रविष्ट कराने के लिए मनुष्य को नित्य जप, तप, सत्संग, सत्कर्म, धर्म, ईश्वर उपासना और स्वाध्याय करना चाहिए।

मुकेश ऋषि

शत प्रतिशत मतदान का सपना

डा. शशांक द्विवेदी

देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर मतदान आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग के इतने सार्थक और सकारात्मक प्रयास के बावजूद लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में औसत वोटिंग 60-65 प्रतिशत ही हो रही है। इसका मतलब है कि बाकी के 35-40 प्रतिशत लोग अपना कीमती वोट नहीं दे पा रहे। करोड़ों लोग अपने अपने पैतृक घर से दूर काम-धंधे, नौकरी की वजह से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और विदेश में रहने की वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। अब समय आ गया है जब अप्रवासी भारतीयों और देश के अंदर विस्थापित भारतीय नागरिकों के लिए आनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल इसमें कई तकनीकी बाधाएं हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए।

वैसे चुनाव आयोग देश में ई-वोटिंग की पहल कर चुका है, लेकिन अभी तक यह योजना विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लागू नहीं हो सकी है। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात नगरपालिका में 2010 और 2011 में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कराया गया था, लेकिन इसके बाद यह योजना बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। आस्ट्रेलिया, नार्वे और कनाडा जैसे कुछ देशों में आनलाइन वोटिंग के प्रयोग शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में भी आनलाइन वोटिंग की सुविधा की मांग की जा रही है। इससे चुनाव में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी है। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक पार्टियां हैकरों की मदद से इस सिस्टम का दुरुपयोग कर सकती हैं। आनलाइन वोटिंग से संबंधित और भी कई तकनीकी समस्याएं हैं जिनके माकूल समाधान के बिना फिलहाल यह संभव नहीं लगता।

आनलाइन वोटिंग से लोगों की चुनावों में भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ेगी जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा

आनलाइन वोटिंग में वोटर की पहचान के लिए आधार कार्ड और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के डाटा को प्रयोग करके उसे आनलाइन लिंक किया जा सकता है। इससे पहचान के फर्जीवाड़े से काफी हद तक बचा जा सकता है। आधार केंद्र सरकार की ओर से हर नागरिक को जारी की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है। जबकि एनपीआर में देश के हर नागरिक की जानकारी दर्ज होती है। आनलाइन हैकिंग और तकनीकी गड़बड़ी दूर करने के लिए चुनाव आयोग देश के 543 लोकसभा के विभिन्न केंद्रों पर आनलाइन वोटिंग की सुविधा भी कर सकता है जिससे घर से दूर बैठे लोग अपनी लोकसभा या विधानसभा के लिए वोट कर सकें। शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं और किए भी जाने चाहिए। इन कदमों से लोगों की चुनाव में भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ेगी जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जमानत का नया और आसान आधार

गत दिनों 'चुनाव प्रचार की सुविधा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें दो जून को पुनः समर्पण करना होगा। वह इस अवधि में मुख्यमंत्री पद से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, शराब घोटाले पर कुछ नहीं बोल सकेंगे और न मामले से संबंधित गवाहों से बातचीत कर सकेंगे। इस आदेश के कई प्रभाव स्पष्ट नजर आते हैं। इससे विचाराधीन बंदी और अपराध करने का मन बना रहे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि जमानत का एक नया और आसान आधार मुहैया हो गया है। चुनाव प्रचार को उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकार से मानव की आवश्यक बुभुक्षा मान लिया है और स्वाभाविक है कि यह अधिकार सबको मिलेगा, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद-14 में समानता का अधिकार संरक्षित है। चुनाव तो देश में कहीं न कहीं होते ही रहते हैं। वे किसी स्तर के हों और सारा देश एक है तथा हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में किसी चुनाव में प्रचार करने का हक है। रही बात बड़े छोटे की, तो जैसे बड़े नेता के लिए लोकसभा का चुनाव महत्व रखता है, वैसे ही गांव-गिराव के नेता के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव। न्यायाधीश के लिए कोई बड़ा-छोटा होता ही नहीं है। ऐसे में विचाराधीन और सजा काट रहे जघन्य अपराधों में संलिप्तता वाले बंदी किसी न किसी चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगेंगे, तब संगत न्यायालय कैसे इन्कार कर पाएंगे! वे यदि मना करेंगे, तो वह आदेश विभेदकारी होगा। कानूनविदों का सोच है कि इसके पहले इस आधार पर जमानतें मांगी गई थीं, जो नहीं प्रदान की गईं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमानत के लिए अदालत गए, लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो गई। कुछ वकील तो जेलों में बंद अलगाववादी मुजरिमों का भी मुद्दा यह कहकर उभार रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए वे भी कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं! तब क्या आदेश होंगे। बहरहाल यह तो निकट भविष्य में साफ हो पाएगा कि उच्च और अवर न्यायालय इस बिंदु पर क्या रुख अपनाते हैं, किंतु एक नई बहस छिड़ तो गई ही है।

रघोत्तम शुक्ल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी

अब बारी हमारी

भारत में लोकतांत्रिक पर्व मनाया जा रहा है। छठे चरण में दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को मतदान करने की बारी है। बारी है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की, देश को आगे बढ़ाने की। भारत निर्वाचन आयोग ने तो 'मैं भी इलेक्शन एंबेसडर' नाम से कैंपेन भी चला रखा है। जिसके माध्यम से हम लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आयोग द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से भी कई सुविधाएं दी जा रहीं, जिसमें आप अपने उम्मीदवार का पूरा बायोडाटा जान सकते हैं। आइए, अपनी आवाज को वोट के माध्यम से संसद तक पहुंचाएं, मतदान करें, अपने देश के लिए, क्योंकि हमसे देश है और हम देश से हैं।

अमन जायसवाल, नई दिल्ली

मेलबाक्स

दायित्व निर्वहन जरूरी

संपादकीय आलेख 'दायित्व निर्वहन का अवसर' पढ़ा। लोकसभा चुनाव के पहले चार चरणों के मतदान में लोगों ने वैसा उत्साह नहीं दिखाया, जैसा साल 2019 में था। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप लगाया है, जिसका आयोग ने खंडन किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव गर्मियों के दिनों में सात चरणों में हो रहा है। यह मई है और अभी तीन चरण और बाकी हैं, अंतिम चरण एक जून को निर्धारित है। मध्य मई से मध्य जून तक चिलचिलाती गर्मी देखी जाती है और सबसे अधिक गर्मी के दिन होते हैं। मतदान में हिस्सा हर वोटरों का संवैधानिक अधिकार है। इनके द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों से सरकार बनती है। इससे लोकतंत्र को बल मिलता है। मतदान न करने वाले सरकार से शिकायत करने का अधिकार नहीं रखते। एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनाने के लिए मतदान करना निहायत ही जरूरी होता है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संग्रह का लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता

बेनकाब होता पाकिस्तान

यह देखना उल्लेखनीय है कि जब भारतीय कश्मीर में लोग मतदान के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अशांति और उपद्रव के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसे देश ही नहीं, दुनिया को भी देखना चाहिए और उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के बिगड़ते हालात और वहां हो रहे लोगों के दमन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करे। वहां की स्थितियों को विश्व मंचों पर उठाने में इसलिए संकोच नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर भारत का ही भू-भाग है और संसद में इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया जा चुका है कि इस हिस्से को हासिल किया जाएगा। इस नाते भारत का यह नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने इस भू-भाग में लोगों के दमन और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वहां के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और दूसरे, पाकिस्तान ने यह माहौल बना रखा है कि उसे भारतीय कश्मीर के मामले में बोलने का अधिकार है। वह जब-तब भारतीय कश्मीर को लेकर विश्व मंचों पर बोलता भी रहता है। यह सही समय है कि पाकिस्तान को आईना दिखाया जाए। उस पर चौतरफा दबाव बनाने का भी यही सही वक्त है, क्योंकि वह भारतीय कश्मीर में हस्तक्षेप करने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। भारत को उस पार के कश्मीर के लोगों को यह संदेश लगातार देना चाहिए कि उनका हित भारत से जुड़ने में है। वहां मानवाधिकारों का जैसी निर्ममता के साथ दमन किया जा रहा है, उसे इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले जिस इलाके को आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में स्थितियां कितनी खराब हैं, इसका पता इससे चलता है कि वहां जब पुलिस से हालात नहीं संभले और उसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, तब सेना को बुलाना पड़ा। इससे भी बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग महंगाई के साथ-साथ अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और यह जान गए हैं कि कश्मीरियों का हितैषी बनने की आड़ में पाकिस्तान किस तरह उनका शोषण करने में लगा हुआ है। वहां के लोग यह भी देख रहे हैं कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद भारतीय कश्मीर में किस तरह हालात तेजी से सुधर रहे हैं और वे पाकिस्तान के शासन के तहत किस प्रकार दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। उनकी केवल हर स्तर पर उपेक्षा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनके संसाधनों का दोहन करने के बाद भी उन्हें विकास से वंचित रखा जा रहा है।

जाम कोई नई बात नहीं

राज्य की राजधानी हो या कोई भी शहर सड़क जाम की समस्या हर जगह है। इस समस्या से एक तो लोगों के समय की बर्बादी होती है दूसरी ओर ईंधन की खपत के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। लगातार कोशिश के बाद भी इस समस्या का व्यावहारिक निदान नहीं निकल पा रहा। रविवार को प्रधानमंत्री पटना पहुंचे। उनके आगमन को लेकर की गई तैयारियों की वजह से कुछ रास्ते ब्लाक किए गए तो कुछ सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। इस प्रसंग को भी राजनीतिक चश्मे से देखा गया। विरोधियों ने रोजी-रोजगार से लेकर लोगों की परेशानी का हवाला देकर इसकी आलोचना की। विचार करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री तो कभी- कभार पटना आएंगे, पटनावासी रोज इस समस्या से जूझते हैं। यह ठीक है कि रोज कमाने-खाने वाले कुछ घंटे सड़क किनारे बैठकर अपना व्यवसाय कर लेते हैं। उन्हें भी अपने व्यवसाय के लिए जगह चाहिए। इसका व्यावहारिक निदान निकालने की जरूरत है। यह सिर्फ पटना की नहीं, मुजफ्फरपुर, भागलपुर हो या गया हर शहर की बड़ी समस्या है। कई शहरों में सब्जी मंडी या व्यापार स्थल को विकसित करने की कोशिश हुई, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। कुछ तो वीरान रह गए, कुछ कार्यशील भी हुए तो ग्राहक वहां तक कम संख्या में ही पहुंचते हैं। विशेषकर सब्जी का बाजार सड़क पर ही सजेगा, यह हमारा संस्कार बन गया है। राजधानी के कुछ हिस्सों में सब्जी बेचने वालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। कुछ दिन इसपर अमल हुआ, लेकिन फिर वही हालात हैं। सड़क के दोनों ओर से ठेला-टोकरी वाले होते हैं। दो बड़े वाहन आमने-सामने हुए तो जाम लगना आम बात है। अधिकांश लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यह भी जाम की बड़ी वजह है। अतः जरूरी है कि फुटपाथी दुकानों के लिए विकल्प की व्यवस्था के साथ यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

फुटपाथी दुकानों के लिए विकल्प की व्यवस्था के साथ यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि प्लेआफ से पहले आइपीएल से किनारा करने वाले खिलाड़ियों की फीस काटी जानी चाहिए?

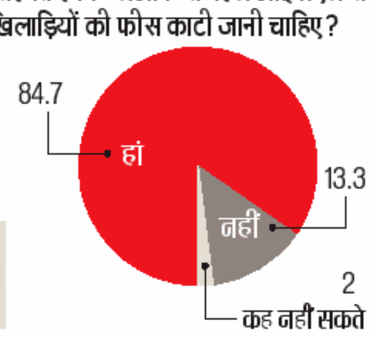

आज का सवाल

क्या भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात को विश्व मंच पर उठाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

चुनाव को प्रभावित करने वाले पहलू

राहुल वर्मा

आधारभूत राजनीतिक पहलू ही किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं

लोकसभा चुनावों के लिए चार चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान को लेकर चौथे चरण के अंतिम आंकड़े आना अभी शेष हैं। चूंकि तीन चरणों में मतदान पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुआ है, जिसकी पक्ष-विपक्ष अपनी-अपनी सुविधा से व्याख्या कर रहे हैं। नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसके लिए सट्टा बाजार से लेकर शेयर बाजार की चाल को पैमाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर भी जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। चूंकि इंटरनेट मीडिया के इस दौर में हर व्यक्ति विश्लेषक बना हुआ है तो चुनाव परिणामों के परिदृश्य को लेकर तरह-तरह के अनुमान एवं आकलन तैर रहे हैं। इन्हीं अनुमानों के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना विमर्श गढ़कर राजनीतिक बढ़त बनाने के प्रयास में हैं।

चुनाव शुरू होने से पहले व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग आसानी से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के दो-तीन हफ्तों के बाद मतदान के कमजोर रुझान और विमर्श का कोई एक बिंदु न उभरने के कारण स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं दिख रहीं। कहीं पर कुछ स्थानीय तो कुछ राज्यों के मुद्दे उभर गए या कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। मतदान के घटते रुझान से भी कोई दल किसी तरह का दावा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या मोदी-फैक्टर अब उतना प्रभावी नहीं रहा है? क्या चुनाव की एकाएक तस्वीर इस प्रकार से बदल गई है कि उसमें राजनीतिक आधारभूत पहलुओं की कोई भूमिका नहीं रह गई है?

आधारभूत राजनीतिक पहलुओं की बात करें तो यही किसी राजनीतिक दल को जीत दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ठोस मुद्दों पर आधारित होते हैं। भाजपा ने भी इन्हीं पहलुओं के इर्दगिर्द अपनी रणनीति बनाई थी और उनके आधार पर ही उसे अपनी जीत का भरोसा रहा। आधारभूत पहलुओं में पहला बिंदु है सामाजिक समीकरणों का। पिछले कुछ समय से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने का प्रयास किया है। यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे पद के माध्यम से भी प्रतीकात्मक संदेश देने का काम किया गया। पहले दलित समुदाय से आने वाले राम नाथ कोविन्द को राष्ट्रपति बनाया गया, फिर उनके बाद आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मु को रायसीना हिल पहुंचाया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लेकर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री चुनते समय इसका ध्यान रखा गया कि सामाजिक समीकरण सधे रहें। क्या डेढ़ महीनों में ही ये सामाजिक समीकरण बदल गए होंगे? कांग्रेस ने भी दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष बनाया, पर वह उसका वैसा संदेश नहीं दे पाई।

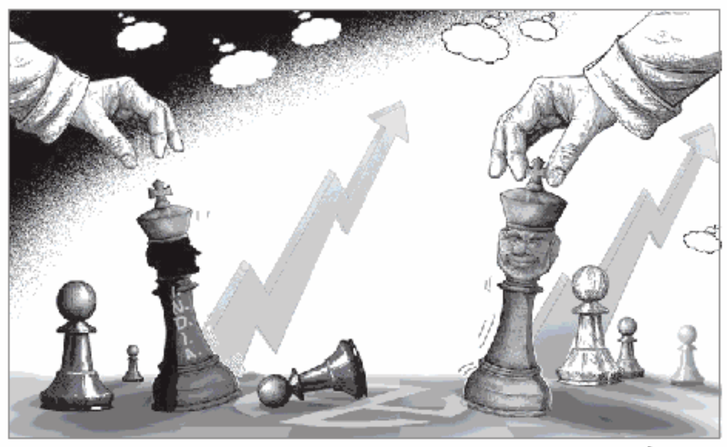

अवधेश राजपूत

दूसरा बिंदु नेतृत्व क्षमता का है, जिसमें भाजपा विपक्षियों पर भारी पड़ती है, क्योंकि उसके पास मोदी जैसा जांचा एवं परखा हुआ चेहरा है, जबकि विपक्षी दल किसी सर्वमान्य नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बना पाए। इसमें तीसरा बिंदु सांगठनिक कौशल का है, जिसमें भाजपा अपने विरोधियों से मीलों आगे दिखाई देती है, क्योंकि एक तो वह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग भी उसकी क्षमताएं बढ़ाता है। सांगठनिक कौशल के मामले में विपक्षी दलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती। चौथा बिंदु विचारधारा और मूल मुद्दों का है, जिस मोर्चे पर भाजपा खासी मुखर रहती है। पार्टी राम मंदिर के निर्माण और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 की समाप्ति जैसे मूल वैचारिक वादों की पूर्ति के साथ ही समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत देकर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दर्शाकर समर्थकों को आश्वस्त करने में लगी है। जबकि विपक्षी दल वैचारिक मुद्दों पर भ्रम एवं दुविधा के शिकार दिखते हैं। जैसे आइएनडीआइए के घटक दलों ने चुनावी घोषणा पत्रों में ऐसे वादे किए हैं, जिनसे शायद दूसरा दल ही पूरी तरह सहमत नहीं। आधारभूत पहलुओं के पांचवें स्तंभ में सरकारों का कामकाज परखा जाता है। इस मोर्चे पर मोदी बार-बार अतीत में कांग्रेस की असफलताओं को रेखांकित करते रहे हैं तो साथ ही अपनी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का बखान भी करते हैं। विपक्षी दल मोदी के नैरेटिव की काट में उतने प्रभावी नहीं दिखते। इन पांचों पहलुओं को देखा जाए तो भाजपा के नेतृत्व वाला राजग चुनावों से पहले जिस तरह आश्वस्त दिख रहा था, अब शायद उसने कुछ रक्षात्मक रणनीति अपना ली है।

विपक्षी दलों ने भाजपा नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है कि उनका चार सौ पार का नारा हवा-हवाई था और कुछ चरणों के चुनाव के बाद वह गायब हो गया है। विपक्षी दल महंगाई से लेकर बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में भाजपा के ट्रंप कार्ड राम मंदिर के प्रभाव को हल्का करने के लिए सवाल कर रहे हैं कि इससे आम आदमी को क्या लाभ होगा? यह कहना मुश्किल है कि उनका यह दांव कारगर सिद्ध होगा या आत्मघाती? जहां मोदी विभिन्न वर्गों को लक्षित करने वाली अपनी कल्याणकारी योजनाओं के सहारे हैं तो विपक्ष उन्हीं योजनाओं में मीनमेख निकालकर अपनी राजनीतिक संभावनाएं खोज रहा है। विपक्षी दल भाजपा पर हिंदू आक्रामकता को बढ़ाने, तानाशाह रवैये को पोषित करने और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखना होगा कि ऐसे आरोप आम मतदाताओं के कितने गले उतरते हैं। जहां तक चुनावी समीकरणों की बात है तो भाजपा ने करीब एक चौथाई सांसदों का टिकट काटा है तो उसे कुछ आंतरिक असंतोष भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसका एक लाभ यह भी होता है कि सांसदों के प्रति असंतोष का खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना पड़ता। पिछले कई चुनावों में भाजपा इस फार्मूले को आजमाती आई है। क्या उसी फार्मूले के सहारे भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी या फिर विपक्षी दलों की व्यूह रचना में फंसकर रह जाएगी? इसका जवाब तो चार जून को ही मिल सकेगा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश

गिरीश्वर मिश्र

मतदाताओं को रिझाने के लिए गैर जिम्मेदाराना ढंग से कुछ भी कहना प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है

चुनाव आयोग संग ईवीएम भी निशाने पर ● फाइल

जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए शासन के महास्वप्न को साथ लेकर लोकतंत्र की शासन विधा आधुनिक युग में सबसे प्रबुद्ध, व्यावहारिक और विवेकशील सरकार चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार की गई है। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के चुने प्रतिनिधि या सीधे जनता से चुने लोगों को शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके मूल में 'सर्वे भवंतु सुखिनः' का ही आदर्श सक्रिय है। सबकी भागीदारी के लिए अवसर देना, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ शासन चलाना, शांति और समानता के सिद्धांतों को जमीनी हकीकत बनाने के साथ प्रतिबद्धता लोकतंत्र की जान होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता से शासन करने के लिए मिली शक्ति की स्वीकार्यता और ठीक-ठीक पहचान बनी रहे। यह भी जरूरी है कि शासन में सत्ता का वितरण विकेंद्रित हो और जनता से सलाह-मशविरा होता रहे। इसमें नियमित रूप से जांच और संतुलन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चुनाव में मतदान से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए नियमपूर्वक और समय से चुनाव होने चाहिए। नियमों और कानूनों का पालन होना चाहिए तथा कानून को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। देश के नागरिकों के सभी मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे। इस सिलसिले में जीवन की, बोलने की, अभिव्यक्ति की और स्वच्छंद घूमने-फिरने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है।

लोकतांत्रिक शासन के संचालन की दृष्टि से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया चार प्रमुख आधार-स्तंभ हैं। इनकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता अखंड बनी रहनी चाहिए। समानता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत भी व्यापक संदर्भ का काम करते हैं जिससे अनुप्राणित होकर ही नियम-कानून बनते हैं, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। सरकार एक जीवनशैली जैसा उपाय है, जो देश और समाज के स्वस्थ विकास के लिए प्रयुक्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने को सुनिश्चित करने में हर स्तर पर समाज की अधिकाधिक जनभागीदारी होनी चाहिए। वह प्राणवायु की तरह होती है, यदि वह अवरुद्ध हो जाए या उसके साथ छेड़खानी हो तो लोकतंत्र और देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद के भारत के संविधान में पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए 1950 में किया गया। संविधान में करीब 80 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए। संविधान की उद्देशिका में बदलाव लाने का भी अभूतपूर्व कार्य किया गया। देश में लोकतंत्र को स्थगित कर आपातकाल लगाना और संविधान को निरस्त करना निश्चय ही लोकतंत्र का गला घोटने जैसा कार्य था। यह भी कांग्रेस का काम था। अनेक राज्य सरकारों को उठाने-गिराने का खेल भी हुआ। अनुच्छेद-370 को लेकर भी कांगेस ने जिस मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया, वह संविधान की प्रतिष्ठा के अनुकूल न था।

पिछले कांग्रेसी शासन में घोटालों की धूम मच रही थी और लगातार तुष्टीकरण पर जोर दिया जाता रहा, ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। अब पंथ-मजहब को आधार बनाकर आरक्षण की बात और विभिन्न वर्गों को मुफ्त की खैरात बांटने एवं कर्जमाफी के प्रस्तावों के साथ जो बेहिसाब उद्घोषणाएं हो रही हैं, उनका कोई वित्तीय आधार नहीं दिखता। सरकार को पूरे देश के समग्र विकास के लिए सोचना होता है और इस दृष्टि से भी विपक्ष कोई विकल्प नहीं दे पा रहा, सिवाय यह कहने के कि मौजूदा सरकार का कार्य पूरी तरह निरर्थक है।

तथ्य यह है कि आज विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था वाला भारत तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है। भारतीयों में अब अपनी आस्था, भाषा और सभ्यता-संस्कृति के प्रति हीन भावना नहीं है। भारत के निवासी भारतीय कहलाने में गर्व की अनुभूति करते हैं। भारतवर्ष की आवाज बड़े विश्व समुदाय में सुनी जाती है। गत दिनों राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विदेश में रहने वाले हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के अनेक अवसर भी हमने देखे। महिलाओं के सशक्तीकरण, आदिवासी समुदायों के उत्थान, समाज के अंतिम जन को अच्छे जीवन का अवसर मुहैया कराने, शिक्षा को प्रासंगिक बनाने और भ्रष्टाचारमुक्त भारत के लिए कठिन संघर्ष की यात्रा जारी है, पर राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थाओं के संचालन में बाधाएं भी आ रही हैं। इसलिए सब ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता।

अगली लोकसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव के लिए प्रचार के माहौल में मतदाताओं को रिझाने के लिए साम, दाम, दंड, और भेद हर तरह की तरकीबों का उपयोग किया जा रहा है। स्टार प्रचारक सामान्य शिष्टाचार भूलकर जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारा विषवमन भी होता दिख रहा है। लोकतंत्र पर खतरा, संविधान परिवर्तन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के हनन और आरक्षण की व्यवस्था को लेकर भय एवं संदेह पैदा करने का प्रयास हो रहा है। चुनाव आयोग के साथ ईवीएम पर अनावश्यक संदेह कर और सवाल खड़े कर एक तरह का हौवा खड़ा करके आम जन को भयाक्रांत करने के लिए काफी विस्फोटक मसाला पैदा किया जा रहा है। गैर-जिम्मेदाराना ढंग से कुछ भी कहना जनता में भ्रम फैलाता है। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह व्यवस्था लोकसंभव होती है यानी लोक या समाज के भीतर से उपजने वाली लोक शक्ति ही इसके लिए नियामक होती है। इसको बचाए रखने की जरूरत है। तभी हम सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। परिवारवादी और वंशवादी सोच की जगह 'लोकाः समस्ताः सुखिनो भवंतु' की सर्वसमावेशी कामना ही हमारा ध्येय होना चाहिए।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन का साथ होना

यह मानव जीवन परमात्मा प्रदत्त है। यह इस सृष्टि में परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, पर प्रायः मनुष्य निज जीवन की महत्ता को नहीं समझता है। यह जीवन प्रभु ने हमें क्यों दिया है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को परमात्मा ने क्या जिम्मेदारी दी है? क्यों दी है? इस विषयवस्तु से प्रायः मनुष्य अनभिज्ञ ही रहता है। महापुरुष, संत, महात्मा अपने जीवन को अभियान के तहत जीकर इस जगत में महान बन जाते हैं। कभी आलस्य, प्रमाद, कामना, वासना, लोभ-लालच, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं। उनकी चेतना कभी सोई नहीं रहती है। उनका मन कभी सुस्त नहीं रहता है। सदा उनके साथ रहता है। उनके मन में सदा क्रांति की चिंगारी धधकती रहती है। तभी तो वे विचार क्रांति का अभियान छेड़कर युग परिवर्तन का इतिहास रचने में सक्षम हो पाते हैं।

जिसका मन सदा साथ होता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श कर पाता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए सोचें तो सर्वप्रथम मन ही पीछे हट जाता है। यही मन की दुर्बलता एवं कुसंस्कारित होने का प्रमुख लक्षण है। मन जब सुसंस्कारित होता है, तभी वह मनुष्य का साथी बन पाता है। मन को साथी बनाना कठिन है, पर मुश्किल नहीं। मन में जब पाप, कुसंस्कार एकत्रित हो जाते हैं तो मन व्यसन, वासना, कामना, निकृष्ट कर्म, आराम और सुषुप्तावस्था को पसंद करने लगता है। वहीं जब मन में पुण्य की प्रबलता होती है तो वह उत्कृष्ट चिंतन, सत्कर्म, जप, तप, सत्संग और ईश्वर उपासना को महत्व देता है।

मन को अपना साथी बना लेने से जीवन सुखी, संतुष्ट, समुन्नत एवं आनंदित हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। अतः मन की सुस्ती, गंदगी, कुसंस्कार को दूर कर इसमें शुभ संस्कार प्रविष्ट कराने के लिए मनुष्य को नित्य जप, तप, सत्संग, सत्कर्म, धर्म, ईश्वर उपासना और स्वाध्याय करना चाहिए।

मुकेश ऋषि

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

जमानत का नया और आसान आधार

गत दिनों 'चुनाव प्रचार की सुविधा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें दो जून को पुनः समर्पण करना होगा। वह इस अवधि में मुख्यमंत्री पद से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, शराब घोटाले पर कुछ नहीं बोल सकेंगे और न मामले से संबंधित गवाहों से बातचीत कर सकेंगे। इस आदेश के कई प्रभाव स्पष्ट नजर आते हैं। इससे विचाराधीन बंदी और अपराध करने का मन बना रहे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि जमानत का एक नया और आसान आधार मुहैया हो गया है। चुनाव प्रचार को उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकार से मानव की आवश्यक बुभुक्षा मान लिया है और स्वाभाविक है कि यह अधिकार सबको मिलेगा, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद-14 में समानता का अधिकार संरक्षित है। चुनाव तो देश में कहीं न कहीं होते ही रहते हैं। वे किसी स्तर के हों और सारा देश एक है तथा हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में किसी चुनाव में प्रचार करने का हक है। यही बात बड़े छोटे की, तो जैसे बड़े नेता के लिए लोकसभा का चुनाव महत्व रखता है, वैसे ही गांव-गिराव के नेता के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव। न्यायाधीश के लिए कोई बड़ा-छोटा होता ही नहीं है। ऐसे में विचाराधीन और सजा काट रहे जघन्य अपराधों में संलिप्तता वाले बंदी किसी न किसी चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगेंगे, तब संगत न्यायालय कैसे इन्कार कर पाएंगे। वे यदि मना करेंगे, तो वह आदेश विभेदकारी होगा। कानूनविदों का सोच है कि इसके पहले इस आधार पर जमानतें मांगी गई थीं, जो नहीं प्रदान की गईं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमानत के लिए अदालत गए, लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो गई। कुछ वकील तो जेलों में बंद अलगाववादी मुजरिमों का भी मुद्दा यह कहकर उभार रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए वे भी कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं। तब क्या आदेश होंगे। बहरहाल यह तो निकट भविष्य में साफ हो पाएगा कि उच्च और अवर न्यायालय इस बिंदु पर क्या रुख अपनाते हैं, किंतु एक नई बहस छिड़ तो गई ही है।

रघोत्तम शुक्ल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी

विविधता का गलत लाभ उठाया

नीरजा माधव द्वारा लिखित आलेख 'राष्ट्रवाद के लिए खतरा वोट बैंक की राजनीति' पढ़ा। भारत विविधताओं का देश है। इस देश में कई जाति-धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इसी विविधता का गलत लाभ उठाकर आजादी के उपरांत देश में वोट बैंक की राजनीति प्रारंभ हो गई। प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की खातिर मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी। आज कई राजनीतिक दल कांग्रेस के पद चिह्नों पर चलते हुए तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल भाजपा को हिंदुत्व का समर्थक बताकर उनका वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। समय के साथ वोट बैंक की राजनीति में क्षेत्रवाद, भाषा और जाति-धर्म की राजनीति शामिल हो गई है। आज कई क्षेत्रीय दल जाति-विशेष की पार्टी बनकर रह गए हैं। कुछ पार्टियां क्षेत्रवाद की आग को भड़का रहे हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

मतदान के प्रति कम उत्साह

संपादकीय आलेख 'दायित्व निर्वहन का अवसर' पढ़ा। भीषण गर्मी के आगे मतदाताओं को बूथों तक पहुंचने में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरणों के मतदान में लोगों ने वैसा उत्साह नहीं दिखाया, जो 2019 में था। 2019 के मुकाबले तीनों चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई है। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें 2019 में दोपहर तीन बजे तक 69.12 प्रतिशत मतदान हुआ था। अबकी बार यह मतदान प्रतिशत 52.6 रहा। जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं में पिछले मतदान की तुलना में इस बार उत्साह ज्यादा था। मत प्रतिशत दोपहर तीन बजे तक 29.93 रहा, जबकि 2019 में 14.43 था। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष राज्यों में मतदान प्रतिशत कम रहा। अब तक के चुनावों में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप लगाया, जिसका आयोग ने खंडन किया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष ने तीन चरणों में हार मान ली है। 2024 का लोकसभा चुनाव गर्मी के 43 दिनों में सात चरणों में हो रहा है। यह मई है और अभी तीन चरण और शेष हैं, अंतिम चरण एक जून को निर्धारित है। मध्य मई से मध्य जून तक चिलचिलाती गर्मी देखी जाती है और सबसे खराब गर्मी के दिन होते हैं। मतदान में हिस्सा लेना हर वोटरों का संवैधानिक अधिकार है। मतदान न करने वाले सरकार से शिकायत करने का अधिकार नहीं रखते।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस प्रकार से वादे कर रहे हैं मानो वे प्रधानमंत्री बन ही गए हों। वे शेखी बघार रहे हैं या फिर यह अपनी आभा का भ्रम है? कौन जाने?

तवलीन सिंह@tavleen_singh

कांग्रेस का औपनिवेशिक सोच रह-रहकर बाहर आता रहता है। चुनाव आयोग कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि कांग्रेस चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह है। मल्लिकार्जुन खरगे को अपने हाईकमान को खुश करने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जम्मू-कश्मीर में 1987 के बाद से पहली बार सबसे अधिक मतदान हुआ है। जो लोग पूछते हैं कि अनुच्छेद-370 और 35-ए हटाने से जम्मू-कश्मीर में क्या बदला, उन्हें मतदान के लिए कश्मीर घाटी में उत्साह करारा जवाब है।

जगदीश उपासने@jdupasane

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने अपने साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट का संगीन आरोप लगाया। अगर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद भी मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षित नहीं हैं तो कौन ही रहेगा?

अविनाश के. झा@iavinashkjha

जनपथ

सबको मिलनी चाहिए 'लेवल प्लेइंग फील्ड',
सबको मिलनी चाहिए इक कानूनी 'शील्ड'।
इक कानूनी 'शील्ड' चहे चंगू या मंगू,
सब हैं राजा भोज न कोई तेली गंगू।
दिलवाई जिस भांति जमानत है बेढब को,
वही न्याय अभिषेक मनु दिलवाओ सबको।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प, बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक पिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 32

****

जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया गया, वह जीवन नहीं है।
- मदर टेरेसा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों जिस तरह स्थानीय लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उससे पता चलता है कि वहां की आर्थिक परेशानियों और शासन से जनता किस कदर त्रस्त है और हर मंच से कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की पीओके पर पकड़ ढीली पड़ रही है।

पीओके की दुर्दशा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में करों में वृद्धि और आटे व बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के नेतृत्व में चार दिन से चल रहे आंदोलन को लेकर इस्लामाबाद ने जैसा रवैया दिखाया, उससे पाकिस्तान की मुश्किलें जल्द खत्म होती नहीं दिख रहीं। अब वहां की सेना के खिलाफ लड़ रहे चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया है, उससे स्थितियों के और जटिल होने की आशंका भी गहराती है। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन को निष्फल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा फौज तैनात की और निहत्थे लोगों पर आंसू गैस व गोलियां बरसाई गईं, जो दर्शाता है कि इस्लामाबाद की मंशा वार्ता की नहीं, बल्कि आंदोलन को कुचलने की थी। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में जिस तरह विकास की गति तेज हुई है, सड़कों का नेटवर्क बढ़ा है और अब शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसे देखकर श्रीनगर से बमुश्किल डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पीओके के लोग भी अपनी सरकार से वैसी ही उम्मीद करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए और भारतीय ध्वज के प्रति समर्थन दिखाया, उसके गहरे निहितार्थ हैं। इससे भारत के गृह व रक्षा मंत्रियों के हाल ही में दिए गए वे बयान ही सच होते दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का विकास देखकर खुद पीओके के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करेंगे और भारत में मिलने की इच्छा जताएंगे। दूसरी बात यह कि पीओके के इस क्षेत्र में, जिसे दशकों से पाकिस्तान ने गैर-कानूनी ढंग से हथियाया हुआ है, पन-बिजली की बहुतायत है और यहां से पैदा होने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान में जाती है। ऐसे में, बिजली की दरों में रियायत की मांग कर रही अवाम की जब इस्लामाबाद द्वारा अनदेखी होती है, तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि, पहले से बदहाल इस्लामाबाद की अपनी मजबूरियां हैं।

पाकिस्तान को अगले पांच साल में 123 अरब डॉलर की फंडिंग की जरूरत है, पर नए बेल आउट पैकेज की उसकी मांग पर आईएमएफ पहले ही पसोपेश में है। हर मंच से कश्मीर का राग आलापने वाले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की दुर्दशा अब छिपी नहीं रह गई है, जहां के वर्तमान हालात इस क्षेत्र के अस्थिर राजनीतिक चरित्र को रेखांकित करने के साथ यह भी बताते हैं कि यहां की आर्थिक परेशानियों और शासन से जनता किस कदर त्रस्त है। इससे पीओके पर पाकिस्तान की ढीली होती पकड़ का भी संकेत मिलता है।

बयानबाजी, अफवाहें और भय का सूचकांक

नोबेलजयी हर्बर्ट साइमन ने एक बार कहा था कि सूचनाओं की अधिकता फोकस में कमी पैदा करती है। यह विचार राजनीति से लेकर हालिया चुनाव प्रचार पर भी लागू होता है, जिसकी गुणवत्ता और बहस की प्रकृति ने मतदाताओं को हैरान कर दिया है, जिसमें उन्हें उनकी ही पसंद बताई जा रही है।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अटकलों का बाजार गर्म है। बयानबाजी और अफवाहों की बाढ़ से विशेषज्ञ भी संदेह और घबराहट में हैं। पिछले बृहस्पतिवार को बेंचमार्क सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा गिर गया और शेयर बाजार के भय का सूचकांक (भारत वीआईएक्स अस्थिरता सूचकांक) अप्रैल के बाद बढ़ गया और इस हफ्ते 19 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि 'चार जून के बाद बाजार में तेजी आने वाली है।'

यह घबराहट अपरिहार्य है। आंकड़ों पर निर्भर नागरिक, कॉरपोरेट दिग्गज और विरोधी टिप्पणियों पर बारीक नजर रखने के लिए स्पीड-डायलिंग और गूगल कर रहे हैं। लोकसभा सीटों की कई गणनाओं को लेकर बाजार चिंतित है। मुख्य रूप से ध्यान कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार पर है, जहां 116 सीटों में से अकेले भाजपा ने पिछली बार 65 सीटें जीती थीं। क्या भाजपा इसे दोहरा सकती है? क्या इन राज्यों में पार्टी को नुकसान हुआ, तो क्या वह आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उसकी भरपाई कर लेगी?

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

कॉरपोरेट जगत बिहार की सीटों पर नीतीश के प्रभाव के असर को लेकर चर्चा कर रहा है। वे महाराष्ट्र में भाजपा की सीटों के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जातीय गणित का फैलाव और अफवाहों का प्रसार वास्तविक है? वे गुजरात में संभावित नुकसान की सुगबुगाहट, राजस्थान में चार-पांच सीटों पर अनिश्चितता और दिल्ली में केजरीवाल के प्रभाव के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। उन्हें इस बात को लेकर हैरानी हो रही है कि क्या कर्नाटक में मोदी की गारंटी पर कांग्रेस की गारंटी भारी पड़ रही है।

सितंबर, 2023 में एक वरिष्ठ निवेश बैंकर ने हवा में एक सवाल उछाला था कि क्या भाजपा के सत्ता में न लौटने का कोई खतरा है? पटना में विपक्षी गठबंधन बनने के बाद यह कठिन पहेली सामने आई थी। दस साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन किसी रुझान के लिए यह बहुत जल्दबाजी थी।

उसके कुछ महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सारे संदेहों को खत्म करते हुए जीत हासिल की। फिलहाल भाजपा की अगुवाई में राजग की 2019 की जीत को याद करना उपयोगी होगा। राजग गठबंधन ने गुजरात की सभी 26, महाराष्ट्र की 48 में से 41, बिहार की 40 में से 39, कर्नाटक की 28 में से 25, राजस्थान की 25 में से 24, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से नौ पर जीत हासिल की थी। मोदी के जादू ने 50 फीसदी से अधिक वोटों के साथ इन राज्यों में 2014 के 136 सीटों को 2019 में 224 कर दिया था और हिंदी पट्टी में जीत से उन महत्वपूर्ण 200 सीटों पर जीत की संभावना थी, जहां भाजपा का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला था।

फरवरी 2024 में भाजपा ने अपने गढ़ में 'अबकी बार 400 पार' का नारा दिया था। इसके पीछे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह था और समान नागरिक संहिता के वादे ने भाजपा के मूल मतदाताओं को सक्रिय कर दिया था। इसे कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थियों के एक बड़े जनाधार की नींव पर तैयार किया गया था और 2047 तक 'विकसित भारत' के वादे के अनुरूप बनाया गया था। निवेश-आधारित विकास पर ध्यान देने से शेयर बाजार के सूचकांक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए, जिससे निवेशक समुदाय रोमांचित हो गया। लेकिन मई आते-आते सीटों में कमी की बातें होने लगीं। आखिर बीच के इन हफ्तों में ऐसा क्या बदलाव हुआ, जिसने नए सवालों को प्रेरित किया?

प्रचार अभियान की रणनीति में बदलाव को लेकर सट्टेबाजों और आम जनता में काफी हैरानी है। पहले चरण में कम मतदान की आशंका के बाद भाजपा ने पहचान की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ है। केजरीवाल ने अपने प्रचार अभियान के दौरान उत्तराधिकारी के सवाल को उछाल दिया, जिस पर सुगबुगाहट जारी है। संघ परिवार के साथ भी मतभेद की बातें बार-बार उठ रही हैं। यह धारणा भी विवादास्पद है कि मोदी सरकार ने आरएसएस की प्रमुख आकांक्षाओं को पूरा किया है। सट्टेबाजों, सर्वेक्षणकर्ताओं और सियासी पंडितों के बीच बहस यह है कि क्या कहानी और रणनीति में बदलाव भाजपा के मूल मतदाताओं को मजबूत करेगा और/या इधर-उधर डोलने वाले मतदाताओं को भाजपा से अलग कर देगा। यकीनन इन लोगों के सवाल मतदान के इरादे के बारे में कम और बाजार की स्थिति के बारे में ज्यादा हैं। निश्चित रूप से अभी तक किसी ने किसी बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी नहीं की है। सबसे खराब स्थिति की परिकल्पना यह है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा 2014 की सीटों के करीब होगा।

हालांकि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि तेज हमले समर्थकों और विरोधियों के बीच भाजपा के कमजोर पड़ने की धारणा तैयार कर रहे हैं। दलगत राजनीति और पार्टी के भविष्य से अलग जैसी बयानबाजियां हो रही हैं, वे चुनाव प्रचार की गुणवत्ता के बारे में चिंता पैदा करती हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपनी पसंद की सरकार चुनने के पात्र हैं। इनमें से 1.8 करोड़ लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं, जो अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण तलाश रहे हैं। कल ही चौथे चरण के तहत 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ है। इससे पहले 285 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले ही मतदान हो चुके हैं। सैद्धांतिक रूप से चुनाव प्रचार प्रतिस्पर्धी बाध्यताओं और विरोधी संकटों की दुविधा के समाधान के बारे में होता है। इसके बजाय सभी पार्टियां प्रचार के दौरान दावे-प्रतिदावे और खुलासे-खंडन कर रही हैं। नारों के शोर ने मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने में शायद ही मदद की हो।

नोबेलजयी हर्बर्ट साइमन ने एक बार कहा था कि सूचनाओं की अधिकता फोकस की कमी पैदा करती है। साइमन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत (अधूरी जानकारी का प्रभाव और परिणामों पर प्रभाव) की उत्पत्ति सार्वजनिक नीति निर्माण से हुई थी और यह नियम चुनाव प्रचार पर भी लागू होता है। इस बार चुनाव प्रचार की गुणवत्ता और बहस की प्रकृति ने मतदाताओं को हैरान कर दिया है, जिसमें उन्हें उनकी ही पसंद बताई जा रही है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जस्टिन गार्डर

क्या कुछ ऐसा नहीं है, जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे हर किसी का सरोकार हो-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं?

आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता

हर किसी के अपने-अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक-टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई-धागे से कशीदाकारी करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं। किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ लोग केवल समाचार-पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं।

यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है, जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे हर किसी का सरोकार हो-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं?

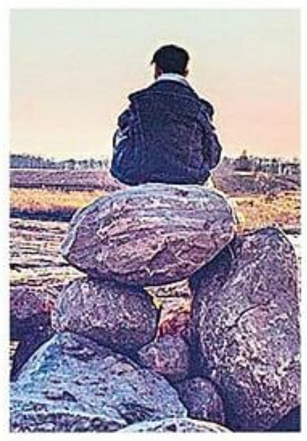

जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें, जो भुखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरनेवाले व्यक्ति से किया जाए, तो उसका उत्तर होगा, गरमाहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से करें, जो अकेला, अलग-थलग, नितांत एकाकी है, तो संभवतः उसका उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है, जिसे सब पाना चाहें, जिसकी सबको जरूरत है? आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए। और सभी को प्यार और देखभाल भी। किंतु कुछ और भी है, इन सबसे अलग, जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है, यह पता लगाना कि हम कौन हैं और यहां क्यों हैं? इस प्रश्न में रुचि लेना डाक-टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं, जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है, जब से मनुष्य यहां रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है, क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों-युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं, जिसमें इन प्रश्नों को कभी न कभी न उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहां से आई? आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने उत्तर खोजने हैं।

दुनिया एक पहेली...

सूत्र

अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है, वैसी ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदी नहीं होता। उसे दुनिया कुछ अनुचित-चौंकाने वाली, एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समान क्षमता है। आप चाहें, तो कह सकते हैं कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है।

8 सवाल

ऐसी सूचनाएं जिनका आपके जीवन से सीधा संबंध होता है, उनके बारे में आपके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब मिलेगा '8 सवाल' में...

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, डिब्बाबंद जूस में फलों का रस 10 फीसदी ही होता है। यही नहीं, पैकिंग की जानकारी भी भ्रम पैदा कर सकती है। आइए, जानते हैं इससे जुड़े कानूनों के बारे में...

खान-पान और कानून

1 रिपोर्ट में क्या है खास?
आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां प्राकृतिक उत्पाद का दावा कर उपभोक्ताओं की आंखों में धूल झोंक रही हैं। शुगर फ्री बताए जाने वाले खाद्य पदार्थों में वसा अधिक होती है। एक-दो अवयवों के नाम पर कंपनियां अपने उत्पाद को पोषक बताती हैं, ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के बजाय हानिकारक हो सकते हैं।

2 स्वस्थ भोजन का अधिकार?
संविधान के अनुच्छेद 21 को अगर अनुच्छेद 47 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो इस में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भोजन का अधिकार निहित है।

3 क्या कहता है कानून?
इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) 1860 की धारा 272 और 273 खाद्य अपमिश्रण से संबंधित है। इसमें खाद्य पदार्थ में मिलावट करने, या हानिकारक वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बनाने या बेचने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954 के अनुसार भी ऐसे पदार्थों को बेचना दंडनीय है।

4 मिलावट पर क्या करें?
खरीदते समय ही सामान की पूरी जानकारी पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी तरह की चूक पाते हैं, तो इसकी संबंधित अथॉरिटी से शिकायत की जा सकती है। इसके कई विकल्प हैं।

5 ऐसे करें शिकायत?
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/consumer grievance/ पर जाकर दिए गए निर्देशों को भरकर शिकायत करें। फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिये भी शिकायत कर सकते हैं।

6 क्या है FSSAI?
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि को नियंत्रित करना है।

7 क्या है सजा का प्रावधान?
खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के अंतर्गत छह महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तहत गलत ब्रांड या घटिया भोजन बेचने पर तीन से पांच लाख रुपये तक जुर्माना। असुरक्षित भोजन से मृत्यु पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड।

8 किन जगहों पर होती है जांच?
मैसूर, पुणे, गाजियाबाद एवं कोलकाता में चार केंद्रीय प्रयोगशालाएं हैं। गाजियाबाद में यूपी, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़ एवं दिल्ली राज्यों के खाद्य पदार्थों की जांच होती है।

आंकड़े

बाहरी कर्ज में कमी

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में बाहरी कर्ज में हाल के वर्षों में कमी आई है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है।

2023	18.6%
2022	20.0%
2021	21.1%
2020	20.9%
2019	19.9%

वर्ष 2023 के आंकड़े सितंबर तक के | स्रोत: RBI

शंकर जी ने कहा, उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे चिड़िया के भाग्य को बदलकर उसके जंगल को हरा-भरा करना पड़ा।

भक्ति की ताकत

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। जंगल सूख गया था। चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी, उसमें पत्ते नहीं थे, केवल सूखी टहनियां थीं। लेकिन वह चिड़िया वहीं रहकर शंकर जी का गुणगान करती रहती थी।

एक बार नारद जी उधर से गुजर रहे थे, तो चिड़िया ने नारद जी से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने बताया कि मैं शंकर जी से मिलने जा रहा हूं। उस चिड़िया ने कहा, वैसे तो भगवान शंकर जी मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन संभवतः उन्हें मेरे सूखे जंगल के बारे में पता नहीं है। आप जरा कहिएगा कि मेरे इस जंगल को हरा-भरा कर दें।

नारद जी ने शंकर जी के पास जाकर चिड़िया का संदेश सुनाया और उस जंगल को हरा-भरा कर देने की बात कहीं। शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके भाग्य में सात जन्मों तक सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी ने फिर कुछ नहीं कहा।

कुछ समय बाद नारद जी जब फिर उस जंगल से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि जंगल पूरी तरह से हरा-भरा था। और जंगल में पेड़ों पर फूल-फल लदे हुए थे। डाल पर बैठकर चिड़िया गा रही थी। नारद जी ने जब शंकर जी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया था, फिर भी वह मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे उसके भाग्य को बदलकर उसके जंगल को हरा-भरा करना पड़ा।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 2 मई, 1987

नेशनल हैरल्ड व कौमी आवाज का प्रकाशन शुरू

नेशनल हैरल्ड व कौमी आवाज का प्रकाशन शुरू

लखनऊ, १ मई, (वार्ता)। एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड के तीन लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में से दो नेशनल हैरल्ड और कौमी आवाज का प्रकाशन आज से फिर शुरू हो गया।

एक वर्ष पूर्व मई दिवस को प्रबंधकों ने इन समाचार पत्रों में तालाबंदी घोषित कर दी थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, श्रममंत्री सईदुल हसन, सूचना राज्यमंत्री श्रीमती दीपाबेल, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष [illegible] तथा अन्य श्रमिक नेताओं ने यहां प्रेस क्लब में आयोजित मई दिवस रैली के दौरान इन समाचार पत्रों के प्रबंधकों और कर्मचारियों को बधाई दी।

एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के तीन लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में से दो- नेशनल हैरल्ड और कौमी आवाज का प्रकाशन फिर शुरू हो गया है। एक वर्ष पूर्व प्रबंधकों ने इनका प्रकाशन बंद कर दिया था।

फनी वीडियो इतने भी फनी नहीं

फनी वीडियो पर कहकहे लगाइए, पर जब उन्हें इंटरनेट पर डालना हो, तो क्या डाला जाए और क्या नहीं, इस पर जरूर विचार करें।

मुकुल श्रीवास्तव | **समाज**

फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब संगीत के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में दर्शकों की पसंद फनी (मजाकिया) वीडियो या प्रैंक वीडियो ही हैं। खाली वक्त में जब करने के लिए कुछ खास न हो और हाथ में मोबाइल हो, तो लोग अक्सर इन वीडियो की तलाश में रहते हैं। जब स्क्रॉल करते हुए कुछ रोचक दिख जाता है, वे उसे देखने लगते हैं।

इंसान सदियों से एक-दूसरे के साथ मजाक करता आ रहा है। प्रैंक या मजाक ज्यादातर सांस्कृतिक मानकों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिनमें टीवी, रेडियो और इंटरनेट द्वारा स्थापित मानक भी शामिल हैं। लेकिन जब सांस्कृतिक और व्यावसायिक मानक मजाक करते वक्त आपस में टकराते हैं और अगर उन्हें जनमाध्यमों का साथ मिल जाए, तो उसके परिणाम भयानक साबित हो सकते हैं। दिसंबर, 2012 में जैसिंथा सल्दान्हा नामक भारतीय मूल की एक ब्रिटिश नर्स ने एक प्रैंक कॉल के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पूरी दुनिया में बहस चल पड़ी कि इस तरह का मजाक किसी के साथ करना और फिर उसे रेडियो टीवी या इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देना कितना जायज है?

वर्ष 2012 में इंटरनेट इतने बहुआयामी माध्यमों के साथ हमसे नहीं जुड़ा था, लेकिन आज के हालात एकदम अलग हैं। आज हिट्स और क्लिक से पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया है कि क्या दिखाया जा रहा है, बस व्यूज मिलने चाहिए। ऐसे में भारत एक खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, जिसमें प्रैंक वीडियो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

दुनिया में ऑनलाइन प्रैंक वीडियो की शुरुआत यूट्यूब और फेसबुक जैसी साइट्स के आने से बहुत पहले हो गई थी। वर्ष 2002 में इंटरेक्टिव फ्लैश वीडियो स्केयर प्रैंक के नाम से पूरे इंटरनेट पर फैल गया था। थॉमस हॉब्स उन पहले दार्शनिकों में थे, जिन्होंने यह माना कि मजाक के बहुत सारे कार्यों में से एक यह भी है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए मजाक का इस्तेमाल सामाजिक शक्ति पदानुक्रम को अस्त-व्यस्त करने के लिए करते हैं। मजाक की श्रेष्ठता के सिद्धांतों को मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संघर्ष और शक्ति संबंधों के संबंध में समझा जा सकता है। विद्वानों ने माना कि संस्कृतियों में मजाक का इस्तेमाल अक्सर 'हिंसा को सही ठहराने और मजाक के लक्ष्य को अमानवीय बनाने के लिए' किया जाता है। इन चर्चाओं के बीच इंटरनेट पर मजाक का शिकार हुए लोगों की चिंताएं गायब हैं।

सबसे मुख्य बात सही और गलत के बीच का फर्क मिटना है। इंटरनेट जिस गति से देश में पैर पसार रहा है, उस गति से लोगों में डिजिटल साक्षरता नहीं आ रही है, इसीलिए निजता के अधिकार जैसी जरूरी बातें कभी विमर्श का मुद्दा नहीं बनतीं। किसी ने किसी से फोन पर बात की, अपना मजाक उड़वाया, यह मामला यहां तक तो व्यक्तिगत है। लेकिन वही वार्तालाप अगर इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक हो जाए, तो जिस कंपनी के सौजन्य से यह सब हुआ, उसे हिट्स, लाइक और पैसे मिले, लेकिन जिस व्यक्ति के कारण यह सब हुआ, उसे क्या मिला? यह सवाल अक्सर पूछा नहीं जाता। ऐसे सैकड़ों ऐप हैं, जिन्हें डाउनलोड करके आप मजाकिया वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो आम लोगों ने ही अचानक बना दिए हैं। कोई व्यक्ति मेन होल में गिर जाता है और उसका मजाकिया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और फिर अनंतकाल तक के लिए सुरक्षित भी हो जाता है।

हमने उस वीडियो को देखकर खूब हंसते हैं, पर कभी उस परिस्थिति में खुद को रखकर नहीं सोचते। इंटरनेट ने निहायत निजी चीजों को सार्वजनिक कर दिया है। ये निजी चीजें जब चारों ओर बिखरी हों, तो हम उन असामान्य परिस्थिति में घटी घटनाओं को भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जिससे एक परपीड़क समाज का जन्म होता है। यही कारण है कि कोई दुर्घटना होने पर लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लग जाते हैं। मजाकिया और प्रैंक वीडियो पर कहकहे लगाइए, लेकिन जब उन्हें इंटरनेट पर डालना हो, तो क्या डाला जाए और क्या नहीं, इस पर जरूर विचार करें। यह फैसला कोई सरकार नहीं करेगी, हमें ही करना है। इसी से तय होगा कि हमारा भविष्य का समाज कैसा होगा।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के खतरे हजार

आपदाएं यों तो कभी कह कर नहीं आतीं, लेकिन इनकी मार बहुत गहरी होती है। यह बात भी सही है कि बाढ़, तूफान, सूखा व अतिवृष्टि जैसी आपदाएं मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी रहती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कराए गए अध्ययन में यह तथ्य चौंकाने वाला है कि देश के आपदा प्रभावित कुछ राज्यों में महिलाएं और बच्चे इन्हीं आपदाओं के कारण सेहत से जुड़े कई खतरों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से इन इलाकों में महिलाओं में समय पूर्व प्रसव, कम वजन की संतान का पैदा होना और बच्चों का कद कम रहने की आशंका ज्यादा रहने लगी है।

इस अध्ययन में यह जानकारी तो और भी डराने वाली है कि हमारे देश में इक्यावन फीसदी बच्चे गरीबी और जलवायु परिवर्तन से जुड़े दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं। जाहिर है कि लगातार आपदा आते रहने के कारण बच्चों के पोषण पर भी असर गरीबी की वजह से ही ज्यादा पड़ता है। सिर्फ बच्चों में ही नहीं गर्भवती महिलाओं में भी कुपोषण का संकट गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु के शारीरिक विकास पर भी विपरीत असर डालता है। इन तमाम खतरों के बीच लगातार बढ़ता तापमान भी गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ बच्चों में घातक संक्रामक बीमारियों के प्रसार का खतरा बढ़ाने के लिए काफी है। मंत्रालय के अध्ययन में इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई है कि नीति निर्माण के दौरान कुपोषण, कम उम्र में गर्भधारण व महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा तक के बढ़ते मामलों के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। बात सिर्फ आपदाओं की ही नहीं, समुचित पोषण की भी है। महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे तो भावी पीढ़ी को मजबूत करने का काम कैसे हो सकेगा। इस अध्ययन में ही उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में 35 करोड़ से ज्यादा बच्चे साल में कम से कम एक बार जरूर किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं। ऐसे में हमें इस संकट के समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत है।

चिंता इस बात की भी है कि सरकारों की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समुचित लाभ संबंधित लोगों तक या तो पहुंच ही नहीं पाता या जरूरत के वक्त नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के साथ महिलाओं और बच्चों के पोषण की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। आजादी के करीब 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के बड़े हिस्से में महिलाएं व बच्चे संकटग्रस्त हों, तो यह वाकई चिंता की बात है। इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने ही होंगे।

मुंबई उत्तर : पिछले दो चुनाव जीते गोपाल शेट्टी का टिकट काट कर भाजपा ने खेला बड़ा दांव

भाजपा हैट्रिक लगाने की तैयारी में, उद्धव को साथ लेकर कांग्रेस रोकने को है सामने

मुंबई से
दौलत सिंह चौहान

मुंबई महानगर की छह सीटों में से मुंबई नॉर्थ सीट भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मैदान में उतरने से सुर्खियों में है। मुंबई के सायन इलाके के निवासी सीए गोयल अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे राज्यसभा से दो बार केन्द्र सरकार में मंत्री बने हैं। मुंबई और भाजपा में उनका बड़ा नाम है। पिछले दो चुनाव से भाजपा की लगातार जीत वाली यह सीट महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस ने यहां से अपने स्थानीय नेता भूषण पाटिल को उतारा है। यहां से 2014 और 2019 का चुनाव भाजपा के गोपाल शेट्टी ने 4-4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता। शेट्टी हालांकि टिकट न मिलने से हैट्रिक बनाने की कोशिश नहीं कर पाए, लेकिन पीयूष गोयल की उम्मीदवारी से भाजपा इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीतने की उम्मीद कर रही है।

फर्क तो पड़ेगा

गोपाल शेट्टी का टिकट उनके विवादित मामलों को लेकर कटा बताते हैं और यह भी दावा किया जा रहा है कि वे नाराज नहीं हैं और पूरी तरह से गोयल के साथ हैं। भाजपा ने गोयल का नाम काफी पहले घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय करने को लेकर अंत तक असमंजस रहा। राजस्थानी और गुजराती प्रवासी बहुल इस इलाके में उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कालूभाई पुदलिया, जो गुजराती हैं, का नाम भी चर्चा में आया। अंत में फैसला स्थानीय और मराठी नेता और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूषण पाटिल के पक्ष में गया। टिकट कटने से भाजपा में गोपाल शेट्टी और कांग्रेस में कालूभाई की नाराजगी की बात को हालांकि भाजपा और कांग्रेस के नेता गलत बता रहे हैं, लेकिन शेट्टी और पुदलिया के समर्थक कहते हैं कि फर्क तो पड़ेगा। शंकर लेन स्थित कांग्रेस ऑफिस में मिले पुराने कांग्रेसी श्याम भाई ने तो यहां तक कह दिया कि गोयल को हराने का अवसर हमने खो दिया। शेट्टी के समर्थकों का कहना है कि उनको चुनाव के बाद बड़ा पद देने का वादा किया गया है।

पीयूष गोयल

भूषण पाटिल

क्या कहता है मतदाता

शंकरलेन में फल की रेड़ी लगाकर बैठे उत्तर प्रदेश बनारस के रमाशंकर ने कहा बदलाव तो होना चाहिए लेकिन अभी साफ-साफ पता नहीं चल रहा है कि लोगों के मन में क्या है। बरसों पहले राजस्थान के फालना से आकर मुंबई में जनरल स्टोर चला रहे रूपाराम चौधरी ने सवाल के जवाब में सवाल किया, विपक्ष है कहां? इसी वजह से सब मोदी जी के साथ हो गए, मोदी ही भारी पड़ेंगे। कपड़ा व्यवसायी भैरूलाल जैन ने बताया कि रेड़ी-ठेले वालों से दुकानदारों को हो रही समस्या को लेकर गोयल ने हमें समाधान का आश्वासन दिया है। लोकल ट्रेन में सफर कर रहे असलम खान ने कहा पहले से सब कुछ तय तो है वोट देने का कोई मतलब नहीं है। मुंबई में लंबे समय से टैक्सी चलाकर पेट पाल रहे इलाहाबाद निवासी राममिलन यादव बोले किसी नेता का कोई भरोसा नहीं है। जनता का विश्वास नेताओं पर से उठ गया है। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से व्यथित यादव बोले करोड़ों रुपए बेरोजगारों से जमा कर लिए और कह दिया कि पेपर लीक हो गया। हालात अच्छे नहीं है।

सीट का इतिहास

पिछले दो लोकसभा चुनाव से भाजपा का गढ़ बनी यह सीट 2014 से पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। 2004 में यहां से भाजपा के दिग्गज राम नाइक को कांग्रेस के फिल्म अभिनेता गोविंदा और 2009 में कांग्रेस के संजय निरुपम ने हराया। अब ये दोनों कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसके बाद 2014 में भाजपा के गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस के संजय निरुपम और 2019 में कांग्रेसी प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को हराया। अब हालात काफी बदल चुके हैं। मुंबई उत्तर भाजपा ने स्थिति मजबूत बना ली है।

भाजपा का पलड़ा भारी

मुंबई सिटी का गेटवे कही जाने वाली इस लोकसभा सीट में बोरीवली, दहीसर, मगाथेन, कादिवली ईस्ट, चारकोप और मलाड वेस्ट 6 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में इनमें से 4 विधायक भाजपा के, शिवसेना शिंदे और कांग्रेस का 1-1 विधायक है। सघन आबादी वाले इस इलाके में साढ़े पांच लाख मराठियों के बाद सबसे बड़ी संख्या में गुजराती और राजस्थानी (लगभग 5 लाख) मतदाता हैं। उत्तर भारतीय साढ़े तीन लाख, मुस्लिम डेढ़ लाख और दक्षिण भारतीय सवा लाख भी अहम भूमिका में हैं। गोयल का बड़ा नाम होने के साथ क्षेत्र में कुल 6 में से 4 विधायकों के मद्देनजर भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है।

पीयूष गोयल की उम्मीदवारी से भाजपा जीत को लेकर सौ टका आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस के नए चेहरे भूषण पाटिल के समर्थकों को इस बार शिवसेना उद्धव के सपोर्ट के सहारे नैया पार लगने की उम्मीद है। पाटिल के चुनाव कार्यालय में मिले शिवसेना उद्धव के नेता सुरेश शिंदे ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से पाटिल के साथ हैं। उत्तर मुंबई की भाजपा की प्रचार प्रमुख नीला सोनी राठौड़ से कार्यालय में मुलाकात हुई। सोनी का दावा इस बार रेकॉर्ड तोड़ अंतर से जीत होगी। गोयल पूरे इलाके को दो बार कवर कर चुके हैं। गोयल ने यहां बन रहे 400 बेड के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को इलाके की जरूरत को देखते हुए 1000 बेड का करने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल के मुख्य चुनाव कार्यालय में मिले मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि गोयल इस इलाके के नहीं सायन के हैं और अब ज्यादातर समय में वे दिल्ली में रहते हैं। भूषण उत्तर मुंबई के भूमि पुत्र और लोगों के बीच काम करने वाले नेता हैं। उनको गरीबों की समस्याओं का पता है। मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष संदेश कोंडविलकर ने कहा गोयल तो जीत कर दिल्ली चले जाएंगे फिर वापस इलाके में आएंगे या नहीं, कौन जानता है। भूषण को यहीं जनता के बीच रहना है।

मोदी के भाषणों का असर

पहले दो चरणों के कम मतदान के बाद आई खबरों को देखते हुए पीएम मोदी ने जिस तरह अपने भाषणों का 'गियर' बदला है, उसका असर मुंबई में भी साफ देखने को मिला। मतदाता भी राम मंदिर, हिंदू- मुस्लिम की बात करने के साथ विपक्ष पर सवाल उठाने लगा है। हाल ही हिंदू-मुस्लिम आबादी को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आंकड़ों और रिपोर्ट जारी होने की टाइमिंग पर बहस शुरू हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से सैम पित्रोदा का बयान, राम मंदिर के शुद्धीकरण संबंधी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भाजपा के लिए 'आइसिंग ऑन द केक' की तरह है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हर स्तर के नेता ने इन बयानों को हाथों-हाथ लिया है और वे विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस शोरगुल में खो चुके हैं। विपक्ष की तरफ से भी महाविकास अघाड़ी के नेता मोदी और भाजपा पर आक्रामक हैं। 20 मई तक स्थिति क्या बनेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हां, गर्मी की छुट्टियों में खासकर प्रवासी मतदातोओं के अपने घर लौटने की वजह से मतदान प्रतिशत को लेकर भाजपा में चिंता बनी हुई है।

जापान : शाही उत्तराधिकारी कानून पर बहस

जनमानस साम्राज्ञी पर विचार के समर्थन में

संदीप गोयल
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, रिडिफ्यूजन एडवरटाइजिंग
@patrika.com

जापान में हाल ही क्योडो न्यूज द्वारा करवाए गए एक पोल में सामने आया है कि 90 प्रतिशत लोग जापान में महिला शासक (साम्राज्ञी) के विचार का समर्थन करते हैं। पिछले कई सालों में जन मानस में यह बड़ा बदलाव आया है। वर्तमान शासक नारूहीतो के साम्राज्य की पांचवी वर्षगांठ से ठीक पहले मार्च-अप्रेल में करवाए गए सर्वे के परिणामों से स्पष्ट है कि जापान की अधिकांश जनता इस बात पर मुहर लगाती है अब महिला को शासन का अधिकार मिले। अभी यहां पितृसत्तात्मक शासन परम्परा के तहत पुरुष उत्तराधिकारी को ही शासनाधिकार मिलता आया है।

जापान के शाही परिवार में पुरुष उत्तराधिकारियों की कमी के चलते यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। सर्वे में भाग लेने वाले 72 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें 'शाही उत्तराधिकारी संकट' का अंदाजा है। 1947 के राजसी नियमों के अनुसार, देश का राजा पैतृक परिवार का पुरुष उत्तराधिकारी ही होना तय हुआ है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि परिवार की महिला सदस्य विवाह के बाद शाही परिवार का दर्जा छोड़ देगी। जापान के राजा नारूहीतो(64) के परिवार में तीन संभावित पुरुष उत्तराधिकारी हैं-उनके भाई क्राउन प्रिंस फुमीहीतो(58), उनके भतीजे प्रिंस हिसाहीतो(17) और उनके चाचा प्रिंस हिताची(88)। सम्राट व रानी मसाको के केवल एक संतान है -22 वर्षीय राजकुमारी आइको।

2021 में एक सरकारी पेनल को यह कार्य सौंपा गया था कि वह स्थायी शाही उत्तराधिकारी पाने के लिए अध्ययन कर पता लगाएं कि क्या महिला या मातृसत्तात्मक सदस्य शाही उत्तराधिकारी हो सकती है। सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन की पक्षधर दिखाई दे रही है ताकि दुनिया के सबसे पुराने राजतन्त्र को उत्तराधिकार संकट से छुटकारा दिलवाया जा सके। पारम्परिक कट्टरपंथियों ने पहले इस परिवर्तन का विरोध किया था, परन्तु अब पार्टी दो प्रस्ताव लाई है। पहला 2021 में ही ले आई थी, जिसे 'वाजिब' और 'व्यवहारिक' माना गया। एक संभावित सुझाव के अनुसार शाही परिवार की महिलाओं को इस बात की अनुमति मिल कि वे शादी के बाद भी अपना शाही दर्जा कायम रख सकें। इस प्रकार उनकी पुरुष संतान उत्तराधिकार योग्य मानी जाएगी। दूसरा सुझाव यह है कि परिवार की उन शाखाओं की बहाली की जाए जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्म समर्पण के बाद अमान्य मान ली गई थीं। कारण यह था कि तत्कालीन शक्तियां जापानी शासक की ताकत को कम करना चाहती थीं। अपनी शाखाओं को फिर से परिवार से जोड़ कर शाही परिवार को बहुत से उत्तराधिकारी यानी पुरुष उत्तराधिकारी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

2005 में जापानी संसद डाइट में महिला उत्तराधिकारी पर रोक का कानून खत्म करने को लेकर बहस चल रही थी कि खबर आई कि राजा के भाई प्रिंस अकीशीनों फुमोहोतो और उनकी पत्नी के एक और संतान होने वाली है। इसलिए सुधारात्मक बहस रुक गई। प्रिंस हिसाहीतो के रूप में शाही परिवार में पुरुष संतान जन्मी तो सारी चर्चा पर विराम लग गया। आज क्राउन प्रिंस उत्तराधिकारी की पंक्ति में पहले नम्बर पर आते हैं। उनके पुत्र हिसाहीतो अगले नंबर पर आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अपने आठ वर्षों के कार्यकाल के दौरान शाही परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के अवसरों को बर्बाद करने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे दोषी हैं। उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि अगले 40 वर्षों तक किसी कानूनी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्राट नारूहीतो के दो पुरुष उत्तराधिकारी हैं।

कमल खिलावन | POLI नोक-झोंक | पंजा सिंह

वो आ गया...

(राजधानी दिल्ली। थोड़ी सी बारिश के बाद सीपी (कनाट प्लेस) पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। तिरंगे वाले गार्डन में सेल्फी खिंचाने के बाद दो परम प्रिय धुर विरोधी आमने-सामने)

पंजा सिंह: *वो आ गया.. वो आ गया...।*

कमल खिलावन: *पुरानी फिल्म देख ली क्या, रात को कोई.. जो मुखड़ा गुनगुना रहे हो...।*

पंजा सिंह: *वो आ गया और उसने बोलती बंद करा दी...।*

कमल खिलावन: *कौन आया... किसकी बोलती बंद...।*

पंजा सिंह: *हमारे विपक्षी गठबंधन का ब्रेन जेल से आ गया। और उसने तुम सभी की बोलती बंद करा दी।*

कमल खिलावन: *अरे वो.. एक आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया है। इसमें क्या बोलती बंद ? 2 जून को फिर अंदर..।*

पंजा सिंह: *उसके एक बयान '75 साल' पर तुम्हारी हवाइयां उड़ गईं। अपनी पार्टी का संविधान टटोलने लगे। ऊपर से नीचे तक सब सोशल मीडिया पर जवाब देते फिर रहे हो।*

कमल खिलावन: *हमे फर्क नहीं पड़ता।*

पंजा सिंह: *फर्क नहीं पड़ रहा होता तो जेल भेजते क्या, चुनाव के समय।*

कमल खिलावन: *ईडी के समन का जवाब नहीं दिया, इसलिए इस समय जेल गए।*

पंजा सिंह: *ये वकीलों की भाषा है, कोर्ट में ही अच्छी लगती है। जनता सब जानती है।*

कमल खिलावन: *आप जनता हैं?*

पंजा सिंह: *जितनी कम सीट पर सिमटते जा रहे हैं, जनता ही हो जाते कुछ दिनों में। हां, पर इस बार के गठबंधन से उम्मीद बंधी हैं हमारी।*

कमल खिलावन: *4 जून को गठ अलग हो जाएगा बंधन अलग। लिखवा कर ले लो।*

पंजा सिंह: *लिखकर मत दो फंस जाओगे। ऐसा ही एक बयान लोकपाल आंदोलन के बाद दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था। 'हिम्मत है तो राजनीति में आकर दिखाओ'.. वो आ गया.. और फिर जम गया।*

कमल खिलावन: *हां ये तो है, कई बार बड़े बोल, उलटे पड़ जाते हैं। पर तुम्हारी दिल्ली राज्य की सत्ता जिसने सिमटाई.. इस बार तुम उसी के भरोसे हो।*

पंजा सिंह: *मजबूरी है। राजनीति में आपको मिटाने वाले से भी पंजा मिलाना पड़ता है। अपने आपको बचाने के लिए।*

कमल खिलावन: *गजबे राजनीति है तुम्हारी।*

पंजा सिंह: *तुम्हारी नहीं क्या.. आधे तो हमारे यहां के ही आ गए।*

कमल खिलावन: *हम तुमसे देश को मुक्त कराने का नारा लेकर चले हैं। पूरा करेंगे।*

पंजा सिंह: *लगता नहीं। अभी तो हमारे 'ब्रेन' से बचो। वो रोज ऐसा बयान देगा, तुम जवाब ही नहीं दे पाओगे।*

कमल खिलावन: *और सुकेश ने जेल से चिट्ठी लिख दी तो वो जवाब दे पाएंगे क्या।*

पंजा सिंह: *बात को घुमाओ मत।*

कमल खिलावन: *(हाथ घुमाता है, गाल पर लगता है) तो ये घुमाऊं।*

(पंजा सिंह भी घुमा कर देता है। दोनों गुत्थम-गुत्था। पब्लिक देख रही है। दिल्ली की पब्लिक ऐसे मौकों पर कुछ बोलती नहीं, चुनाव के दिन ही बोलती है।)

- सुप्रिया शर्मा

पर्यावरण : बढ़ते अग्निकांडों के चलते वनों एवं कचरागाहों पर निरंतर निगरानी रखना आवश्यक है

जीवन बचाने के लिए आग का तांडव रोकें

डॉ. विवेक एस. अग्रवाल
संचार और शहरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ
@patrika.com

> आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने संपूर्ण जैव विविधता को प्रभावित किया है। अत्यधिक गर्मी के कारण वानस्पतिकी के लिए आवश्यक कीट पतंगों की भी हानि होती है।

इन दिनों आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में अग्नि विभीषिका ने तो संपूर्ण प्रशासन को हिला कर रख दिया है। दुनिया के सबसे बड़े 50 कूड़े के ढेर में शुमार गाजीपुर समेत अनेकानेक कचरागाहों पर भी निरंतर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। बची खुची कसर स्वच्छता सर्वेक्षण की आड़ में शहरों को साफ रखने की कवायद में अनियंत्रित खुले कूड़े के ढेर भी जलाए जा रहे हैं। इन सबसे आम जन का जीवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। कुछ पर यह आंच आज आ रही है तो बाकी सब भी भविष्य में प्रभावित होने ही वाले हैं। ये घटनाएं महज क्षेत्रीय स्तर पर नहीं देख कर वातावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से देखी जानी चाहिए।

वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड में लगी आग ने तो सभी का ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन अन्य कचरागाहों में लगने वाली आग से आम जन बेखबर रहता है क्योंकि प्रथमतः वे शहरी हद से दूर होते हैं और द्वितीय कूड़े की तरफ देखना कोई पसंद भी नहीं करता। अग्नि मात्र तपिश ही पैदा नहीं करती अपितु वातावरण में जहर घोलने का कार्य भी करती है। आग से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान प्राणवायु ऑक्सीजन को कम करती है और परिणामस्वरूप विभिन्न गंभीर बीमारियों का कारक बन जाती है। स्वतः ज्वलनशील मीथेन गैस तो स्वाभाविक रूप से कार्बन उत्सर्जन करने वाली और विष रूप ही है जो जलवायु परिवर्तन की जड़ है। सीधे तौर पर इस कारण श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कई बार अग्नि क्षेत्र में सांस लेने मात्र से मृत्यु तक हो जाती है। श्वास में ऑक्सीजन की कमी के कारण रक्त की कमी, हृदय एवं तंत्रिका संबंधी रोगों की आशंका, विषैले पदार्थों की अधिकता समेत अनेक व्याधियां जन्म ले लेती हैं। जंगलों या कचरागाहों पर लगने वाली आग के पीछे मूलतः दो कारण होते हैं जिसमें एक मानवीय और दूसरा पारिस्थितिकी जन्य होता है। मानवीय कारण में बीड़ी-सिगरेट का उक्त स्थलों पर बिना सोचे समझे उपयोग, जंगलों में आयोजित होने वाली पार्टियां भी हैं। इस तरह की आग की सूचना समय पर मिल जाने से इस पर शीघ्र काबू पा लिया जाता है।

वातावरणीय परिवर्तन यथा तेज गति से वायु प्रवाह, बिजली गिरना, बहुत ज्यादा तापमान आदि कारण भी आग लगती है। इन परिस्थितियों में आग यकायक लग जाती है और उसके बारे में जानकारी बहुत बाद में मिलती है। ऐसे में इस तरह की आग नियंत्रण के बाहर हो जाती है। ऐसी आग को नियंत्रित करने के लिए अपरिमित संसाधन आवश्यक होते हैं और विस्तार की गति सीधे तौर पर वायु की गति पर निर्भर करती है। उत्तराखण्ड के जंगलों में लगी आग चीड़ के पेड़ों एवं सूखे पत्तों की बहुतायत होने से भीषण हो गई। जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कम वर्षा, तेज तापमान से बढ़ते सूखे ने भी वनों में अग्नि की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार कचरगाहों पर प्लास्टिक, कागज एवं कपड़े भी आग के फैलाव में सहायक बनते हैं। हाल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सूखे पत्तों को हटाने का अभियान छेड़ा है, जो सराहनीय है। आग लगने के बाद आग बुझाने के अभियान के साथ निवारक कदम उठाना भी अपेक्षित है। विगत 7-8 माह से वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म माह के कीर्तिमान कायम हो रहे हैं, जो आग लगने की घटनाओं के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। गत वर्ष कनाडा, अमरीका, दक्षिणी अमरीका के अनेक देशों ने सदी की सबसे बड़ी जंगलों की आग का सामना किया है। आग की घटनाओं का हिमालय क्षेत्र में विस्तार शुभ संकेत नहीं है। भारत के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र के वन विशेष महत्त्व रखते हैं क्योंकि इन्हीं से ही मौसम और पारिस्थितिकी का संतुलन होता है। हिमालय क्षेत्र की आग से भूस्खलन एवं भूमि में कटाव की घटनाएं बढ़ने का अंदेशा भी प्रबल हो जाता है। साथ ही अग्नि नियंत्रण के लिए संसाधनों की आवश्यकता से बढ़ता आर्थिक बोझ भी नकारा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुराने कचरागाहों से मुक्ति बाबत किए गए प्रयासों के बावजूद कूड़े के ढेर कम नजर होते प्रतीत नहीं हो रहे। दस वर्षों के प्रयास से कूड़े के संग्रहण में तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है किंतु उसके प्रसंस्करण एवं निस्तारण में अपेक्षित अभिवृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप जितने कूड़े के ढेर साफ होते हैं उससे अधिक पैदा हो जाते हैं और कूड़े में आग लगने के लिए अनुकूल वातावरण बना देते हैं। इन कूड़े के ढेरों में लगने वाली आग ज्यादा विनाशकारी है। इसकी वजह यह है कि कचरागाहों पर पुनःचक्रण के लिए वस्तुएं बीनने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। ये लोग भी हादसों के शिकार हो जाते हैं। यदि बालश्रम कानून की खुली धज्जियां उड़ते देखना हो तो कचरागाहों का अवलोकन कर सकते हैं।

आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने संपूर्ण जैव विविधता को प्रभावित किया है। अत्यधिक गर्मी के कारण वानस्पतिकी के लिए आवश्यक कीट पतंगों की भी अस्वाभाविक रूप से हानि होती है। इनके अभाव में विभिन्न जैव उत्पादों को गैर नैसर्गिक तरीके से उन्नत किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। मानव जीवन एवं अन्य दृश्य प्राणियों के बचाव के लिए तो प्रयास किए जाते हैं लेकिन सृष्टि के लिये महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म एवं अदृश्य प्रकृति के जीवों को संरक्षित करना प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों में नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार आग लगने की बढ़ती घटनाओं के चलते जीव जंतुओं के साथ अनेकानेक कीट पादपों का अस्तित्व ही संकटमय हो जाएगा। अत्यधिक ताप के कारण इन सभी की प्रजनन गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। अत्यधिक तापमान का आनुवंशिकी स्तर पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

आग लगने की घटनाओं को मात्र समय या स्थान विशेष की घटना ही नहीं समझना चाहिए। इसके व्यापक प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए और समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, इस बाबत पुराने आंकड़ों के आधार पर सुस्पष्ट एवं विश्वसनीय भविष्यवाणी के तंत्र को विकसित करना भी आवश्यक है। वनों एवं कचरागाहों पर निरंतर निगरानी रखना नितांत आवश्यक है। एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भविष्य के लिए सुदृढ़ निवारक नीति की आवश्यकता है।

आज का सवाल

कमजोर सार्वजनिक परिवहन तंत्र के क्या नुकसान हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

अनदेखी का परिणाम

सरकारी विभागों की अनदेखी के चलते क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक नहीं किया जाता। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगा दी जाती है। इससे सड़क शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाती है।
-आनंद सिंह राजावत, पाली

जनता को जागना होगा

जनता को जागरूक होना होगा और संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को जगाना होगा, तभी क्षतिग्रस्त सड़कों पर हो रहे हादसों से बचा जा सकता है।
-शंकर गिरि, रावतसर, हनुमानगढ़

गारंटी ली जाए

तकनीक का इतना विकास हो चुका है, इसके बावजूद सड़कों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठेका देते समय ही ठेकदार से निर्माण कार्य की पांच साल की गारंटी ली जाए।
-मुकेश भटनागर, भिलाई, छत्तीसगढ़

भ्रष्टाचार का खेल

सड़क निर्माण में कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार का खेल चलता है। क्षतिग्रस्त सड़कों की सुध नहीं ली जाती और अच्छी खासी सड़कों को तोड़ कर दोबारा बना दिया जाता है।
-नरेश कानूनगो, देवास, मध्यप्रदेश

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'क्षतिग्रस्त सड़कों को समय रहते ठीक क्यों नहीं किया जाता?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें
rb.gy/rr3p0q

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

सच्ची आजादी उसके भाग्य में नहीं, जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है। अपने आप को गंवाकर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है।

– सरदार पूर्णसिंह

भ्रम का जाल

कुछ दिन पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आइसीएमआर की आनुषंगिक संस्था राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने अपने एक अध्ययन में बताया था कि जीवन-शैली संबंधी आधी से अधिक बीमारियां खानपान में गड़बड़ी की वजह से होती हैं। अब उसी क्रम में आइसीएमआर ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ऊपर लिखी जानकारियां भ्रामक हो सकती हैं। इसलिए उनके चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। उसने बकायदा उदाहरण देकर समझाया है कि फलों के रस के नाम पर बिकने वाले पेय में दस फीसद ही फलों का अंश हो सकता है, बाकी शर्करा हो सकती है। ऐसे अनेक खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर भ्रामक दावे लिखे मिल सकते हैं कि उनका उपयोग सेहत के लिए अच्छा है। निश्चय ही आइसीएमआर के इस सुझाव से लोगों में कुछ जागरूकता पैदा हो सकती है। मगर सवाल है कि जब यह बात खुद आइसीएमआर जैसी स्वास्थ्य से जुड़ी शीर्ष संस्था को पता है कि भ्रामक जानकारियों के साथ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बाजार में बेचे जा रहे हैं, तो इसके प्रति वह केवल उपभोक्ता को जागरूक बना कर इस समस्या से पार पा लेने का कैसे भरोसा कर सकती है।

लंबे समय से इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि डिब्बाबंद और तुरंता आहार खासकर बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। इनके चलते मोटापा, मधुमेह, हृदयरोग जैसी अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। फिर भी हैरानी की बात है कि ऐसे खाद्य पदार्थों के जोखिम खुद उपभोक्ता के कंधे पर डाल कर जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ दशक पहले जब डिब्बाबंद खाद्य और पेय पदार्थों में हानिकारक तत्त्व मिले होने को लेकर सवाल उठने शुरू हुए थे, तब सरकार ने ऐसे उत्पाद की गुणवत्ता पर नजर रखने और कंपनियों को जवाबदेह बनाने की गरज से भारत खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआइ का गठन किया था। यह नियम बना कि एफएसएसआइ से प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कोई भी डिब्बाबंद या पैकेट वाला खाद्य पदार्थ बाजार में नहीं उतारा जा सकता। बाजार में उपलब्ध इस तरह के हर खाद्य पदार्थ की थैली या डिब्बे पर इस प्रमाणपत्र का उल्लेख होता है। मगर इसके बावजूद उनमें हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल और भ्रामक दावे बंद नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है।

आइसीएमआर ने तो डिब्बों पर लिखे विवरण जांच कर ही खाद्य पदार्थ खरीदने की सलाह जारी कर दी है, मगर सवाल है कि ऐसा कितने लोग कर पाते हैं और कर पाएंगे। खाद्य पदार्थों की थैलियों और डिब्बों पर अव्वल तो विवरण इतने महीन अक्षरों में लिखे होते हैं कि उन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। ज्यादातर विवरण अंग्रेजी में होते हैं। कितने लोग अंग्रेजी पढ़ पाते हैं। दूर-दराज गांवों के लोगों के लिए तो वह विवरण काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। फिर, ऐसे पदार्थों के उपभोक्ता ज्यादातर बच्चे, किशोर और युवा होते हैं। उनकी जीभ पर अब ऐसी चीजों का स्वाद इस कदर चढ़ चुका है कि वे विवरण बांच कर उन्हें खरीदते ही नहीं। ऐसे में जिम्मेदारी आखिरकार स्वास्थ्य और खाद्य से जुड़ी संस्थाओं की है कि वे ऐसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर ही अंकुश लगाने का कोई उपाय तलाश करें, जिनसे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है।

फिर अव्वल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नतीजे इस वर्ष भी उत्साहजनक रहे। इन परिणामों के आंकड़ों के विश्लेषण के साथ-साथ इसके सामाजिक पहलू पर भी चर्चा स्वाभाविक है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार चले आ रहे रुख के मुताबिक इस वर्ष भी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी। हालांकि छात्रों की सफलता का अनुपात भी काफी अच्छा है, मगर आगे होने के जो मानक तय किए गए हैं, उसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बारहवीं के नतीजों में कुल 87.33 फीसद विद्यार्थी पास हुए। इस बार 91.52 फीसद लड़कियों ने परीक्षा पास की है, जो लड़कों से 6.40 फीसद ज्यादा है। इसी तरह, दसवीं की परीक्षा में भी 94.75 फीसद लड़कियां सफल हुईं, जो लड़कों के मुकाबले 2.04 फीसद अधिक है।

जाहिर है, एक बार फिर लड़कियों ने यह साबित किया है कि यह महज अवसर मिलने की बात है। वे हर मोर्चे पर साबित कर सकती हैं कि एक पुरुष प्रधान समाज में उनकी क्षमताएं कहीं भी लड़कों से कम नहीं हैं। पढ़ाई-लिखाई के तमाम क्षेत्रों में यही देखा गया है कि लड़कियों को जहां भी मौका मिला है, वे लड़कों के मुकाबले अपेक्षया कम संसाधनों में भी बेहतर नतीजे देती हैं। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि सामाजिक स्तर पर कई तरह की वंचना और बाधाओं के बीच भी वे खुद को बेहतर साबित कर सकती हैं। यह छिपा नहीं है कि जन्म से लेकर बाद के जीवन तक में पढ़ाई-लिखाई से लेकर हर क्षेत्र में उनके सामने किस-किस तरह की अड़चनें आती रही हैं। लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रहों और संकीर्ण सोच वाले परिवार और समाज आमतौर पर उनके प्रति सहयोगात्मक रुख नहीं अख्तियार करते हैं। हालांकि वक्त बदलने के साथ काफी संख्या में माता-पिता अब अपनी बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई और उनके बेहतर भविष्य को लेकर सजग हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर होना इस बात का सबूत है। मगर लड़कियों की कामयाबी की यह धमक सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में कम दिखती है। सरकार और समाज को इस पहलू पर सजग होना होगा।

महिला उद्यमियों की बढ़ती जगह

विगत कुछ वर्षों में 'स्टार्टअप' उपक्रमों में महिलाओं की सहभागिता पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल देश में ऐसे आठ हजार से अधिक 'स्टार्टअप' उपक्रम हैं, जिनकी संस्थापक महिलाएं हैं।

अजय जोशी

आर्थिक क्षेत्र में नवप्रवर्तन करने, व्यवसाय और उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं तथा जोखिमों का सामना करने की योग्यता और प्रवृत्ति उद्यमिता है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं उन्हें साहसी या उद्यमी कहते हैं। देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसी आर्थिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण महिला उद्यमिता का अभाव है। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार देश के सभी उद्यमों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी केवल चौदह फीसद है। 'बेन एंड कंपनी' की एक रपट के अनुसार भारत में लगभग बीस फीसद उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। कई महिलाएं अपने उत्कृष्ट उद्यमिता कौशल से इस क्षेत्र में तेजी से आगे भी बढ़ रही हैं। ई-कामर्स, विज्ञान, विज्ञापन, मीडिया, मनोरंजन आदि कुछ क्षेत्र हैं, जहां भारतीय महिला उद्यमी तेजी से सफलता हासिल कर रही हैं।

वर्ष 2017 में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप दस फीसद थे, जो वर्ष 2022 में बढ़ कर अठारह फीसद हो गए। यानी हर पांच स्टार्टअप में से एक से भी कम में महिला की भागीदारी है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप उपक्रमों के विकास और विस्तार के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। इनमें महिलाओं की सहभागिता पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में देश में ऐसे आठ हजार से अधिक स्टार्टअप उपक्रम हैं, जिनकी संस्थापक महिलाएं हैं। अब तक इन स्टार्टअप की कुल राशि लगभग 23 अरब डालर यानी करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए है। इस दशक के आखिर तक महिला उद्यमियों की स्थिति में और सुधार आने की संभावना है। 'बेन एंड कंपनी' और गूगल की वर्ष 2019 की रपट के अनुसार वर्ष 2030 तक महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई तक पहुंच सकती है।

एक दशक पहले हुई आधिकारिक आर्थिक जनगणना से पता चला था कि भारत में कुल उद्योगों में महज 14 फीसद का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। अब यह हिस्सेदारी बढ़ कर 20 फीसद हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित उपक्रमों में लगभग 65 फीसद ग्रामीण क्षेत्र में हैं। दक्षिण के राज्यों की महिलाओं की हिस्सेदारी उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अधिक है। इन उपक्रमों में पिछली आर्थिक जनगणना के अनुसार लगभग 80 फीसद महिलाओं के उद्यम स्वयं वित्त पोषित हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं ने लघु महिला उद्यमियों को सबसिडी वाली और सुलभ पूंजी प्रदान करके, उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ कर, कौशल और बाजार विकास सहायता, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और आसान सूक्ष्म वित्त तक पहुंच प्रदान करके महत्त्वपूर्ण रूप से सहायता की है। मसलन, मिशन शक्ति जो 2021-22 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऐसा एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों को विभिन्न रूपों में सहायता की जाती है। इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की समर्थ योजना भी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है।

'अन्नपूर्णा' योजना योजना के अंतर्गत खाद्य और खानपान के व्यवसाय में महिला उद्यमियों को पचास हजार रुपए ऋण दिया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा शुरू की गई 'उद्योगिनी' योजना भी गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह योजना मुख्य रूप से देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाली अशिक्षित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।

> **माना जाता है कि महिलाओं की भूमिका घरेलू कर्तव्यों तक सीमित होनी चाहिए, इस कारण महिलाएं स्वयं भी अपनी भूमिका घर परिवार तक सीमित कर लेती हैं। इसके अलावा भारत में महिला उद्यमियों को अक्सर पूंजी जुटाने की समस्या आती है। उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने और ऋण प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि व्यवहार में देखा गया है कि महिलाएं अधिक ईमानदार ऋणी होती हैं। महिला उद्यमियों को अक्सर अपने उपक्रम के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उसको पर्याप्त सलाह और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता।**

हालांकि इन सभी योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों के संचालन में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, लेकिन उनको अभी भी बहुत-सी व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती तो देश में प्रचलित सामाजिक मानदंड और रूढ़ियां हैं। माना जाता है कि महिलाओं की भूमिका घरेलू कर्तव्यों तक सीमित होनी चाहिए, इस कारण महिलाएं स्वयं भी अपनी भूमिका घर परिवार तक सीमित कर लेती हैं। इसके अलावा भारत में महिला उद्यमियों को अक्सर पूंजी जुटाने की समस्या आती है। उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने और ऋण प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि व्यवहार में देखा गया है कि महिलाएं अधिक ईमानदार ऋणी होती हैं। महिला उद्यमियों को अक्सर अपने उपक्रम के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उसको पर्याप्त सलाह और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। इस कारण वे खुद में कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास की कमी महसूस करती हैं।

महिला उद्यमियों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं से अभी भी अपने घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके व्यवसाय के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा देना मुश्किल हो जाता है। महिला उद्यमियों की नेटवर्क, संसाधनों और अनुभव की कमी के कारण अक्सर बाजारों तक पहुंच सीमित होती है। इससे उनके लिए ग्राहक ढूंढ़ना, उनके साथ लेन-देन करना और अपना व्यवसाय बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। भारत में महिला उद्यमियों के पास अक्सर ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का भी अभाव रहता है, जो उन्हें उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में मार्गदर्शन दे सकें। शीर्ष पर महिला उद्यमियों की कमी के कारण महिलाओं के लिए खुद को उद्यमी के रूप में देखना मुश्किल होता है। महिला उद्यमियों के पास अक्सर प्रौद्योगिकी तक पहुंच भी सीमित होती है, जिससे नवाचार और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता में बाधा आ जाती है। इससे महिलाओं के लिए नई तकनीकों को अपनाना और प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो सकता है।

महिला उद्यमियों में अक्सर अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास की कमी नजर आती है, जो उन्हें अपने उद्यमशीलता के सपनों को पूरा करने से रोक सकती है। महिला उद्यमियों के पास विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों के व्यवसाय में सफल होने के लिए अक्सर आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होता है। इससे महिलाओं के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करना मुश्किल हो सकता है।

निस्संदेह महिला उद्यमिता न केवल किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि अत्यधिक व्यापक लैंगिक असमानताओं के कारण मौजूद बंधनों को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो महिलाएं स्वयं अपने में नवाचार और जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करें। इसके लिए परिवार के पुरुष सदस्य उनको प्रोत्साहित और पर्याप्त सहयोग करें। सरकार, समाज और स्थानीय समुदाय उद्यमशील अप्रशिक्षित महिला प्रतिभाओं की पहचान करके और उनको आवश्यक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में सहयोग करें, साथ ही महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु समुचित व्यवस्था करें तो देश की शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमी भी सफलता के नए आयाम स्थापित और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्त्वपूर्ण भागीदारी का निर्वाह कर सकती हैं।

स्वाद बनाम सेहत

पावनी

किसी का जन्मदिन हो, विवाह समारोह या फिर कोई भी मौका, आज देखते ही देखते हर तरह के जश्न में 'फास्ट फूड' की उपस्थिति अनिवार्य-सी हो गई है। हमारे समय का हलवा पूरी और पुदीने की चटनी अब चलन से बाहर हो चुके और एक 'पिछड़ी' हुई रुचि का खाद्य मान लिए गए हैं। अब कोई इनका जिक्र तक नहीं करना चाहता। पिज्जा और बर्गर की पहुंच तो कस्बे ही नहीं, गांव-गांव तक हो गई है। इसलिए अब पेस्ट्री और पास्ता के लिए गांवों में रहने वालों को शहर नहीं भागना पड़ता। पेशेवर तौर पर तैयार खाना घर पहुंचाने वाली कुछ कंपनियां तकनीक में ऐसी चाक-चौबंद और मुस्तैद हैं कि बहुत कम वक्त में अपनी छाप छोड़ चुकी है। यहां भी बच्चों का स्वाद बदलने के लिए आती ही जा रही है। भारत के चौबीस हजार से अधिक गांवों के नाम आज पांच फास्ट फूड पहुंचाने वाली कंपनियों के पास दर्ज हैं। आगे भी तैयारी चल रही है। गांव में कार्यक्रमों का आयोजन करके शायद बाकी गांवों में छा जाने का लक्ष्य है। माता-पिता का नाम, पास्ता और सैंडविच के प्रकार अब स्कूल जाते बहुत सारे पांच साल के बच्चे को भी याद होते हैं। करीब पांच साल के बच्चे तो मंचूरियन को भी दूर से पहचान लेते हैं। आज भारतीय समाज मे बच्चों की स्वाद ग्रंथि पर इन मीठे और नमकीन फास्ट फूड ने जितना गहरा स्थान बना लिया है, उतना नवरत्न चटनी, घी आटे का हलवा, लड्डू, नारियल की खीर, पकौड़े, चटपटे आलू जैसे देसी व्यंजन नहीं बना सके।

दुनिया मेरे आगे

> **यह बेवजह नहीं है कि पारंपरिक भोजन और भोजन शैली की जगह अब तेजी से सिकुड़ती जा रही है। लोगों के स्वाद बदल रहे हैं। इसके प्रति ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है कि कुछ लोग मानने लगे हैं कि यह दबी हुई भूख को जाग्रत कर देता है। पिज्जा या बर्गर का नाम लेते ही कुछ लोगों के मन में एक जायकेदार छवि बनने लगती है।**

ये पुरानी चीजें अब भुलाई जा रही हैं। तुरंता आहार या फास्ट फूड के कारोबार में हर दिन नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इनका आकार प्रकार, इस्तेमाल होने वाले रसायन, स्वाद, खुशबू, रंग, विविधता, खाने में सुविधाजनक होना फास्ट फूड की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। यह बेवजह नहीं है कि पारंपरिक भोजन और भोजन शैली की जगह अब तेजी से सिकुड़ती जा रही है। लोगों के स्वाद बदल रहे हैं। इसके प्रति ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है कि कुछ लोग मानने लगे हैं कि यह दबी हुई भूख को जाग्रत कर देता है। पिज्जा या बर्गर का नाम लेते ही कुछ लोगों के मन में एक जायकेदार छवि बनने लगती है। एक लत की तरह की रुचि का अध्ययन करने की जरूरत है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है! इसमें कौन-सी ऐसी चीज का प्रयोग किया जाता है कि लोग ऐसा सोचने लगते हैं!

आज हालत यह है कि बर्गर का एक टुकड़ा मुंह में रखकर आखें बंद कर आनंद से खाने वाला अगर परांठा खाए तो शायद उसे अरुचि हो। जबकि परांठे के गुण पिज्जा से हर हाल में कई-कई गुना अधिक है। मगर इस पर लोग अब शायद सोचते भी नहीं। दो-तीन दशक पहले तक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर गौर किया जाता था। वह ताजा बना हुआ है, यह भी देखा जाता था। अब ताजा और बासी का कोई प्रयोजन नहीं करना होता। 'ओवन' में बस कुछ सेकंड में बासी सैंडविच को गरमागरम ताजा बना लिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, कम से कम बीस लाख 'फास्ट फूड' के डिब्बे या पार्सल की आपूर्ति केवल राजधानी दिल्ली में होती है। इनमें सैंडविच, पिज्जा, बर्गर आदि खासतौर पर होते हैं। यह हैरानी की बात हो सकती है, मगर इसके साथ ही ठंडे पेयों की बिक्री का आंकड़ा शायद और भी चौंकाए।

स्वाद और जायके की दुनिया में गोते लगाएं और सेहत का रंग रूप भूल जाएं, यही मकसद है फास्ट फूड के कारोबार का। पार्सल को खोलकर उसमें से गरमागरम खाद्य पदार्थ निकालना और फिर आराम से बैठकर इसको एक-एक कौर दांतों से काटकर जीभ से रसीला बनाकर इसमें खो जाना एक तरह की खुशी है। कुछ समय पहले एक पाश्चात्य गायक किसी फास्ट फूड का प्रचार करते हुए इसे चटखारे लेकर खाए जा रहे थे। उनका एक संकेत यह भी था कि भोजन की फिक्र में सिर किसलिए खपाया जाए..! उनको इस तरह देखने वाले लोग भी दाल-चावल रोटी, साग, रायता, पापड़, चटनी भूलकर उसी खाने पर रीझ रहे होंगे। मनमोहक इश्तिहार देखकर मजबूत मन भी उसके साथ हिलने-डुलने लगता है। बच्चे हों या किशोर, युवा हों या वयस्क, हैसियत का पैमाना मान लिए गए फास्ट फूड के इंद्रजाल में ऐसे फंसते हैं जैसे सांप को रस्सी समझ लिया जाए। विडंबना यह है कि इसके नुकसान झेलने के बावजूद ऐसी नासमझी बरकरार रहती है। इसे सुधारा नहीं जाता। भले ही कब्ज हो, दस्त लग जाए, गला खराब हो, रसायन युक्त खाद्य से बदन ही दुखने लगे, बाल गिरने लगे, दांत खराब हो, कान दुखने लगे। मगर हर अगली भूख को तृप्त करने के लिए फिर उसी सम्मोहन में डूबे रहना लोगों को अच्छा लगता है।

आजकल छोटे-छोटे बच्चे इस तरह के खानपान के शौकीन बनकर इसके अर्ध कल्पित, अर्ध परिचित अर्ध सत्य के भ्रम में सेहत का नुकसान कर रहे हैं। उनके भविष्य को लेकर जरूर चिंतित होना चाहिए। इस तरह के खाने का उद्देश्य न तो किसी की सेहत बनाना है, न किसी को भोजन के माध्यम से अच्छी औषधीय गुण वाले व्यंजन परोसना है। हमारे यहां पारंपरिक भोजन में रायता और चावल को खाने से अतिसार एकदम ठीक हो जाता है। मूंग दाल का स्वादिष्ट चीला अगर पुदीने की चटनी के साथ खाया जाए तो पेट की समस्या, यानी अपच और कब्ज भी ठीक होती है। नारियल की चटनी और चने की रोटी या भरवां करेला ही मजे से खाया जाए तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज का सलाद खाने से लू नहीं लगती। मेथी की चपाती या पकौड़ी से बदन का दर्द दूर होता है। सवाल है कि हर तरफ पसर रहे बाजार के तुरंता खाने से सेहत में कितना सुधार होता है! अगर केवल स्वाद और आकर्षण में डूबा जाए तो धन तो जाएगा ही, सेहत भी दांव पर लगेगी।

नाकामी के बाद

'अंक नहीं जीवन' (7 मई) पढ़ा। आज बच्चों पर पढ़ाई का दबाव इतना अधिक है कि कई बच्चे खतरनाक कदम उठा चुके हैं। आज की बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अभिभावकों को यह समझना होगा कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता उन पर इतना बोझ न डालें कि वे ऐसा कदम उठा लें, जिन्हें वे जिंदगी भर नहीं भूल सकें। हमें उन लोगों के उदाहरण देने होंगे जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, मगर आगे सफल रहे। बच्चों में यह प्रवृत्ति विकसित की जाए कि एक परीक्षा में असफलता मिली है तो अगली में सफल हुआ जा सकता है। कहीं न कही परीक्षाओं में नंबर हासिल करने की गलाकाट स्पर्धा शिक्षा को नीरस व अवसाद पैदा करने वाली बना रही है। जीवन अवसर देता है और बार-बार देता है। क्या किसी एक परीक्षा की सफलता-असफलता पर ही भविष्य की सारी सफलताएं, योजनाएं निर्भर करती हैं? नहीं। जीवन में सफलता का पैमाना सिर्फ नंबर नहीं है। अब समय आ गया है जब बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करना होगा, समाज को युवाओं को हालात से लड़ना सिखाना होगा, मनोबल मजबूत करने के हरसंभव प्रयास करने होंगे।

– साजिद अली, चंदन नगर, मप्र

उदासीनता और दावानल

गर्मी आते ही जगह-जगह जंगल में आग लगने की खबरें आने लगती हैं। दावानल वह पीड़ादायी सत्यता है जिसमें वन तो जलकर खाक होता ही है, साथ में घास-फूस, पेड़ पौधों के कचरे से बनने वाली उर्वरा शक्ति, वन्य जीवों के आहार और नए पनपने वाले पौधों को भी समाप्त कर देता है। इस आग से जो नुकसान पर्यावरण को होता है, वह अलग से। अब तक इस समस्या का स्थायी कारगर उपाय नहीं कर पाना हमारी उदासीनता को दर्शाता है। दावानल को रोकने के लिए स्थायी उपाय खोज कर उन्हें मूर्तरूप देने के लिए काम करना होगा। विशाल वन क्षेत्रों के हर हिस्से में जलाशय बना कर आग को सीमित क्षेत्र में बांधा जा सकता है। गर्मी के दिनों में लगातार निगरानी तथा आग लगते ही युद्ध स्तर पर किए गए प्रयास से ही वन संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। जनसहयोग तथा प्रशासनिक नेकनीयत से जंगल की आग पर काबू पाना कोई मुश्किल बात नहीं है।

– हुकुम सिंह पंवार, टोड़ी, इंदौर

मतदान का हक

हाल ही में सूरत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कुछ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन कुछ दस्तावेजी त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया। इंदौर में भी इसका उदाहरण सामने आया, क्योंकि यहां भी भाजपा के सामने मुख्य विरोधी दल कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन के आखिरी दिन अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर भाजपा का दामन थाम लिया। मगर बिना चुनाव कराए किसी प्रत्याशी की जीत घोषित कर देना क्या स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सही है? मतदाताओं से उनके अधिकार को छीनना कितना सही है? चुनाव आयोग को सोचना होगा कि ईवीएम में एक नोटा का भी बटन होता है जो मतदाताओं को मतदान में हिस्सा लेने और राजनीतिक दलों द्वारा घोषित उम्मीदवार के प्रति असंतुष्टि को बयां करने का अधिकार देता हैं। कई ऐसे भी मतदाता होंगे, जिनमें पहली बार मतदान करने का अलग ही उत्साह रहा होगा।

– दिनेश शाह, सिंगरौली

हौसले से जीवन

मनुष्य का जन्म पाना सौभाग्य का सूचक माना गया है। घर में बच्चे का जन्म होता है, तो उस घर के लोगों को जो खुशी होती है, उसे बयान करना कठिन है। इससे परिवार बनता है। बच्चे के मां-पिता इसकी बेहतरी के लिए और अधिक कमाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हर संतान को माता-पिता का यह ऋण अच्छे काम करके चुकाना चाहिए। आज लोग मां-पिता के त्याग की कद्र नहीं करते। कोई युवा प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण खुदकुशी कर रहा है, तो कोई कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी जान ले रहा है। आत्महत्या के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद उसके माता-पिता बेहद तनाव में रहते हैं। वे चार लोगों से अपना दुख भी नहीं कह सकते। इसलिए व्यक्ति को आखिरी सांस तक अपने जीने का हौसला बनाए रखना चाहिए।

– दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AllNewsPaper_pdf

www.readwhere.com

चिंतन

चाबहार पोर्ट समझौता भारत की बड़ी उपलब्धि

चीन और ईरान के बीच बढ़ती दोस्ती के बीच भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए दस वर्षीय दीर्घकालीन समझौता कर बड़ी कूटनीतिक सफलता पाई है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अब भारत पाकिस्तान को बायपास कर सीधे अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया व यूरोप तक पहुंच सकेगा। बीच आम चुनाव के दौरान हुए इस समझौते से भारत के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट के महत्व को समझा जा सकता है। मुंबई पोर्ट से चाबहार पोर्ट तक जलमार्ग भारत के लिए यूरोप का द्वार खोलता है। भारत और ईरान ने चाबहार में स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के टर्मिनल के परिचालन के लिए सोमवार को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह पहला मौका है जब भारत विदेश में स्थित किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं, लाभ अफगानिस्तान को भी होगा। चाबहार बंदरगाह 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा' (आईएनएसटीसी) परियोजना का एक प्रमुख लिंक है। आईएनएसटीसी परियोजना भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल-ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी एक बहुस्तरीय परिवहन परियोजना है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में, 23 मई, 2016 को चाबहार में निर्माण को लेकर रणनीतिक समझौता हुआ था। इसके बाद वर्ष 2018 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रुहानी नई दिल्ली आए तो चाबहार बंदरगाह पर भारत की भूमिका पर बातचीत हुई थी। जनवरी 2024 में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर तेहरान में थे, तब भी यह मुद्दा उठा था। वर्ष 2016 से भारत चाबहार को विकसित कर रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के बाद से भारत की उदासीनता के चलते चाबहार डील की गति सुस्त हो गई थी। बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य में चीन की ईरान में बढ़ती दिलचस्पी से चाबहार पोर्ट समझौता पर भी ग्रहण लगता नजर आया, पर ईरान ने भारत के साथ अपने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों को अधिक तवज्जो दिया और अंततः चाबहार समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत ईरान का बड़ा तेल खरीदार है। भारत ने हाल में जिस तरह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए हैं और सऊदी अरब व ईरान में नजदीकी बढ़ी है, उसे देखते हुए ईरान के साथ भारत की व्यापारिक प्रगाढ़ता से मध्य एशिया व खाड़ी क्षेत्र में नई दिल्ली की पैठ बढ़ेगी। ईरान प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक है। अरब सागर, अदन की खाड़ी व लाल सागर में भारतीय नौसैनिक बहुत मजबूत है, इसलिए इन क्षेत्र के देशों से भारत के अच्छे रिश्ते भारत के लिए अच्छा है। इस समझौते से भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ-साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए चाबहार का उपयोग करना चाहते हैं। यह समझौता भारत की प्रगति के लिए बड़ी उपलब्धि है।

विश्लेषण

आर.के. सिन्हा

संगठन-सरकार में रणनीति के 'शाह'

अमित शाह ने पहले भाजपा के संगठन में रहते हुए और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए उनके संगठनात्मक कौशल को सबने देखा। फिर, 2019 में, वह केंद्रीय गृह मंत्री बने, और इसके साथ ही शुरू हुआ कई बड़े फैसलों को लेने का दौर। पिछले पांच वर्षों में, अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को नया रूप दिया है। गृहमंत्री बनने के तीन महीने बाद, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकारी कदम में सबसे आगे थे। अमित शाह की सरपरस्ती में, आंतरिक आतंकवाद का खतरा भी कम हुआ है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया है।

आज चार चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग ने चार सौ पार का नारा दिया है। उसी अनुरूप भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा का सांगठनिक ढांचा बेहद शिद्दत से चुनाव के लक्ष्य को अंजाम देने में जुटा है। भाजपा की तैयारी में सबसे अहम भूमिका पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह निभाते हैं। अमित शाह राजधानी में अपने साउथ ब्लॉक के दफ्तर में जब काम करते होंगे, तब उनके जेहन में भी देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार पटेल का ख्याल अवश्य आता होगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने भी इसी साउथ ब्लॉक में बने गृह मंत्री कार्यालय से ही से देश की आंतरिक सुरक्षा को एक नई दिशा दी थी। वे भी बोलने में कम और काम करने में अधिक यकीन करते थे। अमित शाह का एक गुण यह भी है कि वे किसी अनावश्यक विवाद को खत्म करने में देर नहीं करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शायद सोचा होगा कि वे अमित शाह को देश का भावी प्रधानमंत्री बताकर एक विवाद खड़ा कर देंगे, पर उनकी यह मंशा सफल नहीं हुई, क्योंकि अमित शाह ने साफ कर दिया कि नरेन्द्र मोदी ही 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

अमित शाह ने पहले भाजपा के संगठन में रहते हुए और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए उनके संगठनात्मक कौशल को सबने देखा, लेकिन जो लोग उन्हें गुजरात के दिनों से जानते थे, वे बहुत हैरान नहीं हुए। फिर, 2019 में, वह केंद्रीय गृह मंत्री बने, और इसके साथ ही शुरू हुआ कई बड़े फैसलों को लेने का दौर। पिछले पांच वर्षों में, अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देखरेख में भारतीय दंड विधान (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को बदला गया। अमित शाह मानते हैं कि कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। 1860 से 2023 तक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ।

आपको याद होगा जब जब भारत अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे। नए आपराधिक कानून उनमें से एक को पूरा करते हैं। सरकार ने नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम दिया है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को प्रधानमंत्री का विश्वास और पूरा भरोसा प्राप्त है। वास्तव में, जब कोई राजनीतिक या सरकारी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष लाया जाता है, तो कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति से अमित शाह से भी सलाह लेने के लिए कहते हैं। 2019 में, गृहमंत्री बनने के तीन महीने बाद, अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकारी कदम में सबसे आगे थे। इसके लिए कुशल राजनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता थी। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा समर्थन हासिल था। चार साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वैधता को बरकरार रखा,

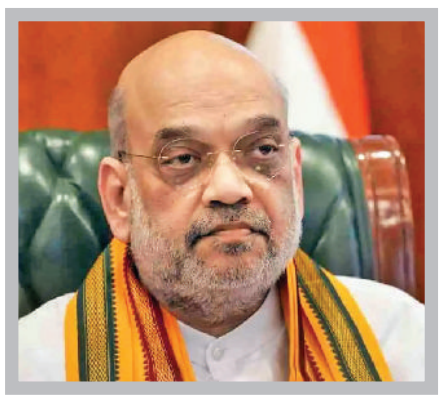

जो कि भाजपा ने भारत के अंतिम एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा था।

अमित शाह 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की पीछे प्रेरक शक्ति भी रहे हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं - उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आशंका थी कि सीएए को विपक्ष मुद्दा बनाएगा। पर यह नहीं हुआ। इसकी बेशक एक बड़ी वजह यह रही कि अमित शाह देश के मुसलमानों को भरोसा देते रहे कि सीएए कानून का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। याद करें कि राजधानी के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ महिलाओं ने लंबा धरना दिया था। धरने देने वाली महिलाएं कह रही थीं कि सीएए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। धरना कोविड के फैलने के कारण सरकार ने सख्ती से बंद करवा दिया था। उस समय धमकी दी जा रही थी कि सीएए के खिलाफ धरना फिर शुरू होगा। पर यह नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बार-बार मुसलमानों को भरोसा देते रहे कि सीएए से उन्हें घबराने की कोई वजह नहीं है। इसका सकारात्मक असर हुआ। जब केन्द्र सरकार ने सीएए की पिछली 11 मार्च को अधिसूचना जारी की तो एक बार लगा कि इसका विरोध होगा, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए की अधिसूचना के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सीएए को लागू करने के मसले को लोकसभा चुनाव में उठाएंगे। सीएए, एनआरसी और धारा 370 जैसे मुद्दे कॉंग्रेस के घोषणापत्र से ही गायब हैं। सीएए पर दिल्ली से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गया था और जल्दी ही यह हिंदू- मुस्लिम विवाद में बदला था। दिल्ली में सार्वजनिक संपत्ति को खूब नुकसान पहुंचाया गया और विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हुए थे। एक लोकतांत्रिक देश में हर मुद्दे पर विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी हक है। जबकि विधेयक में पहले दिन से कहा गया था कि यह पाक, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए केवल उन शरणार्थियों पर लागू किया जाएगा जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण के लिए मजबूर थे।

खैर, अमित शाह की सरपरस्ती में, आंतरिक आतंकवाद का खतरा भी कम हुआ है। इस्लामिक स्टेट का उदय, पहले सीरिया और बाद में अफगानिस्तान में, चरमपंथी प्रवृत्ति वाले कई युवाओं को विदेशी जमीन में युद्ध लड़ने के लिए देश से बाहर जाते हुए देखा गया। इससे 2014 में कट्टरपंथ और ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंग के नए खतरों के बारे में चिंता पैदा हुई थी, लेकिन गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां आज इनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित राज्यों में, सुरक्षा बल धीरे-धीरे उन क्षेत्रों में वापस आ रहे हैं जिन्हें कभी रेड जोन माना जाता था। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नक्सलियों पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऐसा पिछले साल दिसंबर महीने में भी देखने को मिला था। अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा के कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। फिर वो चाहे, नक्सलवाद के खिलाफ हो या आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद और नक्सलवाद लोकतांत्रिक तरीके नहीं हैं और इन्हें समाप्ति कर देना चाहिए। केंद्र में भाजपा नीत राजग के तीसरी बार सत्ता में आने में अमित शाह की रणनीति की अहम भूमिका होगी।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार व पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

टेक अलर्ट

शिशिर शुक्ला

बिंजवाचिंग की बढ़ती लत लोगों को बना रही बीमार

तकनीकी के इस दौर में लगभग प्रत्येक व्यवस्था का डिजिटल रूप भी अस्तित्व में आ चुका है। उदाहरण के तौर पर पढ़ाई से संबंधित तमाम कंटेंट ऑफलाइन तो उपलब्ध है ही, साथ ही वह डिजिटल रूप में ऑनलाइन भी विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हमारे लिए सुलभ है। हम में से हर कोई यह भली-भांति जानता है कि ड्रग्स का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है किंतु फिर भी एक बड़ा वर्ग और विशेषकर युवा वर्ग ड्रग्स की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। अचंभे की बात तो यह है कि डिजिटलीकरण ने ड्रग्स को भी नहीं छोड़ा और उनके डिजिटल स्वरूप को जन्म दे दिया। जी हां, मेरा आशय है डिजिटल ड्रग से। सुनकर बड़ा अटपटा लगता है और दिमाग में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से कौंधने लगता है कि आखिरकार यह क्या बला है। लेकिन यह एक कटुसत्य है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग डिजिटल ड्रग का आदी हो चुका है।

मामले को पूर्णतया समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि डिजिटल ड्रग आखिरकार क्या है। जिस प्रकार ड्रग का इस्तेमाल लोग अपने मस्तिष्क को अल्पकालिक शांति अथवा प्रसन्नता का अनुभव कराने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल ड्रग का अर्थ है– ऐसे डिजिटल कंटेंट को देखने की लत लग जाना जो दिमाग को सुकून एवं खुशी का एहसास कराते हैं। इनमें कोई संगीत हो सकता है, कोई मूवी अथवा कोई वेब सीरीज भी हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर एक बार वेबसीरीज देखना शुरू कर दें तो उनकी प्रवृत्ति कुछ यूं बन जाती है कि मानो सारे के सारे एपिसोड खत्म करके ही उनको चैन मिलेगा। आजकल ओटीटी प्लेटफार्मों पर वेबसीरीज की भरमार है। मूवी तो फिर भी दो से ढाई घंटे में खत्म हो जाती है लेकिन वेबसीरीज में अमूमन दस से लेकर बारह तक एपिसोड रहते हैं और प्रत्येक एपिसोड लगभग एक घंटे का होता है। इस हिसाब से एक वेबसीरीज को पूरी तरह से देखने के लिए लगभग दस घंटे चाहिए। अब अगर किसी के अंदर लगातार दस घंटे तक मोबाइल अथवा लैपटॉप में आंखें गड़ाकर पूरी वेबसीरीज को खत्म करने की लगन है, तो कहीं न कहीं उसे सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये लक्षण एक विशेष तरह के एडिक्शन की तरफ इशारा करते हैं। जाहिर सी बात है कि लगातार दस घंटे तक मोबाइल फोन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए पूर्णतया घातक है।

लगातार कई घंटे तक टेलीविजन अथवा मोबाइल को देखते रहना तकनीकी शब्दकोश में बिंजवाचिंग कहलाता है। प्रायः हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि अपने पसंदीदा संगीत को सुनने अथवा पसंदीदा मूवी एवं वेबसीरीज को देखने से हमें एक विशेष प्रकार की खुशी मिलती है। किंतु यह भी सत्य है कि इस प्रकार की खुशी सदैव क्षणिक अथवा अल्पकालिक होती है। ज्यों ही हम उस माहौल से बाहर निकलकर पुनः वास्तविकता के घेरे में प्रवेश करते हैं, हमारी मनःस्थिति पुनः परिवर्तित होने लगती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पसंदीदा संगीत अथवा मूवी आदि पर अपना ध्यान पूर्णतया केंद्रित कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन स्रावित होता है। यह रसायन ही उस क्षणिक प्रसन्नता के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही डोपामाइन का प्रभाव शांत होता है, हम पुनः उसी अवस्था में वापसी कर जाते हैं। यह क्रियाविधि हूबहू वैसी ही है जैसे कि नशे की दवाइयां अथवा इंजेक्शन की होती है। खास बात यह है कि डिजिटल ड्रग की लत के दुष्प्रभाव भी वैसे ही हैं जैसे कि नशे की दवाओं के। पहली बात तो यह कि घंटों मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहने से विकिरण की एक बड़ी मात्रा हमारे मस्तिष्क एवं आंखों के संपर्क में आती है। पूर्वी फिनलैंड विश्वविद्यालय में हुए एक शोध के अनुसार टीवी एवं मोबाइल पर एक सीमा से अधिक समय बिताना हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह एवं रक्तचाप जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल ड्रग एवं बिंजवाचिंग की लत के अनेक अन्य गंभीर दुष्परिणाम भी सामने आए हैं ,जैसे डिप्रेशन की समस्या, एंग्जायटी की समस्या, मूड स्विंग की समस्या इत्यादि। इसके अलावा जो लोग लगातार लंबे समय तक स्क्रीन से संपर्क बनाए रहते हैं उनके लिए अनिद्रा भी एक बेहद गंभीर समस्या बन जाती है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जो अगर एक बार किसी के साथ लग गईं तो फिर इनसे पीछा छुड़ा पाना एक नितांत मुश्किल कार्य हो जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि डिजिटल ड्रग की लत आज के समय में एक बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका है। यदि समय रहते इसका निवारण न किया गया तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यह जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाएगा।

(लेखक विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय, मुमुक्षु आश्रम, शाहजहांपुर हैं।)

मन की एकाग्रता जरूरी, चंचलता से भटकाव

संकलित

दर्शन

जिसने भी अपने मन को साध लिया उसके लिए हर लक्ष्य आसान हो जाता है। मन की एकाग्रता हमें हमारी आत्मा से साक्षात्कार कराकर हमारी सफलता के नए द्वार खोलती है। इसलिए आज से ही मन को साधने में जुट जाइए। मनुष्य के मन का स्वाभाविक गुण है चंचल होना यानी एकाग्र न होना। इसका चंचल गुण बार-बार हमें हमारे लक्ष्यों से विमुख करता रहता है। मनुष्य का मन उसको भावनाओं और कामनाओं के जाल में बांधकर भांति-भांति के कार्य करवाता है। हमारा मन हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी होता है। इसका जिस ओर मन करता है वह उधर ही इसको ले जाता है। इसमें प्रायः गलत राह भी पकड़ ली जाती है। मन का अधिक झुकाव विषयों एवं विकारों की तरफ रहता है। वहां पर हमें इसको बांधने और रोकने की जरूरत महसूस होती है। इसके लिए गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, 'हे अर्जुन यदि तुम धीर मति वाले और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हो तो मन की चंचलता पर काबू पाया जा सकता है। मन का मुंहजोर घोड़ा आरंभ में सवार को अपनी पीठ पर आसीन नहीं होने देता है, लेकिन अगर बार-बार कोशिश की जाए तो वह उसे सवार भी होने देगा, उसकी बात मानेगा और उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा भी, पर सबसे कठिन होता है मन को किसी एक लक्ष्य पर टिका कर रखना। मन के दृढ़ निश्चयी होने पर ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना।

योग का अर्थ अपने कार्यों में दक्षता लाना

संकलित

प्रेरणा

'योग का अर्थ अपने कार्यों में दक्षता लाना है।' योग सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि किसी विशेष परिस्थिति में दक्षता के साथ यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो वह भी योग ही है। नवीनता, पूर्वाभास, कौशल और बेहतर संवाद, ये सभी योग के ही प्रतिफल हैं। यह शरीर, मन और भावनाओं को सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़ता है। योग का अर्थ है- जोड़ना। जीवन के समस्त तत्वों को विधिवत जोड़ना। धन से हमें खुशी और आराम मिलता है। योग एक ऐसा धन है, जिससे हमें संपूर्ण आराम मिलता है। योग से न सिर्फ हमारा शरीर रोगमुक्त होता है, बल्कि समाज भी हिंसा रहित होता है। संशय से मुक्त मन, बुद्धि की स्पष्टता, आघात मुक्त स्मृति और दुख से मुक्त आत्मा तो प्रत्येक मानव जीवन का अधिकार है। सभी लोग इस मकसद को पाने के लिए तड़प रहे हैं। योग इसका आसान-सा उत्तर है। लोग सोचते हैं कि योग महज कसरत भर है। ऐसा नहीं है। आज यह जानकर प्रसन्नता होती है कि योग के महत्व को पहचानकर उसे मुख्य धारा में लाया जा रहा है। विश्व भर में योग आराम, खुश रहने और रचनात्मकता का पर्याय माना जाने लगा है। योग तो व्यक्ति का व्यवहार बदल देता है। व्यवहार व्यक्ति के तनाव के स्तर से सीधे संबंध रखता है। यह उस व्यक्ति में मित्रता के भाव जाग्रत करता है। योग हमारे वाइब्रेशन में फर्क लाता है। हम अपनी उपस्थिति से कई बार बहुत कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं, जितना कि हम बोलकर नहीं कर सकते।

कामयाबी की खुशी

सीबीएससी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास होने के बाद ऐसी खुशी।

आज की पाती

भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत

भीषण गर्मी के चलते प्रदेश के अधिकतर जलाशयों और बांधों का जलस्तर काफी गिर गया है। कई तालाब सूख गए हैं। वहीं, पेयजल की किल्लत विकराल हो रही है। मई के प्रारंभ में ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां लोगों का हाल बेहाल हो गया है, वहीं पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। पेयजल को लेकर राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भटकना लोगों की मजबूरी बन गई है। पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। जल आवर्धन योजनाएं अधूरी होने का खामियाजा प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

– *राकेश चौहान, रायपुर*

करंट अफेयर

इजराइली सेना ने रफह को बताया हमास का आखिरी गढ़

इजराइली सेना ने रविवार को गाजा पट्टी में फलस्तीनी उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के साथ ही युद्ध के दौरान लगभग तबाह हो चुके उत्तर के कुछ हिस्सों में भी कार्रवाई की। हालांकि, सेना ने कहा कि उसने महीनों पहले ही उत्तर के इलाकों को हमास के नियंत्रण से मुक्त करा लिया था, लेकिन सुरक्षा बलों के हटने के बाद समूह एक बार फिर इन इलाकों में एकत्र होने का प्रयास कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के रफह शहर को हमास का आखिरी गढ़ करार दिया है। सेना का कहना है कि हमास को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उसे कार्रवाई जारी रखनी होगी। इजराइल की तरफ से हाल के दिनों में कार्रवाई तेज करने की बात कहे जाने के बाद 3,00,000 लोगों को क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। फलस्तीनियों ने बताया कि जबालिया शरणार्थी शिविर और उत्तरी गाजा पट्टी के अन्य क्षेत्रों में इजराइल की ओर से रात भर भारी बमबारी की गई, जिससे व्यापक तबाही हुई है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इजराइली युद्धक विमानों ने शरणार्थी शिविर और गाजा शहर के पूर्व में जिटौन क्षेत्र पर हमला किया, जहां सैनिक एक सप्ताह से अधिक समय से फलस्तीनी उग्रवादियों से लड़ रहे हैं।

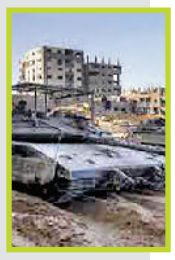

ऑफ बीट

शिव जी का इकलौता मंदिर जहां नहीं है नंदी की प्रतिमा

शिवालयों में नंदी की पूजा किए बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हर शिवालय में शिवलिंग के सामने नंदी जरूर होते हैं लेकिन देश का एकलौत शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक के गोदावरी तट के पास कपालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहां भगवान शिव की प्रतिमा तो है लेकिन उनके वाहन नंदी स्थापित नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। चार मुख वेदोच्चारण करते थे और पांचवां मुख हमेशा लोगों की बुराई करता था। एक बार इंद्रसभा की सभा में ब्रह्मदेव का पांचवा मुख भगवान शिव की निंदा करने लगा जिससे क्रोधित होकर उस मुख को ब्रह्मदेव के धड़ से अलग कर दिया। भोलेनाथ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए सोमेश्वर में एक बछड़े ने शिवजी को उपाय बताया। इस बछड़े पर भी अपने मालिक जो ब्रह्मण था उसकी हत्या का पाप लगा था। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए बछड़े ने शिव जी को वही उपाय बताया जो उसने स्वयं किया था। बछड़े ने शिव जी को नासिक के पास स्थित रामकुंड में स्नान करने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ ने बछड़ा यानी कि नंदी को अपना गुरु मान लिया।

ट्रेंड

आम आदमी को लाभ मिला

चुनाव प्रचार के मेरे आखिरी दिन हमारी टीम ने लद्दाख के जांस्कर में ऐतिहासिक नई निम्मू-पदुम-दारचा सड़क पर टेस्ट ड्राइव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में 10 वर्षों के भीतर हमारे देश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को बदल दिया है। इसका सीधा लाभ आम आदमी को मिला है।

-किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

आ चुके होंगे रुपए

एक जुलाई 2024 को सुबह सुबह गरीब परिवार की महिलाएं जब अपना अकाउंट चेक करेंगी तो उसमें 8500 रुपए आ चुके होंगे और इंडिया की सरकार में ऐसा हर महीने की पहली तारीख को होगा। ये है आपके एक वोट की ताकत।

-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

बाहर आ जाऊंगा

अगले 21 दिनों में जहां-जहां संभव होगा, वहां जाऊंगा और बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करूंगा। आप लोग अब जमकर मेहनत कीजिए। मुझे 2 जून को वापस जेल जाना होगा लेकिन अगर आप लोग 4 जून को इंडिया की सरकार बनवाएंगे तो मैं 5 को ही बाहर आ जाऊंगा।

-अरविंद केजरीवाल, सीएम दिल्ली

मां को खुश रखो

जब से पैदा हुआ हूं, तबसे मां का धन्यवाद करते हुए मां दिवस मना रहा हूं। आजकल हर बात का एक दिन बन गया तो हैप्पी मदर डे आप सबको, जीवन में खुश रहना चाहते हो तो पूरा जीवन मां को खुश रखो। जय माता की।

-अनुपम खेर, अभिनेता

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com